ध्येयIAS®
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

यूपीएससी व पीसीएस परीक्षाओं के लिए संपूर्ण पाक्षिक

वर्ष 5 | अंक 11 | जून 2023 / Issue 01 | मूल्य: ₹ 55

dhyeyaias.com

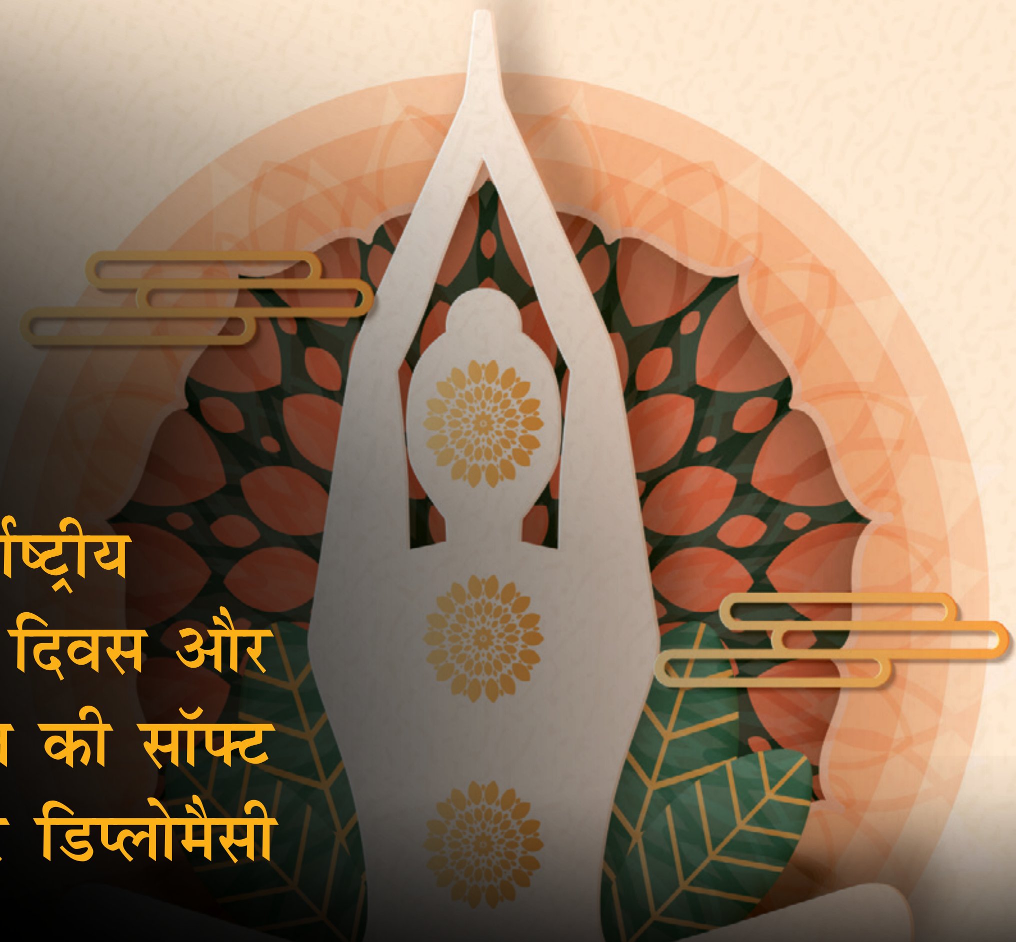

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और भारत की सॉफ्ट पॉवर डिप्लोमैसी

- भारत में एथेनॉल क्षेत्र से संबंधित नीतिगत उपाय और उपलब्धियां
- समुद्री जैव विविधता के समक्ष उभरते नए खतरे
- द केरल स्टोरी: विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दे
- हिंद महासागर सम्मेलन के जरिए भारत की महासागरीय कूटनीति
- राष्ट्रीय सुरक्षा में नेशनल इनवेस्टिगेशन एजेंसी की भूमिका का मूल्यांकन
- जी-20 की जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक का महत्त्व

मुख्य परीक्षा विशेष: इतिहास व कला एवं संस्कृति पर आधारित महत्त्वपूर्ण प्रश्न

परफेक्ट-7

करेंट अफेयर्स मैगजीन ही क्यों?

1. सर्वप्रथम परफेक्ट-7 करेंट अफेयर्स मैगजीन, **प्रत्येक 15 दिन** में प्रकाशित होती है जिससे छात्र करेंट अफेयर्स से अप-टू-डेट रहते हैं, वहीं अन्य कोचिंग संस्थानों की पत्रिकाएं मासिक होती हैं जिससे महीने भर की करेंट अफेयर्स एक साथ एकत्र हो जाती हैं। अधिक करेंट अफेयर्स होने के कारण छात्र प्रायः सभी लेखों को पढ़ नहीं पाते। अंततः वे वार्षिकी और अर्द्धवार्षिक मैगजीन पर निर्भर हो जाते हैं।
2. परफेक्ट-7 मैगजीन **आईएएस और पीसीएस केंद्रित परीक्षा** को ध्यान में रखकर बनाई गई है, वहीं अन्य कोचिंग संस्थानों की पत्रिकाओं में आईएएस और पीसीएस परीक्षा के नाम पर अनावश्यक एवं अतिरिक्त सामग्री शामिल कर देते हैं, जिससे छात्रों में कन्फ्यूजन हो जाता है।
3. परफेक्ट-7 मैगजीन में 15 दिन के दौरान महत्त्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी घटनाओं पर **विषय विशेषज्ञों द्वारा 7 संपादकीय लेख, महत्त्वपूर्ण घटनाओं और सूचनाओं पर 42 लेख, रचनात्मक शैली में 7 ब्रेन-बूस्टर, करेंट अफेयर्स, वन लाइनर, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा संबंधित प्रश्न** आदि दिए जाते हैं। इसके साथ व्यक्ति विशेष नाम का एक खंड भी है जो ऐतिहासिक व्यक्तित्व के देश और समाज के प्रति योगदान को दर्शाता है। इस तरह 15 दिन की अवधि में आईएएस, पीसीएस परीक्षा केंद्रित कोई भी महत्त्वपूर्ण सूचना और खबर नहीं छूटती।
4. इसके साथ ही **केस स्टडी खंड** के माध्यम से छात्र यह सीखते हैं कि एक अधिकारी को अपने कार्यकाल के दौरान कैसी परिस्थितियों का सामना करना होता है और उसका क्या समाधान हो सकता है?
5. परफेक्ट-7 करेंट अफेयर्स मैगजीन के माध्यम से Dhyeya IAS के सबसे महत्त्वपूर्ण परीक्षा कार्यक्रम **PMI (Pre + Mains + Interview)** की अच्छे से तैयारी हो जाती है।
6. करेंट अफेयर्स आधारित कक्षाओं में परफेक्ट-7 के माध्यम से तैयारी कराई जाती है जिससे छात्रों की गुणवत्तापूर्ण तैयारी हो पाती है।
7. परफेक्ट-7 मैगजीन **प्रत्येक माह की 10 और 25 तारीख** को छात्रों के लिए उपलब्ध हो जाती है, वहीं अन्य संस्थानों की मैगजीन में करेंट अफेयर्स पिछले महीने का होता है और पत्रिका में आगे का अगला महीना अंकित होता है, अर्थात करेंट अफेयर्स लगभग 1 माह पुराना होता है।
8. परफेक्ट-7 मैगजीन में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा केंद्रित मॉक टेस्ट रहते हैं जिसके माध्यम से छात्र अपनी तैयारी को और भी सटीक बना सकते हैं।

-: For any feedback Contact us :-
+91 6393005298
perfect7magazine@gmail.com

OUR OTHER INITIATIVES

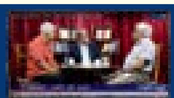

DHYEYA TV
Current affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
Ex. Editor RSTV) & by Dhyeya Team
Broadcasted on YouTube & Dhyeya TV

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

पहला पन्ना

करेंट अफेयर्स संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों की ओर से आयोजित परीक्षाओं की तैयारी में अति महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों पर प्रासंगिक सूचनाओं से जुड़ाव होना अभ्यर्थियों के लिए काफी जरूरी समझा गया है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए परफेक्ट-7 पत्रिका का पाक्षिक प्रकाशन किया जा रहा है। आईएएस और पीसीएस की तैयारी तभी पूर्ण मानी जाती है जब प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू स्तर की गतिशील प्रकृति के राज्यों और विश्लेषणों को आप सभी तक समावेशी रूप में रखा जाये। परफेक्ट-7 मैगजीन इसी विजन और दृष्टिकोण को ध्यान में रखती है और विद्यार्थियों की कटेंट के स्तर पर बहुआयामी जरूरतों को समझती है। इसीलिए इस मैगजीन को करेंट अफेयर्स के साथ-साथ सामान्य अध्ययन के महत्त्वपूर्ण खंडों से जुड़े अति प्रासंगिक कंटेंट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। एक तरफ जहां करेंट अफेयर्स के स्तर पर सबसे पहले मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 7 ज्वलंत विषयों पर समसामयिक लेखों को, स्वतंत्रता आंदोलन और अन्य क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तित्व की जीवनी और भूमिकाओं को, सामान्य अध्ययन के विविध खंडों के सर्वाधिक उपयोगी विषयों पर मुख्य परीक्षा के स्तर पर कवरेज दिया जा रहा है, वहीं प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर 15 दिन पर सबसे महत्त्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के मुद्दों को कवर किया जा रहा है जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र, लोक प्रशासन, कला-संस्कृति, विज्ञान-प्रौद्योगिकी, राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर जोर दिया जाता है।

विद्यार्थियों की संकल्पना के स्तर पर समझ को बढ़ने के लिए ब्रेन-बूस्टर सेक्शन में 7 ग्राफिक्स के जरिये विषय को संक्षेप और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके अलावा सिविल सर्विसेज की परीक्षा में प्रमुखता से पूछे जाने वाले ग्लोबल इनिशिएटिव्स, वैधिक संस्थाओं, संगठनों की संरचना, कार्यप्रणाली, महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट्स, सूचकांकों पर अपडेटेड जानकारी इस पत्रिका में शामिल रहती है। इस मैगजीन को केवल बच्चों व केवल एनालिसिस पर जोर देते हुए नहीं बनाया गया है बल्कि इस मैगजीन का ध्येय यह है कि सिविल सेवा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के उभरते हुए ट्रेंड्स और प्रश्नों की नई प्रकृति को देखते हुए अभ्यर्थियों को एक ऐसी समावेशी मैगजीन उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे सिविल सेवा एग्जाम की नई जरूरतों को समझते हुए अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें। पत्रिका के प्रारूप में अभ्यर्थियों की तथ्यात्मक आवश्यकताओं, मानसिक विकास, लेखन प्रविधि विकसित करने जैसे विषयों को ध्यान में रखते हुये स्तंभ शामिल किये गये हैं। इसके साथ ही हम अभ्यर्थियों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप नये स्तंभ शुरू करते रहे हैं और आगे भी यह क्रम जारी रहेगा। आशा है कि आप सभी के लिये यह अंक उपयोगी सिद्ध होगा। हमें आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ।

विनय कुमार सिंह
संस्थापक
ध्येय IAS

ध्येयIAS
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

यूपीएससी व पीसीएस परीक्षाओं के लिए संपूर्ण पाक्षिक

इस अंक में ...

प्रबंध संपादक : विजय सिंह
: बाघेन्द्र सिंह
संपादक : विवेक ओझा
सह-संपादक : आशुतोष मिश्र
: सौरभ चक्रवर्ती
उप-संपादक : हरि ओम पाण्डेय
: भानू प्रताप
प्रकाशन प्रबंधन : डॉ.एस.एम. खालिद
संपादकीय सहयोग : दीपक त्रिपाठी
: सल्तनत परवीन
: नितिन अस्थाना
: ऋषिका तिवारी
: ऋतु, प्रत्यूषा
: नीरज, लोकेश
मुख्य समीक्षक : ए.के. श्रीवास्तव
शोध एवं समीक्षक : शशांक त्रिपाठी
डिजाइनिंग एवं डेवलेपमेंट : अरूण मिश्र
: पुनीष जैन
सोशल मीडिया सहयोग : केशरी पाण्डेय
: जीवन ज्योति
मार्केटिंग सहयोग : रवीश, प्रियांक
टंकण : सचिन, तरून
तकनीकी सहायक : वसीफ खान
कार्यालय सहायक : राजू, चंदन, गुड्डू
: अरूण, राहुल

समसामयिकी लेख 5-19

1. भारत में एथेनॉल क्षेत्र से संबंधित नीतिगत उपाय और उपलब्धियां
2. हिंद महासागर सम्मेलन के जरिए भारत की महासागरीय कूटनीति
3. समुद्री जैव विविधता के समक्ष उभरते नए खतरे
4. राष्ट्रीय सुरक्षा में नेशनल इनवेस्टिगेशन एजेंसी की भूमिका का मूल्यांकन
5. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और भारत की सॉफ्ट पॉवर डिप्लोमैसी
6. द केरल स्टोरी: विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दे
7. जी-20 की जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक का महत्त्व

राष्ट्रीय 20-24
अंतर्राष्ट्रीय 25-29
पर्यावरण 30-34
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 35-39
आर्थिकी 40-44
विविध 45-49
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की महत्त्वपूर्ण खबरें 50-53
समसामयिक घटनाएं एक नजर में ... 54
ब्रेन-बूस्टर 55-61
प्रीलिम्स आधारित बहु-विकल्पीय प्रश्न 62-67
मुख्य परीक्षा विशेष: इतिहास व कला एवं संस्कृति पर आधारित महत्त्वपूर्ण प्रश्न 68-79
समसामयिकी आधारित बहु-विकल्पीय प्रश्न 80-81
व्यक्तित्व 82

साभार:- PIB, PRS, AIR, ORF, प्रसार भारती, योजना, कुरूक्षेत्र, द हिन्दू, डाउन टू अर्थ, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, WION, Deccan Herald, HT, ET, ToI, दैनिक जागरण व अन्य

आगामी अंक में

- अखंड भारत विचार का इतिहास और भारत के पड़ोसी देशों पर इसका प्रभाव
- भारत की विदेश व्यापार नीति 2023 के महत्वपूर्ण पहलू : भारत के व्यापार विविधिकरण को बढ़ावा
- एससीओ के पूरक के रूप में एक्सिस ऑफ सेवन: मध्य एशिया में चीन का बढ़ता कद और भारत पर इसका प्रभाव
- बाहय अंतरिक्ष में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना समय की मांग
- कार्बन सीमा समायोजन तंत्र: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भारत पर इसके प्रभाव
- बाईस्टैंडर इफेक्ट: मानव सामाजिक जीवन पर वैश्वीकरण का प्रभाव
- भारतीय नौसेना और भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के तकनीकी सहयोग से नौसैन्य क्षमता में मजबूती

भारत में एथेनॉल क्षेत्र से संबंधित नीतिगत उपाय और उपलब्धियां

"लगभग 7-8 साल पहले देश में एथेनॉल की चर्चा शायद ही कभी होती थी, लेकिन अब एथेनॉल 21वीं सदी के भारत की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक बन गया है। एथेनॉल पर ध्यान केंद्रित करने से पर्यावरण के साथ-साथ किसानों के जीवन पर भी बेहतर प्रभाव पड़ रहा है।''- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

परिचय:

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2023 में बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक (IEW) 2023 का उद्घाटन करते हुए 21वीं सदी की दुनिया के भविष्य की दिशा निर्धारित करने में ऊर्जा क्षेत्र और ऊर्जा संक्रमण की प्रमुख भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कार्बन रहित भविष्य (Decarbonisation) के माध्यम से ऊर्जा संक्रमण की भारत की रणनीति में इथेनॉल सम्मिश्रण की भूमिका पर प्रकाश डाला।
- उन्होंने 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 20% इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (E-20) लॉन्च किया जिसका उद्देश्य उत्सर्जन में कटौती के साथ ही विदेशी मुद्रा की निकासी वाले आयात पर निर्भरता को कम करने हेतु जैव-ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना।

एथेनॉल और भारत के लिए इसका महत्त्व:

- आर्थिक विकास, बढती जनसँख्या और शहरीकरण के कारण हमारे देश में ऊर्जा की मांग बढ़ रही है। सड़क परिवहन क्षेत्र में ईंधन की आवश्यकता का लगभग 98 प्रतिशत वर्तमान में जीवाश्म ईंधन से और शेष 2 प्रतिशत जैव ईंधन द्वारा पूरा किया जाता है।
- एथेनॉल प्रमुख जैव-ईंधन में से एक है जो प्राकृतिक रूप से यीस्ट द्वारा शर्करा के किण्वन द्वारा या एथिलीन हाइड्रेशन जैसी पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित होता है। इसका उपयोग वैकल्पिक जैव- ईंधन स्रोत के रूप में किया जाता है।
- घरेलू जैव-ईंधन देश को रणनीतिक अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि वे आयातित जीवाश्म ईंधन पर देश की निर्भरता को कम करते हैं।
- इसके अतिरिक्त जब उचित देखभाल के साथ उपयोग किया जाता है, तो जैव-ईंधन पर्यावरण के अनुकूल, स्थायी ऊर्जा स्रोत हो सकते हैं।
- वे रोजगार सृजित करने, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत को बढ़ावा देने, किसानों की आय दोगुनी करने और अपशिष्ट से धन सृजन को बढ़ावा देने में भी मदद हो सकते हैं।

भारत के नीतिगत उपाय और एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम:

- सरकार ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संवृद्धि के लक्ष्यों के अनुरूप देश में एथेनॉल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बहु-आयामी सुधार शुरू किया है।
- एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम जनवरी 2003 में लॉन्च हुआ था जबकि वर्ष 2006 में 20 राज्यों और 4 केन्द्रशासित प्रदेशों में 5% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री शुरू की गई थी।
- पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पेट्रोल में एथेनॉल का प्रयोग 2001 में शुरू हुआ था। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम के तहत, 2030 तक पेट्रोल में एथेनॉल के 20% सम्मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, परन्तु 'द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स-CCEA' द्वारा पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य को 2025 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया।
- भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 2018 में 'जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति' प्रकाशित की तथा जून 2022 में इसमें संशोधन किया गया। इस नीति का उद्देश्य घरेलू जैव ईंधन उत्पादन को बढ़ावा देकर पेट्रोलियम उत्पादों के आयात को कम करना था। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2022 में निम्न संशोधन किये गये हैं:
  - 2025-26 तक पेट्रोल में 20% बायो एथेनॉल के सम्मिश्रण लक्ष्य को हासिल करने की समय सीमा को निश्चित करना।
  - जैव ईंधन के उत्पादन के लिए अतिरिक्त फीडस्टॉक्स को बढ़ावा देना।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने '2020-2025 में भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण के रोडमैप पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट' जारी की जिसमें निम्न दो सुझाव दिये गये:
  - 2025-26 तक इथेनॉल के उत्पादन और आपूर्ति के लिए एक वार्षिक रोडमैप बनाना।
  - इथेनॉल के देशव्यापी विपणन के लिए सिस्टम में तेजी लाना।

मुख्य अवलोकन और सिफारिशें:

- पेट्रोल सम्मिश्रण के लिए भारत की इथेनॉल की आवश्यकता 2019-20 में 173 करोड़ लीटर से बढ़कर 2025-26 में 1,016 करोड़ लीटर होने की उम्मीद है।
- 20% इथेनॉल (E-20) के साथ मिश्रित ईंधन को 2025 तक सुनिश्चित करने के लिए अप्रैल 2023 से चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जाना है।
- एक लीटर एथेनॉल बनाने में करीब 2,860 लीटर पानी की जरूरत होती है। जल संरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, रिपोर्ट ने सिफारिश की है कि-
  - कम पानी की खपत वाली फसलों से इथेनॉल प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन का उपयोग किया जाना।
  - मक्का और दूसरी पीढ़ी के स्रोतों से उत्पादन को बढ़ावा देना।
- उच्च इथेनॉल मिश्रणों का उपयोग करने के लिए, इंजन की विफलता और कम ईंधन बचत को रोकने के लिए वाहनों को समग्र रूप से डिजाइन करने की आवश्यकता है। भविष्य में इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल संगत वाहनों का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए कमिटी ने सुझाव दिया कि:
  - E-20 सामग्री के अनुरूप और E-10 ट्यून किए गए इंजन वाले वाहन अप्रैल 2023 से पूरे देश में शुरू करने पर जोर देना।
  - E-20 ट्यून किए गए इंजन वाले वाहन अप्रैल 2025 से रोल आउट किये जाने की संभावना।
- सरकार ने 2014 से इथेनॉल के प्रशासित मूल्य को अधिसूचित किया है। 2018 के दौरान पहली बार, सरकार द्वारा इथेनॉल उत्पादन

के लिए उपयोग किए गए फीड स्टॉक के आधार पर इथेनॉल के अंतर मूल्य की घोषणा की गई थी।

भारत में इथेनॉल क्षेत्र की उपलब्धियां:

- भारत को अगले दो दशकों में किसी भी अन्य देश की तुलना में ऊर्जा मांग में सबसे तीव्र वृद्धि देखने का अनुमान है, जो ऊर्जा की मांग में वैश्विक वृद्धि का लगभग 28 प्रतिशत है। गन्ने के साथ-साथ टूटे हुए चावल और अन्य एग्रो उत्पाद से निकाले गए इथेनॉल के उपयोग से दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल उपभोक्ता और आयातक देश को विदेशी शिपमेंट पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। भारत फिलहाल अपनी तेल जरूरतों को पूरा करने के लिए 85 प्रतिशत आयात पर निर्भर है।

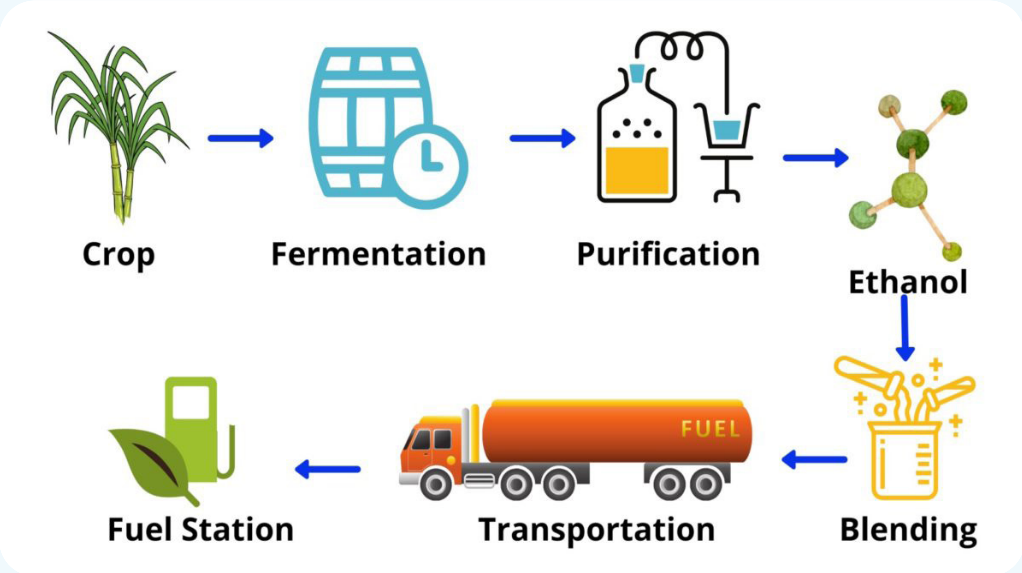

- स्वच्छ पेट्रोल की तुलना में E-20 के उपयोग से दोपहिया वाहनों में कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 50 प्रतिशत और चार पहिया वाहनों में लगभग 30 प्रतिशत की कमी का अनुमान है। दोपहिया और यात्री कारों दोनों में हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन में 20 प्रतिशत की कमी देखने को मिली है।
- 30 नवंबर 2022 को समाप्त आपूर्ति वर्ष के दौरान पेट्रोल में (440 करोड़ लीटर) एथेनॉल मिलाया गया था। अगले वर्ष के लिए 540 करोड़ लीटर एथेनॉल मिलाये जाने की आवश्यकता है।
- औसत 10 प्रतिशत सम्मिश्रण प्राप्त करने का लक्ष्य जून, 2022 में प्राप्त किया गया था जो नवंबर, 2022 की लक्ष्य तिथि से बहुत पहले ही हासिल कर लिया गया था। इस सफलता से उत्साहित सरकार ने 2030 से 2025 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य को निर्धारित किया। भारत सरकार ने किसानों को लाभान्वित करने के साथ ही, 10 प्रतिशत सम्मिश्रण से 53,894 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा की बचत की है।
- यह कार्यक्रम गन्ना किसानों को आय का एक अतिरिक्त स्रोत प्रदान करता है। पिछले आठ वर्षों के दौरान, एथेनॉल आपूर्तिकर्ताओं ने 81,796 करोड़ रुपये कमाए हैं जबकि किसानों को 49,078 करोड़ रुपये मिले हैं। देश ने विदेशी मुद्रा व्यय में 53,894 करोड़ रुपये की बचत की। साथ ही, इससे 318 लाख टन कार्बन-डाइऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन में कमी आई है।
- देश में वर्तमान वार्षिक एथेनॉल उत्पादन क्षमता लगभग 1,037 करोड़ लीटर है जिसमें 700 करोड़ लीटर शीरा और 337 करोड़ लीटर अनाज आधारित उत्पादन क्षमता है। नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए रोडमैप के अनुसार, जो पेट्रोल की अनुमानित बिक्री पर आधारित है, पेट्रोल के साथ सम्मिश्रण के लिए एथेनॉल की अनुमानित आवश्यकता 2022-23 के लिए 542 करोड़ लीटर है जिसके ईएसवाई 2025-26 तक बढ़कर 1016 करोड़ लीटर होने का अनुमान है।
- पानीपत (हरियाणा), बठिंडा (पंजाब), बरगढ़ (ओडिशा) और नुमालीगढ़ (असम) में दूसरी पीढ़ी (2जी) इथेनॉल जैव-रिफाइनरियों की स्थापना की जा रही है, जिनमें प्रत्येक की उत्पादन क्षमता 100 किलो लीटर प्रतिदिन है। तेल कंपनियों ने 30 जनवरी, 2023 तक 80.09 करोड़ लीटर एथेनॉल की खरीदारी की है।

आगे की राह:

- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का हवाला देते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा था कि वर्तमान दशक में भारत की ऊर्जा मांग सबसे अधिक होगी। भारत ने 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों के माध्यम से 500 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है जो देश की कुल ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 50% है।
- वित्त वर्ष 2019 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास और कई नवीकरणीय फीडस्टॉक्स का उपयोग करके एकीकृत जैव-इथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु 'प्रधानमंत्री जी-वैन (Ji-Van) योजना' को मंजूरी दी। ये कारक भविष्य में भारतीय इथेनॉल उद्योग के विकास के लिए अत्यधिक अनुकूल होंगे।
- ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने सही ही कहा है कि 'इथेनॉल सम्मिश्रण से भारत को निर्धारित लक्ष्य और ऊर्जा संक्रमण के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। जैव ईंधन का बढ़ता उपयोग दुनिया के कई गरीब देशों में आय सृजन, सामाजिक समावेश और गरीबी कम करने में एक महत्त्वपूर्ण योगदान देगा।'

हिंद महासागर सम्मेलन के जरिए भारत की महासागरीय कूटनीति

हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए 6वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ढाका में किया गया जिसमें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर और मॉरीशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन की महत्त्वपूर्ण भागीदारी रही। हिंद महासागर सम्मेलन के छठवें संस्करण का आयोजन बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक इंडिया फाउंडेशन के साथ मिलकर किया गया। इसका उद्‍घाटन करते हुए बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि हिंद महासागर न केवल बांग्लादेश के लिए, बल्कि इस क्षेत्र के सभी देशों के लिए अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। इस महत्त्वपूर्ण आयोजन के साथ ही हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़े एक अन्य अहम बैठक में भारत ने अपना विजन और पक्ष रखा है। दरअसल, दूसरे ईयू-इंडो पैसिफिक मिनिस्ट्रियल फोरम में भाग लेने के लिए भारतीय विदेश मंत्री हाल ही में स्वीडन की अपनी पहली यात्रा पर स्टॉकहोम पहुंचे। यूरोपीय संघ और वैश्विक नेताओं को संबोधित करते हुए उनका कहना था कि हिंद-प्रशांत वैश्विक राजनीति की दिशा में तेजी से केंद्रीय भूमिका में पहुंच रहा है। यह जिन मुद्दों को उठाता है उनमें वैश्वीकरण के स्थापित मॉडल में निहित समस्याओं से जुड़े मुद्दे शामिल रहते हैं। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब हिंद-प्रशांत क्षेत्र में दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में चीन की आक्रामक कार्यवाही देखी जा रही है। भारतीय विदेश मंत्री ने चीन के नाम का जिक्र किए बगैर स्पष्ट रूप से कहा कि एक बहुध्रुवीय दुनिया, जिसे यूरोपीय संघ पसंद करता है, एक बहुध्रुवीय एशिया द्वारा ही संभव है। भारत का कहना है कि हिंद-प्रशांत के साथ इस तरह के जुड़ाव में, यूरोपीय संघ स्वाभाविक रूप से समान विचारधारा वाले भागीदारों की तलाश करेगा। एशिया की मल्टीपोलर इकोनॉमी और राजनीति को यूनिपोलर इकोनॉमी बनाने की चाह रखने वाले चीन से एशिया तथा यूरोप में बहुपक्षीयता को कितना बड़ा खतरा है? यह स्पष्ट करने में भारत विशेष रुचि और सक्रियता लगातार दिखा रहा है।

भारत की महासागरीय कूटनीति के लक्ष्य और विजनः

- हिंद महासागर हो या प्रशांत महासागर भारत का विजन क्लियर है। भारत का मानना है कि समुद्री प्रशासन के मामले में दुनिया भर के देश 'यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी' के प्रावधानों के अनुरूप काम करें और किसी भी देश के समुद्री संप्रभुता का उल्लंघन करने की कोशिश न करें। कोई देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में कृत्रिम द्वीप बनाने की फिराक में न रहे, महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों को अपना एकाधिकार न समझे, कोई किसी देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण न करें, अवैध मत्स्यन, अनरेग्युलेटेड एण्ड अनरिपोर्टेड फिशिंग के कामों में लिप्त होकर सतत विकास लक्ष्यों की राह में रोड़ा न बनें। धारणीय विकास, धारणीय उपभोग, धारणीय मत्स्यन आदि के नीतिगत स्तर पर राष्ट्रों के बीच संवेदनशीलता बनी रहनी चाहिए। समुद्री संसाधनों के अति दोहन की होड़ सागर को बंजर बना दे, उससे पहले हिंद महासागर के देशों में इस बात पर आपसी सहमति बननी जरूरी है कि हिंद महासागर को शांति और समृद्धि का क्षेत्र कैसे बनाया जाए? महासागरों पर सबका हक है, महासागरों के अंदर जो भी संसाधन हैं उनका दोहन और उन पर अधिकार के लिए नियमों कानूनों के हिसाब से ही कार्य होना चाहिए। हिंद महासागर के तटीय देशों को कोई भी देश अगर ऋण जाल में फंसाने की कोशिश करता है और अधारणीय निवेश परियोजनाओं तथा विकास परियोजनाओं के लिए देशों को उधार देता है या हिंद महासागर के देशों में अवसंरचनात्मक कूटनीति को बढ़ावा देते हुए अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने की कोशिश करता है तो यह केवल भारत की ही नहीं, बल्कि सभी हिंद महासागर के देशों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे तत्वों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाए। अन्यथा ऐसी सोच वाले देश हिंद महासागर को अपनी आर्थिक सामरिक महत्त्वाकांक्षा की झील बनाकर इसके संसाधनों का अवैध प्रकार से दोहन करते रहेंगे। यह जरूरी हो जाता है कि हिंद महासागर के लघु द्वीपीय देश इस बात को समझें कि वह अपने किसी भी महत्त्वपूर्ण सामरिक बंदरगाह व एयरपोर्ट पर चीन जैसे देशों को एक्सेस न दें। भारत इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सभी छोटे बड़े राष्ट्रों के लिए फ्रीडम ऑफ नेवीगेशन की बात करता है जिससे महासागर व्यापार या ब्लू इकोनामी का लाभ सभी देशों को मिल सके।

हिंद महासागर सम्मेलन में भारत ने देशों की आर्थिक संप्रभुता पर दिया जोरः

- चीन पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला बोलते हुए भारतीय विदेश मंत्री ने ढाका की बैठक में कहा कि जब राष्ट्र कानूनी दायित्वों की अवहेलना या लंबे समय से चले आ रहे समझौतों का उल्लंघन करते हैं, तो भरोसे को भारी नुकसान पहुंचता है। उनका इशारा चीन की तरफ था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गैर-व्यवहार्य परियोजनाओं द्वारा उत्पन्न ऋण हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण साझा चिंता है। गौरतलब है कि भारत 60 अरब डॉलर के 'चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे' का विरोध करता रहा है क्योंकि यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है, जिससे चीन को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ग्वादर बंदरगाह के माध्यम से अरब सागर तक पहुंच मिलती है। भारत ने इस प्रोजेक्ट को अपनी प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन करने वाला बताया है। इसलिए स्थिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाने के लिए कानून व मानदंडों का पालन करना और नियमों का सम्मान करना एक महासागर सुरक्षा का महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक पहलू बन चुका है।

भारत की क्वाड के साथ हिंद-प्रशांत क्षेत्र में जलवायु प्रबंधन की नीतिः

- क्वाड सदस्य देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग प्रबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा को बढावा देने के मुद्दे पर हाल के समय में विशेष ध्यान केंद्रित किया है। क्वाड सदस्य देशों ने क्वाड क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन पैकेज (Q-CHAMP) लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन

और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में कटौती व अनुकूलन प्रयासों को मजबूती देना है। क्यू चैम्प के तहत क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप की चल रही गतिविधियां भी शामिल होंगी जैसे ग्रीन शिपिंग और हरित बंदरगाहों के विकास पर जोर, एक साझे ग्रीन कॉरिडोर फ्रेमवर्क का विकास आदि। यह प्रयास अल्प कार्बन अर्थव्यवस्था के विकास की दिशा में बढ़ाया गया कदम है। इसके तहत क्वाड के प्रत्येक सदस्य देशों के स्वच्छ ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में योगदान को बढ़ाने पर बल दिया गया है। क्लीन हाइड्रोजन पर बल देते हुए प्राकृतिक गैस क्षेत्र से मिथेन उत्सर्जन में कटौती के लिए काम 'क्यू चैम्प' के तहत किया जाएगा। इस दिशा में सिडनी एनर्जी फोरम के योगदान का क्वाड देशों ने स्वागत किया है। इस पहल के तहत प्रशांत द्वीपीय देशों के जलवायु सूचना सेवाओं के लिए रणनीति तैयार की गई है। आपदा जोखिम कटौती और आपदा जलवायु परिवर्तन के झटकों को सहने में समर्थ अवसंरचनाओं के निर्माण पर बल दिया गया है। विशेषकर कोलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलियंट इन्फ्राट्रक्चर के तत्वावधान में काम करने पर बल दिया गया है। क्यू चैम्प के तहत क्लीन फ्यूल अमोनिया, कार्बन रीसाइक्लिंग और पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत एडवांस हाई इंटीग्रिटी कार्बन मार्केट के लिए क्षमता निर्माण व सहयोग, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर 'सब-नेशनल क्लाइमेट एक्शन' पर ज्ञान को साझा करने तथा इको सिस्टम आधारित अनुकूलन पर बल देने की बात शामिल है।

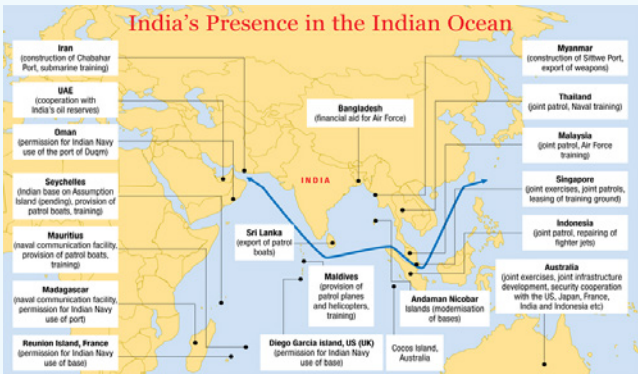

कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की हिन्द महासागर की सुरक्षा में भूमिकाः

- पिछले दो वर्षों में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के तहत नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल, डेप्युटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल और भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के स्तर पर बैठकें आयोजित हुई हैं जिसमें एनसीबी के तत्वावधान में बैठक इसी साल मार्च माह में हुई है। यह फोरम हिंद महासागर के तटीय देशों के हित से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करके समाधान की राह खोजने के लिए जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग और संगठित अपराधों से निपटने के कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के सदस्यों के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों द्वारा प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं और साथी ही इस मामले पर आपसी सहयोग भी सुनिश्चित किया गया है। भारत ने इन बैठकों में साइबर सुरक्षा और साइबर टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल की सिफारिश पर जोर दिया है। बांग्लादेश म्यांमार के विस्थापित नागरिकों को उनके देश सुरक्षित वापसी में भारत के सहयोग की अपेक्षा ऐसे मंच पर करता रहा है। हजारों विस्थापित म्यांमारी नागरिक उग्रवाद, कट्टरपंथ और ड्रग्स की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, अतः भारत के पास इस मुद्दे को प्रभावी तरीके से संबोधित करने के लिए यह कारगर मंच है। हिंद महासागर के देशों की अर्थव्यवस्था बड़े स्तर पर मेरीटाइम सेफ्टी पर निर्भर है, फिर भी मालदीव जैसे देश अभी भी तस्करी, संगठित अपराध और आतंकवाद के खतरे की संभावना से मुक्त नहीं हुए हैं। मालदीव का कहना है कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के सदस्यों को सुरक्षा के मुद्दे पर सूचना, कौशल और ज्ञान को साझा करना होगा। इसके सदस्य देश (भारत, मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस, बांग्लादेश और सेशेल) हिंद महासागर क्षेत्र में साइबर सुरक्षा, आतंकवाद, कट्टरपंथी ताकतों, नशीले पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए सहयोग का स्तर बढ़ाने की बात करते हैं। साथ ही अवैध, अनरिपोर्टेड एण्ड अनरेगुलेटेड फिशिंग और पर्यावरण क्षतियों से निपटने पर भी यह मंच बल देता है।
- ये देश भारत के पड़ोसी प्रथम की नीति, भारत के एक्सटेंडेड नेबरहुड की नीति, सागर विजन, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी और द्वीपीय कूटनीति के अंग हैं। हिन्द महासागर में भारत के समुद्री व्यापारिक हितों के लिहाज से इनका काफी महत्त्व है। 2011 में एक त्रिपक्षीय समुद्री सहयोग तंत्र के रूप में काम करने वाला कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जिन क्षेत्रों में सहयोग करता है उनमें मेरीटाइम सेफ्टी, काउंटर टेररिज्म, कट्टरता विरोधी सहयोग यानी काउंटर रेडीकलाइजेशन, तस्करी और संगठित अपराधों से निपटना, साइबर सुरक्षा, मानवतावादी सहायता, आपदा राहत सहायता आदि शामिल हैं।
- हिंद महासागर क्षेत्र की शांति, स्थिरता व समृद्धि इन सभी देशों की सुरक्षा और विकास के लिए जरूरी है। कई महासागर आधारित उद्योगों विशेषकर शिपिंग के लिए हिंद महासागर सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। मलक्का जलडमरूमध्य हो या होरमुज स्ट्रेट, बाब अलमंदेव की खाड़ी हो या यमन की खाड़ी, अरब सागर का विस्तार हो या बंगाल की खाड़ी सहित अंडमान सागर ये सभी जलराशियां हिंद महासागर की गौरवपूर्ण महत्ता की गवाह हैं। हिंद महासागर के तटीय देश आज एक साथ कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आतंकवाद, बढ़ता उग्रवाद अथवा चरमपंथ, इस्लामिक कट्टरता, समुद्री मार्ग से नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी गंभीर चुनौती बने हुए हैं। इनसे निपटने के लिए हिंद महासागर के देशों को एकजुट होना होगा। यहीं कारण है कि पिछले 3 वर्षों में दुनिया के कई देशों ने साथ ही क्षेत्रीय संगठनों ने भी 'फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रणनीति' अपनाई है। बांग्लादेश ने इसी वर्ष अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति अपनाई है। इससे पहले जर्मनी, यूरोपीय संघ, कनाडा, दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने विविध हितों की सुरक्षा के लिए इंडो पैसिफिक रणनीति लॉन्च किया था। यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे पहल भी लॉन्च कर चुका है।

समुद्री जैव विविधता के समक्ष उभरते नए खतरे

हाल ही में प्रकाशित 'मीजरिंग अंडरवाटर नॉइज लेवल रेडिएटेड बाइ शिप इन इंडियन वाटर' नामक रिपोर्ट में समुद्री जैव विविधता के समक्ष चुनौती का उल्लेख किया गया है। यह रिपोर्ट कहती है कि भारतीय जल में चलने वाली समुद्री जहाजों तथा नावों से होने वाला मानव निर्मित अंडरवाटर नाइज एमिशन समुद्री स्तनपायी जीवों (Sea Mammals) के ऊपर खतरे उत्पन्न कर रहा है। इन समुद्री स्तनपायी जीवों में बॉटलनोज डॉल्फिन, मानाटीज, पायलट व्हेल, सील और स्पर्म व्हेल शामिल हैं। भारतीय जलीय क्षेत्र में अंडरवाटर नॉइज एमिशन (जल के अंदर होने वाले ध्वनि प्रदूषण से उत्सर्जन) समुद्री स्तनपायी जीवों के व्यवहार से जुड़ी कई गतिविधियों जैसे मेटिंग, कम्युनल इंटरएक्शन, फीडिंग, क्लस्टर कोहेशन, फॉरेजिंग (समुद्री जीव जंतुओं द्वारा आहार खोजना) पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है जिसके चलते समुद्री जैवविविधता प्रभावित हो रही है। उल्लेखनीय है कि समुद्री स्तनपाई जीवों के कई व्यवहार संबंधी गतिविधियों (Behavioural Activities) के लिए जो मुख्य ऊर्जा है, वह ध्वनि पर निर्भर है और सागर के अंदर ध्वनि प्रदूषण के चलते इनकी गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं।

तटीय क्षेत्रों में मानव हस्तक्षेप से समुद्री जैव विविधता प्रभावित:

- हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट जारी किया है। भारत के कैग का कहना है कि भारत के पूरे तटीय क्षेत्रों में शहरी स्थानीय निकायों में सीवेज ट्रीटमेंट फेसिलिटी के अभाव के चलते समुद्री क्षेत्र में समुद्री जीव जंतुओं के लिए ऑक्सीजन का क्षरण एक गंभीर चुनौती बन गया है। कैग ने यह भी कहा है कि समुद्री खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला (Food Web And Food Chain) में विषाक्त तत्वों की मात्रा बढ़ने के चलते मानव जीवन भी खतरे में पड़ गया है।
- कैग ने कहा है कि कोस्टल रेगुलेशन जोन अधिसूचना 2011 तटीय जल में अपशिष्ट पदार्थों और औद्योगिक अपशिष्ट को डालने पर प्रतिबंध लगाता है तथा अधिसूचना में यह भी कहा गया था कि जनवरी 2013 तक बिना उपचारित अपशिष्ट (Untreated Waste) और औद्योगिक अपशिष्ट (Affluents) पदार्थ को तटीय क्षेत्रों में प्रवाहित करने की परंपरा बंद होनी चाहिए।
- कैग ने इस बात की भी आवश्यकता महसूस किया है कि तटीय क्षेत्रों और जल में प्रदूषण से निपटने के लिए एक एक्शन प्लान होना चाहिए जो समयबद्ध तरीके से बने जिसे प्रौद्योगिकी और वित्तीय सहायता के लिए भारत के पर्यावरण मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्च 2021 की रिपोर्ट 'नैशनल इन्वेंट्री ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स' में कहा गया है कि गुजरात में सीवेज उत्पादन 5,013 मिलियन लीटर प्रति दिन (MLD) होता है, जबकि कुल ट्रीटमेंट कैपसिटी (प्रस्तावित सहित) 3,378 मिलियन लीटर प्रति दिन (MLD) अनुमानित है। इस अंतर को भरने की रणनीति पर काम करके ही समुद्री पर्यावरण को बचाया जा सकता है।

प्रवाल भित्तियों के नष्ट होने से समुद्री जैव विविधता प्रभावित:

- जलवायु परिवर्तन और समुद्र की गर्म लहरों के कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चट्टानों पर बड़े पैमाने पर प्रवाल खत्म होते जा रहे हैं। भारत सहित दुनिया के अनेक हिस्सों में कोरल रीफ नष्ट हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ के उत्तरी छोर पर, लिजर्ड द्वीप के आसपास 44 साल के प्रवाल की मौजूदगी के रिकॉर्ड की जांच की गई और अध्ययन में पाया गया कि प्रवाल की 16 प्रतिशत प्रजातियां कई वर्षों से नहीं देखी गई हैं या तो स्थानीय स्तर पर उनके विलुप्त होने का खतरा है या फिर वे इस क्षेत्र से गायब हो रही हैं। यह चिंताजनक है क्योंकि स्थानीय स्तर पर विलुप्ति अक्सर व्यापक और अंततः वैश्विक स्तर पर प्रजातियों के विलुप्त होने की घटनाओं का संकेत देती है। वहीं भारत की बात करें तो भारत में 7,500 किमी से अधिक की विशाल समुद्र तट के साथ समृद्ध समुद्री जैव विविधता है। व्हेल शार्क, कछुओं और बड़े स्तनधारियों जैसे व्हेल, डॉल्फिन और डोंगोंग से लेकर चमकदार समुद्री चट्टानों सहित रंगीन मछलियों और शार्क से न केवल समुद्री जीवन की विविधता बढ़ती है, बल्कि इनसे मानव हित के कई संसाधन भी पैदा होते हैं। समुद्री व्यापार और परिवहन, भोजन, खनिज संसाधनों, सांस्कृतिक परंपराओं और आध्यात्मिक मूल्यों के इन संसाधनों पर लाखों लोग निर्भर हैं। इसी से प्रेरणा लेकर दुनिया भर से पर्यटक भी इनकी ओर आकर्षित होते हैं। भारत में समुद्री जीवन के विशाल आर्थिक, पारिस्थितिक और सांस्कृतिक मूल्यों के बावजूद, यहां की समुद्री जीव प्रजातियों तथा समुद्री कछुओं को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिनमें इनका अवैध शिकार शामिल है। ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थितियों के प्रबंधन हेतु समन्वय, कार्यवाही और लोगों की भागीदारी की आवश्यकता होती है जो समुद्री प्रजातियों तथा उनके आवासों के दीर्घकालिक संरक्षण में मदद करेगा।
- वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड (WWF) की गणना के अनुसार, विश्व की समस्त प्रवाल भित्तियां करीब 800 अरब अमेरिकी डॉलर की पूंजी हैं और धरती पर लगभग 85 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा व आजीविका के लिए प्रवाल-आधारित इकोसिस्टम पर निर्भर हैं। लगभग 100 देश प्रवाल भित्ति में मौजूद जैव विविधता के कारण मछली पालन, पर्यटन और तटीय सुरक्षा का लाभ पा रहे हैं। इन 100 देशों में से एक चौथाई के सकल घरेलू उत्पाद का 15% पर्यटन पर निर्भर है। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रवाल भित्ति से दुनिया भर में तीन करोड़ अमेरिकी डॉलर का वार्षिक लाभ कमाया जाता है। इन्हें ब्लीचिंग और दूसरे कारणों से हो रहे नुकसान के चलते मछली उद्योग तथा पर्यटन को प्रतिवर्ष क्रमशः 57 लाख और 96 लाख अमेरिकी डॉलर का घाटा उठाना पड़ रहा है। प्रवाल के वैश्विक स्तर पर क्षरण से सर्वाधिक आर्थिक नुकसान दक्षिण-पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और ओसियाना के द्वीपों को पहुंचने की आशंका है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रवाल भित्तियों के तीन करोड़ अमेरिकी डॉलर के योगदान का 60 प्रतिशत

हिंद-प्रशांत कटिबंधीय क्षेत्र से होता है। पृथ्वी पर समुद्री क्षेत्र का केवल 0.2 से 0.25 फीसदी हिस्सा होने के बावजूद प्रवाल समुद्री जीवन की एक चौथाई 20 लाख प्रजातियों का संरक्षण करते हैं। कई द्वीपीय देशों और उष्ण कटिबंधीय देशों के लिए ये मौसम के प्रभावों से बचाव तथा राहत का काम करते हैं। प्रवाल संरचनाएं जेनेटिक संग्रहालय का भी काम करती हैं जिनकी जैव विविधता के कारण इन्हें समुद्री क्षेत्र के वर्षा वन भी कहा जाता है।

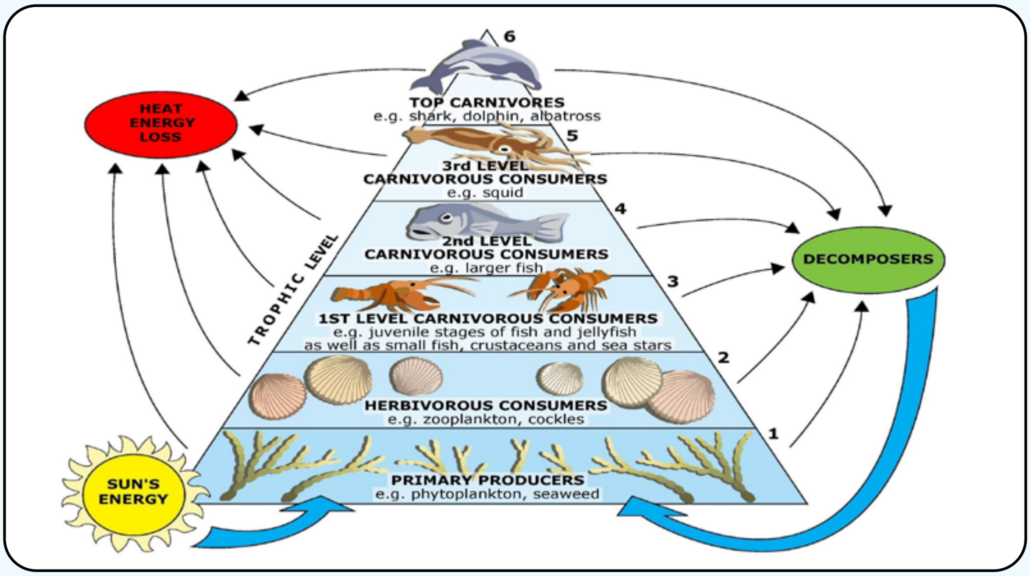

समुद्री घासों का संरक्षण आवश्यकः

- समुद्री घास समुद्र तथा महासागरों में पानी के अंदर पाई जाने वाली घास है। समुद्री घास फूल वाले समुद्री पौधे होते हैं, जो सागरीय परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। समुद्री घास सामान्यतः उथले समुद्री तटों में पाई जाती हैं जो कई बार व्यापक घने घास के मैदान का भी निर्माण करती हैं। पूरे विश्व के समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय महासागरों में लगभग 72 प्रकार की समुद्री घास प्रजातियां पायी जाती हैं। समुद्री घास महासागरीय पारिस्थितिक तंत्रों और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले मनुष्यों के लिए अत्यधिक महत्त्व रखती है। समुद्री घास पानी की गुणवत्ता में सुधार करने, CO_2 को अवशोषित और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा यह मछलियों की सैकड़ों प्रजातियों के लिए एक प्राकृतिक आवास और शरणस्थली प्रदान करता है। समुद्री घास तटीय खाद्य जाल के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है। चूंकि यह घास सामान्यतः तटीय क्षेत्रों में पायी जाती है, जिससे यह समुद्र तट के क्षरण को रोकने और विनाशकारी तूफान के प्रभाव को कम करने में मदद करती है। सूरज की पराबैंगनी किरणों से बचाने वाली सनस्क्रीन भी अब समुद्री जीवन के लिए खतरा बन रही है। अध्ययन में पाया गया है कि सनस्क्रीन लोशन में पाए जाने वाले केमिकल भूमध्य सागर की समुद्री घास पर जमा हो रहे हैं। वैज्ञानिकों ने पोसिडोनिया ओशनिका (Posidonia Oceanica) के तनों पर पराबैंगनी फिल्टर्स की खोज की है। पोसिडोनिया ओशनिका समुद्री घास की एक प्रजाति है जो मलोर्का के तट पर पाई जाती है।

भारत में समुद्री जैवविविधता के संरक्षण हेतु किए गए प्रयासः

- विशाल समुद्री जीवों और कछुओं के लिए एक संरक्षण प्रतिमान रखने की आवश्यकता को देखते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2021 में नई दिल्ली में 'मरीन मेगा फॉना स्ट्रैंडिंग गाइडलाइन्स' और 'नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान' जारी किया। भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने समुद्री किनारों या नाव में फंसे हुए समुद्री जीवों के बचाव प्रबंधन की नीति भी तैयार की है।
- भारत ने ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (GBF) के लक्ष्यों विशेषकर लक्ष्य-3 के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। नए जैव विविधता ढांचे का लक्ष्य-3 महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि इसके लिए वैश्विक स्तर पर सहयोग की आवश्यकता होगी
- 23 लक्ष्यों में से लक्ष्य-3, बोलचाल की भाषा में "30×30" के रूप में जाना जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि स्थलीय, अंतर्देशीय जल, तटीय और समुद्री क्षेत्रों का कम से कम 30 प्रतिशत, विशेष रूप से जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र कार्यों तथा सेवाओं के लिए विशेष महत्त्व के क्षेत्र, पारिस्थितिक रूप से प्रतिनिधि, संरक्षित क्षेत्रों के अच्छी तरह से जुड़े व समान रूप से शासित प्रणालियों तथा अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपायों के माध्यम से प्रभावी ढंग से संरक्षित और प्रबंधित किए जाते हैं।
- समुद्री जीव डुगोंग (Sea Cow) के संरक्षण के लिए भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में पाक जलडमरूमध्य में स्थित मन्नार की खाड़ी में बनाया गया है।
- बेहतर समन्वय के साथ की गई कार्यवाही से समुद्री प्रजातियों और उनके आवासों को होने वाले खतरे को कम किया जा सकता है। समुद्री जीवों के बर्बाद हो चुके आवासों को पुर्नस्थापित किया जा सकता है, लोगों की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है, वैज्ञानिक अनुसंधान में आगे बढ़ा जा सकता है, समुद्री स्तनधारियों, समुद्री कछुओं तथा उनके आवासों के बारे में जानकारियों के आदान-प्रदान को और बढ़ाया जा सकता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा में नेशनल इनवेस्टिगेशन एजेंसी की भूमिका का मूल्यांकन

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हाल ही में कश्मीर स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के एक सदस्य को जम्मू-कश्मीर में आतंकी साजिश मामले में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एनआईए ने उसे इस आधार पर गिरफ्तार किया कि वह पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद कमांडर के लगातार संपर्क में था। इससे स्पष्ट है कि कश्मीर में अभी भी पाक प्रायोजित आतंकवाद एक चुनौती के रूप में बना हुआ है, भले ही उसकी गंभीरता में थोड़ी कमी आई हो। इसके अलावा राष्ट्रीय जाँच एजेंसी इस समय देश में खासकर उत्तर भारत में माफिया गिरोहों, गैंगस्टर और आतंकियों के बीच लिंक को तोड़ने में लगा हुआ है। गैंगस्टर को हथियार कहां से मिल रहे हैं? गैंगस्टर अपराध को बढावा देने में हथियारों की अवैध तस्करी को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं? छोटे अपराधियों को विदेशी हथियार कैसे प्राप्त हो रहें हैं? इन बातों का पर्दाफाश राष्ट्रीय जाँच एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में जिगाना पिस्टल की आपूर्ति में पंजाब के गैंगस्टर का हाथ होने का खुलासा भी राष्ट्रीय जाँच एजेंसी द्वारा किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि संगठित अपराध नेटवर्क और आतंकियों के बीच का गठजोड़ देश की कानून व्यवस्था के लिए अभी भी एक चुनौती के रूप में विद्यमान है।

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी का नक्सलवाद और माओवाद पर प्रहार:

- छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में कुछ ही समय पहले डीआरजी ग्रुप पर हुए नक्सली हमले की जांच कर रही एनआईए की टीम बिहार और झारखंड तक पहुंची थी। केंद्रीय एजेंसी एनआईए ने इन दोनों राज्यों में 14 से अधिक ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन किया। यह सर्च ऑपरेशन सीपीआई (माओवादी) से जुड़े लोगों या उनके समर्थकों के ठिकानों पर चला। एनआईए के तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि 25 अप्रैल, 2022 को एक एफआईआर दर्ज किया गया था। इसमें पाया गया था कि देश में पहले से प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) अपने संगठन का विस्तार कर रही है। यह विस्तार छत्तीसगढ़ के अलावा बिहार और झारखंड में भी किया जा रहा है। इसके लिए संगठन से जुड़े लोग युवाओं को गुमराह करने प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में संगठन के पोलित ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी के सदस्यों को नामजद भी किया गया है। इसके साथ ही हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने झारखंड के प्रतिबंधित नक्सल संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (PLFI) के सुप्रीमो दिनेश गोप को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने कहा है कि 'आरोपी के खिलाफ 102 आपराधिक मामले थे और 30 लाख रुपये का इनाम रखा था।' इस प्रकार स्पष्ट है कि एनआईए भारत में वामपंथी उग्रवाद के खात्मे के लिए एक विशेष रणनीति के तहत कार्य कर रहा है। नक्सलियों की फंडिंग, भर्ती, प्रशिक्षण रोकने की दिशा में एनआईए द्वारा प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं। PLFI जिसे पूर्व में झारखंड लिबरेशन टाइगर्स (JLT) के रूप में जाना जाता था, उसके बारे में एनआईए ने जांच कर बताया है कि PLFI झारखंड में सैकड़ों आतंकी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है, जिसमें आग्नेयास्त्रों का उपयोग करके कई हत्याएं करना शामिल हैं। 'यह संगठन बेरोजगार युवाओं को मोटरबाइक, मोबाइल फोन तथा आसानी से पैसे देकर लुभाता था और प्रशिक्षण देने के बाद उन्हें आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए घातक हथियारों से लैस करता था।' जबरन वसूली पीएलएफआई की आय का प्रमुख स्रोत है और यह संगठन झारखंड के विभिन्न जिलों में विकास परियोजनाओं में शामिल कोयला व्यापारियों, रेलवे ठेकेदारों और विभिन्न निजी संस्थाओं को लक्षित कर रहा है। नक्सल संगठन ने इन विभिन्न आपराधिक गिरोहों के साथ गठजोड़ भी किया था, इसलिए इन सबके खिलाफ कार्यवाही हो रही है।

राष्ट्रीय सुरक्षा में एनआईए की बहुआयामी भूमिका पर जोर:

- नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की भूमिका भारत की आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती देने में अति महत्त्वपूर्ण रही है। इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया (ISIS) से संबंध रखने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही हो, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के द्वारा भारत में जेहाद कल्चर को उभारने पर रोक लगाने की बात हो, साइबर आतंकवाद, नार्को आतंकवाद, नक्सलियों और माओवादियों के फंडिंग रूट को ब्लॉक करने की बात हो, राष्ट्रीय जाँच एजेंसी ने पूरी सक्रियता के साथ अपनी भूमिका निभाई है। एनआईए ने ही पिछले साल अमरावती के उमेश कोल्हे हत्याकांड की कई परतें भी खोली थीं। इस केस में एनआईए ने पाया था कि देश में इस्लामिक कट्टरता को बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसके पूर्व बांग्लादेश से जाली भारतीय नोटों की तस्करी के आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने का मामला हो या खालिस्तान समर्थक गतिविधियों के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में रहने वाले 16 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर करने का मामला हो, साइप्रस से प्रत्यर्पित फरार खालिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार करने का मामला हो, पाकिस्तान से तस्करी करके ड्रग्स बेचकर खालिस्तान लिबरेशन फोर्स की अवैध गतिविधियां चलाने में संलग्न लोगों के खिलाफ कार्यवाही का मामला हो या फिर सबसे प्रमुख रूप में आतंकी संगठन आईएसआईएस के भारत में षड्यंत्र का मामला हो, एनआईए ने एक सक्रिय संघीय जांच एजेंसी के रूप में बहुआयामी भूमिका निभाई है।

ड्रग्स तस्करी और नार्को आतंकवाद के खिलाफ एनआईए:

- राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में अवैध ड्रग माफियों के खिलाफ छापेमारी की है। एनआईए का यह सर्च ऑपरेशन भारत और श्रीलंका में ड्रग तथा हथियारों के अवैध व्यापार से जुड़ा है। एनआईए ने इसे एक गंभीर मामला इसलिए माना है क्योंकि यह मामला पाकिस्तान स्थित एक सप्लायर के साथ काम करने वाले श्रीलंकाई ड्रग माफिया की संदिग्ध गतिविधियों से

संबंधित है। ऐसे लिंक के सबूत लगातार सामने आते रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पिछले साल 'रविहंसी' नाम की एक श्रीलंकाई नाव में श्रीलंकाई नागरिकों से ड्रग्स और हथियार जब्त करने के मामले में नामित चार आरोपियों की 3.59 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। ईडी ने एनआईए द्वारा दर्ज मामले के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच किया था। इससे पता चला था कि ड्रग्स की बिक्री से होने वाली इनकम से ड्रग्स की अगली खेप खरीदने और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाना था।

अलगाववाद तथा धार्मिक कट्टरता के खिलाफ एनआईए की कार्यवाही:

- आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों के द्वारा भारत और अन्य देशों में आतंकवाद के जिस स्वरूप को मजबूती देने की कोशिश की गई है उसे धार्मिक आतंकवाद की श्रेणी में रखा जाता है। आतंकवाद का यह स्वरूप घातक रूप में देश की आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के सेकुलर ताने बाने पर बड़े खतरे उत्पन्न करता है। आईएसआईएस जिस धार्मिक आंतकवाद के सहारे एक अखिल इस्लामिक गणराज्य की स्थापना का मंसूबा रखता है, वह भारत जैसे देशों के लिए इसलिए अधिक खतरनाक है क्योंकि धर्म ग्रंथों की गलत और अति कट्टर व्याख्या करके भारतीय युवाओं को चरमपंथी, धार्मिक मतांध बनाकर उनके मन में धार्मिक पूर्वाग्रह, दुराग्रह, ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुता के भावों का बीजारोपण किया जाता रहा है। अब इस काम को अधिक बखूबी अंजाम देने के लिए ऑनलाइन उग्रवाद को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है जो साइबर आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम है। इससे निपटने के लिए नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भारत में आतंकवाद से जुड़े मामलों में जांच पड़ताल करने, चार्जशीट दाखिल करने, मुकदमा चलवाने के लिए अधिकृत एजेंसी है जो इस काम को अपने विशेष न्यायालयों के जरिए पूरा करती है। पिछले साल एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने देश में आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़कर षड्यंत्र करने वाले चेन्नई के नागरिक को 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने स्पेशल कोर्ट को जानकारी देते हुए कहा था कि भारत में आईएसआईएस षड्यंत्र मामलों की जांच के दौरान यह पाया गया कि आईएसआईएस भारत और विदेश में निवासी तथा अनिवासी भारतीयों की भर्ती के लिये बड़ी साजिश रचने में लगातार सक्रिय है। एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने आईएसआईएस के संपर्क वाले जिस व्यक्ति को 7 वर्ष के कारावास का दण्ड दिया था उसका प्रत्यर्पण सूडान से किया गया था। एनआईए के विशेष अदालत द्वारा ऐसे अपराधियों को जिन कानूनी धाराओं के तहत दंड दिया जाता है, वे भारतीय दंड संहिता की धारा-120बी (आपराधिक साजिश), गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धारा-18 (आतंकी कृत्य की साजिश रचना), धारा-18बी (आतंकी कृत्य के लिये लोगों की भर्ती), धारा-38 (आतंकी संगठन का सदस्य होने) और धारा-39 (आतंकी संगठन की मदद करने) के तहत उसे दोषी ठहराया है।

नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मिले नए अधिकार तथा शक्तियां:

- आतंकवाद के विभिन्न स्वरूपों और उसके संगठित अपराधों से जुड़े लिंक को तोड़ने के मकसद से ही पिछले साल एनआईए संशोधन अधिनियम, 2019 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को आतंकी मामलों से निपटने के साथ ही साइबर सुरक्षा से जुड़े मामलों, जाली मुद्रा कारोबार से जुड़े अपराधों, विस्फोटक पदार्थ से जुड़े अपराधों, मानव तस्करी से जुड़े मामलों, जांच का अधिकार क्षेत्र विदेशों तक बढ़ाने और ऐसे व्यक्तियों को भी जांच के घेरे में रख सकने का अधिकार दिया गया है, जो भारत के बाहर भारतीय नागरिकों के खिलाफ या भारत के हितों को प्रभावित करने वाला अनुसूचित अपराध करते हैं। ऐसे विधायन का महत्त्व तब समझ में आता है जब देश के सामने आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों के पेशेवर आतंकियों द्वारा भारत में साइबर अपराधों में लिप्त होकर देश में धार्मिक कट्टरता के लिए हिंसा को ऑनलाईन वैधता देते हुए पाया जाता है।
- भारत में आईएसआईएस की उपस्थिति के सबूत समय-समय पर गृह मंत्रालय और एनआईए ने दिए हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि दक्षिणी भारतीय राज्यों सहित विभिन्न राज्यों के कुछ लोगों के इस्लामिक स्टेट में शामिल होने की बात सुरक्षा एजेंसियों के सामने आई है। गृह मंत्रालय ने भी कहा है कि एनआईए ने तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में आईएस की उपस्थिति से संबंधित 17 मामले दर्ज किए हैं और 122 आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। एनआईए की जांच में पता चला है कि इस्लामिक स्टेट केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में सबसे अधिक सक्रिय है। भारत के गृह मंत्रालय ने भारतीय राज्यों में आईएसआईएस की उपस्थिति और सक्रियता होने की सार्वजनिक तौर पर पुष्टि सितंबर, 2020 में की थी। भारत के युवाओं में कट्टरपंथ के प्रसार का साक्ष्य संयुक्त राष्ट्र के इस्लामिक स्टेट, अल कायदा और अन्य संबंधित व्यक्तियों और इकाईयों से संबंधित एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम की 26वीं रिपोर्ट में दिया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आईएस और अल कायदा के कई सदस्य कर्नाटक तथा केरल में मौजूद हैं। ऐसी भी आशंका रिपोर्ट में व्यक्त की गई है कि आईएसआईएल से संबद्ध भारतीय शाखा हिन्द विलायाह में लगभग 200 सदस्य हैं जो इस्लामिक चरमपंथी मानसिकता के शिकार हैं।
- भारत में आईएसआईएस की सक्रियता से निपटने की रणनीति को बहुस्तरीय और बहुआयामी बनाने की जरूरत है जो एनआईए के नेतृत्व में किया जा रहा है। अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए आईएस इंटरनेट आधारित विभिन्न सोशल मीडिया मंचों का इस्तेमाल कर रहा है। इसे देखते हुए संबद्ध एजेंसियां साइबर स्पेस की सतत निगरानी कर रही हैं और कानून के अनुसार कार्यवाही कर रही हैं। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार के

पास सूचना है कि इन लोगों को वित्त कैसे मुहैया कराया जा रहा है? आतंकी गतिविधियों को संचालित करने के लिए उन्हें विदेशों से कैसे मदद मिल रही है? इसलिए आतंक के वित्त पोषण को रोकने की रणनीति के तहत जाली मुद्रा कारोबार, ब्लैक मनी, मनी लांड्रिंग, हवाला कारोबार से निपटने पर विशेष जोर दिया गया है।

NIA (Amendment) Bill 2019 – Key Points

Three major changes have been proposed under the NIA (Amendment) Bill 2019 with an aim to promote zero tolerance towards terrorism. These include:

Provisions	Existing Provisions	Proposed Amendment
SCOPE	NIA can investigate offences under Acts such as the Atomic Energy Act, 1962 and the Unlawful Activities Prevention Act, 1967.	Scope extended to investigate offences related to human trafficking, counterfeit currency, manufacture or sale of prohibited arms, cyber-terrorism, and offences under the Explosive Substances Act, 1908.
JURISDICTION	NIA officers have the same power as other police officers and these extend across the territorial boundaries of the country.	NIA officers to have the power to investigate offences committed even outside India.
SPECIAL TRIAL COURTS	The Centre to constitute special courts for trials under the purview of NIA.	To enable the Central government to designate sessions courts as special courts for such trials.

- कट्टरता, धर्मांधता, धार्मिक और अन्य आधारों पर उग्रवादी मानसिकता, रूढ़िवादिता के जरिए आतंकी गतिविधि, अलगाववादी आंदोलन, जेहादी विचारधारा को फलने फूलने का अवसर मिला है। इस बात की गंभीरता को ध्यान में रखकर भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भी देश में हर तरह के रेडिकलाइजेशन (कट्टरता) की वर्तमान स्थिति को जानने व उसके हिसाब से देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए काम करने के उद्देश्य से एक व्यापक अध्ययन को मंजूरी दी है। देश में कट्टरता की स्थिति का पता लगाने संबंधी अनुसंधान इस दिशा में देश में पहली बार किया जा रहा है। इसके तहत कट्टरता शब्द को वैधानिक रूप से परिभाषित किया जाएगा जिसके अनुरूप वैधानिक क्रियाकलाप (रोकथाम) अधिनियम, 1967 में आवश्यक संशोधन करने की सिफारिश की जाएगी। गृह मंत्रालय के तत्वावधान में इस अध्ययन और अनुसंधान को दिशा देने वाले नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (दिल्ली) ने स्पष्ट किया है कि देश में किस किस प्रकार की कट्टरता है उसकी वजह क्या है? उसको बढ़ावा देने वाले कारक कौन से हैं? कट्टरता की सोच को खत्म कैसे किया जा सकता है? इन सब अध्ययनों को धार्मिक रूप से तटस्थ होकर संपन्न किया जाएगा।
- भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत देश में चरमपंथ और कट्टरपंथी सोच से निपटने के लिए आतंकवाद-रोधी एवं कट्टरवाद रोधी (CTCR) प्रभाग बनाया गया है। यह आतंकवाद से मुकाबला करने, कट्टरपंथीकरण, गैर कानूनी क्रियाकलाप (रोकथाम) अधिनियम, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अधिनियम, फेक इंडियन करेंसी नेटवर्क (FICN) और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के आतंक के वित्त पोषण को रोकने, काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के प्रयासों को दिशा देता है। इसके अलावा कट्टरपंथ से निपटने के लिए भारत के सशस्त्र बलों, अर्ध सैनिक बलों के द्वारा कट्टरपंथ, अलगाववाद और आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावी तरीके से सिविक एक्शन प्रोग्राम एण्ड परसेप्शन मैनेजमेंट रणनीति के जरिए गुमराह युवाओं में शासन प्रशासन के प्रति विश्वसनीयता के भावों का विकास किया जाना जरूरी है। जेहादी साहित्य, दस्तावेज आदि के प्रसार को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का प्रभावी विनियमन जरूरी है। उग्रवाद, आतंकवाद और कट्टरतावाद या चरमपंथ को केवल बल के इस्तेमाल से पराजित नहीं किया जा सकता है। इसके लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता को स्वीकार करना राष्ट्रों के लिए जरूरी है। अतिवादी और हिंसक विचारधाराओं को बढ़ावा देने के लिए वेब और सोशल मीडिया के उपयोग को रोकना, युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और आतंकवादी कार्यकर्ताओं की भर्ती करने में धार्मिक केंद्रों के उपयोग को रोकने तथा सहिष्णुता को बढ़ावा देने के उपाय राष्ट्रों द्वारा किए जाने आवश्यक हैं। इस संदर्भ में उरुग्वे के सवाब और हेदायह केंद्र जैसी पहलों के योगदान का उदाहरण दिया जा सकता है जो चरमपंथी विचारधाराओं का मुकाबला करने तथा अंतर्राष्ट्रीय उग्रवाद-विरोधी सहयोग को ऑनलाइन स्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही चरमपंथ विरोधी केंद्रों के गठन की जरूरत भारत में भी है। इसके अतिरिक्त आधुनिक शिक्षा प्रणाली जिसमें मानवीय मूल्य, लोकतांत्रिक मूल्यों और सरोकारों, मानवाधिकारों के राष्ट्रीय एकीकरण के भावों को संवेदनशीलता के साथ रखा गया हो, उसे चरमपंथ प्रभावित क्षेत्रों में कुशलता से रखा जाना आवश्यक है। जोर इस बात पर होना चाहिए कि गुमराह युवाओं का डी-रेडीकलाइजेशन रणनीति के तहत कैसे उनकी कट्टरपंथी सोच और वैचारिकी का खात्मा किया जा सकता है? गृह मंत्रालय के तत्वावधान में गुमराह युवाओं को उनकी कट्टरपंथी सोच से उन्हें मुक्त करने के लिए डी-रेडीकलाइजेशन के लिए महाराष्ट्र मॉडल का अध्ययन किया गया है जहां इस दिशा में सफलता पाई गई है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और भारत की सॉफ्ट पॉवर डिप्लोमेसी

21 जून को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रही है। इसके लिए अभी से कार्यक्रमों का आयोजन भी शुरू हो चुका है। विश्व भर में भारत के जितने दूतावास या उच्चायोग हैं, वहां योग के महत्त्व के प्रसार के लिए भारत का विदेश मंत्रालय अभी से सक्रिय हो चुका है। भारत का मानना है कि वैश्विक शांति सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में योग की महत्त्वपूर्ण भूमिका का लाभ लिया जाना आवश्यक है। आज विश्व में जिस तरीके से युद्ध, अपराध, सिविल वॉर, घरेलू हिंसा, मानवाधिकारों का उल्लंघन जैसी समस्याएं व्याप्त हैं, उन सब का कारण विकृत चित्त है और योगा में इतनी शक्ति है कि वह विकृत चित्त वाले व्यक्ति को स्थिर चित्त वाले व्यक्ति में बदल सकता है जिससे व्यक्ति, परिवार, समाज, देश तथा वैश्विक समुदाय को एक बेहतर कार्य संस्कृति मिल सकती है। वर्तमान समय में पूरा विश्व योग के महत्त्व को मान रहा है क्योंकि योग संस्कृति से जुड़कर कई समाजों ने शांतिपूर्ण समाजों का दर्जा हासिल किया है। आयुष सचिव पद्मश्री राजेश कोटेचा ने एम्स दिल्ली के एक अध्ययन का हवाला देते हुए बताया है कि संपूर्ण स्वास्थ्य में योग का महत्त्व साबित हो चुका है। जिम जाने वाले और योग का अभ्याय करने वालों के बीच के तुलनात्मक अध्ययन में सामने आया कि योग का अभ्यास करने वालों में सतो गुण और जिम जाने वालों में रजो गुण तथा तमोगुण की अधिकता देखी गई है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हाल ही में भारत के आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) ने 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में अपने समारोहों की शुरुआत कर दी है।

जलवायु परिवर्तन को देखते हुए पर्यावरण मित्र जीवन शैली आज दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत है और योग ने विश्व में इसकी राह दिखायी है। योग भारत की सांस्कृतिक विरासत है। योग के जरिये पर्यावरण संरक्षण संकल्प पूरे विश्व के लिए जरूरी है। योग का पहली बार उल्लेख सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋगवेद में किया गया था। यह आध्यात्मिक विधा एक सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित है, जिसका उद्देश्य शरीर और मस्तिष्क के बीच सद्भाव लाना है। योग के महत्त्व को समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि योग क्या है? योग हजारों वर्षों से ऋषियों के अथक ध्यान का परिणाम है। हमारे ऋषियों ने योग को 'समत्वम योग उच्यते' के रूप में परिभाषित किया है, जिसका अर्थ है सुख और दुख दोनों में संतुलित रहना। योग ने विश्व को एक सूत्र में पिरोया है, वैश्विक मूल्यों को नया अर्थ दिया है और विभिन्न स्वास्थ्य प्रणालियों को एक-दूसरे के निकट लाया है।

आधुनिक युग में योगः

- स्वामी विवेकानंद आधुनिक काल में योग का प्रसार करने वाले प्रमुख योगियों में से एक थे। इस अवधि में योग करने का मुख्य उद्देश्य शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना था। रमण महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, बीकेएस अयंगर, के पट्टाभि जोइस, परमहंस योगानंद ने हठ योग, वेदांत योग और भक्ति योग के प्रसार तथा लोकप्रियता में भाग लिया। सदियों से योग में व्यापक परिवर्तन होते रहे हैं, लेकिन जब यह 21वीं सदी में प्रवेश किया, तब योग का सार आत्मा, मन, शरीर और प्रकृति के साथ एकता की भावना में समन्वय करना रहा है।

योग और कोविड महामारी प्रबंधनः

- पूरा विश्व कोविड-19 के रूप में कठिन समय से गुजरता रहा है। योग और आयुर्वेद ने महामारी पर नियंत्रण पाने में सहायता की है। रिपोर्टों के अनुसार, कोविड-19 रोगियों के मनोवैज्ञानिक संकट को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है जिसका समाधान नहीं किया जाता है। कोविड-19 देखभाल अस्पतालों में चिंता और तीव्र अवसाद के बाद आत्महत्या की भी रिपोर्ट प्राप्त हुई। विभिन्न देशों से प्राप्त समाचारों के अनुसार, कई रोगियों को पृथकवास की चिंता और लक्षणों के बिगड़ने के डर से बड़े संकट का सामना करना पड़ा था। इस दौरान श्वसन संकट, हाइपोक्सिया, थकान, अनिद्रा और अन्य लक्षणों जैसी जटिलताओं को भी देखा गया। योग और प्राकृतिक चिकित्सा प्रणालियों के प्रयोग ने कोविड-19 रोगियों को ठीक करने में सहायता प्रदान किया था। श्वांस लेने के सरल व्यायाम और प्राणायाम को महामारी के लक्षण वाले रोगियों तथा श्वसन संकट वाले लोगों में एसपीओ 2 के स्तर को बढ़ाने में सहायक रहा।

योगा और सांस्कृतिक कूटनीतिः

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से हुई। 27 सितंबर, 2014 को पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एकसाथ योग करने की बात कही थी। इसके बाद महासभा ने 11 दिसंबर, 2014 को इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और तभी से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अस्तित्व में आया। इसे भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के रूप में भी देखा जाता है। वैश्विक स्तर पर योग की बढ़ती लोकप्रियता ने भारत और कई देशों के सांस्कृतिक संबंधों को इस आधार पर मजबूती दी है। यूरोपीय देशों के साथ ही चीन जैसे देशों में भी योग की लोकप्रियता में वृद्धि हुई है। इसी क्रम में चीन में भी पांचवे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया था। भारतीय राजदूत विक्रम मिस्री ने इस संदर्भ में कहा था कि योग भारत और चीन के लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो दोस्ती एवं सहयोग की भावना के साथ मिलकर काम करने के लिए फायदेमंद है। वहीं नौफ मरवाई जिन्हें सऊदी अरब में आधिकारिक तौर पर पहली महिला योग टीचर के तौर पर चुना गया, उन्हें भारत अपनी योग डिप्लोमेसी के तहत पद्म श्री के सम्मान से सम्मानित कर चुका है ताकि योग का प्रसार अरब या खाड़ी क्षेत्रों में हो।
- यह भारतीय पहल की ही देन है कि सऊदी अरब खेल मंत्रालय ने जेद्दा में एक योग कार्यशाला का आयोजन किया। योग कार्यशाला

का आयोजन 'अरब यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम' के बैनर तले किया जा गया जिसमें 11 अरब देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन अरब देशों में संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, यमन, फिलिस्तीन, मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया और मॉरिटानिया शामिल हैं।

➢ वहीं भारत में राज्यों के स्तर पर योग के प्रचार प्रसार की बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा में सौ एकड़ क्षेत्र में योग विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में 550 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जिनमें से आधे से अधिक केंद्रों को आयुष से जोड़ा जाएगा। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने योग-आयोग की स्थापना की है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों में योग इंस्ट्रक्टर नियुक्त किए जा रहे हैं। कालेजों, विश्वविद्यालयों में योग के अध्ययन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

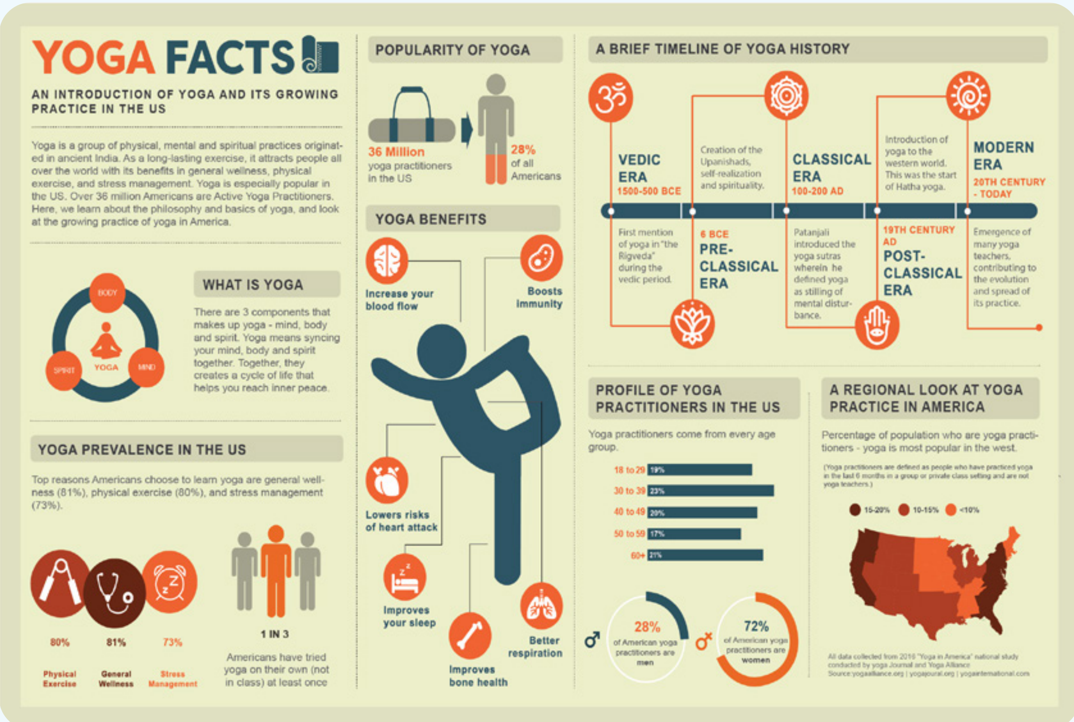

➢ भारत इस वर्ष जी-20 की अध्यक्षता कर रहा है। विश्व के लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण को समृद्ध करने के लिए अपने सॉफ्ट पावर योग को आगे बढ़ाने की हमारी विशेष जिम्मेदारी है। इस वर्ष हम आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में सामान्य योग प्रोटोकॉल (CYP) का प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। जयपुर में योग महोत्सव को मिली अद्भुत प्रतिक्रिया से योग को एक वैश्विक स्वास्थ्य सेवा आंदोलन बनाने के हमारे प्रयासों को बल मिला है।

आसान व प्राणायाम का महत्त्व:

➢ योग में विभिन्न प्रकार के प्राणायाम और कपालभाति जैसी योग क्रियाएं शामिल हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावी सांस की क्रियाएं हैं। इनका नियमित अभ्यास करने से लोगों को सांस संबंधी समस्याओं और उच्च व निम्न रक्तदाब जैसी बीमारियों में आराम मिलता है। योग वह इलाज है जिसका प्रतिदिन नियमित रूप से अभ्यास किया जाए, तो यह बीमारियों से धीरे-धीरे छुटकारा पाने में काफी सहायता करता है। यह हमारे शरीर में कई सारे सकारात्मक बदलाव लाता है और शरीर के अंगों की प्रक्रियाओं को भी नियमित करता है। कपालभाति, अनुलोम-विलोम, भ्रामरी एवं भस्त्रिका प्राणायाम स्वास्थ्य के साथ वजन को कम करने में भी लाभकारी होते हैं। प्राणायाम के द्वारा डायबिटीज, अत्यधिक वजन, मानसिक तनाव आदि से छुटकारा पा सकते हैं। स्वस्तिकासन से पैरों के दर्द में, गोमुखासन से यकृत, गुर्दे एवं गाठिया को दूर करने में, गोरक्षासन से मांसपेशियों में रक्त संचार बढ़ाने एवं योगमुद्रासन चेहरा सुन्दर व मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। योग के सभी आसनों से लाभ प्राप्त करने के लिए सुरक्षित और नियमित अभ्यास की आवश्यकता है। योग के दौरान श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेना और छोड़ना सबसे मुख्य है।

योग के फायदे:

योग के फायदे बच्चों से लेकर बूजुर्गों, महिलाओं एवं गर्भवती महिलाओं सभी को होते हैं। योग में हजारों बिमारियों को ठीक करने के गुण छुपे हुए हैं। दैनिक जीवन में योग का अभ्यास करना हमें बहुत सी बीमारियों से बचाने के साथ ही कई सारी भयानक बीमारियों जैसे- कैंसर, मधुमेह (डायबिटीज), उच्च व निम्न रक्त दाब, हृदय रोग, किडनी का खराब होना, लीवर का खराब होना, गले की समस्याओं तथा अन्य बहुत सी मानसिक बीमारियों से भी हमारी रक्षा करता है। इस बात को देश-विदेश के चिकित्सक तक मान चुकें हैं जो बीमारियां दवाइयों से ठीक नहीं हो पाती, उनका इलाज भी योग में सम्भ्व है। नियमित योग करने से शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करने लगते हैं, योग के विभिन्न आसनों से शरीर के अलग-अलग हिस्सों को फायदा पहुंचता है।

द केरल स्टोरीः विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दे

हाल ही में द केरल स्टोरी नामक मूवी ने भारत की राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा, संप्रभुता तथा विचार अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े प्रश्नों को उभारा है। ऐसे में इस बात का विश्लेषण जरूरी हो जाता है कि राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर राष्ट्रव्यापी साक्षरता और देश में सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए जिससे सिनेमा (जिसे समाज का दर्पण कहते हैं) का उद्देश्य भी पूरा हो जाए और राष्ट्रीय एकीकरण के सूत्र भी अप्रभावित रहें। वस्तुतः इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत के कुछ हिस्सों में आईएसआईएस की विचारधारा का प्रभाव पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है। खासकर युवाओं के मन में इस आतंकी विचारधारा के प्रति आकर्षण बढ़ा जिससे वे जुड़ने को मजबूर हुए। द केरल स्टोरी केरल में हिंदू और ईसाई लड़कियों की कहानी है, जिन्हें पहले लव जिहाद में फंसाया गया और बाद में आईएसआईएस आतंकवादी बनने के लिए इराक, सीरिया तथा अफगानिस्तान भेजा गया। ये फिल्म 32 हजार लड़कियों के गायब होने के दावे और उससे जुड़ी घटना पर बनी है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2016 में केरल के 21 लोगों ने इस्लामिक स्टेट जिहादी आतंकवादी समूह में शामिल होने के लिए देश छोड़ दिया था। उनमें से एक छात्रा ने शादी से पहले इस्लाम कबूल किया था। रिपोर्ट में कहा गया कि उसने जब देश छोड़ा तब वह आठ महीने की गर्भवती थी जिसका कारण लव जेहाद माना गया था। भारत में पहली बार केरल के ईसाई गिरिजाघरों ने 'लव जिहाद' शब्द गढ़ा था। चर्च का कहना था कि इस्लाम का विस्तार करने के लिए कट्टरपंथी लोगों की कार्यप्रणाली में 'लव जिहाद' भी शामिल रहा है। समय के साथ इसका स्वरूप और नाम बदलते रहे हैं, लेकिन इसका अंतिम लक्ष्य धर्मांतरण ही रहा है। दक्षिण भारत के महिलाओं और पुरूषों दोनों का ही ब्रेनवाश कर उन्हें धार्मिक कट्टरता, चरमपंथी सोच, धार्मिक रूढ़िवादिता, धार्मिक पूर्वाग्रहों से जोड़कर राष्ट्र विरोधी कार्य कराने के लिए तैयार करने की एक सुनियोजित रणनीति बनाई जाती रही है। बड़ी संख्या में भारत की महिलाओं के मन में आईएसआईएस की विचारधारा के प्रति सहानुभूति जगना, राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती रहा है।

आतंकवाद पर अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट 'कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेरोरिज्म, 2020' में वैश्विक आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट में 66 भारतीय मूल के लड़ाकों के होने की जानकारी मिली। अमेरिका की ओर से जारी रिपोर्ट में दावा किया गया था कि नवंबर 2020 तक इस्लामिक स्टेट से भारतीय मूल के 66 लड़ाकों के जुड़ने की जानकारी मिली थी। इसके अनुसार कोई विदेशी आतंकवादी लड़ाका (FTF) वर्ष 2020 के दौरान भारत नहीं लौटा। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया था कि एनआईए ने इस्लामिक स्टेट से जुड़े 34 मामलों की जांच की और 160 लोगों को गिरफ्तार किया था जिनमें सितंबर, 2021 में केरल व पश्चिम बंगाल से अलकायदा से जुड़े 10 सदस्य शामिल थे। इसके साथ ही रिपोर्ट में एनआईए सहित भारत के आतंकवाद रोधी एजेंसियों की सक्रियता से अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय आतंकवादी ताकतों का पता लगाने व उन्हें रोकने के लिए सराहना की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों को इकट्ठा करने वाली एजेंसियों का दावा है कि 2014 के बाद से भारत से 62 युवाओं की पहचान की गई है जो आईएसआईएस में शामिल हुए थे। आंकड़े यह भी कहते हैं कि विदेशों में बसे 68 भारतीयों के आईएसआईएस से संबंध हैं। इन 130 में से करीब 95 प्रतिशत दक्षिण भारत से हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसी द्वारा लगातार निगरानी के चलते 274 लोगों को आईएसआईएस या उसके सहयोगियों के साथ संबंध रखने के कारण गिरफ्तार किया गया है। कुछ ही समय पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक साथ तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक आदि राज्यों में 100 जगहों पर छापेमारी की थी। यह बताया गया था कि आईएसआईएस वीडियो के जरिए युवाओं की भर्ती कर रहा है। एनआईए को पिछले कुछ समय में ऐसे कई वीडियो की जानकारी मिली थी जिसमें युवाओं का ब्रेनवॉश किया जा रहा था।

भारत में पंथनिरपेक्षता के मूल्य बने रहें और सांप्रदायिक सौहार्द को भी क्षति न पहुंचे, इसके लिए ऐसी प्रवृत्तियों के खिलाफ कार्य करना जरूरी माना गया है। इसीलिए विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आधार बनाते हुए केरल स्टोरी मूवी का निर्माण भी किया गया जिसमें यह बताने की कोशिश की गई कि दक्षिण भारतीय राज्यों में इस्लामिक कट्टरता को किस प्रकार मजबूती मिली? महिलाओं में धार्मिक चरमपंथी सोच कैसे विकसित हुई? कैसे महिलाएं आतंकी संगठनों का साथ देने के लिए तैयार हुई? इस बात का विश्लेषण करने के क्रम में पता चलता है कि धर्म परिवर्तन और लव जिहाद एक प्रमुख कारण रहा है, जब एक सामान्य महिला ने इन परिस्थितियों में अपने को आतंकवादी मानसिकता में ढलने को तैयार किया। राजनीतिक विश्लेषक यह भी मानते हैं कि आज जिस प्रकार धार्मिक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिजाब, तीन तलाक कानून जैसे मुद्दे सामने आए हैं उनसे भी कुछ धर्म विशेष के लोगों ने धार्मिक कट्टरपंथी सोच की राह चुनी है। इसके साथ ही यह भी जरूरी माना गया है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर जिन भी मूवी का निर्माण किया जाए उनमें कोई अतिशयोक्ति का वर्णन न हो, पूर्वाग्रह और एकपक्षीय सोच न प्रदर्शित की जाये। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आईएसआईएस ने दक्षिण भारतीय राज्यों के युवाओं तथा महिलाओं को प्रभावित किया है, लेकिन वे कितनी संख्या में आईएसआईएस की सक्रियता वाले देशों में गए? कितने बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन या लव जिहाद का इस्तेमाल कर इस्लामिक तालिबानी सोच को मान्यता दिलाने का प्रयास किया गया? इन सबमें स्पष्टता होनी चाहिए।

भारत के संविधान में अनुच्छेद-19(1)(ए) में प्रत्येक नागरिक को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। इसमें जानने का अधिकार, विचारों की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद-19(2) के तहत यह बताया गया है कि विचार और अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदी कब लग सकती है? आजादी के बाद जब संविधान बना, तब अनुच्छेद-19 में भारतीय नागरिकों को वे सभी अधिकार दे दिए गए, जिसके लिए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी थी। संविधान में अनुच्छेद-19 से 22 तक कई सारे

अधिकार दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद-19(1)(A) में सभी भारतीय नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद-19 के तहत सभी अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही मिले हैं। अगर कोई विदेशी नागरिक है तो उसे ये अधिकार नहीं दिए गए हैं। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है कि एक भारतीय नागरिक लिखकर, बोलकर, छापकर, इशारे से या किसी भी तरीके से अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद-19(2) में उन परिस्थितियों के बारे में भी बताया गया है जब बोलने की आजादी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। जैसे:

- भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा हो।
- राज्य की सुरक्षा को खतरा हो।
- विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध बिगड़ने का खतरा हो।
- सार्वजनिक व्यवस्था के खराब होने का खतरा हो।
- शिष्टाचार या सदाचार के हित खराब हों।
- अदालत की अवमानना हो।
- किसी की मानहानि हो।
- अपराध को बढ़ावा मिलता हो।

भारत में धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान:

भारत का संविधान भारत को एक पंथनिरपेक्ष देश घोषित करते हुए कुछ धार्मिक अधिकारों को मूल अधिकार के रूप में प्रदान करता है जिससे देश में पंथनिरपेक्षता, धर्म के मामले में व्यक्ति की स्वतंत्रता और देश में धार्मिक सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, लेकिन इन अधिकारों का दुरुपयोग करने पर कार्यवाही करनी भी जरूरी हो जाती है। यह बात केरल स्टोरी नामक मूवी से भी जाहिर होती है। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को निम्नलिखित धार्मिक अधिकार देता है:

- **अनुच्छेद-25:** यह धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, जिसमें किसी धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार शामिल है।
- **अनुच्छेद-26:** यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है।
- **अनुच्छेद-27:** यह किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिये करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता निर्धारित करता है।
- **अनुच्छेद-28:** यह कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा अथवा धार्मिक पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता देता है।
- भारत में व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार-प्रसार करने की आजादी है, लेकिन धर्म के प्रचार में आईएसआईएस की विचारधारा का समर्थन या उसको बढ़ावा देना एक अपराध है। धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार व्यक्ति को स्वैच्छिक स्तर पर धर्म परिवर्तन का अधिकार तो देता है लेकिन लव जेहाद के जरिए बहला फुसलाकर या बाध्यतामूलक ढंग से धर्म परिवर्तन कराकर किसी को आतंकी विचारधारा या कार्यवाही से जोड़ना एक अपराध है।
- उल्लेखनीय है कि कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित करने वाले कानून पारित किये हैं। मार्च 2022 में हरियाणा राज्य विधानसभा ने प्रलोभन, जबरदस्ती या धोखाधड़ी के माध्यम से धर्म परिवर्तन के खिलाफ हरियाणा धर्म परिवर्तन रोकथाम विधेयक, 2022 पारित किया। वहीं अगस्त 2022 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2022 भी पारित किया, जिसमें बड़े पैमाने पर धर्मांतरण को अपराध बनाने की मांग की गई थी।

द केरल स्टोरी का वैश्विक प्रसार:

- द केरल स्टोरी को अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में 200 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया। इस फिल्म के निर्देशक सुदीप्तो सेन का मानना है कि यह फिल्म एक मिशन है जो सिनेमा की रचनात्मक सीमाओं से परे है। यह एक ऐसा आंदोलन है जिसे दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। जो चीजें मानवाधिकार उल्लंघन तथा मौलिक अधिकार उल्लंघन को बढ़ावा देती हैं, जो राष्ट्र की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ काम करने वाली हों उनके खिलाफ मीडिया, सोशल मीडिया, मूवी के स्तर पर जागरूकता प्रसार होना आवश्यक है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों (हिंदू जिनमें जैन, सिख, बौद्ध और ईसाई) का बड़े स्तर पर शोषण हुआ है। इस शोषण का आलम यह रहा है कि इन देशों में अल्पसंख्यक समुदाय अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। दुनिया भर में इस्लामिक राज्य का शासन लाने में आईएसआईएस की क्रूरता, चीन में अल्पसंख्यकों का शोषण चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा किया जाना, उत्तर कोरिया की कम्युनिस्ट आधारित तानाशाही, धर्मांतरण रैकेट और ऐसी कई अन्य अमानवीय गतिविधियां दुनिया के बड़े हिस्से में हो रही हैं जिनके खिलाफ मीडिया के स्तर पर कार्य होना जरूरी है। इन सब मुद्दों पर वैश्विक स्तर पर मूवी भी बन चुकी हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भारत में सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने हेतु विभिन्न धार्मिक समुदायों के मध्य आपसी विश्वास को बढ़ावा देने वाले पहलों का समर्थन किया जाना आवश्यक है, लेकिन इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे जिन्हें धार्मिक कारक प्रभावित करता है, उससे समझौता भी नहीं किया जा सकता है।

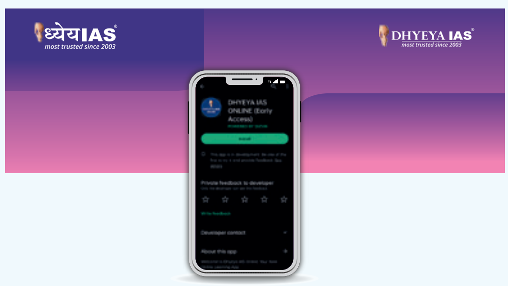

DOWNLOAD OUR
ANDROID MOBILE APP
Google Play Store

जी-20 की आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक का महत्त्व

संदर्भः

हाल ही में जी-20 की आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दूसरी बैठक 23-25 मई 2023 को मुंबई में सम्पन्न हुई।

परिचयः

भारत की अध्यक्षता में आयोजित हो रहे जी-20 बैठकों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक भी आयोजित की गई। मुंबई में हुई इस बैठक में 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। ध्यातव्य है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह, आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर सेंदाई फ्रेमवर्क (2015 से 2030) का एक भाग है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह के बारे में :-

- आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह सेंदाई फ्रेमवर्क का एक भाग है। इस कार्य समूह को 2023 में भारत की जी-20 अध्यक्षता के अंतर्गत आयोजित किया गया। ध्यातव्य है कि इस कार्य योजना की 3 बैठकें हुईः
  - प्रथम बैठक , गांधीनगर 29 मार्च से 1 अप्रैल 2023
  - द्वितीय बैठक मुंबई , 23 से 25 मई 2023
  - तीसरी बैठक 24 से 26 जुलाई 2023, चेन्नई (प्रस्तावित)

आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठकों के बारे में:

अब तक भारत के नेतृत्व में जी-20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दो बैठके हो चुकी हैं जिनमे आपदा से संबंधित जोखिमों तथा उनसे निदान हेतु उपायों पर चर्चा कि गई जिनका वर्णन निम्नवत है-

प्रथम बैठक के दौरान प्रमुख चर्चाः

- इस बैठक में आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह ने जी-20 देशों की सरकारों से यह आग्रह किया है कि वे आपदा रोधी प्रणाली के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर भी ध्यान दें।
- इसके साथ ही इस बैठक के दौरान आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह को सेंदाई फ्रैमवर्क के कार्यों की मध्यावधि समीक्षा के लिए भी अधिकृत किया गया।

इस बैठक में 5 प्रमुख प्राथमिकताओं पर ध्यान दिया गया जो निम्नवत हैं-

- आपदा से संबंधित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को वैश्विक स्तर पर बहाल करना।
- अवसंरचना प्रणालियों को आपदा प्रतिरोधी बनाने की दिशा में प्रतिबद्धता।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिये मजबूत राष्ट्रीय वित्तीय ढाँचा।
- राष्ट्रीय एवं वैश्विक आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत करना।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए पारिस्थितिक तंत्र-आधारित दृष्टिकोण के अनुप्रयोग को बढ़ाना।

द्वितीय बैठक के प्रमुख निष्कर्षः

मुंबई में आयोजित हुई इस बैठक में प्रतिनिधियों ने मुख्य रूप से निम्नलिखित विषयों पर चर्चा कीः

- आपदा-रोधी इंफ्रास्ट्रक्चर और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वित्तपोषण के महत्त्व पर।
- एक संस्थागत ढांचा के कानूनी समर्थन पर विचार जो निम्नलिखित कार्य करेः
  - इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निवेश का समर्थन।
  - इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के विखंडन से संरक्षण।
  - इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के निष्पादन को बढ़ावा।
- सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों पर आपदाओं के प्रभाव को कम करने में सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों की भूमिका।
- अगले तीन वर्षों के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह के रोडमैप पर चर्चा।

द्वितीय बैठक के दौरान भारत की भूमिकाः

- भारत ने डाटा प्रबंधन, प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्यवाही, लचीला बुनियादी ढांचे और आपदा जोखिम में कटौती के लिए वित्तपोषण के क्षेत्रों में सार-संग्रह के सह-विकास के माध्यम से समर्थन की पेशकश की।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए पर्यावरण-आधारित दृष्टिकोण।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण को जी-20 की प्रमुखता में लाना।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठकों का महत्त्वः

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए जी 20 देशों द्वारा सामूहिक कार्यवाही की आवश्यकता का प्रस्तुतीकरणः

आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए जी-20 देशों द्वारा सामूहिक कार्यवाही की आवश्यकता को रेखांकित किया है तथा इस संदर्भ में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत कियाः

- G-20 देशों की समग्र जनसंख्या 4.7 बिलियन है तथा ये देश विश्व मे सर्वाधिक संपत्ति का संकेन्द्रण भी करते हैं। इस संपत्ति संकेन्द्रण के लिए प्रयोग की गई प्रथाओं के फलस्वरूप ये देश आपदा जोखिम और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अधिक संवेदनशील हैं।
- हालिया विश्व जोखिम सूचकांक में शीर्ष 10 कमजोर देशों में G-20 के 4 सदस्य देश हैं।
- आपदाओं के कारण G-20 देशों की सामूहिक औसत वार्षिक हानि 218 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। यह राशि इन देशों द्वारा संयुक्त इंफ्रा निवेश का 9 % है।
- इस प्रकार सामूहिक समस्या के लिए सामूहिक निराकरण की आवश्यकता है।

आपदा जोखिम को कम करने के लिए प्रमुख अभ्यासों पर चर्चाः

- इन दोनों बैठकों के दौरान आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए कुछ प्रमुख अभ्यासों पर चर्चा की गई है। उदाहरणस्वरूप इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निवेश का समर्थन, अवसंरचना प्रणालियों को आपदा प्रतिरोधी बनाने की दिशा में प्रतिबद्धता, डाटा प्रबंधन,

प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्यवाही को महत्त्व, आपदा के वित्तीयन में सहयोग इत्यादि।

सेंडाई फ्रेमवर्क की समीक्षाः

- बैठकों के दौरान आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह को आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर सेंदाई फ्रेमवर्क (2015 से 2030) की मध्यावधिक समीक्षा के लिए सशक्त किया गया है। इस प्रक्रिया के द्वारा सेंदाई फ्रेमवर्क की प्रगति का मूल्यांकन भी किया जाएगा।

अन्य क्षेत्रों के साथ आपदा की संलग्नता पर चर्चाः

- इन बैठकों की चर्चाओं से यह स्पष्ट हुआ है कि आपदा जोखिम को कम करने के लिए पर्यावरण के दृष्टिकोण तथा सामाजिक सुरक्षा को अपनाने की आवश्यकता है। अतः यह बैठक आपदा जोखिम को पर्यावरण सामाजिक सुरक्षा सहित अन्य क्षेत्रों के साथ संलग्न करती है।

अल्पकालिक रणनीतिः

- आपदा जोखिम पर कार्य समूह की बैठक न सिर्फ इस वर्ष चलेगी बल्कि इसे लगातार 3 वर्षो तक जारी रखा जाएगा। इस स्थिति में हम यह कह सकते हैं कि इन बैठकों से हमें जल्द ही आपदा जोखिम पर एक सुदृढ़ रणनीति प्राप्त होगी।

बैठकों के दौरान निष्कर्षित प्रमुख अनुशंसाओं के समक्ष चुनौतियाँः

- इन बैठकों के दौरान सामूहिक वित्तीयन तथा आपदा प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की चर्चा की गई है। अतः यह आवश्यक है कि विकसित देशों को विकासशील देशों में आपदा जोखिम को कम करने संबंधी निवेश करना चाहिए। वर्तमान विश्व में बन रहा संरक्षणवाद इस अनुशंसा के समक्ष एक प्रमुख चुनौती है।
- वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या है जिसे कम करने के लिए यूएनएफसीसीसी की लगातार बैठकों में विभिन्न देशों के लिए विभिन्न प्रतिबद्धताओं को निश्चित किया गया है। परंतु अधिकांश देश यूएनएफसीसीसी द्वारा बताई गई प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने के लिए विशेष रूचि नहीं प्रदर्शित कर रहे। ऐसे में यह शंका जाहिर होती है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण की कार्य समूह द्वारा दी गई अनुशंसाओं को वह पूर्ण करेंगे या नहीं।
- इन बैठकों के दौरान यह चर्चा की गई कि आपदा जोखिम को कम करने के लिए आपदाओं को पर्यावरण तथा सामाजिक सुरक्षा सहित अन्य क्षेत्रों के साथ संलग्न करने की आवश्यकता है। इन चर्चाओं के दौरान यह नहीं बताया गया कि किस प्रकार से आपदा को सामाजिक सुरक्षा या पर्यावरण के साथ जोड़ करके एक रणनीति तैयार की जाए?
- इस बैठक को लगातार तीन वर्ष तक जारी रखने की बात की गई है परंतु क्या 3 वर्ष आपदा जोखिम के न्यूनीकरण के लिए उपयुक्त है? यह एक बड़ा प्रश्न है।

भविष्य की चुनौती हेतु तैयारियांः

आपदा जोखिम को कम करने के लिए कुछ अन्य प्रमुख रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं जिनका वर्णन निम्नवत हैः

- आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए बेहतर वित्तपोषण की आवश्यकता है। यद्यपि इन बैठकों के दौरान वित्त पोषण की आवश्यकता पर चर्चा की गई है परंतु वित्त पोषण के संबंध में सबसे बड़ी चुनौती उसके प्रभावी क्रियान्वयन की होगी। अधिकांश देश मात्र सरकारी बजट के माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण की वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम नहीं होंगे। अतः इस स्थिति में निजी क्षेत्र को तथा जी-20 देशों के सामूहिक वित्तपोषण के प्रथा को स्वीकार करना होगा।
- बुनियादी संरचना का विकास करते समय यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि शहरों का निर्माण सस्टेनेबल हो। शहरों का विकास करते समय पर्यावरण की सुरक्षा, गरीबी तथा असमानता में कमी जैसे स्थितियों पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। इन प्रथाओं के द्वारा आपदाओं की जोखिम तथा संवेदनशीलता को कम किया जा सकता है।
- वर्तमान समय में भारत सहित कई देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जा रहा है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर जैसेः सड़के, हवाई अड्डे, रेलवे लाइन इत्यादि अवसंरचना आपदाओं के प्रति लचीली बनाई जाएं।
- आपदा जोखिम को क्षेत्रीय समस्या के स्थान पर एक वैश्विक समस्या के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है।। यह आवश्यक है कि वैश्विक, राष्ट्रीय व स्थानीय स्थानों पर अलग-अलग आपदाओं के लिए अलग-अलग शमन रणनीतियां बनाई जाए जिससे उनका प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके।
- आपदा प्रबंधन के लिए विज्ञान तथा तकनीक के अनुप्रयोगों को बढ़ावा दिया जाए।

अन्य तथ्य

आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु पहलः

- वैश्विक स्तर परः
  - जलवायु जोखिम और पूर्व चेतावनी प्रणाली (CREWS)
  - आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु संेदाई फ्रेमवर्क 2015-2030
  - जलवायु सूचना और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली पर हरित जलवायु कोष के क्षेत्रीय दिशा-निर्देश।
- भारत की पहलः
  - आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे के लिये गठबंधन (CDRIS)
  - राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP)

निष्कर्षः

आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दो बैठकों के दौरान कई योजनाओं तथा प्रथाओं पर चर्चा की गई। हालांकि यह आवश्यक है कि आपदा जोखिम से संबंधित चुनौतियों को तीसरी बैठक के दौरान मुख्य रूप से रेखांकित किया जाए तथा इस पर वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देकर के संेदाई फ्रेमवर्क के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाए।

1. आदर्श कारागार अधिनियम, 2023

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गृह मंत्रालय (MHA) ने 'आदर्श कारागार अधिनियम 2023' तैयार किया है जो जेल प्रशासन को बदलने के लिए ब्रिटिश युग के कानून को प्रतिस्थापित करेगा तथा कैदियों के सुधार और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करेगा।

आदर्श कारागार अधिनियम 2023:

- मौजूदा जेल कानून अपराधियों के पुनर्वास और समाज में पुर्नएकीकरण को प्राथमिकता नहीं देता है। यह नया कानून दोषियों को शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और मानसिक स्वास्थ्य सहायता देने पर केंद्रित है ताकि वे अपनी रिहाई के बाद गौरव पूर्ण जीवन जी सकें।
- इसमें कारागार अधिनियम-1894, कैदी अधिनियम-1900, कैदियों का स्थानांतरण अधिनियम-1950 और वर्तमान समय की आवश्यकतानुसार प्रांसगिक प्रावधानों को शामिल किया गया है।
- 2023 का आदर्श कारागार अधिनियम राज्यों के लिए अपने स्वयं के अधिकार क्षेत्र में लागू करने हेतु एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा।
- पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPRD) ने इसे राज्य जेल अधिकारियों, सुधारक पेशेवरों और अन्य हितधारकों के सहयोग से पूरा किया है।
- यह जेल विकास बोर्ड, जेल के डिजाइन, विकास और रखरखाव की देखरेख करेगा।
- इसके द्वारा अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करने और स्वतंत्रता के लिए उनके संक्रमण को आसान बनाने के लिए कैदियों को पैरोल, छूट या जल्दी रिहाई दी जा सकती है।
- यह महिला कैदियों, ट्रांसजेंडर कैदियों और अन्य कमजोर समूहों के लिए अलग आवास प्रदान करेगा।
- यह स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, परामर्श आदि के माध्यम से कैदियों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करेगा।
- यह जेल प्रशासन में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर दिशानिर्देशों की पेशकश करके तथा दोषियों की रिहाई, फर्लो (Furlough) और अच्छे व्यवहार को पुरस्कृत करने के प्रावधानों को पेश करके वर्तमान अधिनियम में व्यापक बदलाव करेगा।

कारागार अधिनियम 1894:

- 1894 का जेल अधिनियम 22 मार्च, 1894 को पारित किया गया था और 1 जुलाई, 1894 को प्रभावी हुआ। यह कानून भारतीय जेल के रखरखाव करने के इरादे से बनाया गया था।
- अधिनियम के अध्याय-II में जेल के रखरखाव और अधिकारियों को संबोधित किया गया है। यह अधिनियम जेल अधिकारियों की नियुक्ति की अनुमति देता है जिसमें अधीक्षक, चिकित्सा अधिकारी, जेलर और आवश्यक माने जाने वाले अधिकारी आदि शामिल होते हैं।
- महानिरीक्षक जेल के प्रभारी होंगे जो राज्य के निर्देशानुसार कार्यों का निष्पादन करेंगे। अधिकारियों को जेल के भीतर कैदियों के आवास के लिए उपयुक्त स्थान की व्यवस्था का प्रावधान है।

आगे की राह:

आदर्श कारागार अधिनियम 2023 का मुख्य उद्देश्य राज्यों को उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में एक मार्गदर्शक के रूप में मदद करना है। यह कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों और जेल मानकों के समझौते व संधियों के तहत अपने कर्त्तव्यों को पूरा करने में सहायता भी करेगा। माना जा रहा है कि इस अधिनियम से दोषियों के जीवन और पूरे समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

2. डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) को वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही (Q3) के लिए डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स (DGQI) मूल्यांकन में 66 मंत्रालयों में से दूसरे स्थान पर रखा गया है। इस मंत्रालय को 5 में से 4.7 अंक मिले हैं। यह डेटा गवर्नेंस में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- यह अध्ययन उन सुधारों को भी इंगित करता है जो मंत्रालय के भीतर निर्बाध डेटा इंटरचेंज और सहक्रियाशील उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं। साथ ही इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट मार्ग भी उल्लिखित हैं।
-
- आईआईटी मद्रास में बंदरगाहों, जलमार्गों और तटों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र को DGQI आवश्यकताओं के अनुसार MoPSW की प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) विकसित करने का काम सौंपा गया है जिसने इस सफलता में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- डीजीक्यूआई ने पांच MoPSW परियोजनाओं जैसे-सागरमाला, R-D, शिपिंग, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स (ALHW), अंतर्देशीय जल मार्ग भारतीय प्राधिकरण (IWAI) और अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWT) के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) पोर्टलों का मूल्यांकन किया है ताकि डेटा प्रवाह, डेटा की गुणवत्ता में सुधार हो सके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग (AI/ML) जैसी नई तकनीकों को शामिल किया जा सके।
- नीति-निर्माता, डेटा-संचालित दृष्टिकोण का उपयोग करके प्रवृत्तियों, अवसरों और सुधार के क्षेत्रों की सही पहचान करते हैं जो विश्वसनीय डेटा के आधार पर निर्णय लेकर मंत्रालय हेतु बेहतर परिणाम प्रदर्शित करता है।

डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स:

- डीजीक्यूआई एक व्यापक ढांचा है जो भारत सरकार के कई

मंत्रालयों और एजेंसियों के डेटा शासन प्रथाओं का आंकलन करता है।

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (NITI) आयोग के साथ साझेदारी में DGQI मूल्यांकन जारी करता है।
- डेटा जनरेशन, डेटा गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी का उपयोग, डेटा विश्लेषण, उपयोग और प्रसार, डेटा सुरक्षा व मानव संसाधन क्षमता और केस स्टडी छह प्राथमिक मुद्दे हैं जो DGQI द्वारा मूल्यांकन किए जाते हैं।

बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) के बारे में:

- बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत जहाज निर्माण व जहाज-मरम्मत, प्रमुख बंदरगाह, राष्ट्रीय जलमार्ग और अंतर्देशीय जल परिवहन शामिल हैं।
- भूतल परिवहन मंत्रालय को सन् 2000 में दो मंत्रालयों में विभाजित किया गया था जिसके अंतर्गत भूतल परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा शिपिंग मंत्रालय शामिल था।
- शिपिंग मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय को 2004 में पुनः मिलाया गया जिसका नाम बदलकर शिपिंग, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कर दिया गया। इसके अंतर्गत दो विभाग थे- एक शिपिंग के लिए और दूसरा सड़क परिवहन व राजमार्गों के लिए।
- वर्ष 2020 में पुनः एक आदेश द्वारा शिपिंग मंत्रालय को शिपिंग तथा जलमार्ग मंत्रालय नाम दिया गया जिसके वर्तमान मंत्री सर्बानन्द सोनोवाल हैं।

आगे की राह:

डेटा-संचालित निर्णय लेने के लिए MoPSW की भारत के लोगों की सफलतापूर्वक सेवा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। MoPSW ने अन्य मंत्रालयों और विभागों के लिए डेटा तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके एक उच्च बेंचमार्क स्थापित किया है।

3. प्रीटर्म बर्थ के मामले में भारत शीर्ष 5 देशों में शामिल: अध्ययन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रकाशित हुई 'बॉर्न टू सून: डिकेड ऑफ एक्शन ऑन प्रीटर्म बर्थ 2023' रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में सभी प्रीटर्म जन्मों में से लगभग आधे 5 देशों (भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया, चीन और इथियोपिया) में हुए।

रिपोर्ट के बारे में:

- यह रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य के लिए भागीदारी (PMNCH) द्वारा जारी की गई है जो महिलाओं, बच्चों और किशोरों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा गठबंधन है।
- रिपोर्ट बच्चों के अस्तित्व और स्वास्थ्य के लिए एक 'मौन आपातकाल' का संकेत देती है।
- अनुमानित 37 सप्ताह से पूर्व जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं को प्रीटर्म बर्थ की श्रेणी में रखा जाता है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- पिछले दशक में 152 मिलियन बच्चे प्रीटर्म थे जो उच्च मृत्यु दर के जोखिम के संपर्क में थे।
- यह रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रत्येक 10 में से 1 प्रीटर्म बच्चे जन्म लेते हैं जिनमें से 1 बच्चे की प्रत्येक 40 सेकेंड में मृत्यु हो जाती है।
- दुनिया भर में पांच देशों (भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया, चीन और इथियोपिया) में 45% बच्चे प्रीटर्म होते हैं।
- अनुमानित 13.4 मिलियन बच्चे 2020 में समय से पहले पैदा हुए थे, जिनमें लगभग 10 लाख की मृत्यु हो गई थी।
- 2020 में, बांग्लादेश में सबसे अधिक प्रीटर्म बर्थ (16.2%) हुए जिसके बाद मलावी (14.5%) और पाकिस्तान (14.4%) था।
- रिपोर्ट में पाया गया है कि पिछले दशकों में दुनिया के किसी भी क्षेत्र में समय पूर्व जन्म दर में कोई बदलाव नहीं आया है। वैश्विक प्री-टर्म जन्म दर 2020 में 9.9% थी, जबकि 2010 में यह 9.8% थी।

भारत में प्रीटर्म जन्म के कारक:

- नवजात देखभाल के लिए बुनियादी ढांचे को और अधिक विस्तृत तथा उपयोगी बनाने की आवश्यकता है।
- जीवनशैली में बदलाव, पुरानी बीमारियाँ और आईवीएफ गर्भधारण जैसे कई कारक शहरी केंद्रों में प्रीटर्म जन्मों में वृद्धि के साथ जुड़े हुए हैं।
- यहां तक कि कम प्रजनन स्तर और सहायक गर्भधारण भी समय से पहले जन्म के जोखिम के बिना नहीं हैं।

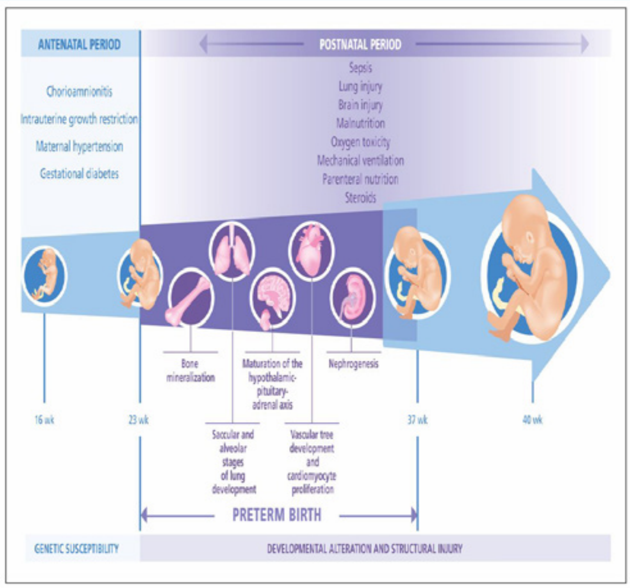

रिपोर्ट द्वारा दिए गए सुझाव:

- रिपोर्ट में नवजात स्वास्थ्य में निवेश को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय नीतियों के कार्यान्वयन में तेजी लाने, इन क्षेत्रों में प्रयासों को एकीकृत करने

और देखभाल की गुणवत्ता व पहुंच में सुधार का समर्थन करने के लिए स्थानीय नेतृत्व वाले नवाचार और अनुसंधान का समर्थन करने सहित कई कार्यवाहियों का आह्वान किया गया है।

- जोखिमों की पहचान और प्रबंधन के लिए गर्भावस्था से पहले व उसके दौरान गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बनाकर रोकथाम में भी प्रगति होनी चाहिए।

आगे की राह:

रिपोर्ट प्रीटर्म बर्थ कैजुअल्टी की खतरनाक स्थिति पर प्रकाश डालती है। राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम और भारत नवजात कार्य योजना आदि योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन से प्रीटर्म बर्थ के मुद्दों को हल किया जा सकता है।

4. सरकार ने डॉक्टरों के लिए यूनिक आईडी अनिवार्य किया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने एक नया प्रस्ताव पारित किया है जिसमें भारत में चिकित्सा का अभ्यास करने वाले सभी डॉक्टरों के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या (UID) होना अनिवार्य कर दिया है। नए नियम के अनुसार, एनएमसी एथिक्स बोर्ड द्वारा यूआईडी को केंद्रीय रूप से तैयार किया जाएगा, जिसमें प्रेक्टिसनर्स को एनएमआर में पंजीकरण और भारत में चिकित्सा का अभ्यास करने की पात्रता प्रदान की जाएगी।

मुख्य विशेषताएं:

- एनएमसी का नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड देश में सभी पंजीकृत चिकित्सकों के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय चिकित्सा पंजीकरण (NMR) बनाए रखेगा।
- एनएमआर में सभी राज्य चिकित्सा परिषद रजिस्ट्रियों के पंजीकृत चिकित्सकों के रिकॉर्ड शामिल होंगे।
- एनएमआर में चिकित्सा व्यवसायी के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी जैसे चिकित्सा योग्यता, विशेषता, उत्तीर्ण होने का वर्ष, विश्वविद्यालय, संस्थान का नाम जहां से योग्यता अर्जित की गई थी और रोजगार का स्थान (अस्पताल का नाम/ संस्थान) शामिल होगी। एनएमआर को एनएमसी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से कोई भी एक्सेस कर सकता है।
- एनएमसी की घोषणा के अनुसार, चिकित्सा का अभ्यास करने का लाइसेंस हर पांच साल में नवीनीकृत किया जाना चाहिए। लाइसेंस की वैधता समाप्त होने से तीन महीने पहले चिकित्सकों को लाइसेंस नवीनीकरण के लिए राज्य चिकित्सा परिषद में आवेदन करना होगा। एथिक्स मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड (EMRB), एनएमसी लाइसेंस को अपग्रेड करने के लिए कोई शुल्क नहीं लेगा।
- यदि राज्य चिकित्सा परिषद लाइसेंस नवीनीकरण आवेदन से इनकार करती है, तो चिकित्सक नैतिकता और चिकित्सा विनियमन बोर्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के बारे में:

- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) एक सांविधिक निकाय है जो भारत में चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अभ्यास के नियमन के लिए जिम्मेदार है।
- इसकी स्थापना 2019 में हुई थी जिसने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) का स्थान लिया था।
- एनएमसी देश में सभी पंजीकृत चिकित्सकों के राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है।
- नेशनल मेडिकल काउंसिल का प्रमुख लक्ष्य भारत में चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अभ्यास की गुणवत्ता में सुधार करना है।
- यह चिकित्सा शिक्षा और अभ्यास के लिए मानदंड व मानक बनाकर उसे लागू करता है।
- एनएमसी यह सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार है कि देश में योग्य और सक्षम चिकित्सक उपलब्ध हों।

विशिष्ट पहचान संख्या (UID):

- यूआईडी एनएमसी की नैतिक समिति द्वारा उत्पन्न 12-अंकीय आई. डी. नंबर है।
- यूआईडी को एनएमआर से जोड़ा जाएगा और भारत में इसका इस्तेमाल डॉक्टरों की पहचान करने व उन्हें ट्रैक करने के लिए किया जाएगा।
- भारत में प्रैक्टिस करने की इच्छा रखने वाले सभी डॉक्टरों के लिए यूआईडी आवश्यक होगा।

राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर (NMR) क्या है:

- एनएमआर एक डेटाबेस है जिसमें भारत में सभी पंजीकृत चिकित्सकों की जानकारी शामिल है।
- एनएमसी एनएमआर पर नजर रखेगा जिसमें व्यवसायी का नाम, योग्यता, विशेषज्ञता, उत्तीर्ण होने का वर्ष और रोजगार का स्थान जैसी जानकारी शामिल होगी।

आगे की राह:

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) भारत में चिकित्सा शिक्षा तथा अभ्यास की गुणवत्ता को बनाए रखने और सुधारने के लिए जिम्मेदार एक नियामक निकाय है। इसका उद्देश्य देश में योग्य और सक्षम चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा सभी के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है।

5. सीसीपीए और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म

चर्चा में क्यों?

सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने एक एडवाइजरी जारी करके मैन्युफैक्चरर्स और ई-कॉमर्स कंपनियों को कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर बनाने या बेचने पर रोक लगा दी है। CCPA ने शीर्ष पांच ई-कॉमर्स- Amazon, Flipkart, Snapdeal, Shopclues और Meesho के खिलाफ भी एक आदेश जारी किया है और उन्हें कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप की बिक्री की अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि सीसीपीए ने यह फैसला स्वप्रेरणा से लिया है।

सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप्स:

- इन उपकरणों को सीट बेल्ट बकल में डालने के लिए निर्मित किया जाता है ताकि सीट बेल्ट न लगाने पर अलार्म बजने से रोका जा सके। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा बताए गए आंकड़ों के अनुसार, सीट बेल्ट नहीं लगाने के कारण 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में कुल 16,397 लोगों की मौत हुई।
- सीट बेल्ट रिमाइंडर/अलार्म ड्राइवर और यात्रियों को सचेत करता है जब वाहन के अंदर किसी ने सीट बेल्ट नहीं बांधी हो।
- आगे की सीट के यात्रियों के लिए यह सीट बेल्ट रिमाइंडर सभी वाहन निर्माताओं हेतु अनिवार्य है। सितंबर, 2022 में एमओआरटीएच ने पिछली सीट के यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट लगाने के अनिवार्य प्रावधान पर चर्चा की थी।

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के खिलाफ दिशा-निर्देश:

- अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, Shopclues और Meesho जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को सीसीपीए ने अपनी वेबसाइटों से ऐसे उत्पादों की बिक्री को तुरंत वापस लेने का निर्देश दिया है। इन उत्पादों के निर्माताओं, विक्रेताओं, आयातकों, वितरकों की जानकारी भी 15 दिनों के अन्दर मांगी है।
- सीसीपीए ने अपने आदेश में कहा है कि ये सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर डिवाइस मोटर वाहन अधिनियम-1988 का उल्लंघन करते हैं जो चालकों और यात्रियों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य करता है। यह उपभोक्ता अधिकारों और सुरक्षा नियमों का प्रमुख उल्लंघन है।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA):

- सीसीपीए एक वैधानिक निकाय है, जिसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम- 2019 के तहत स्थापित किया गया है। यह अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकृत है कि कोई भी व्यक्ति अनुचित व्यापार प्रथाओं में खुद को शामिल न करे।
- सीसीपीए का नेतृत्व एक मुख्य आयुक्त द्वारा किया जाता है जिसे केंद्र सरकार द्वारा 3 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक नियुक्त किया जाता है।
- इसके पास भ्रामक विज्ञापनों के निर्माताओं, समर्थनकर्ताओं और प्रकाशकों पर 10 लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना व 5 वर्ष तक कारावास लगाने की शक्ति प्राप्त है।
- यह असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेने, अनुचित व्यापार प्रथाओं को बंद करने तथा उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की गई कीमत की प्रतिपूर्ति का आदेश भी दे सकता है।

आगे की राह:

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सीट बेल्ट पहनने से चालकों और अन्य बैठे लोगों में मृत्यु का जोखिम 45 से 50% तक कम हो जाता है, जबकि पिछली सीट के यात्रियों के लिए मृत्यु और गंभीर चोटों का जोखिम 25% तक कम हो जाता है। सुरक्षा उपायों से बचने वाले ऐसे उपकरण न केवल चोट लगने की जोखिम को बढ़ाते हैं, बल्कि कानून व्यवस्था एजेंसियों के लिए भी बाधा उत्पन्न करते हैं।

6. असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने कहा कि विधायी कार्यों के माध्यम से बहुविवाह प्रथा पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इस मुद्दे से संबंधित व्यापक समझ के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

बहुविवाह क्या है?

- बहुविवाह एक से अधिक विवाहित जीवनसाथी-पत्नी या पति रखने की प्रथा है। परंपरागत रूप से, बहुविवाह एक पुरुष की एक से अधिक पत्नियाँ रखने की स्थिति थी।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-20) में बताया गया कि ईसाईयों में बहुविवाह का प्रसार 2.1%, मुसलमानों में 1.9%, हिंदुओं में 1.3% और अन्य धार्मिक समूहों में 1.6% था।
- अध्ययनों में पाया गया है कि जनजातीय आबादी में सबसे अधिक बहुविवाह की प्रथा का प्रसार पाया जाता है।

बहुविवाह की कानूनी स्थिति:

- विवाह व्यक्तिगत कानूनों द्वारा नियमन के अंतर्गत आता है। इसलिए अलग-अलग धार्मिक पर्सनल लॉ के तहत अलग-अलग कानूनी स्थिति है।
- द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 (THM) के तहत बहुविवाह एक अवैध प्रथा है। टीएचएम अधिनियम 1955 में बौद्ध, जैन और सिख भी शामिल हैं।
- हिंदू विवाह अधिनियम की धारा-5 यह निर्धारित करती है कि विवाह दो हिंदुओं के बीच संपन्न हो सकता है, यदि (अन्य शर्त) विवाह के समय किसी भी पक्ष का पति या पत्नी जीवित नहीं है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा-17 में द्विविवाह/बहुविवाह को एक अपराध के रूप में वर्णित किया गया है।
- पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 के तहत भी बहुविवाह को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है। हालाँकि, द्विविवाह अपराध होने के बावजूद, द्विविवाह से पैदा होने वाली संतान को कानून के तहत पहली शादी से पैदा हुए बच्चे के समान अधिकार प्राप्त होंगे।
- मुस्लिम पर्सनल लॉ अर्थात शरीयत अधिनियम, 1937 के तहत मुस्लिम व्यक्ति को चार पत्नियां रखने की अनुमति है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले, सरला मुद्गल बनाम भारत संघ में कहा कि द्विविवाह के एकमात्र उद्देश्य के लिए इस्लाम में धर्म परिवर्तन करना असंवैधानिक है।

बहुविवाह के लिए सजा:

- भारतीय दंड संहिता की धारा-494 (पति या पत्नी के जीवनकाल के दौरान फिर से शादी करना) द्विविवाह और बहुविवाह को दंडित करती है। आमतौर पर भारत के संबंध में जब पहली पत्नी शिकायत दर्ज करती है कि उसके पति ने पुनर्विवाह किया है, तो अदालत यह देखती है कि दूसरा विवाह कानूनी रूप से मान्य है या नहीं।

- ➢ व्यभिचारी संबंध कानून के तहत एक वैध विवाह के रूप में योग्य नहीं है।
- ➢ आईपीसी की धारा-494 भी लागू नहीं होती है, अगर पहला पति या पत्नी 7 साल की अवधि के लिए लगातार अनुपस्थित रहे हैं।
- ➢ यह कानून दोषी के लिए अधिकतम 7 साल तक की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान करता है, जबकि आईपीसी की धारा-495 द्विविवाह के मामले में दूसरी पत्नी के अधिकारों की रक्षा करती है।

आगे की राह:

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति का कहना है कि बहुविवाह महिलाओं की गरिमा का उल्लंघन करता है, इसलिए इसका उन्मूलन होना चाहिए। पत्नियों के साथ असमान व्यवहार कई मानसिक मुद्दों और परिवार के कामकाज में समस्या पैदा करता है।

7. अनुच्छेद-239 (AA) के प्रावधान को लेकर विवाद

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अनुच्छेद-239 (AA) के संबंध में दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के मध्य कार्य क्षेत्र की सीमा को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ।

अनुच्छेद-239 AA (4) के बारे में:

- ➢ ध्यातव्य है कि अनुच्छेद-239 (AA) को बालकृष्ण समिति की सिफारिश पर 69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1991 द्वारा जोड़ा गया था।
- ➢ अनुच्छेद-239 (AA) प्रावधान करता है कि उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की मंत्री परिषद के सलाह पर काम करेंगे, किन्तु वह किसी मामले को राष्ट्रपति के विचारार्थ रख सकते हैं, बशर्ते यह मामला दुर्लभतम श्रेणी का होना चाहिए।
- ➢ अनुच्छेद-239 (AA) उपराज्यपाल की दुर्लभतम मामलों में प्राप्त एक विशेष शक्ति है जो दिल्ली के उपराज्यपाल को अन्य राज्यों के राज्यपालों से अलग और अधिक शक्ति प्रदान करती है। इसके हालिया प्रयोग से उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के मध्य टकराव/तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा।

मुख्य मुद्दे:

- ➢ फरवरी 2023 में राज्य (दिल्ली) में एक साम्प्रदायिक हिंसा से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा लोक अभियोजक की नियुक्ति की मांग को दिल्ली सरकार द्वारा खारिज कर दिया गया। दिल्ली सरकार का कहना है कि उक्त साम्प्रदायिक हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस की जांच को न्यायालय द्वारा निष्पक्ष नहीं पाया गया है। अतः पुलिस पैनल की मंजूरी एक निष्पक्ष जांच में बाधा बन सकती है।
- ➢ दिल्ली सरकार ने गृह विभाग को इस संबंध में उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में मामले की सुनवाई के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ वकीलों का पैनल बनाने निर्देश दिया तथा एक प्रस्ताव तैयार करके उपराज्यपाल के पास भेजा।
- ➢ उपराज्यपाल ने उक्त विषय में दिल्ली सरकार के प्रस्ताव पर असहमति जताते हुए संविधान के अनुच्छेद-239 AA(4) के तहत प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए इस मामले को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लिया तथा स्वयं ही लोक अभियोजकों की नियुक्ति कर दी जिससे दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई।
- ➢ ध्यातव्य है कि दिल्ली तथा पुदुचेरी ऐसे केन्द्रशासित प्रदेश हैं जहाँ विधानसभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था है तथा उपराज्यपाल को परामर्शदात्री शक्तियां प्राप्त हैं। भूमि, सार्वजनिक व्यवस्था तथा पुलिस को छोड़कर दिल्ली सरकार राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है।

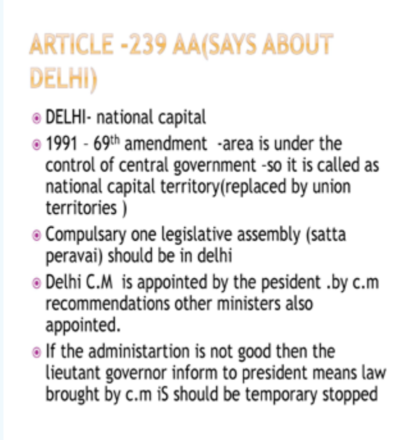

विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला:

- ➢ सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार लोक अभियोजकों की नियुक्ति 'सामान्य' मामले की श्रेणी में आता है, अतः इस संबंध में दिल्ली सरकार को निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। यह दुर्लभ मामला नहीं है जिसमें उपराज्यपाल हस्तक्षेप करें।
- ➢ वर्ष 2018 सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा था कि भूमि, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था को छोड़कर उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली सरकार के अन्य मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, साथ ही दिल्ली मंत्रिपरिषद की 'सहायता और सलाह' उपराज्यपाल पर बाध्यकारी है।
- ➢ संविधान पीठ द्वारा यह भी कहा गया है कि उपराज्यपाल की कोई भी स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति नहीं हैं। उन्हें या तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होगा या फिर उनके द्वारा राष्ट्रपति को भेजे गये मामले में राष्ट्रपति द्वारा लिये गए निर्णय को लागू करना होगा।
- ➢ निर्वाचित सरकार के पास मनोनीत उपराज्यपाल से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं।

आगे की राह:

निर्वाचित सरकार के निर्णयों में मनोनीत उपराज्यपाल का अत्यधिक हस्तक्षेप लोकतंत्र एवं विकेंद्रीकरण की भावना के विरुद्ध है। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल दोनों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। सहकारी संघवाद की स्थापना करने हेतु केंद्र (उपराज्यपाल) तथा राज्य (दिल्ली सरकार) को आपसी सहयोग की भावना विकसित करनी चाहिए।

1. अरब लीग का दूसरी बार सदस्य बना सीरिया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मिस्र की राजधानी काहिरा में आयोजित अरब लीग के 22 में से 13 सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने सीरिया की सदस्यता को बहाल करने हेतु मतदान किया। लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों पर राष्ट्रपति बशर अल-असद की क्रूर कार्यवाही के बाद 2011 में सीरिया को अरब लीग से बाहर कर दिया गया था, जिसके कारण देश में गृहयुद्ध चल रहा था। इस संघर्ष में लगभग आधे मिलियन लोग मारे गए हैं और लगभग 23 मिलियन विस्थापित हुए हैं।

अरब लीग क्या है?

- अरब लीग की स्थापना वर्ष 1945 में छह देशों (मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब और सीरिया) के द्वारा हुई थी। अरब लीग का मुख्यालय मिस्र की राजधानी काहिरा में स्थित है। वर्तमान में, इसके 22 सदस्य देश हैं, जो एक दूसरे का आर्थिक और सैन्य मामलों के अलावा अन्य विभिन्न मुद्दों पर सहयोग करते हैं। इसमें बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है, लेकिन सदस्यों को प्रस्तावों का पालन कराने के लिए कोई बाध्य तंत्र नहीं है। कई अवसरों पर आंतरिक संघर्षों और महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सामूहिक निष्क्रियता के लिए इसकी आलोचना होती रही है।

अरब लीग ने सीरिया की सदस्यता को बहाल क्यों किया?

- अरब लीग का यह निर्णय बशर अल असद द्वारा किये गये कूटनीतिक प्रयासों की परिणति है, जिसे फरवरी महीने में तुर्की और सीरिया में बड़े पैमाने पर आए भूकंप के बाद व्यापक सहानुभूति मिली जिसमें हजारों लोगों की जान गयी थी। राष्ट्रपति असद ने प्रतिद्वंद्वी अरब देशों से मानवीय सहायता की मांग करने और पश्चिमी देशों द्वारा सीरिया पर लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त करने या आसान बनाने के लिए उनका समर्थन हासिल करने का प्रयास किया।
- अरब लीग के सदस्य देशों ने महसूस किया है कि पश्चिम एशिया की स्थिरता के लिए सीरिया के अलगाव को समाप्त करने की आवश्यकता है। इसके अलावा ये देश सीरिया में शरणार्थियों के किसी प्रकार का प्रत्यावर्तन (Repatriation) चाहते हैं और सीरिया के विशाल बहु अरब डॉलर उत्पादित अत्यधिक नशीली दवाओं के व्यापार पर अंकुश हो ताकि सऊदी अरब और जॉर्डन जैसे देश अपने लोगों को इन दवाओं की लत से बचा सकें।
- हालांकि कुवैत और जॉर्डन जैसे कई देशों ने अरब लीग के इस निर्णय से असहमति जताई है। उनका कहना है कि सीरिया को अपने नागरिकों पर अंधाधुंध बमबारी और जहरीली गैस के हमलों जैसे अत्याचारों को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार ठहराए बिना संगठन में वापस लाने से गलत संदेश जाता है।

आगे की राह:

सीरिया के पुनर्वास में एक अन्य उत्प्रेरक चीन की मध्यस्थता से सऊदी अरब और उसके कट्टर दुश्मन ईरान के बीच राजनयिक संबंधों की फिर से स्थापना है, जो इस साल मार्च में हुई थी। अरब लीग में सीरिया की सदस्यता की बहाली असद के लिए एक बड़ी प्रतीकात्मक जीत है, परन्तु अब भविष्य में गृहयुद्ध को समाप्त करने और नशीली दवाओं के व्यापार को कम करने हेतु राष्ट्रपति असद को मजबूत कदम उठाना होगा, तभी दीर्घावधि के लिए शांति व स्थिरता की स्थापना की जा सकेगी।

2. आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट (GRID) 2023

चर्चा में क्यों?

आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र (IDMC) की आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट (GRID) 11 मई, 2023 को प्रकाशित हुई। इस वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले वर्ष 2022 में आपदाओं के कारण 32.6 मिलियन लोग विस्थापित हुए जो 2021 की तुलना में 40% अधिक थे। GRID-2023 के अनुसार, 2016 के बाद पहली बार 10 में से 6 आपदा विस्थापन बाढ़, तूफानों को दबाने के कारण हुए। इन मौसमी आपदाओं में 'ट्रिपल-डिप' ला नीना का प्रभाव शामिल था।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:

- वर्ष 2022 में दुनिया में सबसे अधिक 8.16 मिलियन लोगों का विस्थापन पाकिस्तान में हुआ, जिसके बाद फिलिपींस (5.44 मिलियन), चीन (3.63 मिलियन), भारत (2.5 मिलियन) के साथ क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहे।
- वर्ष 2022 के अंत तक दुनिया भर में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की संख्या 71.1 मिलियन तक पहुंच गई, जो वर्ष 2021 की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है।
- इसी दौरान संघर्ष और हिंसा से दुनिया भर में 28.3 मिलियन आंतरिक विस्थापन हुआ, वहीं अकेले यूक्रेन में संघर्ष के कारण लगभग 17 मिलियन लोग विस्थापित होने के लिए मजबूर हुए।
- वर्ष 2022 में उप-सहारा अफ्रीका में 16.5 मिलियन आंतरिक विस्थापन दर्ज हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है। उप-सहारा अफ्रीका में सबसे अधिक विस्थापन

नाइजीरिया (2.4 मिलियन) में हुआ जो जून और नवंबर के बीच गंभीर बाढ़ का परिणाम थी।

- पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में ला नीना का प्रभाव कम रहा। इस क्षेत्र में आपदाओं के कारण औसत विस्थापन 2021 में 13.7 मिलियन की तुलना में वर्ष 2022 में लगभग 10.1 मिलियन रहा।

'ट्रिपल-डिप' ला नीना:

- 'ट्रिपल-डिप' ला नीना भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर की सतह के तापमान का एक बहुवर्षीय शीतलन है, जो सूखे, भयंकर पवनों एवं भारी वर्षा का कारण बनता है। डब्लूएमओ के अनुसार, ला नीना का प्रभाव लगातार तीन उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु की अवधि में विस्तृत रहा जिसकी शुरुआत सितंबर 2020 में हुई थी जो फरवरी 2023 में समाप्त हुआ। यह 21वीं सदी का पहला ट्रिपल-डिप ला नीना घटना रही। भारतीय संदर्भ में, ला नीना मानसून के मौसम के दौरान अच्छी वर्षा से जुड़ा है, जो अल नीनो के विपरीत है।

आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट (GRID) के बारे में:

- आईडीएमसी द्वारा प्रकाशित यह रिपोर्ट आंतरिक विस्थापन पर डेटा विश्लेषण का प्रमुख स्रोत है। वर्ष 2018 में आईडीएमसी ने आपदा प्रवाह (सूखे को छोड़कर) की निगरानी शुरू की जिसकी पहली रिपोर्ट 2019 में प्रकाशित हुई। आईडीएमसी की स्थापना नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल द्वारा 1998 में की गयी थी जिसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है जो एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है।

आगे की राह:

असामयिक मौसमी घटनाओं, हिंसा, युद्ध और भेदभाव का सबसे अधिक प्रभाव वल्नरेबल सेक्शन पर होता है। वैश्विक समुदाय को इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि बिना सभी के सहयोग के एक स्थिर, शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज की स्थापना नहीं हो सकती है।

3. पर्सोना नॉन ग्रेटा (Persona non grata)

चर्चा में क्यों?

कनाडा ने 8 मई को चीनी राजनयिक झाओ वेई को कनाडा के विपक्षी सांसद माइकल चोंग के खिलाफ डराने-धमकाने के आरोप पर निष्कासित करने की घोषणा की। उसके एक दिन बाद चीन ने कनाडा के महा वाणिज्य राजदूत जेनिफर लिन लालोंडे को अवांछित व्यक्ति (Persona non grata) घोषित करने का फैसला किया। अपने बयान में कनाडा के विदेशमंत्री मेलानी जोली ने कहा कि कनाडा आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार के विदेशी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा।

पर्सोना नॉन ग्रेटा (Persona non grata) क्या है?

- पर्सोना नॉन ग्रेटा एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ 'अवांछित व्यक्ति' होता है। कूटनीति में यह एक राजनयिक या विदेशी व्यक्ति से संदर्भित होता है जिसका किसी देश में प्रवेश करना या रहना उस देश द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- सन 1961 के वियना कन्वेंशन फॉर डिप्लोमैटिक रिलेशंस में इस पदनाम को राजनयिक अर्थ मिला। इस संधि के अनुच्छेद-9 में उल्लेख किया गया है कि कोई देश किसी भी समय अपने निर्णय की व्याख्या किए बिना राजनयिक स्टाफ के किसी भी सदस्य को अवांछित व्यक्ति घोषित कर सकता है।
- ऐसी घोषणा के तुरंत बाद, संबंधित व्यक्ति आमतौर पर अपने गृह देश लौट जाता है। यदि वे उचित अवधि के भीतर ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो वह देश संबंधित व्यक्ति को मिशन के सदस्य के रूप में मान्यता देने से इंकार कर सकता है। इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि किसी व्यक्ति को किसी देश में आने से पहले ही अवांछित व्यक्ति घोषित किया जा सकता है।
- ऐतिहासिक रूप से कई देशों ने इसका उपयोग अन्य राष्ट्रों के कार्यों के प्रति अपने असंतोष को व्यक्त करने हेतु किया है। शीत युद्ध के समय यह 'जैसे को तैसा' प्रतिबंध बन गया था, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने कई बार एक-दूसरे के राजनयिकों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया था।

भारत और वियना कन्वेंशन:

- वर्ष 1961 में बना वियना कन्वेंशन 24 अप्रैल, 1964 को अस्तित्व में आया। भारत ने 1965 में राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन को स्वीकार किया तथा इसे प्रभावी बनाने के लिए डिप्लोमैटिक रिलेशंस (वियना कन्वेंशन) अधिनियम, 1972 को अधिनियमित किया।
- कुलभूषण जाधव मामले में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने कहा था कि पाकिस्तान ने जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस न देकर कॉन्सुलर संबंधों पर वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया। ICJ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान द्वारा जाधव की गिरफ्तारी के तीन सप्ताह बाद भारतीय वाणिज्य दूतावास को सूचित करना, कन्वेंशन के प्रावधानों का उल्लंघन था।

आगे की राह:

सभी देशों को व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का दुरूपयोग नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश कोई मतभेद है, तो उसे राजनयिक स्तर पर बातचीत के माध्यम से समाप्त करना चाहिए, तभी सच्चे अर्थों में विधि का शासन, स्वतंत्रता और समानता स्थापित किया जा सकेगा।

4. भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (TCC)

चर्चा में क्यों?

भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (TCC) की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक 16 मई को ब्रसेल्स (बेल्जियम) में सम्पन्न हुई। इसमें रणनीतिक प्रौद्योगिकियों, डिजिटल कनेक्टिविटी, स्वच्छ ऊर्जा, व्यापार और निवेश में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गई। भारत की ओर से वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा यूरोपीय संघ की ओर से डोंब्रोव्स्की और वेस्टेगर द्वारा इस परिषद की सह-अध्यक्षता की गई।

भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (TCC) के बारे में?

- इस परिषद के गठन की घोषणा अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के बीच नई दिल्ली में हुई थी। इसका उद्देश्य भारत और यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक व तकनीकी संबंधों को मजबूत करना है। यह व्यापार और प्रौद्योगिकी सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर उच्च स्तरीय चर्चा व सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है।

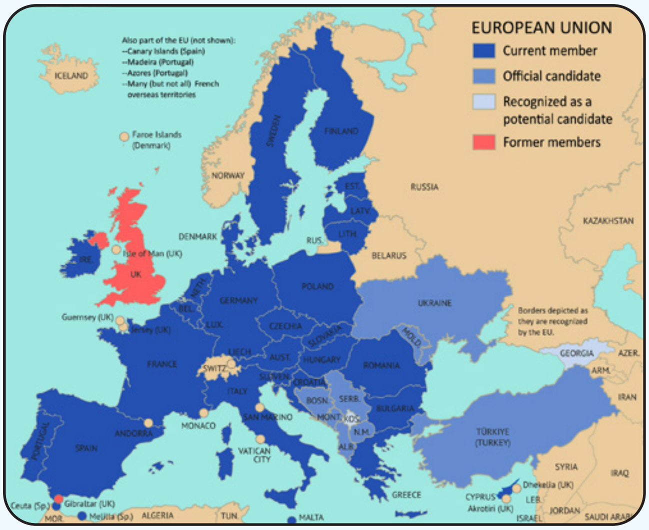

सामरिक प्रौद्योगिकियों, डिजिटल कनेक्टिविटी और हरित ऊर्जा पर जोर:

- आगामी मंत्रिस्तरीय बैठक में रणनीतिक प्रौद्योगिकियों, डिजिटल कनेक्टिविटी और हरित ऊर्जा पर जोर दिए जाने की उम्मीद है। ये क्षेत्र भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार व प्रौद्योगिकी सहयोग के भविष्य को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें नवाचार को बढ़ावा देने, कनेक्टिविटी बढ़ाने और स्थायी ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। इस बैठक में भारत ने निम्न मुद्दों पर जोर दिया:
  - मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिए चल रही बातचीत तेज करना।
  - आपसी बाजार पहुंच के मुद्दों को संबोधित करना।
  - विश्व व्यापार संगठन में सुधारों के साथ-साथ आपसी हितों के कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना।

भारत-यूरोपीय संघ टीटीसी बैठक फोकस क्षेत्र:

- पहली मंत्रिस्तरीय बैठक तीनों कार्य समूहों के तहत सहयोग के लिए रोडमैप तैयार करेगी और आने वाले वर्ष में अगली मंत्रिस्तरीय बैठक से पहले वांछित परिणाम प्राप्त करने की दिशा प्रदान करेगी। भारत-यूरोपीय संघ टीटीसी बैठक की चर्चाओं के तहत तीन कार्यकारी समूह होंगे:
  - सामरिक प्रौद्योगिकियों, डिजिटल शासन और डिजिटल कनेक्टिविटी पर कार्य समूह।
  - ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर वर्किंग ग्रुप।
  - व्यापार, निवेश और लचीली मूल्य शृंखलाओं पर कार्य समूह।

आगे की राह:

रूस-यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न चुनौतियां, चीन की बढ़ती साम्राज्यवादी नीतियां, जलवायु परिवर्तन और बढ़ता कट्टरवाद मानव सभ्यता के समक्ष खतरा है। क्योंकि ये देश स्वतंत्रता, समानता, बन्धुत्व, मानवाधिकार और विधि के शासन को बहुत महत्त्वपूर्ण मानते हैं, ऐसे में भारत-ईयू के बेहतर संबंध विश्व शांति और सुरक्षा के लिए आवश्यक हो जाता है।

5. छठा हिन्द महासागर सम्मेलन 2023

चर्चा में क्यों?

बांग्लादेश के ढाका में 12 से 13 मई 2023 को आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का केन्द्रीय विषय 'हिन्द महासागर क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार एवं विस्तार' था। सम्मेलन का उद्घाटन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा किया गया। इस सम्मेलन में 25 से अधिक देशों के 150 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिसमें सार्क, बिम्सटेक और D-8 जैसे क्षेत्रीय समूहों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। इन देशों ने हिन्द महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के मुद्दे पर बातचीत की।

आयोजक:

- इस सम्मेलन का आयोजन इंडिया फाउंडेशन, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय तथा एस. राजरत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के सहयोग से किया गया।
- इस सम्मेलन की थीम 'शांति, समृद्धि और लचीले भविष्य के लिए साझेदारी' थी।

हिंद महासागर सम्मेलन के बारे में:

- हिंद महासागर सम्मेलन (IOC) को दिल्ली स्थित थिंक टैंक इंडिया फाउंडेशन, सिंगापुर, श्रीलंका और बांग्लादेश की संयुक्त भागीदारी में वर्ष 2016 में शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य तटवर्ती देशों के मंत्रियों, विद्वानों, विचारकों, राजनयिकों, नौकरशाहों एवं चिकित्सकों को साझा मंच प्रदान करना।
- हिंद महासागर सम्मेलन (IOC) का पहला संस्करण वर्ष 2016 में सिंगापुर में और पाँचवाँ सम्मेलन 2021 में अबू धाबी (संयुक्त अरब अमीरात) में आयोजित किया गया था।

'सागर' (SAGAR) पहल:

- 'सागर' (Security and Growth for All in the Region-क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा और विकास) पहल को वर्ष 2015 में शुरू किया गया था जो भारत की रणनीतिक पहल है।

सम्मेलन के प्रमुख बिंदु:

क्षेत्रीय कनेक्टिविटी:

- हिन्द महासागर क्षेत्र में भारत एक प्रमुख अभिकर्ता है तथा इस क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी हेतु उसे विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में भारत ने कनेक्टिविटी सुधार हेतु सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया है जिसके दीर्घकालिक आर्थिक, राजनीतिक,

एवं रणनीतिक परिणाम महत्त्वपूर्ण होंगे।

- भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों (ASEAN) के साथ कनेक्टिविटी सुधार के महत्त्वपूर्ण क्रांतिकारी प्रभावों/परिणामों पर जोर दिया। भारत ने खाड़ी और मध्य एशिया में भी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी विकसित करने की इच्छा व्यक्त की है।

कानूनी दायित्वों एवं समझौतों के पालन पर जोर:

- चीन द्वारा प्राय: अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों, संधियों एवं समझौतों का उल्लंघन किया जाता रहा है। इस संबंध में भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि स्थिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना हेतु अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों, नियमों, मानदण्डों और समझौतों का पालन आवश्यक है।

साझे एवं लक्षित प्रयासों पर जोर:

- हिन्द महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता तथा समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए साझा एवं लक्षित (Targated) प्रयास आवश्यक है।
- साथ ही इस सम्मेलन में जलवायु कार्यवाही, पर्यावरण, सुरक्षा, व्यापार, आतंकवाद विरोधी पहल, उग्रवाद और कट्टरवाद तथा इससे उत्पन्न समस्याओं के समाधान जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर भी जोर दिया गया।

पारदर्शी ऋण व्यवस्था एवं धारणीय परियोजनाएं:

- भारत द्वारा पारदर्शी ऋण प्रथाओं एवं वास्तविक/व्यावहारिक परियोजनाओं पर जोर दिया गया। बहुत से छोटे-छोटे देश जैसे-नेपाल श्रीलंका आदि चीन के ऋण ट्रैप में फंस चुके हैं जिससे उन्हें चीन की परियोजनाओं को मंजूरी देना पड़ता है।

आगे की राह:

हिंद महासागरीय क्षेत्र विश्व की कुल महासागरीय क्षेत्र का लगभग 20% हिस्सा कवर करता है और इस क्षेत्र में वैश्विक आबादी के लगभग एक तिहाई (2.7 बिलियन) लोग रहते हैं। हिंद महासागर सम्मेलन के साझा प्रयासों से वैश्विक शक्ति संतुलन में सहायता मिलेगी। साथ ही इस क्षेत्र में चीन के अवांछित हस्तक्षेप को रोका जा सकेगा। भारत अपने समुद्री पड़ोसियों को चीन के ऋण ट्रैप से बचा सकेगा जिससे भारत को सामरिक लाभ होगा। इससे ब्लू इकोनामी के विकास में सहायता मिलेगी, क्योंकि विश्व के 15% मत्स्यन क्षेत्र हिंद महासागर क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। भारत आसियान तथा अन्य हिंद महासागरीय देशों के बीच समुद्री कनेक्टिविटी शुरू होने से व्यापार एवं आर्थिक विकास को गति मिलेगी, साथ ही क्षेत्रीय एवं वैश्विक समस्याओं जैसे-पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, समुद्री डकैती आदि समस्याओं के समाधान में मदद मिल सकती है।

6. दक्षिण एशिया गैस इंटरप्राइज (SAGE)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 2,000 किलोमीटर लंबी $5 बिलियन की ऊर्जा परियोजना को शुरू करने पर चर्चा हुई जो मध्य पूर्व को भारत से जोड़ेगी। इसके शुरू होने से द्रवित प्राकृतिक गैस (LNG) के समान आयात की तुलना में लगभग 7,000 करोड़ रूपये की वार्षिक बचत हो सकती है।

SAGE के बारे में:

- दक्षिण एशिया गैस इंटरप्राइज (SAGE), गहरे पानी की पाइपलाइन परियोजनाओं में विशेषज्ञता रखने वाली कंपनियों का एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है जिसने खाड़ी क्षेत्र से भारत तक एक अंडरसी/समुद्री गैस पाइपलाइन विकसित करने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय और अन्य संस्थाओं का समर्थन मांगा है।
- एसएजीई के निदेशक सुबोध कुमार जैन के अनुसार, परियोजना की तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यताओं को पूरा कर लिया गया है, तथा विभिन्न हितधारकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया भी प्राप्त हुई है। अब इसे आगे बढ़ाने के लिए कूटनीतिक और राजनीतिक समर्थन चाहिए होगा क्योंकि इसके लिए दीर्घकालिक सरकारी स्तर पर समझौते की आवश्यकता है।

मध्य पूर्व-भारत डीप वॉटर पाइपलाइन (MEIDP) के बारे में:

- लगभग एक दशक पहले ईरान और भारत (पोरबंदर) के बीच 'मध्य पूर्व-भारत डीपवाटर पाइपलाइन' (MEIDP) की अंडरसी अंतर्राष्ट्रीय/ट्रांसनैशनल गैस पाइपलाइन परियोजना की कल्पना की गई थी, लेकिन पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण इसे शुरू नहीं किया जा सका।

मुख्य मुद्दे:

- 2,000 किलोमीटर लंबा ऊर्जा गलियारा जिसका उद्देश्य भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राकृतिक गैस के परिवहन हेतु गैस समृद्ध खाड़ी और मध्य पूर्व क्षेत्रों को भारत से जोड़ना है।
- हाल ही में ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में नई बड़ी गैस खोजें हुई हैं तथा मध्य पूर्व ने 2030 तक 14 बिलियन क्यूबिक फीट प्रति दिन (BCFD) गैस उत्पादन बढ़ाने के लिए 120 अरब डॉलर से अधिक खर्च करने की योजना बनाई है। ऐसे में पाइपलाइन परियोजना के लिए दीर्घकालिक सरकारी स्तर पर समझौते स्थापित करने का यह एक उपयुक्त क्षण है।
- भू-राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों से बचते हुए अरब सागर के रास्ते ओमान और संयुक्त अरब अमीरात पहुंचा जा सकेगा।
- यह परियोजना ओमान, यूएई, सऊदी अरब, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कतर सहित कई देशों से गैस आयात करने का विकल्प प्रदान करेगी, जिनके पास सामूहिक रूप से 2,500 ट्रिलियन क्यूबिक फीट (TCF) का महत्त्वपूर्ण गैस भंडार है।

- एसएजीई (SAGE) के मुताबिक, बिजली और उर्वरक उद्योगों में सस्ती गैस की मांग बढ़ रही है, जबकि कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था बनने में गैस की हिस्सेदारी को 6% से 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। इसके परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धी कीमतों पर 700 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर प्रति दिन (MMSCMD) की वार्षिक गैस मांग होगी।
- तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) की तुलना में, गैस पाइपलाइन 2,500-3,000 किमी तक की दूरी के लिए अधिक लागत प्रभावी हैं क्योंकि गैस द्रवीकरण, परिवहन और पुनर्गैसीकरण से जुड़े उच्च व्यय हैं। इसके अतिरिक्त, LNG की कीमतें अस्थिर होती हैं।
- प्रस्तावित 20-वर्षीय दीर्घकालिक आपूर्ति अनुबंध के तहत, परियोजना का लक्ष्य भारत को 31 मिलियन मीट्रिक मानक क्यूबिक मीटर प्रति दिन (MMSCMD) गैस वितरित करना है। अन्य खरीददार देश भी एसएजीई (SAGE)को $2 से $2.25 प्रति मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (MMBTU) पाइपलाइन शुल्क का भुगतान करके मध्य पूर्व से गैस खरीदने में सक्षम होंगे।

आगे की राह:

इससे भारत की गैस आयात की लागत में कमी आएगी। ऊर्जा जरूरतों को आसानी से पूरा करने में मदद मिलेगी। भारत को सामरिक लाभ होगा और भारत के मध्य पूर्व/पश्चिम एशिया एवं खाड़ी देशों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। भारत सस्ती दर पर स्वच्छ ऊर्जा तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम हो सकेगा।

7. भारत-प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, तीसरा भारत-प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच (FIPIC) शिखर सम्मेलन पोर्ट मोरेस्बी (पापुआ न्यू गिनी) में आयोजित किया गया। इसकी सह-अध्यक्षता भारतीय और पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने की थी जिसमें 14 प्रशांत द्वीप देशों (PIC) ने भाग लिया था।

तीसरे FIPIC शिखर सम्मेलन के प्रमुख बिंदु:

- भारत सभी देशों की संप्रभुता और अखंडता का समर्थन करता है तथा वैश्विक दक्षिण की आवाज को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की साझा प्राथमिकता पर जोर देता है।
- भारत ने पीआईसी में स्वास्थ्य सेवा, साइबर स्पेस, स्वच्छ ऊर्जा, जल, छोटे और मध्यम उद्यमों के क्षेत्रों में 12 सूत्री विकास कार्यक्रम का भी अनावरण किया जिसके अनुसार:
    1. भारत फिजी में एक सुपर-स्पेशियलिटी कार्डियोलॉजी अस्पताल स्थापित करेगा, सभी 14 पीआईसी में डायलिसिस यूनिट और समुद्री एम्बुलेंस शुरू करेगा तथा सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए जन औषधि केंद्र स्थापित करेगा।
    2. भारत प्रत्येक प्रशांत द्वीपीय राष्ट्र में छोटे और मध्यम स्तर के उद्यम क्षेत्र के विकास का समर्थन करेगा।
    3. भारत ने पानी की कमी के मुद्दों को दूर करने के लिए अलवणीकरण इकाइयां प्रदान करने का भी वचन दिया।
- भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने पापुआ न्यू गिनी के समकक्ष के साथ टोक पिसिन (पापुआ न्यू गिनी की आधिकारिक भाषा) में तमिल क्लासिक 'थिरुक्कुरल' का विमोचन किया, ताकि भारतीय विचार और संस्कृति को इस दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत द्वीप के लोगों के करीब लाया जा सके।

एफआईपीआईसी के बारे में:

- नवंबर 2014 में पीएम मोदी की फिजी यात्रा के दौरान फोरम फॉर इंडिया-पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन (FIPIC) की शुरुआत की गई थी।
- FIPIC में 14 द्वीप देश कुक आइलैंड्स, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, नौरू, नीयू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, तुवालु और वानुअतु शामिल हैं जो कि प्रशांत महासागर में स्थित हैं।

उद्देश्य:

- यह मंच व्यापार, निवेश, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पीआईसी के साथ भारत के संबंधों को बढ़ावा देता है।
- FIPIC पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर संवाद तथा परामर्श के लिए एक मंच भी प्रदान करता है।
- इस पहल को और मजबूत करने के लिए FICCI ने 2015 में FIPIC के लिए व्यवसाय त्वरक लॉन्च किया।

व्यवसाय त्वरक (Business Accelerator) के मुख्य उद्देश्य:

- व्यापार और निवेश की संभावनाओं के संबंध में दोनों पक्षों के व्यवसायियों को आवश्यक जानकारी और सुविधा प्रदान करना।
- दोनों पक्षों के संबंधित व्यवसायियों के बीच बैठकों की सुविधा प्रदान करना।
- भारत और प्रशांत द्वीपीय देशों के बीच व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान करना।
- ऑनलाइन और ऑफलाइन मैच मेकिंग सेवाएं।
- कार्यक्रमों/व्यापार मेलों का आयोजन करना।

आगे की राह:

भारत-प्रशांत द्वीपीय देश ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध साझा करते हैं। ये देश विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय प्लेटफार्मों जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन, संयुक्त राष्ट्र और एफआईपीआईसी के माध्यम से पीआईसी के साथ जुड़ते रहे हैं। PICs के साथ भारत का जुड़ाव एक मुक्त, खुले और समावेशी भारत-प्रशांत क्षेत्र के साथ-साथ PICs की विकास आकांक्षाओं व जलवायु लचीलेपन का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता से प्रेरित है। फोरम फॉर इंडिया-पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन भारत और प्रशांत देशों के बीच संबंधों को अधिक मजबूत कर रहा है।

पर्यावरणीय मुद्दे

1. 2040 तक प्लास्टिक प्रदूषण को 80% कम किया जा सकता है: UN रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने कहा है कि 2040 तक प्लास्टिक प्रदूषण को 80% कम किया जा सकता है। इसके लिए बड़े बदलावों की आवश्यकता होगी। यदि अभी भी सक्रियता से कार्य किया जाये तो, ये प्रयास सुविधाजनक और किफायती होंगे।

रिपोर्ट की महत्त्वपूर्ण विशेषताएं:

- रिपोर्ट में उन परिवर्तनों की रूपरेखा दी गई है जो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने और एक चक्रीय अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आवश्यक हैं।
- यूएनईपी रिपोर्ट ठोस प्रथाओं, बाजार में बदलाव और नीतियों के समाधान-केंद्रित विश्लेषण के रूप में वर्णित करता है जो सरकार की सोच और व्यावसायिक कार्यवाही को सूचित कर सकते हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार रिफिल करने योग्य बोतलों, बल्क डिस्पेंसर, डिपॉजिट रिटर्न स्कीम और पैकेजिंग टेक-बैक स्कीम सहित पुनः उपयोग विकल्पों को बढ़ावा देने से 2040 तक प्लास्टिक प्रदूषण में 30% की कमी आ सकती है।
- रिपोर्ट के अनुसार, 2040 तक प्लास्टिक प्रदूषण को 20% तक कम करना संभव है, यदि पुनर्चक्रण अधिक भरोसेमंद और लागत प्रभावी हो जाए।
- यह भी दावा किया गया है कि जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को खत्म करने, पुनर्चक्रण में सुधार के लिए डिजाइन मानदंडों का पालन करने और अन्य कदमों से व्यावसायिक रूप से पुनः उपयोग योग्य प्लास्टिक का अनुपात 21% से 50% तक बढ़ जाएगा।
- प्लास्टिक अब माउंट एवरेस्ट की चोटी से लेकर गहरे पानी तक पूरी दुनिया को दूषित कर रहा है। माइक्रोप्लास्टिक्स भोजन और पेय के साथ-साथ साँस के माध्यम से ग्रहण किए जा रहे हैं जो लोगों के रक्त और स्तन के दूध में पाए गए हैं।
- मार्च 2022 में, 193 देशों ने प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की थी जो 2024 तक कानूनी रूप से बाध्यकारी है जिसकी मेजबानी यूएनईपी द्वारा की जा रही है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के बारे में:

- इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में है।
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP), संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में पर्यावरणीय प्रतिक्रियाओं के समन्वय का प्रभारी है।
- जून 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद संगठन के पहले निदेशक मौरिस स्ट्रॉन्ग ने इसकी स्थापना की थी।
- यह संगठन दुनिया भर में पर्यावरण संधियों का भी निर्माण करता है। यह पर्यावरण विज्ञान को प्रकाशित करता है और बढ़ावा देता है जो पर्यावरण लक्ष्यों को पूरा करने में सरकारों की सहायता करता है।

प्लास्टिक प्रदूषण मनुष्य को कैसे प्रभावित करता है?

- प्लास्टिक प्रदूषण, पर्यावरण में सिंथेटिक प्लास्टिक उत्पादों का जमाव इस हद तक करता है कि यह वन्यजीवों और उनके आवासों के साथ-साथ मानव आबादी के लिए भी समस्याएं पैदा करता है।
- प्लास्टिक जीवनचक्र के साथ-साथ साँस लेने, अंतर्ग्रहण और सीधे त्वचा के संपर्क के माध्यम से मनुष्य कई प्रकार के जहरीले रसायनों तथा माइक्रोप्लास्टिक्स के संपर्क में आते हैं।
- प्लास्टिक में पाए जाने वाले जहरीले रासायनिक योजक और प्रदूषक मानव स्वास्थ्य के लिए वैश्विक स्तर पर खतरा पैदा करते हैं। वैज्ञानिक रूप से सिद्ध स्वास्थ्य प्रभावों में कैंसर पैदा करना या हार्मोन गतिविधि में परिवर्तन (अंतःस्रावी व्यवधान के रूप में जाना जाता है) शामिल हैं जो प्रजनन, विकास और संज्ञानात्मक हानि का कारण बन सकता है।

माइक्रोप्लास्टिक्स:

- माइक्रोप्लास्टिक्स, प्लास्टिक के छोटे टुकड़े होते हैं जिनकी लंबाई 5 मिमी (0.2 इंच) से कम होती है, जो प्लास्टिक प्रदूषण के परिणामस्वरूप पर्यावरण में प्रवेश करते हैं। माइक्रोप्लास्टिक कॉस्मेटिक्स से लेकर सिंथेटिक कपड़ों तक तथा प्लास्टिक बैग से लेकर बोतलों तक कई तरह के उत्पादों में मौजूद हैं। इनमें से कई उत्पाद आसानी से कचरे के रूप में पर्यावरण में प्रवेश कर जाते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स को दो प्रकारों में बांटा गया है: प्राथमिक और द्वितीयक माइक्रोप्लास्टिक्स।
- **प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक:** वे छोटे कण होते हैं जिन्हें व्यावसायिक उपयोग के लिये डिजाइन किया जाता है जो माइक्रोफाइबर कपड़ों और अन्य वस्त्रों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण: व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों, प्लास्टिक छर्रों और प्लास्टिक फाइबर में पाए जाने वाले माइक्रोबीड्स आदि।
- **द्वितीयक माइक्रोप्लास्टिक्स:** ये पानी की बोतलों जैसे बड़े प्लास्टिक के टूटने से बनते हैं।

माइक्रोप्लास्टिक का स्रोत:

- पॉलीथीन (पीई) -प्लास्टिक बैग, सिक्स-पैक रिंग।
- पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) -रस्सी, बोतल के ढक्कन, गियर।
- पॉलीस्टीरिन (विस्तारित) - बेट (Bait) बॉक्स, कप
- पॉलीस्टाइनिन (पीएस)- बर्तन
- पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी)- फिल्म, पाइप।
- पॉलियामाइड या नायलॉन- गियर, रस्सी
- पॉलीथीन टेरेफ्थलेट (पीईटी) -बोतलें, स्ट्रैपिंग
- पॉलिएस्टर राल + ग्लास फाइबर- कपड़ा
- सेल्युलोज एसीटेट- सिगरेट फिल्टर

आगे की राह:

यह अनुसंधान जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को समाप्त करने का भी सुझाव देता है जो नई प्लास्टिक वस्तुओं की लागत को कम करने, पुनर्चक्रण को निरुत्साहित करने और वैकल्पिक सामग्रियों के विकास में सहायता करता है। लगभग सभी प्लास्टिक, जीवाश्म ईंधन से प्राप्त मूल सामग्री

से बने होते हैं।

2. एरेटमोप्टेरा मर्फी (Eretmoptera Murphy)

चर्चा में क्यों ?

ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वेक्षण (BAS) द्वारा किये गये एक नये अध्ययन में पाया गया कि अंटार्कटिका का सिग्नी द्वीप (Signy Island), जिसका आधा हिस्सा हमेशा बर्फ से ढका रहता है, वर्षों से एक उड़ान रहित मिज 'एरेटमोप्टेरा मर्फी' से प्रभावित हो रहा है। वर्तमान समय में एरेटमोप्टेरा मर्फी एक बड़ी समस्या बन गई है क्योंकि यह छोटा कीट कई गुना आबादी के साथ बहुत बड़े क्षेत्र में फैल गया है जिससे इस द्वीप की पारिस्थितिक संरचना तेजी से बदल रही है।

अध्ययन के मुख्य बिंदु:

- मृत कार्बनिक पदार्थ इस प्रजाति का मुख्य आहार है जो तेजी से पौधों के अपघटन का कारण बनता है। यह मिट्टी के नाइट्रेट स्तर को द्वीप के उन स्थानों की तुलना में तीन-पांच गुना बढ़ा देता है जहां मिज (midge) अनुपस्थित है और केवल देशी अकशेरूकीय प्रजातियां रहती हैं।
- अध्ययन के अनुसार, इसने द्वीप की मिट्टी में नाइट्रेट के स्तर को इतना बढ़ा दिया है, जो पहले केवल पेंगुइन या सील (Penguins and Seals) जैसी बड़ी प्रजातियों के क्षेत्रों में देखा जाता था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मिज लार्वा की जनसंख्या घनत्व कुछ साइटों पर प्रति वर्ग मीटर 20,000 से अधिक तक पहुंच गयी।
- अध्ययन में मर्फी के प्रसार का कारण द्वीप पर वैज्ञानिकों तथा शोधार्थियों का आगमन माना जा रहा है। संभव है कि ये उनके जूतों से चिपकर यहाँ तक पहुंचे हों। दूसरा कारण है कि यह एक द्वीप से अन्य द्वीपों में फैला हो क्योंकि यह पानी में जीवित रह सकता है।
- जलवायु परिवर्तन के संयोजन में सिग्नी द्वीप पर मिज की गतिविधि, संभावित रूप से अन्य प्रजातियों के स्थापित होने के लिए 'द्वार खोलती है' जो जलवायु परिवर्तन को और तेज कर सकती है।

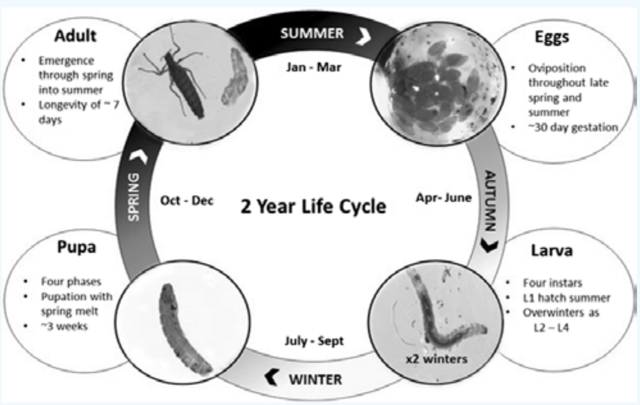

एरेटमोप्टेरा मर्फी (Eretmoptera Murphy) के बारे में:

- इरेटमोप्टेरा मर्फी अंटार्कटिका के सिग्नी द्वीप पर एक आक्रामक प्रजाति है। यह दक्षिण जॉर्जिया, एक उप-अंटार्कटिका द्वीप का मूल निवासी (Native) है जो गलती से 1960 के दशक में वनस्पति विज्ञान के प्रयोग के दौरान सिग्नी द्वीप पर आया जिसका प्रसार 1980 के दशक में स्पष्ट हो गया था।

आगे की राह:

अंटार्कटिक की एक विशेषता रही है कि इसमें अब तक बहुत कम हमलावर प्रजातियां रही हैं, लेकिन मिज के आक्रमण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कठोर रहने की स्थिति जैसे-बहुत कम तापमान, नमी और पोषक तत्वों की उपलब्धता आदि द्वारा प्रदान की जाने वाली पर्यावरण की सुरक्षा अब अभेद्य नहीं है। यह ग्लोबल वार्मिंग संकट को बढ़ा सकता है, इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना एक बहुत ही उच्च प्राथमिकता होना चाहिए।

3. जलवायु परिवर्तन से समुद्री तितलियों को खतरा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में यह देखा गया है कि समुद्र का अम्लीकरण न केवल खोलीदार (Shelled) तथा छोटी समुद्री तितलियों के लिए अधिक खतरनाक है, बल्कि पूरे समुद्री खाद्य जाल को प्रभावित कर सकता है।

मुख्य बातें:

- सुंदर समुद्री तितलियाँ (जो समुद्री घोंघे का एक उपवर्ग हैं) छोटे जानवर हैं जो समुद्री पारिस्थितिकी में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक नए अध्ययन के अनुसार, दक्षिणी महासागर में स्थित यह इस समूह की सबसे छोटी प्रजाति है जो जलवायु परिवर्तन के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं जिनकी संख्या में कमी आ रही है।
- खुले तैरने वाले समुद्री घोंघे, जिन्हें शेल्ड टेरोपोड के नाम से जाना जाता है, समुद्र की सतह पर या उसके बहुत निकट रहते हैं। इनके पास घोंघे के समान मजबूत पैर होते हैं, लेकिन ठोस सतहों पर ग्लाइडिंग करने के बजाय, ये इन पैरों को फड़फड़ाने के रूप में उपयोग करके पानी में तैरती हैं।
- समुद्र जोकि कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) की बढ़ती मात्रा को अवशोषित करता है जो पानी को अधिक अम्लीय बनाता है तथा पतली बाहरी आवरण के कारण इन छोटी समुद्री तितलियों के 'घरों' को नुकसान पहुँचाता है जिससे इन नाजुक प्रजातियों का जीवित रहना मुश्किल हो जाता है।
- सर्दियों में समुद्र सबसे अधिक अम्लीय होता है क्योंकि ठंडा पानी अधिक CO_2 अवशोषित करता है। इसका तात्पर्य है कि खोलीदार समुद्री तितलियों के लिए सर्दियों के महीने सबसे अधिक खतरनाक होते हैं।

समुद्री तितलियों के बारे में:

- समुद्री तितलियां या टेरोपोड के रूप में संदर्भित छोटे समुद्री गैस्ट्रोपोड मोलस्क, थेकोसोमाटा की एक उपप्रजाति है। ये समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में अपने कार्य और विशिष्ट खोल संरचना के लिए प्रसिद्ध हैं।

- समुद्री तितलियों के रूप में जाने जाने वाले प्लैंकटोनिक प्राणियों में अद्वितीय शैल संरचनाएँ होती हैं। इनकी खोल पतले, पारदर्शी और अक्सर एक तितली के पंखों के आकार की होती है। समुद्री तितलियाँ सीपों का स्राव करती हैं, जो इनके नाजुक शरीर को अन्य तत्वों से ढाल प्रदान करती है।
- समुद्री तितलियों के लिए मुख्य भोजन का स्रोत शाकाहारी जीव फाइटोप्लांकटन हैं जो पानी में रहने वाला एक प्रकार का छोटा पौधा है।

जलवायु परिवर्तन समुद्री तितलियों की आबादी को कैसे प्रभावित करता है?

- कार्बोनेट आयनों की उपलब्धता में कमी जो शैल विकास और रखरखाव के लिए आवश्यक हैं।
- जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का तापमान बढ़ रहा है जिससे समुद्री तितलियों की मात्रा और वितरण में परिवर्तन होता है।
- महासागरों में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है जो गर्म और अधिक स्तरीकृत होते हैं। यह समुद्री तितलियों के ऊर्जा संतुलन और श्वसन को प्रभावित करता है।

आगे की राह:

बढ़ते उत्सर्जन के साथ समुद्र के अम्लीकरण में तेजी पूरे बसंत ऋतु तक जारी रहता है, जो समुद्री तितलियों के अंडे देने और लार्वा के समय होता है। अम्लीय परिस्थितियों में लंबे समय तक संपर्क, लार्वा के विकास में नुकसान पहुंचाता है जो स्वस्थ वयस्कों की मात्रा को कम कर सकता है।

4. मिल्कवीड (Milkweed) बटरफ्लाई

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इंसेक्ट कंजर्वेशन जर्नल में प्रकाशित एक शोध ने दक्षिण भारत में मिल्कवीड बटरफ्लाई के प्रवास पैटर्न और दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ इनके संबंध पर प्रकाश डाला है। यह अध्ययन इन प्रजातियों के ग्लोबल वार्मिंग, भूमि उपयोग परिवर्तन और आवास क्षरण के खिलाफ संरक्षण में सहायता करेगा।

मिल्कवीड बटरफ्लाई:

- मिल्कवीड बटरफ्लाई या दानैनी (Danainae) फेली निम्फालिडे की उपप्रजाति हैं जो अपने अंडे विभिन्न मिल्कवीड्स पर देती हैं।

वितरण:

- दुनिया भर में मिल्कवीड बटरफ्लाई की लगभग 300 प्रजातियाँ मौजूद हैं। उनमें से अधिकांश उष्णकटिबंधीय एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में पायी जाती हैं।
- इस समूह के कुछ लोकप्रिय प्रजाति जैसे मोनार्क बटरफ्लाई समशीतोष्ण क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं।

अध्ययन के प्रमुख बिन्दु:

- मिल्कवीड बटरफ्लाई गर्मी से बचने के लिए दक्षिण-पश्चिम मानसून के बाद पूर्वी घाटों और मैदानी इलाकों से पश्चिम की ओर अर्थात पश्चिमी घाटों की ओर बढ़ती हैं।
- अक्टूबर से अप्रैल तक, पश्चिमी घाट में अधिकांश मिल्कवीड बटरफ्लाई सर्दियों और शुष्क मौसम के दौरान कुछ स्थानों पर बड़ी संख्या में इकट्ठा होती हैं। अध्ययन के अनुसार, अधिकांश बटरफ्लाई के पंख उनके पश्चिम की ओर जाने की तुलना में उनके पूर्व की ओर प्रवास पर अधिक झड़ते हैं।
- अध्ययन का एक अन्य निष्कर्ष यह भी है कि पश्चिमी घाट के मध्य और ऊंचाई वाले सदाबहार तथा अर्ध-सदाबहार जंगलों में डार्क ब्लू-टाइगर एण्ड डबल-ब्रांडेड कौवा जैसी प्रमुख प्रजातियों को प्रजनन करते हुए नहीं देखा गया है।

प्रवासन का क्षेत्र:

- प्रवासी प्रजातियों के लिए यरकौड हिल्स (शेवरॉय हिल्स), पंचमलाई, कोल्ली हिल्स और कलवारायण प्रमुख स्थान हैं।
- इनका पलायन पश्चिमी घाट की पहाड़ी शृंखलाओं, नीलगिरी, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु में पलानी पहाड़ियों और केरल में परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में भी देखा गया था।

प्रवासन का महत्त्व:

- मिल्कवीड बटरफ्लाई का प्रवास पारिस्थितिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये परागणकर्ता हैं इसलिए इनकी गतिविधि पूरे पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करती है। ये एक संकेतक प्रजाति भी हैं इसलिए ये पारिस्थितिकी तंत्र की अन्य प्रजातियों की समग्र स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं।
- ये पर्यावरणीय पारिस्थितिकी के साथ-साथ सामुदायिक संरचना के पहलुओं में गुणवत्ता और परिवर्तन को भी दर्शाती हैं।

खतरे:

- वर्षा के पैटर्न में बदलाव, अशांत मौसम के पैटर्न और निवास स्थान का विनाश इन प्रजातियों के अस्तित्व के लिए प्रमुख चुनौतियां हैं।

आगे की राह:

सूक्ष्म जीव जैसे तितलियों के प्रवास पैटर्न और भोजन व्यवहार का अध्ययन पौधे पशु जीवन की परस्पर संबद्धता का पता लगाने के लिए उपयोगी होगा। इसलिए बदलते जलवायु परिवर्तन में जैव विविधता की रक्षा के लिए गहन शोध और अध्ययन की आवश्यकता है।

5. फ्लाइंग गेको (Flying Gecko)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मिजोरम विश्वविद्यालय और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी, तुबिंगन (जर्मनी) के शोधकर्ताओं की एक टीम ने भारत-म्यांमार सीमा के साथ-साथ मिजोरम में गेको छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी है। यह नई प्रजाति सरक (Glide) सकती है, इसलिए शोधकर्ताओं ने इसे पैराशूट गेको नाम दिया है।

प्रमुख विशेषताएं:

- गेको आमतौर पर छोटी और मांसाहारी छिपकली है जो पूरी दुनिया के गर्म क्षेत्रों में पाई जाती है।
- यह नई प्रजाति मिजोरम के लॉन्गतलाई शहर और अन्य उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों में खोजी गई है। लॉन्गतलाई नई दिल्ली

से लगभग 1,600 मील दक्षिण-पूर्व में है जो मिजोरम के उत्तर-पूर्व में एक सीमावर्ती जिला है। यह राज्य पश्चिम में बांग्लादेश पूर्व में म्यांमार और उत्तर में शेष भारत से घिरा है।

- मिजोरम राज्य के नाम पर इस नई प्रजाति को गेको मिजोरमेन्सिस नाम दिया गया है। मिजोरम में खोजी गई यह प्रजाति पहले बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया जैसे दक्षिण एशियाई देशों में पाई गई है।
- नई प्रजाति गेको पॉपेंसिस से संबंधित है, लेकिन इसका आकार और रंग पैटर्न अलग है। नई पाई गई प्रजाति अपने समाभासी प्रजातियों से 7-14% तक भिन्न है।
- यह नई प्रजाति वृक्षवासी है जो पेड़ों पर रहती है और लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी है। यह रात्रिचर होती है और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा सकती है।
- फ्लाइंग गेको दक्षिण पूर्व एशिया के लिए स्थानीय हैं और उपजाति टाइकोजून से संबंधित हैं। ये छिपकलियां, जिन्हें कभी-कभी ग्लाइडिंग गेको या पैराशूट गेको के रूप में जाना जाता है, पेड़ों के बीच छलांग लगा सकती हैं।

गेको मिजोरमेन्सिस के बारे में:

- पाइचोजून (Ptychozoon), गेको जीनस की एक उपजाति है।
- यह दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है और दुनिया भर में जानी जाने वाली 13 प्रजातियों में से एक हैं।
- इस प्रजाति की खोज से पहले मिजोरम में पाइचोजून लियोनोटम या स्मूथ-बैक्ड ग्लाइडिंग गेको की एकमात्र प्रजाति थी।
- इसकी सीमा बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया के साथ-साथ मिजोरम तक भी फैली हुई है।
- यह वृक्षारोपणीय और रात्रिचर है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर ग्लाइडिंग करती है।
- यह नई प्रजाति अपनी अन्य प्रजाति गेको पॉपेंसिस से सबसे अधिक निकटता से संबंधित है, जिसमें से यह 7-14% के असंशोधित जोड़ीवार अनुक्रमण विचलन के साथ-साथ आकारिकी और रंग पैटर्न में असतत परिवर्तन में भिन्न होती है।
- ये प्रजातियां पैराफाईलेटिक हैं, जिनमें कई गूढ़ प्रजातियां भी हैं।

भारत में छिपकली की अन्य प्रजातियां:

- इंडियन गोल्डन गेको -(तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश) का मूल निवासी है।
- यह WPA (वन्यजीव संरक्षण अधिनियम) की अनुसूची-1 में सूचीबद्ध है।
- आईयूसीएन लाल सूची: सबसे कम चिंता (एलसी)
- टोके गेको -भारत-मलयान क्षेत्र में व्यापक है।
- संरक्षण की स्थिति: डब्ल्यूपीए की अनुसूची-4
- आईयूसीएन लाल सूची: कम चिंता (एलसी)

आगे की राह:

नई प्रजाति को पूर्वोत्तर राज्य की विशेष पहचान और संग्रह के सम्मान में शोधकर्ताओं द्वारा मिजोरम राज्य के नाम पर मिजोरमेन्सिस दिया गया है। इस नामकरण प्रक्रिया के माध्यम से राज्य की समृद्ध जैव विविधता को मान्यता दी गई है, जो हेपेटोलॉजी के क्षेत्र में मिजोरम के महत्त्व पर भी जोर देती है।

6. चक्रवात मोखा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठने वाला नवीनतम उष्णकटिबंधीय तूफान 'चक्रवात मोखा' भारत सहित कई देशों में कहर बरपाया। इससे बांग्लादेश व म्यांमार में लगभग 100 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि लाखों लोग स्थानांतरित होने को मजबूर हुए।

चक्रवात मोखा (Mocha) के बारे में:

- चक्रवात मोखा, यमन द्वारा प्रस्तावित नाम है, जो कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध देश के मछली पकड़ने वाले एक छोटे से गांव पर आधारित है।
- 277 किमी प्रति घंटे की रिकॉर्ड की गई हवा की गति के साथ, मोचा 1982 के बाद से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में गति और तीव्रता के मामले में चक्रवात फानी के साथ बनने वाला सबसे मजबूत चक्रवात रहा।
- वहीं अम्फान (2020) में 268 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से, जबकि तौक्ताई ने 2021 में 222 किमी प्रति घंटे की रफ्तार दर्ज की।
- इस चक्रवात से तबाह हुए म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने 'ऑपरेशन करुणा' चलाया था।

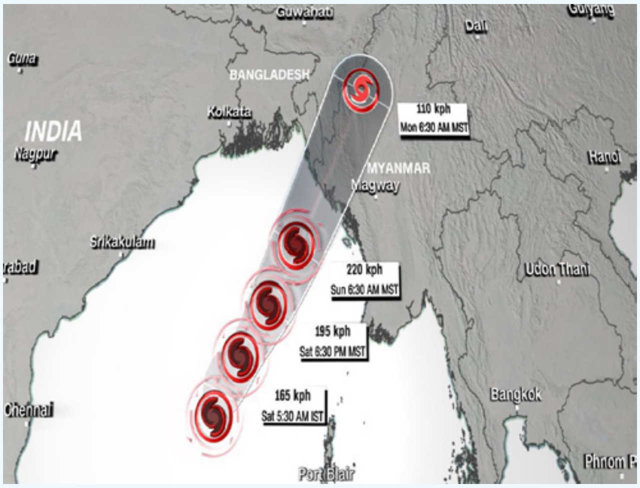

चक्रवात क्या होते हैं?

- चक्रवात एक कम दबाव वाली प्रणाली है जो गर्म पानी के ऊपर बनती है। आमतौर पर कहीं भी उच्च तापमान का मतलब कम दबाव वाली हवा का होना होता है तथा कम तापमान का मतलब उच्च दबाव वाली हवा का होना।
- भारत में चक्रवात शक्तिशाली मौसम प्रणालियाँ हैं जो तेज हवाओं और भारी वर्षा के साथ कम दबाव वाले क्षेत्रों की विशेषतायें हैं।
- यह पवन प्रणाली एक मजबूत कम दबाव केंद्र के चारों ओर

अंदर की ओर (उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त) घूमती है।

- भारत में चक्रवात आमतौर पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आते हैं।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या हैं?

- उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तीव्र गोलाकार तूफान है जो गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों से उत्पन्न होता है। यह कम वायुमंडलीय दबाव, उच्च हवाओं और भारी बारिश की विशेषता है।
- उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की एक विशिष्ट विशेषता आंख, साफ आसमान का एक केंद्रीय क्षेत्र, गर्म तापमान और कम वायुमंडलीय दबाव है।

चक्रवात निर्माण के लिए उत्तरदायी कारक:

- समुद्र की सतह पर गर्म तापमान।
- कोरिओलिस बल।
- वायुमंडलीय अस्थिरता।
- कम ऊर्ध्वाधर पवन।
- निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण।

चक्रवातों का नाम कैसे रखा जाता है?

- दुनिया भर में हर महासागर बेसिन में बनने वाले चक्रवातों का नाम क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्रों (RSMCs) और उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्रों (TCWCs) द्वारा दिया जाता है। दुनिया में छह RSMC हैं, जिनमें भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और पाँच TCWCs शामिल हैं। हाल के वर्षों में, आईएमडी ने नामों की सूची में सांस्कृतिक महत्त्व के नामों को शामिल करना शुरू किया है।

आगे की राह:

शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त, प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज के द्वारा पूर्वानुमानों के आधार पर आकस्मिक योजनाएँ बनाई जाएं तथा समय रहते सामुदायिक तैयारियों का प्रबंधन किया जाये। इसमें चिकित्सा आपूर्ति, भोजन और आपातकालीन आश्रय की पूर्व स्थिति शामिल होनी चाहिए।

7. जंबो (हाथी) गणना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में शेषाचलम पहाड़ियों और कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य में वन अधिकारियों द्वारा किए गए मैनुअल सर्वेक्षण में इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में हाथियों की उपस्थिति दर्ज की गई है।

जंबो गणना:

- यह गणना वन अधिकारियों द्वारा इन क्षेत्रों में तीन दिवसीय दौरे के दौरान की गई। उन्होंने पैरों के निशान, गोबर और उनकी उपस्थिति के कई महत्त्वपूर्ण संकेत देखे हैं।
- इस सर्वेक्षण से पता चलता है कि रेलवे कोडूर, राजमपेटा, सानिपया और बालापल्ले रेंज में 50 से 60 हाथी मौजूद हो सकते हैं।

शेषाचलम हिल्स और कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण:

- शेषाचलम पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट का एक हिस्सा हैं। ये सात पहाड़ियों का एक समूह हैं जिनके नाम शेषाद्री, नीलाद्रि, गरुदाद्री, अंजनाद्री, वृषभाद्रि, नारायणाद्री और वेंकटाद्रि हैं।
- इस साइट को वर्ष 2010 में बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था।
- गणना करने वाली टीम ने कहा कि शेषाचलम पहाड़ियों के कोर बेल्ट में प्रचुर संख्या में वाटरहोल मौजूद हैं। पिंचा, चेयेरू और गुंजना नदियाँ इस विशाल भूभाग से होकर बहती हैं।
- कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य और हाथी रिजर्व एशियाई हाथियों की आबादी वाला आंध्र प्रदेश का एकमात्र अभयारण्य है। यह वन्यजीव अभयारण्य चित्तूर जिले में स्थित है जो दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती और कंटीले जंगलों से आच्छादित है। इन वनों में पलार नदी की कैन्डिन्या तथा कैगल सहायक नदियाँ मिलती हैं

जंबो के लिए सबसे अनुकूल साइट:

इसमें हाथियों के लिए इन क्षेत्रों में मौजूद उपयुक्त परिस्थितियों पर भी प्रकाश डाला गया है-

- इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्राकृतिक जलकुंड (लगभग 1000) मौजूद हैं। चारे और प्राकृतिक जल संसाधनों की पर्याप्त मात्रा इस क्षेत्र को हाथियों के लिए एक सुरक्षित आवास के रूप में स्थापित करती है।
- शेषाचलम पहाड़ियों के आस-पास के गांवों में टमाटर और गन्ने की फसल की खेती की अनुपस्थिति ने मानव-पशु संघर्ष की नगण्य-रिपोर्टिंग में योगदान दिया है।

एशियाई हाथी:

- प्रोजेक्ट एलिफेंट द्वारा 2017 की गणना के अनुसार भारत में बड़ी संख्या में जंगली एशियाई हाथी हैं, जिनकी अनुमानित संख्या 29,964 है। यह प्रजातियों की वैश्विक आबादी का 60% हिस्सा है।
- भारतीय हाथी को भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I तथा वनस्पतियों और जीवों की लुप्तप्राय प्रजातियों (CITES) में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन के परिशिष्ट-I में शामिल किया गया है। ये IUCN रेड लिस्ट के तहत कमजोर प्रजातियों में सूचीबद्ध हैं।

खतरे और संरक्षण के उपाय:

- भारत में हाथियों की आबादी विलुप्त होने के कगार पर है जिसमें मानव-पशु संघर्ष एवं प्राकृतिक आवास की कमी जैसी चुनौतियाँ एक प्रमुख चिंता का विषय हैं।

आगे की राह:

माइक (Monitoring the illegal killing of elephants) कार्यक्रम और प्रोजेक्ट एलीफैंट जैसे सरकार के निरंतर प्रयासों के बावजूद भी हाथियों की आबादी तेजी से घट रही है। इसलिए हाथियों के क्षेत्रों निगरानी प्रणाली इनके संरक्षण के लिए महत्त्वपूर्ण हो जाती है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

1. आईबीएम ने उपग्रह डेटा को उच्च रिज़ॉल्यूशन मानचित्रों में बदलने हेतु नासा के साथ की साझेदारी

चर्चा में क्यों?

आईबीएम ने नासा के सहयोग से एक नए भू-स्थानिक फाउंडेशन मॉडल का अनावरण किया जिसे बाढ़, आग और अन्य परिदृश्य परिवर्तनों से प्राप्त उपग्रह डेटा को उच्च-रिज़ॉल्यूशन मानचित्रों में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि ग्रह के अतीत को समझकर, इसके भविष्य पर संकेत दिया जा सके।

भू-स्थानिक फाउंडेशन मॉडल का विवरण:

- यह मॉडल IBM के watsonx-ai का एक हिस्सा है, जो पारंपरिक मशीन लर्निंग और नई पीढ़ी की AI क्षमताओं को प्रशिक्षित करने, परीक्षण करने, ट्यून करने और तैनात करने के लिए AI बिल्डरों हेतु एक नेक्स्टजेन एंटरप्राइज स्टूडियो है।
- नासा और आईबीएम सहयोग का लक्ष्य शोधकर्ताओं को पृथ्वी प्रक्रियाओं से संबंधित बड़े नासा डेटासेट से विश्लेषण और अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का एक आसान तरीका प्रदान करना है।
- यह सहयोग नासा के ओपन सोर्स साइंस इनिशिएटिव (OSSI) का एक हिस्सा है जो अगले दशक में एक समावेशी, पारदर्शी और सहयोगी खुले विज्ञान समुदाय के निर्माण की प्रतिबद्धता है।
- यह नया भू-स्थानिक फाउंडेशन मॉडल प्राकृतिक आपदाओं और अन्य पर्यावरणीय परिवर्तनों के अनुकूलित मानचित्रों में नासा के उपग्रह अवलोकनों को परिवर्तित करके डिजाइन किया गया है।
- यह मॉडल नासा के हार्मोनाइज्ड लैंडसेट सेंटिनल-2 (HLS) डेटासेट पर लागू होगा।

इम्पैक्ट (इंटरएजेंसी इम्प्लीमेंटेशन एंड एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स टीम):

- इम्पैक्ट नासा के अर्थ साइंस डेटा सिस्टम्स (ESDS) प्रोग्राम का एक घटक है और नासा के हंट्सविले, अलबामा (यूएसए) में मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर में नवाचार, साझेदारी व प्रौद्योगिकी के माध्यम से नासा के पृथ्वी-अवलोकन डेटा के उपयोग के विस्तार के लिए जिम्मेदार है।
- बुनियादी भू-स्थानिक मॉडल के लिए आईबीएम नासा के इम्पैक्ट के तहत काम कर रहा है।

संभावित अनुप्रयोग:

- फसलों, इमारतों और अन्य बुनियादी ढांचे के लिए जलवायु संबंधी जोखिमों का अनुमान लगाने में मदद करना।
- कार्बन-ऑफसेट कार्यक्रमों के लिए वनों का मूल्यांकन और निगरानी करना।
- उद्यमों को जलवायु परिवर्तन को कम करने और अनुकूल बनाने के लिए रणनीति बनाने में मदद करने हेतु भविष्य का मॉडल विकसित करना।

आगे की राह:

फाउंडेशन के भू-स्थानिक मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तैनाती को काफी अधिक स्केलेबल, किफायती और कुशल बनाते हैं जिससे भविष्य की आपदा से बचने हेतु अतीत की गलतियों को हाई रिज़ॉल्यूशन वाले मानचित्रों से समझा जा सकेगा।

2. सोलर और विंड फार्म में फ्लो बैटरियां

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आईआईटी-मद्रास की शोध टीम ने एक 'गैर-जलीय ऑल-ऑर्गेनिक रेडॉक्स फ्लो बैटरी (NORFB)' विकसित की है जो पारंपरिक जलीय प्रवाह बैटरी में बदलाव लाएगी जिसका उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण ग्रिडों में किया जा सकता है।

फ्लो बैटरियां क्या हैं?

- फ्लो बैटरियां पारंपरिक बैटरियों से भिन्न होती हैं क्योंकि ऊर्जा ठोस इलेक्ट्रोड में संग्रहित होती है। फ्लो बैटरी एक रिचार्जेबल बैटरी होती है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट एक या एक से अधिक टैंकों से एक या अधिक इलेक्ट्रोकेमिकल कोशिकाओं के माध्यम से प्रवाहित होता है। जब पर्याप्त जगह हो तब प्रवाह बैटरी को अच्छी ऊर्जा भंडारण उपकरण के रूप में माना जाता है।
- पारंपरिक इलेक्ट्रोड बैटरी की तुलना में इनका आकार आसानी से बढ़ाया जा सकता है।

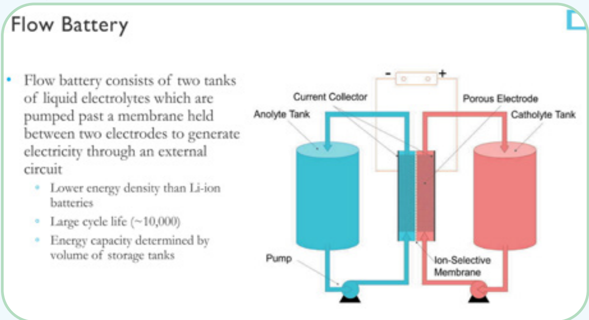

बैटरी के प्रकार:

- **लेड एसिड बैटरी:** लेड-एसिड बैटरी (Lead-acid batteries) बहुतायत में प्रयोग आने वाली बैटरी है। पुन: आवेशित (चार्ज) करने योग्य बैटरियों में यह सबसे पुरानी बैटरी है। सबसे कम उर्जा-से-भार के अनुपात की दृष्टि से निकिल-कैडमियम बैटरी के बाद यह दूसरे स्थान पर आती है। इसमें थोड़े समय के लिये उच्च धारा प्रदान करने की क्षमता होती है। उपरोक्त गुणों के अतिरिक्त यह बहुत ही सस्ती भी होती है जिसके कारण कारों, ट्रकों, अन्य गाड़ियों तथा व्यवधानरहित शक्ति स्रोतों में बहुतायत में प्रयोग की जाती है।

- **निकिल-कैडमियम बैटरी:** निकिल-कैडमियम बैटरी एक प्रकार की पुनर्भरणीय बैटरी (री-चार्जेबल बैटरी) है जिसके एलेक्ट्रोड निकिल आक्साइड हाइड्राक्साइद तथा धात्विक कैडमियम के होते हैं। इसके लाभ में सभी आकारों में उपलब्धता शामिल है, इसे आसानी से इधर-उधर ले जाया जा सकता है। कैडमियम से संबंधित पर्यावरणीय चिंताएँ भी इसमें शामिल हैं।
- **लिथियम आयन बैटरी:** लीथियम आयन बैटरी एक पुन: चार्ज करने योग्य बैटरी है। ये बैटरियाँ आजकल के उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक सामानों में प्राय: उपयोग की जातीं हैं और पोर्टेबल एलेक्ट्रानिक युक्तियों के लिये सबसे लोकप्रिय रिचार्जेबल बैटरियों में से एक हैं। इसके लाभ में उच्च ऊर्जा घनत्व वाला सुपीरियर, हल्का और छोटा शामिल है। मुख्य चिंता कच्चे माल पर निर्भरता, निर्माण में चुनौतियों, कुछ प्रकार के ओवरचार्जिंग से संबंधित है।

गैर-जलीय और जैविक विशेषताओं को क्यों जोड़ा जाता है?

आईआईटी मद्रास ने निम्नलिखित दो पहलुओं पर अपनी दक्षता में सुधार करने के लिए पारंपरिक जलीय प्रवाह बैटरियों (पानी आधारित इलेक्ट्रोलाइट) में सुधार किया है:

- इलेक्ट्रोलाइट्स से गुजरने और ऑपरेटिंग वोल्टेज सीमा व ऊर्जा घनत्व को कम करने से पानी में बदलाव होता है।
- ये बैटरी के उपकरणों को खराब करते हैं।

एनओआरएफबी के लाभ:

- नए प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट- पायरीलियम लवण का उपयोग करके प्रवाह बैटरी का उन्नत संस्करण विकसित करना।
- इनका उपयोग सौर और पवन फर्मो में बिजली को स्टोर करने तथा बिजली की समस्या को हल करने और सिस्टम की स्थिरता को बनाए रखने के लिए करना।
- उपयुक्त संरचनात्मक संशोधनों के साथ यह उच्च-वोल्टेज संचालन की अनुमति देगा। शोधकर्ताओं ने सस्ते और आसानी से विकसित होने वाले कैथोलाइट का इस्तेमाल किया है जिससे इन बैटरियों की निर्माण लागत में कमी आएगी।
- गैर-जलीय प्रवाह बैटरी से जुड़े लाभों के साथ, जैविक पहलू को जोड़ने से बैटरी की ऊर्जा घनत्व में वृद्धि होगी।
- ऑर्गेनिक फ्लो बैटरियों में उच्च मापनीयता (टैंक आकार के समानुपाती क्षमता) होती है जो सिस्टम प्रदर्शन के अधिक लचीलेपन और अनुकूलन की अनुमति देती है।
- ये बैटरियां पर्यावरण के भी अनुकूल होती हैं।

फ्लो या रेडॉक्स बैटरी से जुड़ी चुनौतियाँ:

- गैर-जलीय सभी कार्बनिक रेडॉक्स प्रवाह बैटरी (NORFB) को पारंपरिक प्रवाह बैटरी से जुड़ी अधिकांश समस्याओं को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन नई उन्नत रेडॉक्स बैटरी से जुड़ी कुछ संभावित चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं:
  - इसका भारी वजन इसकी गतिशीलता के लिए चुनौती उत्पन्न करता है। अधिक क्षमता हासिल करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट टैंकों को काफी बड़ा होना चाहिए।
  - इसका बड़ा आकार इसे केवल स्थिर अनुप्रयोगों के लिए ही उपयुक्त बनता है।

आगे की राह:

उन्नत रेडॉक्स प्रवाह तकनीक बैटरी निर्माण उद्योग में एक नया मानदंड स्थापित करेगी। यह शोध एनओआरएफबी बैटरी निर्माण उद्योग के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा, जिसकी वर्तमान गैर-नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण मांग है।

3. माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में एक बच्चे को सफलतापूर्वक जन्म देने के लिए माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट (MDT) का उपयोग किया गया। इसे तीन माता-पिता के बच्चे के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि नवजात शिशु की तीन माता-पिता से आनुवंशिक सामग्री मिलती है। शिशु को मां की माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी से बचाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है।

मुख्य विशेषताएं:

- माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट गंभीर वंशानुगत माइटोकॉन्ड्रियल विकारों वाले परिवारों के लिए उपलब्ध है, जो अपनी संतानों को जीन प्रदान नहीं करते हैं।
- यह एक प्रकार का आईवीएफ है जिसमें रोगी के अंडों में क्षतिग्रस्त माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को दाता अंडे से स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से बदल दिया जाता है।
- बच्चे का अधिकांश डीएनए उसके माता-पिता से आता है, केवल थोड़ा सा हिस्सा दाता से प्राप्त होता है। इसका इस्तेमाल माइटोकॉन्ड्रिया अंडे को निषेचित करने के लिए किया गया है।
- हालांकि मीडिया में आमतौर पर 'तीन माता-पिता के बच्चे' शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन बच्चे के डीएनए का अधिकांश हिस्सा उसके दो माता-पिता से आता है, केवल 0.1% दाता से प्राप्त होता है।
- माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट (MDT) एक ऐसी विधि है जिसमें माता-पिता की आनुवंशिक सामग्री और डोनर की माइटोकॉन्ड्रियल सामग्री का उपयोग करके आईवीएफ के माध्यम से बच्चा पैदा किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल सामग्री माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होती है, जो कोशिका के केंद्रक में पाई जाती है।

माइटोकॉन्ड्रिया क्या है?

- ये झिल्ली-बद्ध कोशिका अंग हैं जो कोशिका के उपापचयी कार्यों के लिए आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन करके कोशिकाओं के ऊर्जा उत्पादक के रूप में काम करते हैं।
- माइटोकॉन्ड्रियल ऊर्जा एक छोटे अणु में संग्रहीत होती है जिसे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट (ATP) के रूप में जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में गुणसूत्रों का अपना सेट होता है।
- **माइटोकॉन्ड्रियल रोग-** जब माइटोकॉन्ड्रिया क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और पर्याप्त ऊर्जा पैदा नहीं करते हैं, तो अंग का कार्य प्रभावित

होता है।

- माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन के कारण होने वाले विकारों को माइटोकॉन्ड्रियल रोग कहा जाता है।
- माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर केवल मां के माध्यम से ही हो सकते हैं।

माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट के लाभ और हानिः

- प्राथमिक लाभ यह है कि एमडीटी महत्त्वपूर्ण माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी से त्रस्त परिवारों को तथा उनके स्वस्थ बच्चों को एक दुखद और अक्सर जीवन-सीमित स्थिति से मुक्त करने का अवसर प्रदान करेगा।
- इस तरह के आनुवंशिक रोगों के साथ पैदा होने वाले कई बच्चों को इतनी कम उम्र में बड़े होने या मरने की पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ेगा।
- इस तकनीक में नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने की क्षमता है।
- यह तकनीक जितनी फायदेमंद हो सकती है, उतनी ही चिंता भी पैदा करती है।
- त्रिपितृत्व के परिणामस्वरूप सामाजिक सरोकार विकसित होते हैं, क्योंकि इन प्रक्रियाओं से उत्पन्न बच्चे पूर्वाग्रह के परिणामस्वरूप भावनात्मक पीड़ा झेलते हैं या कानूनी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।
- इन प्रजनन प्रक्रियाओं द्वारा संबोधित नैतिक, कानूनी और सामाजिक चुनौतियाँ विवादास्पद हैं।

आगे की राहः

इस तथ्य के बावजूद कि माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट में अनुसंधान अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है, माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन उन लोगों के लिए एक वरदान है जो माइटोकॉन्ड्रियल बीमारियों से पीड़ित हैं और जिनके पास कोई इलाज नहीं है।

4. ई-त्वचा (E-Skin)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जेनन बाओ के नेतृत्व में कैलिफोर्निया स्थित स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की अनुसंधान टीम ने एक सॉफ्ट एण्ड फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक त्वचा विकसित की है जो प्राकृतिक त्वचा के कार्य की नकल कर सकती है। इस प्रौद्योगिकी का उद्देश्य कृत्रिम अंगों के लिए एक आवरण प्रदान करना है ताकि वे संवेदी प्रतिक्रिया प्रदान कर सकें और अपंग (Amputees) लोगों की मदद कर सकें।

ई-त्वचा (E-Skin) के बारे में:

- इलेक्ट्रॉनिक त्वचा या ई-त्वचा एक लचीली, फैलने योग्य और स्व-चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स को संदर्भित करती है जो मानव या पशु त्वचा की कार्यात्मकताओं की नकल करने में सक्षम है।
- यह विकास एक नरम और लचीली कृत्रिम त्वचा विकसित करने के लिए किया गया है जो पहनने वाले को दबाव, तनाव या तापमान में परिवर्तन महसूस करने की अनुमति देने के लिए मस्तिष्क (Somatosensory Cortex in the Brain) के इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भी प्रसारित कर सकता है।

ई-स्किन कैसे काम करती है?

- स्वस्थ जीवित त्वचा में यांत्रिक रिसेप्टर्स होते हैं जो संवेदी जानकारी के साथ काम करते हैं और विद्युत स्पंदन में परिवर्तित होते हैं। फिर इन स्पंदनों को आगे प्रतिक्रिया करने के लिए मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। इस तंत्र को कैलिफोर्निया की शोध टीम द्वारा कृत्रिम रूप से डिजाइन किया गया है।
- ई-स्किन को कठोर सेमीकंडक्टर्स से बने सेंसर और एकीकृत सर्किट की आवश्यकता होगी। यह बहुलक की एक लचीली, पतली परत को भी ढांकता हुआ (पतली अर्धचालक परत) के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सेंसर भौतिक परिवर्तनों को विद्युत स्पंदन में परिवर्तित कर मस्तिष्क को भेज सकता है।

ई-त्वचा के अनुप्रयोगः

- शोधकर्ताओं की टीम ने अनुमान लगाया है कि ई-स्किन का उपयोग उन लोगों में किया जा सकता है जिन्हें बड़ी चोटें लगी हैं और संवेदी विकारों से पीड़ित हैं। ई-त्वचा से ढके कृत्रिम अंग वाले लोग भी विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं का अनुभव कर सकते हैं जो उनके सामाजिक जीवन की भरपाई कर सकता है।

ई-स्किन से जुड़ी चुनौतियांः

- ई-त्वचा का विकास अभी भी प्रयोग के प्रारंभिक स्तर पर है। ई-त्वचा के वर्तमान संस्करण का परीक्षण चूहे पर किया गया है जो चूहे के सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स (मस्तिष्क का क्षेत्र शारीरिक संवेदनाओं को संसाधित करने में शामिल होता है) से जुड़ा था। शोध दल ने कहा है कि वे एक कम आक्रामक प्रणाली विकसित करने की उम्मीद करते हैं जिसे मस्तिष्क में प्रत्यारोपित नहीं करना पड़ेगा।
- इसके साथ ही ई-स्किन को एक बाहरी शक्ति स्रोत से सुचारू कार्यप्रणाली के रूप में कार्य करने के लिए इसे एक वायरलेस डिवाइस की भी आवश्यकता होगी।

आगे की राहः

ई-त्वचा की डिजाइनिंग और विकास कृत्रिम अंग क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। हालाँकि यह एक अत्याधुनिक तकनीक होगी जिसके महंगे होने की उम्मीद है। इसलिए इस वैज्ञानिक खोज के व्यापक स्तर पर उपयोग के लिए वैश्विक स्तर पर एक विनियमित तंत्र की आवश्यकता होगी ताकि प्रत्येक देश इस विकास से लाभान्वित हो सकें।

5. मानव पैन-जीनोम मानचित्र

चर्चा में क्यों?

हाल ही में किया गया अध्ययन जो नेचर जर्नल में प्रकाशित हुआ जिसे मुख्य रूप से अफ्रीका, कैरेबियन, अमेरिका, पूर्वी एशिया और यूरोप के 47 गुमनाम (Anonymous) व्यक्तियों का उपयोग करके निर्मित किया गया है, इसका पैन-जीनोम संदर्भ मानचित्र में वर्णन किया गया है।

जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है?

- जीनोम एक कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए निर्देशों का संपूर्ण सेट है। इसमें किसी व्यक्ति के विकास और कार्य करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी शामिल होती है।
- जबकि जीनोम सीक्वेंसिंग चार आधारों (एडेनाइन, थाइमिन, गुआनाइन और साइटोसिन) के सटीक क्रम को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि है जिन्हें क्रोमोसोम में व्यवस्थित किया जाता है। क्रोमोसोम डीएनए स्ट्रिंग का एक सन्निहित खिंचाव (Contiguous Stretch) है जो बदले में लाखों अलग-अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स से बना होता है जिन्हें न्यूक्लियोटाइड या बेस कहा जाता है।
- जीनोम अनुक्रमण हमें आनुवंशिक स्तर पर मानव विविधता को समझने में मदद करता है जिससे पता चलता है कि मनुष्य कुछ बीमारियों के प्रति कितना संवेदनशील है?

संदर्भ जीनोम मानचित्र:

- संदर्भ मानचित्र या संदर्भ जीनोम मानचित्र एक मानक मानचित्र की तरह है जिसका उपयोग वैज्ञानिक नए जीनोम का अनुक्रम और अध्ययन करते समय करते हैं। यह नए अनुक्रमित जीनोम और संदर्भ जीनोम के बीच के अंतर की तुलना करने तथा समझने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। पहला संदर्भ मानचित्र 2001 में बनाया गया था जिसने वैज्ञानिकों को विभिन्न रोगों से जुड़े हजारों जीनों की खोज करने, आनुवंशिक स्तर पर कैंसर जैसी बीमारियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद की।
- लेकिन यह संदर्भ मानचित्र अंतराल व त्रुटियों से युक्त हो सकता है जो सभी मानव के लिए एक समान नहीं है।

पैन-जीनोम मानचित्र:

- संदर्भ मानचित्र के अंतर और त्रुटियों को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने पैन-जीनोम मानचित्र विकसित किया है। पिछले रेखीय संदर्भ जीनोम मानचित्र के विपरीत पैन-जीनोम मानचित्र को एक ग्राफ की तरह दर्शाया गया है।
- पैन-जीनोम में प्रत्येक गुणसूत्र को बांस के तने के रूप में कल्पना की जा सकती है, जिसमें नोड्स होते हैं जहां सभी 47 व्यक्तियों के अनुक्रम एक साथ आते हैं, जो समानता का संकेत देते हैं।
- अलग-अलग लंबाई वाले इंटर्नोड्स अलग-अलग पूर्वजों के व्यक्तियों के बीच आनुवंशिक भिन्नता का संकेत करते हैं।
- वैज्ञानिकों ने पैन-जीनोम मानचित्र में गुणसूत्रों के पूर्ण और निरंतर मानचित्र बनाने के लिए लंबे समय से पढ़े गए डीएनए अनुक्रमण का उपयोग किया है। इस तकनीक ने उन्हें सटीक, लंबे डीएनए स्ट्रैंड का उत्पादन करके एक पूर्ण और निरंतर गुणसूत्र मानचित्र विकसित करने में सक्षम बनायेगा।

पैन-जीनोम मानचित्र का महत्त्व:

- किसी भी दो मनुष्यों के डीएनए का 99% एक समान है लेकिन फिर भी लगभग 0.4% का अंतर है। यह मामूली अंतर न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या में बहुत बड़ा है जो कि लगभग 12.8 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स है।
- मानव का पैन-जीनोम मानचित्र इन अंतरों को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है। यह व्यक्तियों के बीच विविधता को आसानी से समझाएगा।
- इसके साथ ही, यह निम्नलिखित लाभ प्रदान कर सकता है;
  1. अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थितियों में योगदान करने वाले आनुवंशिक परिवर्तनों का अध्ययन करने में सहायता करना।
  2. मौजूदा सटीक संदर्भ जीनोम के खिलाफ भारतीय जीनोम की तुलना और मैप करने के लिए फायदेमंद।
  3. सभी या अधिकांश व्यक्तियों द्वारा साझा किए गए मूल जीनों की पहचान करना और उन्हें वर्गीकृत करना।
  4. परिवर्ती जीनों का लक्षण वर्णन जो केवल व्यक्तियों के एक सबसेट में मौजूद होते हैं।
- इन फायदों के अलावा इस मानचित्र में घनी आबादी वाले भारतीय उपमहाद्वीप और एशिया, ओशिनिया तथा पश्चिम एशियाई क्षेत्रों में इंडिजिनस लोगों का प्रतिनिधित्व शामिल नहीं हैं।

आगे की राह :

पैन-जीनोम मानचित्र वैज्ञानिकों को प्रजातियों के भीतर आनुवंशिक विविधता में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में सक्षम बनाता है और फेनोटाइप या बीमारियों से जुड़े जीनों की पहचान भी करता है। इस मानचित्र में भारतीय जीनोम अनुक्रम को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन भविष्य के पैन-जीनोम मानचित्र में उम्मीद है कि ये इसमें शामिल होंगे।

6. साइबर धोखाधड़ी के लिए एआई सॉल्यूशन (ASTR)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दूरसंचार विभाग (DoT) ने संभावित धोखाधड़ी वाले मोबाइल कनेक्शनों का पता लगाकर, उन्हें ब्लॉक करके साइबर धोखाधड़ी को कम करने हेतु टेलीकॉम सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन (ASTR) के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फेशियल रिकग्निशन पावर्ड सॉल्यूशन नामक एक उपकरण विकसित किया है।

ASTR क्या है?

- ASTR टूल को DoT द्वारा विकसित किया गया है जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फेशियल रिकॉग्निशन टूल है। यह दावा किया जाता है कि यह टेलीकॉम ऑपरेटरों के सब्सक्राइबर डेटाबेस के जाँच की क्षमता रखता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इसमें एक ही व्यक्ति से जुड़े कोई कनेक्शन हैं या नहीं।

ASTR की कार्य पद्धति:

- ASTR टूल एक ही व्यक्ति से जुड़े कई कनेक्शनों की पहचान करने के लिए सिम सब्सक्राइबर के डेटाबेस का विश्लेषण करता है। DoT केवल एक पहचान प्रमाण का उपयोग करके अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन लेने की अनुमति देता है।
- किसी भी मामले में अगर कोई संदिग्ध चेहरा कई मोबाइल कनेक्शन से जुड़ा है, तब ASTR इस चेहरे की तुलना छवियों के एक डेटाबेस से करेगा ताकि एक ही चेहरे से 9 से अधिक कनेक्शनों की पहचान की जा सके या यदि व्यक्ति ने अलग-अलग

नामों से सिम लिया है, तो ASTR इसे संभावित रूप से धोखाधड़ी के रूप में चिह्नित करेगा।

- फजी लॉजिक नाम की तकनीक का उपयोग सब्सक्राइबर के नामों के लिए समानता या अनुमानित मिलानों की पहचान करने के लिए किया जाता है जिससे टाइपोग्राफिकल त्रुटियों (टंकण संबंधी त्रुटियों) को ध्यान में रखा जा सके।

फजी लॉजिक (Fuzzy Logic):

- यह एक गणितीय दृष्टिकोण है जो अनिश्चितता और सटीक जानकारी से संबंधित है। यह पारंपरिक बाइनरी लॉजिक के विपरीत अस्पष्टता और आंशिक सत्य के प्रतिनिधित्व की अनुमति देता है।
- इससे धोखाधड़ी वाले कनेक्शनों की सूची, टेलीकॉम ऑपरेटरों, बैंकों, पेमेंट वॉलेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ साझा की जाती है।

ASTR की उत्पत्ति:

- एएसटीआर परियोजना की अवधारणा और डिजाइन अप्रैल 2021 से जुलाई 2021 के बीच हरियाणा में डीओटी की इकाई द्वारा तैयार की गई है। यह पायलट प्रोजेक्ट हरियाणा के मेवात में शुरू किया गया है। ASTR के इस पायलट प्रोजेक्ट ने लगभग पता लगाया है कि सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों के 16.69 लाख सक्रिय सिम में से 5 लाख सिम फर्जी पाए गए हैं।

आगे की राह:

साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए एआई समाधान महत्त्वपूर्ण होगा क्योंकि आइडेंटिटी टेकओवर, फिशिंग स्कैम, क्रेडिट कार्ड और बैंक धोखाधड़ी की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इसलिए यह सरकारी एजेंसी द्वारा एक सराहनीय कदम है।

7. कोल्ड ब्लडेड एनिमल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वैज्ञानिकों ने ठंडे खून वाले जीवों के बारे में अधिक जानने के लिए यूरेशियन पर्च (Perca Fluviatilis) पर एक अध्ययन किया है। वैज्ञानिकों ने इस अवधारणा के आधार पर कहा कि ठंडे खून वाले समुद्री जीव जैसे-मछली, ग्रह के गर्म होने के कारण कम हो सकते हैं।

अध्ययन की मुख्य विशेषताएं:

- ग्लोबल वार्मिंग के कारण ठंडे खून वाले समुद्री जानवरों के शरीर सिकुड़ जाएंगे।
- ठंडे खून वाले जानवर कम उम्र में तेजी से विकसित होते हैं और उनके शरीर का आकार कम होता है।
- ठंडे खून वाले जानवरों को एक्टोथर्म (Ectotherms) भी कहा जाता है।
- प्रभावित जानवरों में भी उच्च वृद्धि और मृत्यु दर होगी।

कोल्ड ब्लडेड एनिमल (Cold Blooded Animals):

- ठंडे खून वाले जानवरों को अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए भौतिक परिवेश पर निर्भर रहना पड़ता है।
- इसकी तुलना में, गर्म खून वाले जानवर दो चयापचय (metabolism) लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं: जैसे-
  1. स्वस्थ शरीर के वजन को बढ़ाना और बनाए रखना।
  2. स्तनधारियों के लिए 97 से 104 डिग्री फारेनहाइट के बीच और पक्षियों के लिए 106 से 109 डिग्री फारेनहाइट के बीच आंतरिक शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए गर्मी उत्पन्न करना चाहिए।
- इस तरह के जानवरों को एक्टोथर्म कहना अधिक उपयुक्त है क्योंकि 'एक्टो' का अर्थ बाहरी, जबकि ग्रीक शब्द 'थर्म' का अर्थ गर्मी होता है। दूसरे शब्दों में, एक्टोथर्म को अपने शरीर के तापमान को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य से गर्मी प्राप्त करना होता है।

कोल्ड-ब्लडेड के फायदे और नुकसान:

- चूँकि ठंडे खून वाले जानवर चयापचय को बढ़ावा देने के लिए अपने परिवेश से गर्मी को अवशोषित करते हैं, वे अपने भोजन को कई दिनों तक पचा सकते हैं और अगले भोजन की तलाश में एक सप्ताह तक प्रतीक्षा कर सकते हैं।
- सभी ठंडे खून वाले जीव किसी भी मौसम में उच्च तापमान भिन्नताओं के प्रति संवेदनशील होते हैं।

ठंडे खून वाले जानवरों का व्यवहार:

- चूँकि ठंडे खून वाले जानवर के शरीर का आंतरिक तापमान परिवेश के तापमान से निर्धारित होता है, इसलिए ठंड से मृत्यु को रोकने के लिए उसे गर्म वातावरण तक त्वरित पहुँच होनी चाहिए क्योंकि एक्टोथर्म अक्सर गर्म क्षेत्रों में केंद्रित होते हैं।
- जलीय एक्टोथर्म अपने शरीर को गर्म रखने के लिए गर्म पानी की तलाश करते हैं। क्योंकि सभी ठंडे खून वाले जीव अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए अपने परिवेश पर निर्भर होते हैं। वे ज्यादा गर्म होने से एक ठंडे आवास की तलाश करते है, जैसे-चट्टान के पीछे, पेड़ की छाया में या ठंडे पानी में।

गर्म और ठंडे खून वाले जानवर:

- ठंडे खून वाले जीवों को अपने आंतरिक शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए भौतिक वातावरण के तापमान पर निर्भर रहना पड़ता है। अपने शरीर को गर्म करने के लिए, उन्हें गर्मी की तलाश करनी होती है (जैसे-धूप सेंकना) और अपने शरीर को ठंडा करने के लिए, उन्हें ठंडे तापमान (जैसे- गुफा) की तलाश करनी होती है।
- गर्म रक्त वाले जानवर अपने आंतरिक शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए भोजन के चयापचय पर निर्भर होते हैं। गर्मी में सहायता के लिए इनके बाल (और कुछ मामलों में वसा) या पंख होते हैं।

आगे की राह:

संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि ठंडे खून वाले जीव एक स्थिर आंतरिक शरीर के तापमान को बनाए रखने में असमर्थ होते हैं और निर्णय लेने के लिए उन्हें बाहरी उत्तेजनाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। उदाहरण के लिए छिपकली गर्मी और सर्दियों में विभिन्न आदतों का प्रदर्शन करती है, जैसे कि पानी में या जमीन पर रहना।

1. ईएसजी जोखिमों से निपटने के लिए आरबीआई जीएफआईएन के ग्रीनवाशिंग टेकस्प्रिंट में शामिल होगा

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्रीनवाशिंग टेकस्प्रिंट में भाग लेने के लिए ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क (GFIN) के साथ समझौता किया। इस आयोजन का उद्देश्य पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) क्रेडेंशियल्स से संबंधित अतिरंजित (exaggerated), भ्रामक या निराधार दावों से जुड़ी चिंताओं को दूर करना है। टेकस्प्रिंट 13 अंतर्राष्ट्रीय नियामकों, फर्मों और नवप्रवर्तकों को एक ऐसा उपकरण विकसित करने के लिए एक साथ लाएगा जो नियामकों तथा बाजार को वित्तीय सेवाओं में ग्रीनवाशिंग के जोखिमों से सावधान करेगा।

ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क (GFIN) क्या है?

- GFIN को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय नियामक द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया था।
- जीएफआईएन उपभोक्ताओं के हितों में वित्तीय नवाचार का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध एक नियामक नेटवर्क है।
- GFIN नवोन्मेषी फर्मों को नियामकों के साथ बातचीत करने के लिए अधिक कुशल तरीका प्रदान करता है जिससे उन्हें देशों के बीच नेविगेट करने में मदद मिलती है क्योंकि वे नए विचारों पर जोर देते हैं।
- जीएफआईएन का उद्देश्य विभिन्न अनुभवों और दृष्टिकोणों को साझा करते हुए नवाचार से संबंधित विषयों पर वित्तीय सेवा नियामकों के बीच सहयोग के लिए एक नया ढांचा तैयार करना है।

ग्रीनवाशिंग क्या है?

- यह किसी उत्पाद, सेवा या निवेश अवसर के लाभों के बारे में अतिरंजित, भ्रामक या निराधार दावे करने की प्रथा है।
- ग्रीनवाशिंग निवेशकों और उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकता है जो स्थायी वित्त को बढ़ावा देने के समग्र लक्ष्य को नुकसान पहुंचा सकता है।
- यह एक धारणा बनाता है कि एक कंपनी स्थिरता या सामाजिक जिम्मेदारी की दिशा में कदम उठा रही है, लेकिन वास्तव में यह उन प्रथाओं में शामिल हो सकती है जो पर्यावरण या समाज के लिए हानिकारक है।

टेकस्प्रिंट का उद्देश्य:

- ग्रीनवॉशिंग समस्या का समाधान करने के लिए टेकस्प्रिंट इवेंट वित्तीय सेवाओं में ग्रीनवॉशिंग से निपटने में नए टूल विकसित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय नियामकों और फर्मों को एक साथ लाता है।
- इन फर्मों से दुनिया भर के नियामक विशेषज्ञों, विभिन्न हितधारकों और पेशेवरों के साथ काम करने का अवसर मिलेगा।

आगे की राह:

भारत ESG आवश्यकताओं की ओर तेजी से बढ़ रहा है। एक वर्चुअल टेकस्प्रिंट में आरबीआई की भागीदारी अंतर्राष्ट्रीय नियामकों, फर्मों तथा नवप्रवर्तकों के बीच एक सामूहिक प्राथमिकता के रूप में स्थायी वित्त को संबोधित करने और ईएसजी-अनुपालन प्लेटफार्मों का एक वास्तविक नेटवर्क स्थापित करने के लिए समन्वय बढ़ायेगा।

2. यूनिक इकोनॉमिक ऑफेंडर कोड

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार आर्थिक अपराधों के आरोपी प्रत्येक व्यक्ति या कंपनी के लिए एक विशिष्ट कोड लाने की योजना बना रही है।

यूनिक इकोनॉमिक ऑफेंडर कोड:

- आर्थिक अपराधों का पता लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पहचान संख्या को 'यूनिक इकोनॉमिक ऑफेंडर कोड' कहा जाएगा।
- यह कोड प्रत्येक अपराधी के लिए विशिष्ट होगा जो किसी व्यक्ति के मामले में उसकी आधार संख्या या किसी कंपनी के मामले में पैन से जुड़ा होगा।
- वित्त मंत्रालय के तहत केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो ने लगभग 2.5 लाख आर्थिक अपराधियों का एक डेटाबेस बनाया है।
- प्रत्येक अभियुक्त के लिए अद्वितीय कोड उनके खिलाफ एक बहु-एजेंसी जांच को त्वरित शुरू करने में मदद करेगा, क्योंकि एक एजेंसी द्वारा अपनी जांच पूरी करने और चार्जशीट या अभियोजन शिकायत दर्ज करने से पहले उसे आगे की जांच के लिए दूसरों के साथ साझा करने की वर्तमान प्रथा के खिलाफ है।

यूनिक कोड कैसे काम करेगा?

- अद्वितीय आर्थिक अपराधी कोड अल्फा-न्यूमेरिक होगा जो आर्थिक अपराधों के सभी मामलों को टैग करने के लिए कंपनियों और व्यक्तियों के लिए पैन या आधार पर आधारित होगा।
- आर्थिक अपराध वाले व्यक्तियों और कंपनियों को टैग किया जाएगा जिनका प्रोफाइल 360 डिग्री का होगा।
- इस कोड से सिस्टम-जेनरेट किया जाएगा।
- यह कोड एक बार पुलिस या किसी केंद्रीय खुफिया प्रवर्तन एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय आर्थिक अपराध रिकॉर्ड (NEOR) के निर्माणाधीन केंद्रीय भंडार में डेटा फीड करने के बाद दिया जायेगा।

एनईओआर के बारे में राष्ट्रीय आर्थिक अपराध रिकॉर्ड:

- यह सभी आर्थिक अपराधों का एक केंद्रीय भंडार है जो प्रत्येक आर्थिक अपराधी से संबंधित डेटा को केंद्रीय और राज्य खुफिया तथा प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा करेगा।
- एनईओआर को लगभग 40 करोड़ रुपये के बजट के साथ बनाकर, केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) की मदद से समन्वय का कार्य दिया गया है।
- एनईओआर का कार्य अगले 4-5 महीनों में पूरा हो जाएगा।

- केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के सभी डेटा को एपीआई (एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) सॉफ्टवेयर का उपयोग करके राष्ट्रीय रिपॉजिटरी में ट्रांसफर किया जाएगा, जिससे मैन्युअल हस्तक्षेप की गुंजाइश कम हो जाएगी।

आगे की राह:

'यूनिक इकोनॉमिक ऑफेंडर कोड' मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के खिलाफ भारत की विधायी तथा प्रवर्तन कार्यवाहियों को अधिक मजबूत करेगा जिससे आर्थिक अपराधों पर प्रभावी तरीके से नकेल कसने में मदद मिलेगी।

3. WPI 34 महीने के निचले स्तर पर

चर्चा में क्यों?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, थोक मूल्य सूचकांक (WPI) पर आधारित मुद्रास्फीति दर अप्रैल में लगभग तीन साल के निचले स्तर (-)0.92 प्रतिशत पर आ गई, जो 33 महीनों में पहली बार नकारात्मक रही। यह वैश्विक पण्य (Commodity) कीमतों में नरमी के साथ एक उच्च आधार प्रभाव भोजन, ईंधन और अन्य इनपुट लागतों में कमी को दर्शाता है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- मार्च 2023 में थोक मुद्रास्फीति की दर 1.34 प्रतिशत और अप्रैल 2022 में 15.38 प्रतिशत थी। फरवरी से ऑल-कमोडिटी इंडेक्स 150.9 पर अपरिवर्तित रहा है।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) भी अप्रैल 2023 में 18 महीने के निचले स्तर 4.7 प्रतिशत पर आ गया था।
- यह भारतीय रिजर्व बैंक के मध्यम अवधि के मुद्रास्फीति लक्ष्य के 4+/-2 प्रतिशत बैंड के भीतर है।
- थोक मूल्य सूचकांक में अवस्फीति (Deflation) की प्रवृत्ति, जो उत्पादकों के अंत में कीमतों को दर्शाती है, बाद में खुदरा मुद्रास्फीति में भी एक अंतराल के साथ प्रतिबिंबित होने की संभावना है।
- एलपीजी, मिट्टी के तेल और अन्य खनिज तेलों की कीमतों में कमी के कारण ईंधन तथा बिजली की मुद्रास्फीति भी 1 प्रतिशत से कम होकर 0.93 प्रतिशत पर आ गई।

WPI में गिरावट के कारक:

- एक उच्च आधार प्रभाव और वैश्विक कमोडिटी कीमतों में नरमी से WPI, लगभग तीन वर्षों के बाद अवस्फीति का अनुभव किया।
- WPI मुद्रास्फीति दर में गिरावट मुख्य रूप से 'मूल धातुओं, खाद्य उत्पादों, खनिज तेलों, वस्त्रों, गैर-खाद्य वस्तुओं, रसायन और रासायनिक उत्पादों, रबर व प्लास्टिक उत्पादों और कागज उत्पादों की कीमतों में गिरावट' द्वारा योगदान दिया गया था।

थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के बारे में:

- यह थोक व्यवसायों द्वारा अन्य व्यवसायों के लिए थोक में व्यापार की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को मापता है।
- प्रकाशित- आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।
- आधार वर्ष- संशोधित रूप 2004-05 से 2011-12
- कम्पोनेंट्स-
  - निर्मित उत्पाद- 64.2%
  - प्राथमिक लेख- 22.6%
  - ईंधन और बिजली- 13.1%

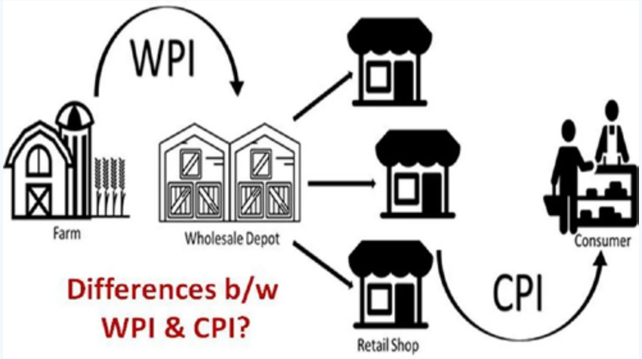

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI):

- द्वारा जारी - राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)
- आधार वर्ष- 2012
- यह वस्तुओं और सेवाओं जैसे भोजन, चिकित्सा देखभाल, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि की कीमत में अंतर की गणना करता है जिसे भारतीय उपभोक्ता उपयोग के लिए खरीदते हैं।
- WPI उत्पादक स्तर पर मुद्रास्फीति को ट्रैक करता है और CPI उपभोक्ता स्तर पर कीमतों के स्तर पर नजर रखता है।

आगे की राह:

विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक पण्य कीमतों में नरमी से विनिर्माण उत्पादों की मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिलेगी। एक कम WPI प्रिंट खुदरा मुद्रास्फीति को CPI मुद्रास्फीति पर इसके पिछले प्रभाव के साथ संतुलित करने में मदद कर सकता है।

4. ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स

चर्चा में क्यों?

सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों और फूड डिलीवरी कंपनियों को अपने डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) से जुड़ने का निर्देश दिया। फ्लिपकार्ट और जोमैटो जैसे कुछ ई-कॉमर्स कंपनियां डिजिटल कॉमर्स के लिए सरकार समर्थित ओपन नेटवर्क में शामिल होने हेतु सहायक कंपनियों को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। Amazon और Swiggy जैसी अन्य बड़ी कंपनियों ने अभी तक इससे दूर रहने का विकल्प चुना है।

ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) क्या है?

- ओएनडीसी एक गैर-लाभकारी संगठन है, जिसकी स्थापना

वाणिज्य मंत्रालय के तहत उद्योग व आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग (DPIIT) द्वारा ओपन ई-कॉमर्स विकसित करने हेतु की गई थी।

- इसे 2021 में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI) और Protean eGov Technologies Limited के शुरुआती निवेश के साथ शामिल किया गया था।
- ओएनडीसी आपस में जुड़े ई-मार्केटप्लेस का एक नेटवर्क है जिसके माध्यम से विक्रेता किसी भी बिचौलियों को दरकिनार करके अपने उत्पादों को सीधे ग्राहकों को बेच सकते हैं।
- ओएनडीसी एक मंच-केंद्रित प्रतिमान से एक खुले नेटवर्क में बदल जाता है जहां खरीददार और विक्रेता दोनों ऑनलाइन व्यापार करने के लिए एक ही नेटवर्क या एप्लिकेशन का उपयोग करेंगे।
- ओएनडीएस के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं में भोजन, किराने का सामान, घर की सजावट, सफाई के आवश्यक सामान और अन्य उत्पादों की डिलीवरी सेवाएं शामिल हैं।

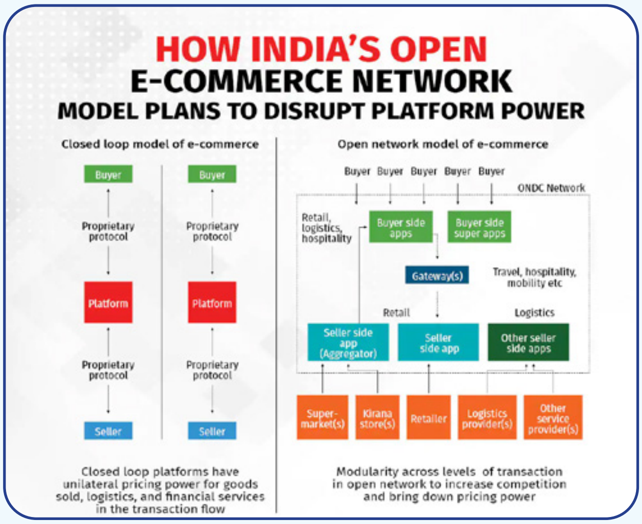

ओएनडीसी प्लेटफार्म के लाभ:

- **विक्रेता-** बड़े बाजार के फर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा करने और ऑनलाइन खोजने योग्य बनने का समान अवसर प्राप्त होना।
- **खरीददार-** एक ही चेकआउट अनुभव के श्रेणियों में उत्पादों के व्यापक वर्गीकरण से एक सहज खरीददारी अनुभव का आनंद लेना।
- **टेक कंपनियां-** उत्पादों और सेवाओं को तेजी से अपनाना और गो-टू-मार्केट प्रयासों में विस्तार होना।
- **फिनटेक-** ई-कॉमर्स में लगी सभी संस्थाओं को ऋण और वित्तपोषण समाधान प्रदान करना।

आगे की चुनौतियां:

- **जटिलता-** ओएनडीसी यूपीआई की तुलना में कहीं अधिक जटिल है जो इसे उपयोग के मामले में कम लोगों के अनुकूल बनाता है।
- **जागरूकता की कमी-** छोटे पैमाने के व्यापार मालिकों के लिए एक जन जागरूकता अभियान की आवश्यकता है क्योंकि इसमें शामिल होने के लिए उनके पास तकनीकी विशेषज्ञता की कमी है।
- **विवाद निवारण-** ग्राहक सेवा और शिकायतों को संभालने की जिम्मेदारी पर स्पष्टता की कमी है।
- विशेषज्ञ इस बात को लेकर आशंकित हैं कि ओएनडीसी सस्ता माल और सेवाएं उपलब्ध नहीं करा सकता है।

आगे की राह:

ओएनडीसी को आम सहमति आधारित और लोगों के अनुकूल बनाने के लिए सरकार को ओएनडीसी के प्रावधानों के बारे में स्पष्ट करना चाहिए। मांग और आपूर्ति पक्ष की बाधाओं को संतुलित करने के लिए एक व्यापक व समावेशी तंत्र होना चाहिए।

5. यूएस डेट-सीलिंग स्टैंडऑफ

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी सचिव जनेट येलेन ने चेतावनी दी कि यदि राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सभा ऋण सीमा को बढ़ाने या निलंबित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं तो अमेरिका जल्द ही डिफाल्ट कर सकता है। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी सरकार ने अपनी 31.4 ट्रिलियन डॉलर उधार लेने की सीमा को पार कर लिया है।

यूएस डेट-सीलिंग क्या है?

- संयुक्त राज्य अमेरिका में ऋण सीमा राष्ट्रीय ऋण की राशि पर एक विधायी सीमा है जो यू.एस. द्वारा खर्च की जा सकती है।
- यूएस कांग्रेस ने अपने विकास को सीमित करने के इरादे से 1939 में सरकार द्वारा जारी किए जा सकने वाले ऋण की एक व्यापक ऋण सीमा को अपनाया था।

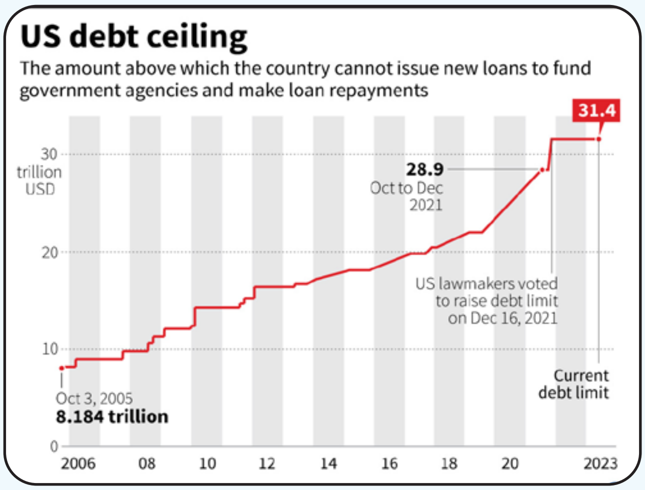

- ट्रेजरी, इस प्रकार यह सीमित करता है कि संघीय सरकार उस ऋण पर कितना पैसा दे सकती है जो उसने पहले से ही अधिक पैसा उधार लेकर खर्च किया था।
- ऋण सीमा एक समग्र आंकड़ा है जो सकल ऋण पर लागू होता है, जिसमें सार्वजनिक और अंतर-सरकारी खातों में ऋण शामिल है।
- ऋण का लगभग 0.5 प्रतिशत सीमा द्वारा कवर नहीं किया जाता है, क्योंकि व्यय अलग कानून द्वारा अधिकृत होते हैं और ऋण सीमा

सीधे सरकारी घाटे को सीमित नहीं करती है।

- वास्तव में, यह केवल ट्रेजरी को सीमा समाप्त होने के बाद व्यय और अन्य वित्तीय दायित्वों के भुगतान से रोक सकता है।
- समय-समय पर यह लिमिट बढ़ाई जाती रही है। वर्ष 1960 से अन्तिम बार 2021 तक यह लिमिट 78 बार बढ़ाई गई है।

कैसे देश मंदी की ओर बढ़ सकता है?

- जब सीमा अधिनियमित किए जाने की सीमा में वृद्धि किए बिना ऋण सीमा तक पहुंच जाता है, तब सरकारी व्यय और दायित्वों को अस्थायी रूप से वित्तपोषित करने के लिए ट्रेजरी को 'असाधारण उपायों' का सहारा लेने की आवश्यकता होती है, जब तक कि कोई समाधान नहीं हो जाता।
- लंबे समय तक चूक वित्तीय संकट और उत्पादन में गिरावट सहित विभिन्न प्रकार की आर्थिक समस्याओं को ट्रिगर कर सकती है जो देश को आर्थिक मंदी में डाल देगी।
- सरकार के दायित्वों का भुगतान जारी रखने के लिए ट्रेजरी विभाग अब 'असाधारण उपायों' का उपयोग करना शुरू करेगा।
- ये उपाय अनिवार्य रूप से राजकोषीय लेखांकन उपकरण हैं जो कुछ सरकारी निवेशों पर अंकुश लगाते हैं ताकि बिलों का भुगतान जारी रहे।
- एक बार जब सरकार अपने असाधारण उपायों को समाप्त कर देती है और नकदी से बाहर हो जाती है, तो वह नया ऋण जारी करने तथा बिलों का भुगतान करने में असमर्थ हो जाती है।
- यदि सरकार अपने बॉन्डधारकों को आवश्यक भुगतान करने में असमर्थ है तो सरकार अपने ऋण पर चूक कर सकती है।

आगे की राह:

ऋण सीमा संकट राजनीतिक शिथिलता का एक लक्षण है। ऐसा परिदृश्य आर्थिक रूप से विनाशकारी होगा जिसका प्रभाव सम्पूर्ण दुनिया को वित्तीय संकट में डाल सकता है।

6. म्युचुअल फंडों द्वारा निगरानी प्रणाली का प्रस्ताव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सेबी ने सुझाव दिया है कि एएमसी के वरिष्ठ प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके कर्मचारियों, डीलरों, स्टॉक ब्रोकरों या किसी अन्य संबंधित संस्थाओं द्वारा संभावित कदाचार का पता लगाने और रिपोर्ट करने के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया जाए।

एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) क्या है?

- एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक फर्म है जो ग्राहकों से एकत्रित धन का निवेश करती है। पूंजी को स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट, मास्टर लिमिटेड पार्टनरशिप और अन्य विभिन्न निवेशों के माध्यम से कामों में लगाती है।
- एएमसी न केवल सलाह देती है, बल्कि ग्राहक की निवेश रणनीति, जोखिम सहिष्णुता और वित्तीय स्थिति के आधार पर निवेश निर्णय भी लेती है।
- एएमसी हेज (Hedge) फंड और पेंशन योजनाओं का प्रबंधन करते हैं। छोटे निवेशकों को बेहतर सेवा देने के लिए वे म्युचुअल फंड, इंडेक्स फंड या एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) जैसी पूल वाली संरचनाएं बनाते हैं, जिन्हें वे एक केंद्रीकृत पोर्टफोलियो में प्रबंधित कर सकते हैं।
- एएमसी को बोलचाल की भाषा में मनी मैनेजर या मनी मैनेजमेंट फर्म भी कहा जाता है।
- एएमसी उच्च-जोखिम और कम-जोखिम दोनों प्रतिभूतियों जैसे स्टॉक, ऋण, रियल-एस्टेट, शेयर, बॉन्ड, पेंशन फंड आदि में निवेश करके पोर्टफोलियो की विविधता को बनाए रखते हैं।
- **रिटर्न**- फंड का रिटर्न बाजार से जुड़ा होता है और फंड के प्रदर्शन पर निर्भर करता है।
- **नियामक**- सभी एएमसी सेबी और एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) द्वारा शासित होते हैं।

एएमएफआई के बारे में:

- AMFI म्युचुअल फंड कंपनियों द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय है।
- **विजन**- एएमएफआई का गठन एक पारदर्शी और नैतिक-संचालित वित्तीय उद्योग की दृष्टि से किया गया था।
- यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक एएमसी एएमएफआई के नेतृत्व वाले नियमों का अनुपालन करे।
- प्रायोजक होने के नाते बैंक आरबीआई के साथ-साथ सेबी और एएमएफआई द्वारा शासित होते हैं।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के बारे में:

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारत सरकार के अंतर्गत वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में भारत में प्रतिभूति और वस्तु बाजार के लिए नियामक निकाय है।
- इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को एक कार्यकारी निकाय के रूप में हुई थी और 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम, 1992 के माध्यम से इसे वैधानिक शक्तियाँ प्रदान की गई थीं।

- सेबी का मूल कार्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना, प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना और उन्हें विनियमित करना है।

आगे की राह:

एएमसी को प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक डेटा के बैक टेस्टिंग के आधार पर अलर्ट प्रकार, पैरामीटर और थ्रेसहोल्ड सहित अपनी निगरानी प्रणाली व आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं को अनुकूलित करना चाहिए। एएमसी के पास गलत काम की संभावना और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर की जाने वाली कार्यवाहियों के प्रकारों पर एक दस्तावेजी नीति होनी चाहिए।

7. भारत में एमएसएमई

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) ने मामूली रिकवरी दर्ज की है। MSMEs क्षेत्र के लिए राजस्व पूर्व COVID स्तर से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि वस्तु और सेवा कर नेटवर्क (GSTN) को एमएसएमई को नकद प्रवाह आधारित उधार देने के लिए अकाउंट एग्रीगेटर (AA) ढांचे के तहत वित्तीय सूचना प्रदाता (FIP) के रूप में शामिल किया जाये।

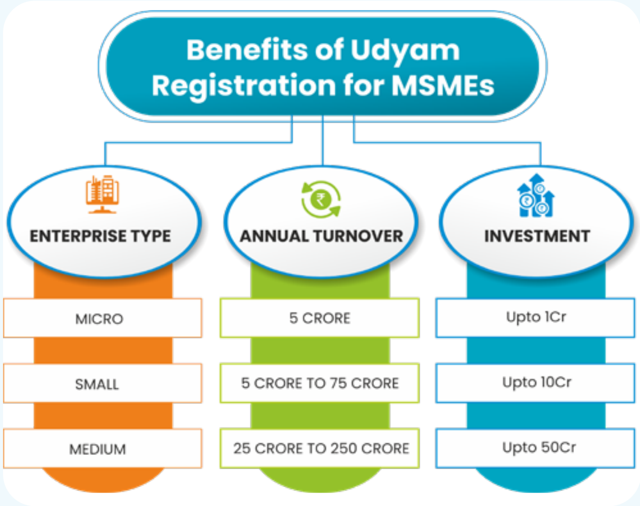

एमएसएमई की परिभाषा:

- **सूक्ष्म उद्यम:** संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं तथा वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं।
- **लघु उद्यम:** संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं तथा वार्षिक कारोबार 50 करोड़ रुपये से अधिक नहीं।
- **मध्यम उद्यम:** संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 50 करोड़ रुपये से अधिक नहीं तथा वार्षिक कारोबार 250 करोड़ रुपये से अधिक नहीं।

MSMEs के संबंध में हालिया विकास:

- हाल के वर्षों में भारत ने तमाम योजनाओं और पहलों के माध्यम से उद्यमिता को सुविधाजनक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है।
- देश में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 2016 में 445 से बढ़कर 2023 में 92,683 हो गई है।
- भारत सरकार की एमएसएमई वार्षिक रिपोर्ट (2022-23) के अनुसार, सूक्ष्म क्षेत्र में 63.05 मिलियन अनुमानित उद्यम हैं जो देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) की कुल अनुमानित संख्या का 99% से अधिक है।
- छोटे क्षेत्र में 0.33 मिलियन उद्यम और मध्यम क्षेत्र में मात्र 5,000 फर्में हैं।
- फरवरी 2023 में, सरकार ने 2023-24 के बजट में घोषणा की कि एक एकीकृत कौशल भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा ताकि मांग-आधारित औपचारिक कौशल, एमएसएमई सहित नियोक्ताओं के साथ जुड़ाव और उद्यमिता योजनाओं तक पहुंच को सुगम बनाया जा सके।
- भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए रैंप (ramp) योजना लांच की जिसका उद्देश्य बाजार और ऋण पहुंच में सुधार करना, केंद्र व राज्य स्तर पर संस्थानों तथा शासन को मजबूत करना, केंद्र-राज्य कनेक्शन तथा साझेदारी में सुधार करना, देर से भुगतान की कठिनाईयों को हल करना और हरित एमएसएमई को बढ़ावा देना है।
- नवंबर 2021 में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय ने उद्यमशीलता और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की।
- एमएसएमई भारत की जीडीपी में लगभग 29 प्रतिशत का योगदान करते हैं और 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं।

आगे की राह:

भारत सरकार ने 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को पांच वर्षों में 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक दोगुना करने की कल्पना की है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में युवा आबादी के लिए करियर के अवसर उत्पन्न कराने होंगे और एमएसएमई में प्रमुख रोजगार जनरेटर के रूप में सेवा करने की क्षमता बढ़ाना होगा। इसलिए, सरकार ने इस क्षेत्र में नए रोजगार सृजित करने के लिए एमएसएमई को बढ़ावा देना शुरू किया है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार को एमएसएमई क्षेत्र के प्रदर्शन में सुधार हेतु और अधिक बैंक तथा वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में निवेश करना चाहिए। इसके साथ ही सरकार को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी काम करना चाहिए।

1. कपिलेश्वर मंदिर एएसआई संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के प्रसिद्ध कपिलेश्वर मंदिर को पुरातत्व विज्ञान सर्वेक्षण (ASI) की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया। एएसआई की संरक्षित स्मारक सूची में कपिलेश्वर मंदिर को लाने के लिए गजट अधिसूचना 5 मई को प्रकाशित हुई थी। यह निर्णय मंदिर के संरचना के बेहतर रखरखाव और संरक्षण के लिए लिया गया है।

कपिलेश्वर मंदिर:

- कपिलेश्वर मंदिर को 14वीं शताब्दी में गजापति कपिलेंद्र देव द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था जिसे अपनी अति सुंदर नक्काशी और भव्य वास्तुकला के लिए जाना जाता है।
- कपिलेश्वर मंदिर वास्तुकला की कलिंग शैली का एक अच्छा उदाहरण है, जो अपनी लालित्य और सादगी के लिए जाना जाता है।
- यह मंदिर, क्षेत्र के समृद्ध इतिहास के साथ-साथ ओडिशा के लोगों की गहन धार्मिक और सांस्कृतिक महत्त्व को परिभाषित करता है।
- कपिलेश्वर शिव मंदिर, जिसे आमतौर पर 'कपिलेश्वर मंदिर' कहा जाता है, ओडिशा राज्य में सबसे पुराने मौजूदा मंदिरों में से एक है।
- इस मंदिर में कपिलस्वारा के नाम पर भगवान शिव की पूजा की जाती है, जो कि 11वीं शताब्दी भुवनेश्वर के पुराने लिंगराज मंदिर से लगभग 1 किमी दूर कपिलप्रसाद क्षेत्र में स्थित है।

भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण:

- एएसआई देश की सांस्कृतिक विरासत के पुरातत्व अनुसंधान और संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है। इसकी स्थापना 1861 ई. में एलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किया गया था।
- एएसआई का प्रमुख कार्य पुरातात्विक स्थलों, प्राचीन स्मारकों और राष्ट्रीय महत्त्व के अवशेषों को सुरक्षित रखना है।
- यह प्राचीन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अनुसार सभी पुरातात्विक गतिविधियों को नियंत्रित करता है।
- यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
- यह पुरातनता और कला खजाना अधिनियम, 1972 को भी नियंत्रित करता है।

धरोहर स्थलों की सुरक्षा हेतु उपाय:

- **प्रौद्योगिकी-सक्षम संरक्षण:** धरोहर स्थलों के प्रलेखन, निगरानी और संरक्षण के लिये उन्नत तकनीकों जैसे- रिमोट सेंसिंग, वर्चुअल रियलिटी व डेटा विश्लेषण का लाभ उठाना।
- **व्यवसाय बढ़ाने हेतु नवीन उपाय:** स्मारकों द्वारा बड़ी संख्या में आगंतुकों को आकर्षित करने तथा उनके सांस्कृतिक महत्त्व को प्रोत्साहित करना।

आगे की राह:

सार्वजनिक-निजी भागीदारी, क्राउड फंडिंग और समुदाय-आधारित फंडिंग जैसे आदि के माध्यम से प्राचीन विरासत स्थलों को संरक्षित करने का प्रयास होना चाहिए। यह धरोहर स्थलों के लिये अतिरिक्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करने और उनका सतत् संरक्षण एवं रख-रखाव सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है।

2. 'सैटेलाइट्स रिवील वाइडस्प्रेड डिक्लाइन इन ग्लोबल लेक वाटर स्टोरेज' रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रकाशित 'सैटेलाइट्स रिवील वाइडस्प्रेड डिक्लाइन इन ग्लोबल लेक वाटर स्टोरेज' नामक एक अध्ययन से पता चला है कि दुनिया भर में आधे से अधिक बड़े झील और जलाशय सूख रहे हैं। जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों को इस संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।

अध्ययन की मुख्य बातें:

- दुनिया के मीठे पानी के भंडार को संरक्षित करने में झीलें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दुनिया की तरल सतह के मीठे पानी का आश्चर्यजनक 87% हिस्सा धारण करने वाले ये निकाय विभिन्न पारिस्थितिक प्रणालियों और मानव जीवन के लिए आवश्यक हैं, परन्तु जलवायु परिवर्तन तथा मानवीय गतिविधियों से इन झीलों को खतरा है।
- हालांकि यह अध्ययन स्थिति की गंभीरता को रेखांकित करता है जो यह दर्शाता है कि इन झीलों की एक बड़ी संख्या को खतरनाक मात्रा में नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।
- मानव गतिविधियों द्वारा पानी की बढ़ती मांग समस्या को और बढ़ा देती है तथा पानी के इन पहले से ही कमजोर निकायों पर अतिरिक्त दबाव डालती है। जलाशयों में भंडारण के नुकसान के प्रमुख कारण के रूप में अवसादन उभरता है, जो प्रभावी रूप से पानी को धारण करने की उनकी समग्र क्षमता को प्रभावित करता है।
- इस अध्ययन से पता चला है कि 1972 में वैश्विक झीलों में से 53% ने 1992-2020 की अवधि में सांख्यिकीय रूप से महत्त्वपूर्ण गिरावट दिखाई दी है।
- पानी के भंडारण में गिरावट से इन पारिस्थितिक तंत्रों और समुदायों को सीधा खतरा है जो पीने के पानी, सिंचाई और मनोरंजन गतिविधियों सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए इन झीलों पर निर्भर हैं।

मानव प्रभाव तथा जल सुरक्षा:

- दुनिया की आबादी का एक-चौथाई या 25% हिस्सा सूखी झील के बेसिन में रहता है, जो इस मुद्दे को संबोधित करने की तात्कालिकता पर बल देता है।
- सतत जल संसाधन प्रबंधन में जलवायु परिवर्तन और अवसादन

प्रभावों को शामिल करना सर्वोपरि हो जाता है।

- वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों की उपलब्धता तथा पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इन कारकों पर विचार करने के महत्त्व पर बल दिया है।

आगे की राह:

झीलों और जलाशयों से 603 घन किलोमीटर पानी खत्म हो गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़े जलाशय लेक मीड में पानी की मात्रा का 17 गुना है। ये आश्चर्यजनक आंकड़े समस्या की भयावहता और समाधान की गंभीर आवश्यकता को उजागर करते हैं।

3. सेन्गोल (Sengol)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नए संसद भवन के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा ऐतिहासिक व पवित्र 'सेन्गोल' की स्थापना किया गया।

'सेन्गोल' राजदंड क्या है?

- 'सेन्गोल' शब्द तमिल शब्द 'सेम्मई' से लिया गया है, जिसका अर्थ है 'नीतिपरायणता-Righteousness'
- सेन्गोल राजदंड एक लंबी छड़ी जैसी वस्तु (5 फीट) है जो चांदी से बनी है जिसकी ऊपरी परत स्वर्ण धातु की है।
- राजदंड के शीर्ष पर एक बैल की नक्काशी है, जिसे नंदी कहा जाता है। यह देश में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण नेतृत्व के महत्त्व के बारे में सभी को याद दिलाता है।
- ऐसा माना जाता है कि तमिलनाडु में एक प्राचीन राज्य चोल राजवंश से इसका संबंध है। इसे तमिलनाडु के एक प्रमुख धार्मिक मठ के मुख्य आधीनम (पुरोहितों) का आशीर्वाद प्राप्त है।
- सेन्गोल राजदंड को जीवंत करने के लिए, चेन्नई के जौहरी वुम्मिदी बंगारू चेट्टी ने इस ऐतिहासिक प्रतीक को तैयार करने का काम किया।

ऐतिहासिक महत्त्व:

'अनाई' आदेश:

- चोल परंपरा में सत्ता के हस्तांतरण समारोह के दौरान राजदंड की प्रस्तुति के अलावा, तमिल में 'अनाई' नामक एक आदेश (तमिल में 'आणई') नए शासक को दिया जाता था।
- यह आदेश क्षेत्र में न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित करने, धर्म के सिद्धांतों के अटूट पालन के साथ शासन करने की जिम्मेदारी का प्रतीक है अर्थात लोगों की सेवा करने के लिए न्याय व निष्पक्षता को सर्वोपरि रखना चाहिए।

सी. राजगोपालाचारी द्वारा दिया गया सुझाव:

- यह वही सेन्गोल है जिसे 14 अगस्त, 1947 की रात को एक विशेष अवसर पर जवाहर लाल नेहरू ने तमिलनाडु के थिरुवदुथुराई आधीनम (मठ) से विशेष रूप से पधारे आधीनमों (पुरोहितों) के साथ सेन्गोल को लॉर्ड माउंटबेटन से प्रतीकात्मक रूप से अंग्रेजों से सत्ता के हस्तांतरण का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राप्त किया था।
- सेन्गोल राजदंड का उपयोग करने का विचार भारत के अंतिम गवर्नर-जनरल सी राजगोपालाचारी ने दिया था। वह प्राचीन चोल वंश में इसी तरह के एक समारोह से प्रेरित थे, जहां सत्ता एक राजा से दूसरे राजा को दी जाती थी।

आगे की राह:

28 मई, 2023 को इतिहास की पुनरावृत्ति हुई, जब नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन के पवित्र प्रतीक सेन्गोल को ग्रहण कर उसे नए संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित किया गया। अपने सांस्कृतिक धरोहर को संजोकर रखना, एक स्वतंत्र देश का कर्त्तव्य होता है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर नये संसद भवन का उद्घाटन और उसमें सेन्गोल की स्थापना निश्चित रूप से गौरव का क्षण है।

4. नदी तट आधारित धार्मिक पर्यटन सर्किट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पूर्वोत्तर भारत में 'नदी तट आधारित धार्मिक पर्यटन सर्किट' विकसित करने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी के साथ सात ऐतिहासिक मंदिरों को जोड़ने वाले एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया गया।

नदी तट आधारित धार्मिक पर्यटन सर्किट:

- इसका उद्देश्य नदी पर्यटन को बढ़ावा देना और असम में पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करना है। यह 'हॉप ऑन हॉप ऑफ-Hop on Hop Off' मोड पर चलने वाली एक आधुनिक फेरी सेवा स्थापित करेगा।
- फेरी टर्मिनल पर यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय में आरामदायक माहौल की आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
- सर्किट में ब्रह्मपुत्र के तट पर सात ऐतिहासिक मंदिरों जैसे-कामाख्या, पांडुनाथ, अश्वकलांता, डौल गोविंदा, उमानंदा, चक्रेश्वर और औनीती सतरा को जोड़ने का प्रस्ताव है।
- ये सेवा हनुमान घाट (उजान बाजार) से आरंभ होगी और सातों धार्मिक स्थलों को 2 घंटे से भी कम समय में पूरा करेगी। इस परियोजना पर 45 करोड़ रुपये की लागत आएगी जो एक साल के भीतर पूरी हो जाएगी।
- **सम्बंधित एजेंसी:** सागरमाला विकास निगम लिमिटेड (SDCL), भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) और असम पर्यटन विकास निगम (ATDC) के बीच धन साझा किया जाएगा।

साइट	आध्यात्मिक महत्त्व
कामाख्या	51 शक्तिपीठों में से एक।
पांडुनाथ	भगवान शिव और पार्वती को समर्पित एक प्राचीन मंदिर।
अश्वकलांता	भगवान विष्णु और उनके अवतार से जुड़ा पवित्र स्थल।
डोल गोविंदा	भगवान कृष्ण को समर्पित जो रास लीला समारोह के लिए जाना जाता है।

- उमानंदा — भगवान शिव को समर्पित उमानंद द्वीप पर स्थित है।
- चक्रेश्वर — भगवान शिव को समर्पित मंदिर वाला पवित्र स्थान।
- औनीती सतरा — प्रमुख वैष्णव मठ और आध्यात्मिक केंद्र।

ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में:

- ब्रह्मपुत्र नदी (स्रोत: चेमायुंगडुंग ग्लेशियर) दक्षिण-पश्चिमी तिब्बत से निकलती है जो सिंधु और सतलुज नदियों के साथ अपने स्रोत क्षेत्र को साझा करती है।
- यह सिंधु-सांगपो संरचना क्षेत्र द्वारा गठित एक अवसाद के माध्यम से बहती है और दिहांग नदी के रूप में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आगे अन्य नदियों में मिल जाने के बाद इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है।
- नदी के बाएं किनारे को धनसिरी, लोहित और दिबांग नदियों द्वारा सिंचित किया जाता है, जबकि दाहिने किनारे पर सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोश नदियाँ मिलती हैं।

आगे की राह:

भारत, ब्रह्मपुत्र के रास्ते ओडीसी और ओडब्ल्यूसी कार्गो मूवमेंट से दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास तक, अंतर्देशीय जलमार्गों की विशाल क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। नदी तट आधारित धार्मिक परियोजना से असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में अंतर्देशीय जलमार्गों की समृद्ध क्षमता विकसित होगी। इससे पहले भी स्वदेश दर्शन योजना, प्रसाद योजना और 'देखो अपना देश' पहल के तहत विभिन्न ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक सर्किटों का विकास किया जा रहा है, जिससे नए भारत के विकास को गति मिलने की संभावना है।

5. प्राचीन तिब्बती बौद्ध ग्रंथों को पुनर्जीवित करने की पहल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के प्रसिद्ध लेखक राहुल सांकृत्यायन द्वारा पहली बार तिब्बत से प्राप्त पांच शास्त्रीय तिब्बती बौद्ध ग्रंथों के लंबे समय से प्रतीक्षित हिंदी अनुवाद अब छपाई के लिए तैयार है। बिहार सरकार ने छपाई लागत के लिए 19.4 मिलियन रुपये में से CIHTS को अब तक 1.55 मिलियन रुपये की प्रारंभिक धनराशि प्रदान किया है।

प्राचीन तिब्बती बौद्ध पांडुलिपियां क्या हैं?

- पवित्र ग्रंथ कर्म विभंग सूत्र, प्रज्ञापारमित्रहृदयसूत्र, आचार्य दीपांकर श्रीज्ञान के 8 संग्रह, मध्यमकलंगकर कारिका भाष्य एवं टीका और अन्य दुर्लभ पांडुलिपियों का सम्पादन शामिल है।
- ये बौद्ध धर्म और उसके दर्शन पर ताड़ के पत्तों पर लिखे गए मूल संस्कृत ग्रंथों के तिब्बती संस्करण हैं।
- ये सैकड़ों खंड ज्योतिष, तंत्र, ध्यान, चिकित्सा, दर्शन, न्याय और कानून सहित विभिन्न विषयों की एक विस्तृत शृंखला को कवर करते हैं।

राहुल सांकृत्यायन:

- राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 ई. में पंडहा (आजमगढ़) में हुआ था जो एक भाषाविद् होने के साथ-साथ रचनात्मक बहुश्रुत भी थे।
- उन्हें संस्कृत, पाली और तिब्बती में धाराप्रवाह के रूप में जाना जाता है, साथ ही वह साहित्य, दर्शन, दुर्लभ पुस्तकों और कला में पारंगत थे।
- सांकृत्यायन ने 10,000 से अधिक तिब्बती पांडुलिपियाँ एकत्र की थीं।

तिब्बती बौद्ध धर्म के बारे में:

- 8वीं शताब्दी CE के अंत में इसे भारत से तिब्बती राजा ठिसोंग देचेन के निमंत्रण पर लाया गया था, जिन्होंने दो बौद्ध आचार्यों को तिब्बत में आमंत्रित किया था।
- सर्व प्रथम भारत में नालंदा के मठाधीश शांतरक्षित आए, उनके बाद पद्मसंभव थे,जिसे गुरु रिनपोछे के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें निंगमा-पा संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा दूसरा बुद्ध माना जाता है।
- तिब्बती बौद्ध धर्म के लिए अद्वितीय तुल्कु (अवतार लामा) की संस्था है, तिब्बत में ऐसे कई लामा हुए हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध दलाई लामा हैं।
- शिक्षक या 'लामा' की स्थिति, जीवन और मृत्यु के बीच संबंध, अनुष्ठानों व दीक्षाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका, समृद्ध दृश्य प्रतीकात्मकता, पहले तिब्बती धर्मों के तत्व, मंत्र और ध्यान अभ्यास हैं।

तिब्बती बौद्ध धर्म समूह	संस्थापक
➢ निंगमा-पा	पद्मसंभव (यह सबसे पुराना संप्रदाय)
➢ काग्यूपा	तिलोपा (988-1069)
➢ सक्यापा	गोंचोक ग्येल्पो (1034-1102)
➢ गेलुग्पा	त्सोंग खापा लोबसंग द्रकपा (1357-1419)

आगे की राह:

इस तिब्बती साहित्य का हिंदी में अनुवाद करने से न केवल बिहार के लोगों, बल्कि पूरे देश को लाभ होगा। इन अनुवादित ग्रंथों में पुरानी नालंदा ज्ञान विरासत के संरक्षण और विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता है। यह बौद्ध धर्म की गहन शिक्षाओं और दर्शन को व्यापक रूप से लोगों तक पहुँचाने का एक सफल प्रयास है।

6. मानव नैदानिक परीक्षण के लिए आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा का उपयोग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिग्पा और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने राष्ट्रीय महत्त्व की कुछ रोग स्थितियों के इलाज में आधुनिक चिकित्सा (साक्ष्य-आधारित चिकित्सा) के साथ आयुर्वेद के उपयोग के लाभों पर साक्ष्य उत्पन्न करने हेतु गुणवत्तापूर्ण

मानव नैदानिक परीक्षण करने के लिए समझौता किया है।

आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा सहयोग के पीछे तर्क:

- दशकों से आयुष प्रणालियों का उपयोग भारत में आधुनिक चिकित्सा के पूरक या वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में किया जाता रहा है।
- हालांकि मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में आयुष की स्वीकृति और एकीकरण में वैज्ञानिक सत्यापन की कमी एक बड़ी बाधा रही है।
- नैदानिक परीक्षण करने में आईसीएमआर की विशेषज्ञता से पिछले अध्ययनों की सीमाओं को दूर करने में मदद मिलने की उम्मीद है, जिसमें वैज्ञानिक सत्यापन का अभाव था।

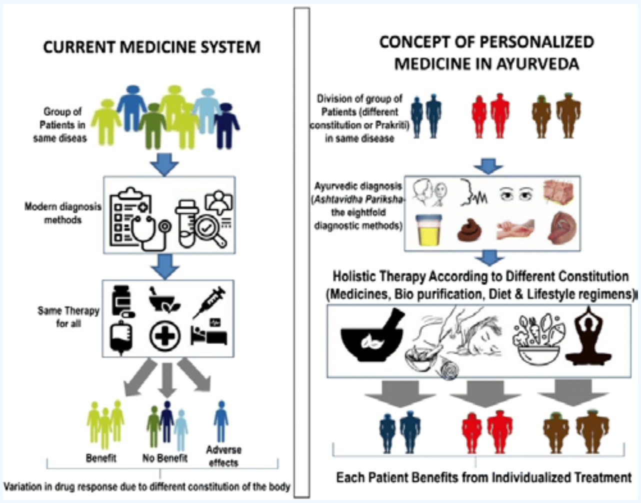

आयुष और आईसीएमआर के बीच सहयोगी पहल का महत्त्व:

आईसीएमआर की विशेषज्ञता स्थापित:

- यह सहयोग गुणवत्तापूर्ण मानव नैदानिक परीक्षणों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- मानव नैदानिक परीक्षणों के संचालन में आईसीएमआर के व्यापक अनुभव से वैश्विक मानकों को पूरा करने वाले गुणवत्ता परीक्षणों को डिजाइन करने और कार्यान्वित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।
- आईसीएमआर की भागीदारी एक महत्त्वपूर्ण लाभ है जो अतीत में किए गए परीक्षणों की प्रमुख कमियों को दूर करने में मदद कर सकता है।

संयुक्त चिकित्सा का वैज्ञानिक सत्यापन:

- इस पहल का एक अन्य अनिवार्य पहलू आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा के संयोजन का वैज्ञानिक सत्यापन है।
- इस सहयोग के तहत किए गए परीक्षणों से आयुर्वेद को आधुनिक चिकित्सा के साथ एकीकृत करने के लाभों पर पर्याप्त सबूत मिलने की उम्मीद है।

हेल्थकेयर सिस्टम के लिए निहितार्थ:

पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा का एकीकरण:

- यह सहयोग संभावित रूप से एकीकृत चिकित्सा हस्तक्षेप के विकास का कारण बन सकता है जो पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा दोनों के सर्वोत्तम रूप को जोड़ता है।
- इस एकीकरण से नए उपचार और उपचारों का विकास हो सकता है जो अधिक प्रभावी व कम दुष्प्रभावी हैं।

रोगी के परिणामों में सुधार और स्वास्थ्य देखभाल लागत में कमी:

- एकीकृत चिकित्सा हस्तक्षेप रोगियों को बेहतर परिणाम प्रदान कर सकते हैं।
- इससे स्वास्थ्य देखभाल की लागत कम हो सकती है, क्योंकि रोगियों को अस्पताल में भर्ती होने और चिकित्सा प्रक्रियाओं की कम आवश्यकता हो सकती है।

वैकल्पिक चिकित्सा की स्वीकृति में वृद्धि:

- इस सहयोग से मुख्यधारा के चिकित्सा समुदाय द्वारा वैकल्पिक चिकित्सा की स्वीकृति में भी वृद्धि हो सकती है।
- आयुर्वेद को आधुनिक चिकित्सा के साथ मिलाने के फायदों की वैज्ञानिक मान्यता से वैकल्पिक चिकित्सा के प्रति कुछ चिकित्सा पेशेवरों के संदेह को दूर करने में मदद मिल सकती है।

आगे की राह:

आयुर्वेद को आधुनिक चिकित्सा के साथ मिलाने के लाभों का अध्ययन करने के लिए गुणवत्तापूर्ण मानव नैदानिक परीक्षण करने हेतु आयुष और आईसीएमआर के बीच सहयोग एक स्वागत योग्य पहल है जिसका भारत में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लिए दूरगामी प्रभाव हो सकता है।

7. वुल्फ-डॉग हाइब्रिडाइजेशन

चर्चा में क्यों?

ग्रासलैंड ट्रस्ट के सिटीजन साइंटिस्ट एण्ड रिसर्चर्स ने पुणे (भारत) में वुल्फ-डॉग हाइब्रिडाइजेशन का पहला फोटो-आधारित साक्ष्य पाया है। यह शोध भारत के प्रायद्वीपीय भाग में स्थित सिटीजन साइंस फैसिलिटीज (इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन जर्नल में प्रकाशित) के निष्कर्षों पर आधारित है।

वुल्फ-डॉग हाइब्रिडाइजेशन:

- वुल्फ-डॉग हाइब्रिड एक शब्द है जिसका उपयोग भेड़िये और घरेलू कुत्ते के बीच संभोग के परिणामस्वरूप होने वाली संतानों की पहचान के लिए किया जाता है।
- सिटीजन रिसर्चर्स ने एक संदिग्ध भेड़िया-कुत्ते संकर (वुल्फ-डॉग हाइब्रिड) जानवर को एक असामान्य रूप से पीले रंग के कोट के साथ पाया है जिसे एक तस्वीर में कैद किया गया था।
- इनके बालों की लटों पर आधारित अनुसंधान और आगे के तुलनात्मक जीनोम अनुक्रमण अध्ययन से प्रायद्वीपीय भारत में भेड़िया-कुत्ते के संकरण की घटना का पता चला है।

सिटीजन साइंस एंड रिसर्चर्स:

- सिटीजन साइंस एक वैज्ञानिक शोध है जो आम जनता की भागीदारी से किया जाता है। इस अभ्यास में जनता के वैज्ञानिक ज्ञान को

बढ़ाने के लिए सार्वजनिक सहयोग का संचालन किया जाता है। सिटीजन रिसर्चर एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो सिटीजन रिसर्चर प्रोजेक्ट (नागरिक शोधकर्ता परियोजना) में भाग लेता है।

- यह अनुसंधान अध्ययन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज के सहयोग से आयोजित किया जाता है जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के तहत एक प्रमुख शोध केंद्र है।

वुल्फ-डॉग हाइब्रिडाइजेशन के कारणः

- मानव आवासों के विस्तार से वन्यजीवों के आवासों का विखंडन हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप जंगली (पालतू) और वन्यजीव जानवरों के बीच परस्पर क्रियाओं की संख्या बढ़ रही है।
- इस तरह का संकरण जंगली भेड़ियों की आबादी के लिए खतरा पैदा कर सकता है और भेड़ियों के पैक की सामाजिक संरचना को बाधित करता है।

शोध के परिणामः

- शोधकर्ताओं ने विश्लेषण किया है कि ये संकर मृत सिरें (Infertile) नहीं हैं क्योंकि कैनिड्स या केनाइन (कुत्ते, भेड़िये, गीदड़, लोमड़ी आदि) के नर और मादा दोनों उपजाऊ (Fertile) होते हैं।
- लेकिन आगे इंटरब्रीडिंग से जंगल में आनुवंशिक विविधता कम हो जाएगी। यह संभव हो सकता है कि भेड़ियों को जंगल में जीवित रहने में सक्षम बनाने वाली प्रमुख आनुवंशिक विशेषताएं कुत्ते के जीन के अंतर्मुखीकरण (Introgression) के कारण समझौता कर सकती हैं।

इंडियन ग्रे वुल्फ के लिए खतराः

- शोधकर्ताओं ने संदेह जताया है कि इस प्रकार का संकरण भारतीय ग्रे भेड़िया के लिए खतरा पैदा करेगा।
- भारतीय वन्यजीव संस्थान ने बताया कि प्रायद्वीपीय भारत में 3,100 भेड़िये हैं। भारतीय ग्रे भेड़िये पहले से ही भारतीय वन्यजीव अधिनियम- 1972 की अनुसूची-I में एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध हैं।
- इन्हें राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में विस्तारित किया जा रहा है। ये घास के मैदानों की शीर्ष परभक्षी प्रजातियां हैं।

आगे की राहः

शोधकर्ताओं ने इस परिदृश्य पर ध्यान दिया है कि अगर नियंत्रित नहीं किया गया तो भेड़ियों की आबादी में भारी कमी आएगी। इसलिए ट्रैकिंग, निगरानी और शिकार के आधार का आंकलन करने तथा मानव और वन्यजीवों के बीच संबंधों की समझ को बढ़ाने की आवश्यकता है।

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

एक ही प्रयास में IAS / PCS में सफलता प्राप्त करने की रणनीति

OPEN SEMINAR
for
IAS / PCS
11 JUNE | 4:30 PM

NEW BATCH
GS PRE-CUM-MAIN
12 JUNE
हिन्दी माध्यम 10:00 AM
English Medium 4:00 PM

GREATER NOIDA

MAIN CRASH COURSE
NEW BATCH
14 JUNE | 1:30 PM

Join UDAAN
A journey to success
12th के साथ, GRADUATION के दौरान, IAS बनने का सपना करें साकार
Qualify IAS in 1st Attempt

4th FLOOR, VEERA TOWER, ALPHA 1, COMMERCIAL BELT, GREATER NOIDA, U.P. 201308
9205336037 / 38

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की महत्त्वपूर्ण खबरें

1. 50 स्टार्ट-अप एक्सचेंज प्रोग्राम

- भारत-बांग्लादेश ने अपने उद्यमी समुदायों के बीच सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एक स्टार्ट-अप विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य ई-कॉमर्स, स्वास्थ्य, परिवहन और रसद, ऊर्जा, शिक्षा तथा कौशल विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अवसरों का पता लगाना, ज्ञान साझा करना और सहयोग बढ़ाना है। कार्यक्रम की रूपरेखा भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित की गयी थी।
- विनिमय कार्यक्रम में भाग लेने वाले बांग्लादेशी स्टार्ट-अप्स को भारत की 'स्टार्ट-अप इंडिया' पहल से परिचित कराया गया, जिससे स्टार्ट-अप की स्थापना और विकास के विभिन्न पहलुओं पर अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। भारत में 10 बांग्लादेशी स्टार्ट-अप्स की यात्रा ने विनिमय कार्यक्रम की शुरुआत को चिह्नित किया, जिससे दोनों देशों के उद्यमी समुदायों के बीच भविष्य की यात्राओं और सहयोग का मार्ग प्रशस्त हो।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य नए और उभरते क्षेत्रों, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता तथा नवाचार में सहयोग बढ़ाना है।
- यह स्टार्ट-अप्स अनुभव को साझा करने, साझेदारी बनाने और एक-दूसरे की सफलताओं तथा चुनौतियों से सीखने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- भारत-बांग्लादेश स्टार्ट-अप के बीच सहयोग में दोनों देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, नौकरी के अवसर पैदा करने और नवाचार को बढ़ावा देने की क्षमता है।

2. गैर-चीनी मिठास (Non-Sugar Sweeteners)

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अस्वास्थ्यकर वजन बढ़ने से रोकने और गैर-संचारी रोगों (NCD) के जोखिम को कम करने के लिए गैर-संचारी रोग (Non-Communicable Diseases) के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
- डिब्बाबंद भोजन और पेय पदार्थों में आमतौर पर गैर-चीनी मिठास जैसे-एस्पार्टेम, स्टीविया और सकरीन का उपयोग चीनी के विकल्प के रूप में किया जाता है।
- डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देश बताते हैं कि एनएसएस वजन नियंत्रण के लिए दीर्घकालिक लाभ प्रदान नहीं करता है जिसके अवांछित प्रभाव हो सकते हैं, जिसमें टाइप 2 मधुमेह, हृदय रोग और मृत्यु दर का बढ़ता जोखिम शामिल है।
- एनएसएस में पोषण मूल्य की कमी होती है जिसे आवश्यक आहार कारक नहीं माना जाता है। चीनी के सेवन को कम करने के वैकल्पिक तरीके जैसे कि फलों का सेवन या बिना चीनी वाले भोजन और पेय पदार्थों का पता लगाया जाना चाहिए।
- पहले से मौजूद मधुमेह वाले व्यक्तियों को छोड़कर एनएसएस के लिए दिशानिर्देश सामान्य आबादी पर लागू होती है।
- इसमें लो-कैलोरी शुगर या शुगर एल्कोहल शामिल नहीं है, जो एनएसएस से अलग हैं।
- यह दिशानिर्देश विशेष रूप से खाद्य और पेय पदार्थों में एनएसएस की खपत से संबंधित है जो व्यक्तिगत देखभाल और स्वच्छता उत्पादों में उनके उपयोग तक विस्तृत नहीं है।
- WHO का उद्देश्य एनसीडी के जोखिम को कम करने और आजीवन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एनएसएस के उपयोग को हतोत्साहित करके दुनिया भर में स्वस्थ खाने की आदतों को बढ़ावा देना तथा आहार की गुणवत्ता में सुधार करना है।

3. खासी जनजाति

- खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (KHADC) ने एक निर्देश जारी किया है कि खासी वंश के व्यक्ति जो अपने पिता का उपनाम अपनाते हैं, अनुसूचित जनजाति (ST) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।
- जयंतिया और गारो के साथ खासी मेघालय में तीन स्वदेशी मातृसत्तात्मक समुदायों में से एक हैं।
- **मातृसत्तात्मक समाज:** खासी समाज की मातृसत्तात्मक प्रणाली का पालन करते हैं, जहां माता के माध्यम से वंश और विरासत का पता लगाया जाता है। सबसे छोटी बेटी, जिसे 'का खद्दूह' के रूप में जाना जाता है, विरासत में संपत्ति की हकदार होती है।
- इसके अधिकांश लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं, जिनकी पारंपरिक मान्यताएं यू ब्ली नोंगथाव नामक व्यक्ति के अनुसार संचालित होती हैं।
- **त्यौहार:** खासी विभिन्न त्यौहार मनाते हैं जिसमें नोंगक्रेम नृत्य और शाद सुक म्यन्सीम शामिल हैं, जो पारंपरिक संगीत, नृत्य और अनुष्ठानों का प्रदर्शन करते हैं।

4. ओडिशा मिलेट मिशन

- ओडिशा मिलेट मिशन (OMM) ओडिशा सरकार द्वारा बाजरे की खेती को पुनर्जीवित करने और किसानों को समर्थन देने के लिए एक महत्त्वपूर्ण पहल है।
- ओएमएम ओडिशा मिलेट मिशन के तहत 600,000 क्विंटल से अधिक रागी की सफलतापूर्वक खरीद की गई है, जिससे किसानों को उनकी उपज के लिए एक सुरक्षित बाजार मिल रहा है। यह खरीद 3,578 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की गई है।

- कोरापुट, रायगढ़ा, मल्कानगिरी, कालाहांडी, गजपति और सुंदरगढ़ सहित ओडिशा के दक्षिणी जिलों में सबसे अधिक रागी की खरीद हुई है।
- सिस्टम ऑफ मिलेट इंटेन्सिफिकेशन (SMI) पद्धति को अपनाने से उपज में सुधार हुआ है जिससे किसान अब प्रति एकड़ लगभग 5-6 क्विंटल की कटाई कर रहे हैं।
- ओडिशा मिलेट मिशन से जुड़े किसानों के बीच उन्नत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने में स्थानीय गैर-लाभकारी, समुदाय-आधारित संगठनों और कृषि विशेषज्ञों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- किसानों को कुशल प्रबंधन और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए बाजरा खरीद व बिक्री (MPAS) ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है।

5. 75/25 पहल

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने '75/25' पहल की शुरुआत की है, जो भारत में गैर-संचारी रोगों (NCD) के प्रबंधन और रोकथाम में क्रांति लाने के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी कार्यक्रम है।
- **लक्ष्यः** इस पहल का उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) पर ध्यान देने के साथ 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह वाले 75 मिलियन व्यक्तियों के लिए मानकीकृत देखभाल सुनिश्चित करना है।
- **प्रशिक्षण चिकित्सा अधिकारीः** लगभग 40,000 प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सा अधिकारियों को सशक्त पोर्टल के माध्यम से एनसीडी के लिए मानक उपचार कार्यप्रवाह में प्रशिक्षित किया जाएगा।
- यह प्रशिक्षण स्वास्थ्य पेशेवरों को सामुदायिक स्तर पर बेहतर सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।

6. मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना

- मध्य प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 'मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना' (Chief Minister Learn and Earn Scheme) को मंजूरी दी है।
- **विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकासः** यह योजना इंजीनियरिंग, होटल प्रबंधन, पर्यटन, आईटीआई, बैंकिंग, बीमा आदि क्षेत्रों में लगभग 700 विभिन्न प्रकार के कार्यों में प्रशिक्षण प्रदान करती है, जिससे युवाओं को अपनी रुचि के अनुरूप क्षेत्रों का चयन करने में मदद मिलती है।
- सरकार भी सक्रिय रूप से स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है।
- नियमित रोजगार दिवस सरकारी गारंटी और ब्याज सब्सिडी द्वारा समर्थित स्व-रोजगार के लिए ऋण प्रदान करते हैं, जिससे हर महीने लगभग 2.5 लाख युवाओं को लाभ मिलता है।

7. कलवरी क्लास पनडुब्बी

- भारतीय नौसेना की छठी और अंतिम कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी, वाघशीर (Vaghsheer) ने अपना समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया है।
- वाघशीर इन परीक्षणों के पूरा होने के बाद इसे 2024 की शुरुआत में शामिल किया जायेगा।
- ऐसे समय में नौसेना की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट-75 के तहत बनी पनडुब्बी को इसमें शामिल करना है, जब चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है।

परियोजना-75:

- प्रोजेक्ट-75 भारतीय नौसेना के लिए छह उन्नत पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण और अधिग्रहण की भारत की महत्त्वाकांक्षी योजना को संदर्भित करता है।
- इस परियोजना का उद्देश्य देश की नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाना और अपनी समुद्री रक्षा रणनीति को मजबूत करना है।

8. ऑपरेशन ध्वस्त

- राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन ध्वस्त के तहत किए गए राष्ट्रव्यापी छापेमारी में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये छापे आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों से जुड़े नेटवर्क के लिए है।
- स्थानीय पुलिस के साथ एक समन्वित अभियान में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में 129 स्थानों पर छापे मारे गए।
- एनआईए की कार्यवाहियां आतंकवादी नेटवर्क और उनके समर्थन बुनियादी ढांचे को खत्म करने के चल रहे प्रयासों का हिस्सा हैं।
- एजेंसी अगस्त 2022 से तीन मामलों की जांच कर रही हैं, जिसमें लक्षित हत्याएं, खालिस्तान समर्थक संगठनों के लिए आतंकी फंडिंग और जबरन वसूली शामिल हैं।
- विभिन्न राज्यों की जेलों में साजिश रची जा रही थी और एक संगठित नेटवर्क द्वारा अंजाम दिया जा रहा था जिसमें विदेशों में स्थित ऑपरेटिव शामिल थे।
- कुछ अपराधी जो पाकिस्तान, कनाडा, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भाग गए थे, गंभीर अपराधों की योजना बनाने के लिए जेल में बंद व्यक्तियों के साथ सहयोग कर रहे हैं।

9. स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कानून

- हाल ही में केरल कैबिनेट ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए नये कानून को मंजूरी दी।
- यह हिंसा के कृत्यों के लिए कठोर दंड का प्रावधान करता है।
- इसमें हिंसा करने का प्रयास करने वाले या दूसरों को हिंसा करने के लिए उकसाने वाले अपराधियों को 50,000 से 2 लाख रुपये तक के जुर्माने के साथ-साथ छह महीने से लेकर पांच साल तक के कारावास का प्रावधान है।
- गंभीर शारीरिक हिंसा करने वालों को एक से सात साल की कैद और 1 लाख से 5 लाख रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
- यह संशोधन 60 दिनों की समय-सीमा के साथ एक इंस्पेक्टर से कम रैंक वाले पुलिस अधिकारियों द्वारा कुशल जांच भी सुनिश्चित करता है।
- इन परीक्षण प्रक्रियाओं को एक वर्ष के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
- स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा से संबंधित मामलों को संभालने के लिए प्रत्येक जिले में विशेष अदालतें नामित की जाएंगी।
- इस संशोधन में पैरामेडिकल छात्रों, कर्मचारियों, सुरक्षा गार्डों और अस्पतालों में काम करने वाले अन्य लोगों को शामिल करने के लिए

10. फोरम शॉपिंग

- हाल ही में CJI चंद्रचूड़ ने 'फोरम शॉपिंग' की आलोचना की।

फोरम शॉपिंग क्या है?

- फोरम शॉपिंग तब होती है जब वादी या वकील अधिक अनुकूल फैसले की उम्मीद में जानबूझकर अपने मामले को किसी विशिष्ट न्यायाधीश या अदालत में स्थानांतरित करने की याचिका करते हैं।
- वकील उपयुक्त मंच को अपनी मुकदमेबाजी की रणनीति के हिस्से के रूप में मानते हैं, जैसे की अधिक ध्यान आकर्षित करने के लिए जनहित याचिका मामले के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में जाना आदि।
- हालांकि सामान्य प्रक्रिया को दरकिनार करने या किसी विशिष्ट न्यायाधीश से बचने के जबरदस्त प्रयासों को दूसरे पक्ष के साथ हुए अन्याय और कुछ अदालतों पर संभावित बोझ के कारण अस्वीकार कर दिया जाता है।
- यह अदालतों को अधिकार क्षेत्र से इंकार करने और न्याय के हित में मामले को अधिक उपयुक्त मंच पर निर्देशित करने की विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करता है।

विभिन्न न्यायालय के निर्णय:

- 1988 के 'चेतक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड बनाम ओम प्रकाश' के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि वादी अपना मंच नहीं चुन सकते हैं और घोषित किया कि फोरम शोपिंग के हर प्रयास का कड़ा विरोध किया जाना चाहिए।
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने फोरम हंटिंग में लिप्त पाई गई कंपनियों पर जुर्माना लगाया है, जो कानूनी प्रणाली में हेरफेर प्रथाओं को रोकने के लिए अदालत की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। 'बेंच हंटिंग' फोरम शॉपिंग से जुड़ा एक और शब्द है, जहां याचिकाकर्ता एक अनुकूल आदेश सुरक्षित करने के लिए एक विशिष्ट न्यायाधीश या अदालत की तलाश करते हैं।

11. रक्षा उत्पादन क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण वृद्धि का संकेत

- देश में रक्षा उत्पादन का मूल्य पहली बार 1 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है, जो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि का संकेत है।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में रक्षा उत्पादन का मूल्य 1,06,800 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष 95,000 करोड़ रुपये और पांच साल पहले 54,951 करोड़ रुपये था।

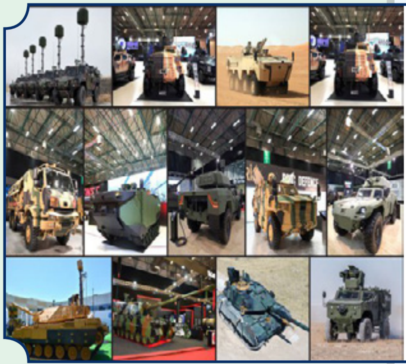

- भारत रक्षा विनिर्माण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर निम्न उपायों को लागू कर रहा है:
  - आयात प्रतिबंध।
  - घरेलू खरीद के लिए एक अलग बजट।
  - प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि।
  - व्यापार करने में आसानी।
- सरकार की नीतियों ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) और स्टार्ट-अप सहित उद्योगों की भागीदारी में वृद्धि की है, जिसके परिणामस्वरूप जारी किए गए रक्षा लाइसेंसों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- 2021 में आयुध निर्माणी बोर्ड (OFB) के निगमीकरण ने भी रक्षा उत्पादन दक्षता और प्रतिस्पधात्मकता को बढ़ाने में योगदान दिया है। वित्त वर्ष 2022-23 में सैन्य हार्डवेयर निर्यात 15,920 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचने के साथ भारत का ध्यान रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने पर है, जिसमें हाल के वर्षों में महत्त्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है।
- भारत कई देशों को हथियारों और प्रणालियों की एक श्रृंखला का निर्यात कर रहा है, जिसमें मिसाइल, तोपखाने की बंदूकें, रॉकेट, वाहन, रडार, निगरानी प्रणाली और गोला-बारूद शामिल हैं।

12. मेथामफेटामाइन

- हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) और भारतीय नौसेना ने केरल तट पर एक संयुक्त अभियान चलाया। इस अभियान के परिणामस्वरूप लगभग 15,000 करोड़ रुपये मूल्य का 2,500 किलोग्राम मेथामफेटामाइन जब्त किया गया।
- मेथामफेटामाइन (जिसे आमतौर पर मेथ के रूप में जाना जाता है) एक अत्यधिक नशे के लिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उत्तेजक दवा है।
- यह दवाओं के एम्फैटेमिन वर्ग से संबंधित है जो रासायनिक रूप से एम्फैटेमिन के समान है।
- मेथामफेटामाइन आमतौर पर अवैध प्रयोगशालाओं में निर्मित होता है और एक सफेद क्रिस्टलीय पाउडर के रूप में आता है जिसे सूंघकर, धूम्रपान, इंजेक्शन या मौखिक रूप से लिया जा सकता है।
- भारत में किसी भी दवा-विरोधी प्रवर्तन एजेंसी द्वारा मौद्रिक मूल्य के मामले में इस दवा की जब्ती अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है।
- यह अभियान 'ऑपरेशन समुद्रगुप्त' का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री मादक पदार्थों की तस्करी को खत्म करना है।

13. क्रॉस-बॉर्डर ट्रेड बूस्ट

- पाकिस्तान और ईरान ने पाकिस्तान-ईरान सीमा के मंड-पाशिन क्रॉसिंग पॉइंट पर पहले बॉर्डर मार्केट का उद्घाटन किया। इस बॉर्डर मार्केट का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सीमा पार व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

- पाकिस्तान के दूर-दराज के इलाकों में ईरानी जनित बिजली उपलब्ध कराने के लिए एक नई विद्युत पारेषण लाइन शुरू की गई।
- यह संयुक्त उद्घाटन बलूचिस्तान और सिस्तान-ओ-बलूचिस्तान प्रांतों में निवासियों के कल्याण के लिए पाकिस्तान व ईरान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- ये पहलें द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करती हैं और उनके सहयोग को आगे बढ़ाने का काम करती हैं।
- नया बॉर्डर मार्केट (जिसे मांड-पाशिन बॉर्डर सस्टेनेंस मार्केटप्लेस कहा जाता है) ईरान के सिस्तान-ओ- बलूचिस्तान प्रांत में पाशिन शहर से सटे मांड शहर (बलूचिस्तान प्रांत) में स्थित है।
- 959 किमी लंबी पाकिस्तान-ईरान सीमा पर मांड-पाशिन बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट तीसरा है।

समसामयिकी घटनाएं एक नजर में

1. हाल ही में शिक्षाविद् मनोज सोनी ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली।
2. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और पैनासिया बायोटेक ने अपने स्वदेशी डेंगू वैक्सीन के लिए सहयोगी चरण-III नैदानिक परीक्षणों के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) को आवेदन किया है।
3. अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने मौलवी अब्दुल कबीर को कार्यवाहक प्रधानमंत्री और कैबिनेट के अंतरिम प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। यह निर्णय तालिबान शासन के कार्यवाहक प्रमुख के खराब स्वास्थ्य के कारण अफगान तालिबान के सर्वोच्च नेता द्वारा लिया गया था।
4. बेनिन और माली ने अपने देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में सफलतापूर्वक ट्रेकोमा को समाप्त घोषित किया।
5. डब्ल्यूएचओ द्वारा सुझाई गई सुरक्षित रणनीति (सर्जरी, एंटीबायोटिक्स, चेहरे की सफाई, पर्यावरण सुधार) ने ट्रेकोमा से निपटने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ट्रेकोमा क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस के कारण होता है जो आंख और नाक के स्राव के साथ-साथ मक्खियों से भी फैलता है।
6. हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य की सड़कों पर गड्ढों के मुद्दे को हल करने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा विकसित 'पैच रिपोर्टिंग ऐप' लांच किया।
7. हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य को हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य के साथ 'ग्रीन हाइड्रोजन नीति' तैयार करने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश में प्रचुर मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन जैसे सूरज की रोशनी, पानी और हवा हैं जो इसे हरित हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं।
8. रय्याना बरनावी और अली अल-कर्नी ने 21 मई 2023 को स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर सवार होकर अंतरिक्ष में पहली अरब महिला यात्री के रूप में इतिहास रचा।
9. हाल ही में प्रवीण सूद ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया।
10. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) लिमिटेड ने जहाज निर्माण में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए GAINS 2023 पहल शुरू की है। GAINS 2023 का उद्देश्य स्टार्टअप्स की क्षमता का दोहन करना और जहाज के डिजाइन व निर्माण में नवीन समाधानों को प्रोत्साहित करना है।
11. नीरज चोपड़ा, पुरुषों की भाला फेंक रैंकिंग में विश्व में नंबर एक खिलाड़ी बन गए। ग्रेनाडा के मौजूदा विश्व चौंपियन एंडरसन पीटर्स (1433) से 22 अंक आगे नीरज चोपड़ा 1455 अंकों के साथ चार्ट में सबसे ऊपर हैं।
12. हाल ही में नाइजीरिया ने डांगोट रिफाइनरी चालू की है। इस रिफाइनरी का लक्ष्य नाइजीरिया में लगातार ईंधन की कमी को दूर करना है, जो अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है।
13. हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2021 के दौरान 1.52 की तुलना में 2022 की समान अवधि के दौरान 6.19 मिलियन विदेशी पर्यटक का आगमन हुआ।
14. भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी (PCIM-H) के फार्माकोपिया आयोग के ई-ऑफिस पोर्टल का उद्घाटन केंद्रीय आयुष मंत्री द्वारा किया गया। यह पोर्टल मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण और ASU-H दवाओं के उचित उपयोग के लिए दिशानिर्देश प्रदान करने, पारंपरिक औषधीय प्रथाओं में सुरक्षा, प्रभावकारिता व एकरूपता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
15. जॉर्जी गोस्पोडिनोव द्वारा लिखित और एंजेला रोडेल द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित उपन्यास 'टाइम शेल्टर' ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जीता। यह पहली बार है जब बल्गेरियाई में मूल रूप से प्रकाशित किसी उपन्यास ने वार्षिक पुरस्कार जीता है। पिछले साल यह पुरस्कार गीतांजलि श्री के 'रेत के मकबरे' को मिला, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया था।
16. हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि केरल ने भारत का पहला पूर्ण रूप से ई-शासित राज्य बनने का गौरव हासिल कर लिया है। इस व्यापक ई-गवर्नेंस पहल के तहत केरल सरकार का लक्ष्य सेवाओं को सीधे जनता तक पहुंचाना है, जिससे नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता बहुत कम हो जाती है।
17. केंद्र सरकार ने बॉम्बे तथा मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्रमशः जस्टिस आर. डी. धानुका और एस. वी. गंगापुरवाला की नियुक्ति को मंजूरी दिया।
18. शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश में एक नई वृक्ष प्रजाति की खोज की है जिसका नाम मेयोगिने अरुणाचलेंसिस रखा है, जो इस क्षेत्र की समृद्ध वनस्पतियों को दर्शाता है।

जन जैव विविधता रजिस्टर

चर्चा में क्यों?

जन जैव विविधता रजिस्टर पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (PBR) के अपडेशन और सत्यापन के लिए राष्ट्रीय अभियान 22 मई (विश्व जैव विविधता दिवस) को गोवा में शुरू किया गया।

लक्ष्य

इसका उद्देश्य मिशन लाइफ के तहत भारत के हर गांव में एक पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर स्थापित करना है।

इसका क्या अर्थ है?

- पीबीआर किसी विशेष क्षेत्र या गांव के स्थानीय रूप से उपलब्ध जैव-संसाधन का एक व्यापक रिकॉर्ड है।
- जैव-संसाधन में किसी भी क्षेत्र के सभी संसाधन और जनसांख्यिकी शामिल होते है।
- यह जैव विविधता प्रबंधन समितियों द्वारा स्थानीय समुदायों के परामर्श से तैयार किया जाता है।

पीबीआर का भविष्य

पीबीआर के राष्ट्रीय अभियान निम्नलिखित क्षेत्रों में सहायता करेंगे:

- आवास परिवर्तन का पता लगाना।
- बायोपायरेसी को रोकना।
- सांस्कृतिक और प्राकृतिक जैव विविधता के ओवरलैप को समझना।
- कार्यकारी अभ्यास में समावेशी दृष्टिकोण को बढ़ावा देना।

उद्देश्य

- पीबीआर उचित सत्यापन के साथ, स्थानीय ज्ञान के औपचारिक रखरखाव के लिए एक व्यवस्था के रूप में डिजाइन किया गया है।
- इसके अंतर्गत एक गांव या पंचायत में प्राकृतिक संसाधनों, पौधों और जानवरों, उनके उपयोग और संरक्षण के बारे में लोगों के ज्ञान, धारणा, दृष्टिकोण का भी रिकॉर्ड तैयार करना है।

जैव विविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी)

- बीएमसी का गठन जैव विविधता अधिनियम 2002 के अनुसार किया गया है।
- वे देश भर में स्थानीय निकायों द्वारा 'संरक्षण, टिकाऊ उपयोग और जैविक विविधता के प्रलेखन को बढ़ावा देने' के लिए बनाए गए हैं।
- इनका गठन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थानीय निकायों द्वारा किया गया है।
- उन्हें स्थानीय समुदायों के परामर्श से पीबीआर तैयार करने का काम सौंपा गया है।
- इसका नेतृत्व स्थानीय निकाय द्वारा नामित एक अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।
- समिति के सदस्य 6 व्यक्तियों से अधिक नहीं हो सकते हैं, जिसमें 1/3 और 18% क्रमशः महिलाओं और एससी/एसटी से संबंधित होने चाहिए।

भारत में पीबीआर की स्थिति

- विभिन्न राज्यों में जैव विविधता प्रबंधन समितियों द्वारा 2,67,608 पीबीआर तैयार किए गए हैं।
- वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भी पीबीआर को डिजिटलाइज (ई-पीबीआर) करने के लिए एक कार्यक्रम चला रहा है।
- कोलकाता एक विस्तृत पीबीआर तैयार करने वाला पहला महानगरीय शहर बना है।

इसका महत्व क्या है?

- पीबीआर भारत की समृद्ध जैव विविधता के प्रलेखन और संरक्षण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- यह स्थानीय लोगों के बौद्धिक संपदा अधिकारों और आनुवंशिक संसाधनों से प्राप्त लाभों के बीच की खाई को पाटने की दिशा में पहला कदम है।
- यह जैव विविधता के बारे में पारंपरिक ज्ञान एकत्रित करता है और स्थानीय समुदायों को उन लाभों को साझा करने में सक्षम बनाता है।
- यह मिशन LiFE (लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट) के दृष्टिकोण के अनुसार तैयार किया गया है।
- यह पर्यावरण केंद्रित रणनीतियों के प्रदर्शन स्तर को ट्रैक करने के लिए एक मानक के रूप में भी कार्य करता है।

अंतर्राष्ट्रीय रोगजनक निगरानी नेटवर्क

चर्चा में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 जैसी संक्रामक बीमारियों के खतरे का तेजी से पता लगाने और उनके प्रसार को रोकने के लिए जानकारी साझा करने में मदद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोगजनक निगरानी नेटवर्क (International Pathogen Surveillance Network-IPSN) नामक एक वैश्विक नेटवर्क लॉन्च किया गया।

अन्य जानकारी

- कोविड-19 ने महामारी के खतरों का सामना करने में पैथोजन जीनोमिक्स की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।
- सार्स सीओवी-2 (SARS CoV-2) वायरस के तेजी से अनुक्रमण के बिना, टीके उतने प्रभावी नहीं होते, न ही जल्दी उपलब्ध होते।
- जीनोमिक्स, प्रभावी महामारी के प्रतिरोध की तैयारी और प्रतिक्रिया के केंद्र में होते हैं।
- आईपीएसएन ऐसी चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगा, क्योंकि यह प्रत्येक देश को अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के हिस्से के रूप में रोगजनक जीनोमिक अनुक्रमण और विश्लेषिकी तक पहुंच प्रदान कर सकता है।
- नेटवर्क का उद्देश्य यह सुनिश्चित करने में मदद करना है कि संक्रामक रोग के खतरों की तेजी से पहचान की जाए और कोविड महामारी जैसी तबाही को रोकने के लिए साझा की गई जानकारी के माध्यम से कार्यवाही की जाए।
- यह कोविड-19 के बाद से शुरू की गई कई पहलों में से नवीनतम है जिसका उद्देश्य महामारी के खतरों को रोकने और अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने की विश्व की क्षमता को मजबूत करना है।

IPSN के बारे में

- आईपीएसएन पैथोजन जीनोमिक कारकों का एक वैश्विक नेटवर्क है, जिसे डब्ल्यूएचओ हब फॉर पैनडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस द्वारा होस्ट किया गया।
- नेटवर्क वायरस, बैक्टीरिया और अन्य रोग पैदा करने वाले जीवों के आनुवंशिक कोड का विश्लेषण करने के लिए रोगजनक जीनोमिक्स पर निर्भर करता है ताकि यह समझा जा सके कि वे कितने संक्रामक और घातक हैं एवं वे कैसे फैलते हैं?
- आईपीएसएन नए रोगजनकों का तेजी से पता लगाने, बीमारियों के प्रसार और विकास की बढ़ी हुई ट्रैकिंग को सक्षम बनाएगा ।
- आईपीएसएन चल रही बीमारी निगरानी का भी समर्थन करता है और महामारी या महामारी बनने से पहले नए रोग के खतरों का पता लगाने में मदद करेगा।
- आईपीएसएन देशों और क्षेत्रों को जोड़ने, नमूने एकत्र करने व विश्लेषण करने के लिए सिस्टम में सुधार करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
- आईपीएसएन का डब्ल्यूएचओ के हब फॉर पैनडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस के भीतर एक सचिवालय होगा।
- यह नेटवर्क जीनोमिक्स और डेटा एनालिटिक्स पर विशेषज्ञों को एक साथ लाएगा जो सरकारों, शिक्षाविदों और निजी क्षेत्र से तैयार किए गए हैं।

जीनोमिक्स और संक्रामक रोग

- जीनोमिक प्रौद्योगिकियां संक्रामक रोग के खतरों के नियंत्रण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- माइक्रोबियल डीएनए का तेजी से सटीक विश्लेषण नए खतरों और प्रकोपों का पता लगाने में सक्षम बनाता है।
- यह नया ज्ञान बीमारी के प्रसार को रोकने और प्रबंधित करने के लिए अधिक प्रभावी हस्तक्षेप को बढ़ावा दे रहा है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन

- डब्ल्यूएचओ, जिसका मुख्यालय जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में है, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है।
- इसकी स्थापना 7 अप्रैल, 1948 को हुई थी।
- इथियोपिया के सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस डब्ल्यूएचओ के पहले अफ्रीकी मूल के महानिदेशक हैं।

विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023

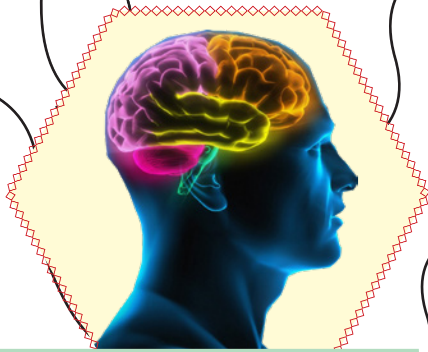

उद्देश्य

- तंबाकू निषेध दिवस का उद्देश्य जनता को तंबाकू उत्पादों के उपयोग से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में शिक्षित करना है।
- यह तम्बाकू छोड़ने के महत्व पर प्रकाश डालता है और तम्बाकू उपयोग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों को प्रोत्साहित करता है।

इतिहास

- 1987 में, विश्व स्वास्थ्य सभा ने प्रस्ताव डब्लूएचए 40.38 पारित किया, जिसके अंतर्गत 7 अप्रैल, 1988 को 'विश्व धूम्रपान निषेध दिवस' घोषित किया गया।
- 1988 में, प्रस्ताव डब्लूएचए 42.19 पारित किया गया, जिसमें हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने का आह्वान किया गया था।

थीम

- इस वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम 'हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं' है।
- विश्व भर में हर साल लगभग 3.5 मिलियन हेक्टेयर भूमि तंबाकू उगाने के लिए परिवर्तित की जाती है जो विश्व में खाद्य सुरक्षा संकट को बढ़ा रही है।

थीम उद्देश्य

- तम्बाकू उगाने पर सब्सिडी समाप्त करने और फसल प्रतिस्थापन कार्यक्रमों के लिए बचत का उपयोग करने के लिए सरकारों को संगठित करना।
- तम्बाकू उत्पादकों में तम्बाकू की खेती को त्यागकर और स्थायी फसलें उगाने के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
- तम्बाकू की खेती को कम करके मरुस्थलीकरण और पर्यावरणीय निम्नीकरण से निपटने के प्रयासों का समर्थन करना।

चर्चा में क्यों?

विश्व तंबाकू निषेध दिवस को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) के नेतृत्व में एक वैश्विक पहल के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य तंबाकू उपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और तंबाकू की खपत को कम करने के लिए प्रभावी नीतियों की वकालत करना है।

स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव

कैंसर:

तंबाकू शरीर में लगभग कहीं भी कैंसर का कारण बन सकता है, जिसमें शामिल हैं:

1. रक्त (एक्यूट माइलॉयड ल्यूकेमिया)
2. मूत्राशय
3. गर्भाशय ग्रीवा
4. बृहदान्त्र और मलाशय
5. घेघा
6. गुर्दे और गुर्दे की श्रोणि (Pelvis)
7. जिगर
8. फेफड़े
9. मुँह और गला
10. अग्न्याशय
11. पेट

हृदय रोग और स्ट्रोक:

धूम्रपान हृदवाहिनी रोग (सीवीडी) का एक प्रमुख कारण है। सीवीडी से होने वाली हर चार मौतों में से एक का कारण धूम्रपान है। धूम्रपान निम्न बीमारियाँ (कारकों) को बढ़ावा दे सकता है–

1. ट्राइग्लिसराइड्स (रक्त में वसा का एक प्रकार)
2. कम 'अच्छा' कोलेस्ट्रॉल (एचडीएल)
3. रक्त को चिपचिपा बनाता है जिसमें थक्का जमने की संभावना अधिक हो, जो हृदय और मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को अवरुद्ध कर सकता है।
4. रक्त वाहिकाओं को पंक्तिबद्ध करने वाली कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त करना।
5. रक्त वाहिकाओं में पट्टिका (Plaque) के निर्माण को बढ़ाना।
6. रक्त वाहिकाओं को मोटा और संकुचित करना।

क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज:

1. क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) उन बीमारियों के समूह को संदर्भित करता है जो वायु प्रवाह में रुकावट और सांस संबंधी समस्याओं का कारण बनते हैं।
2. सीओपीडी में वातस्फीति शामिल है; क्रोनिक ब्रोंकाइटिस; और कुछ मामलों में अस्थमा भी।

गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान:

धूम्रपान करने वाली महिलाओं को गर्भवती होने में अधिक कठिनाई होती है और कभी भी गर्भवती न होने का खतरा बढ़ जाता है।

एक्स-रे पोलरिमीटर सैटेलाइट

परिचय

- इसरो के अनुसार, 'XPoSat चरम स्थितियों में चमकीले खगोलीय एक्स-रे स्रोतों की विभिन्न गतिकी का अध्ययन करेगा।'
- इसे भारत का पहला और दुनिया का दूसरा पोलरिमीटर मिशन बताया गया है, जिसका उद्देश्य चरम स्थितियों में खगोलीय एक्स-रे स्रोतों की विभिन्न गतिकी का अध्ययन करना है।
- इस तरह का अन्य प्रमुख मिशन नासा का इमेजिंग एक्स-रे पोलरिमीटर एक्सप्लोरर (IXPE) है जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था।

चर्चा में क्यों?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एक्स-रे पोलरिमीटर सैटेलाइट (XPoSat) बनाने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (RRI), बेंगलुरु के साथ सहयोग कर रहा है, जिसे इस साल के अंत में लॉन्च किया जाना है।

अंतरिक्ष में एक्स-रे को समझना

- एक्स-रे में बहुत अधिक ऊर्जा और बहुत कम तरंग दैर्ध्य (0.03 और 3 नैनोमीटर के बीच) होते हैं।
- किसी वस्तु का भौतिक तापमान उसके द्वारा उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य को निर्धारित करता है। वस्तु जितनी अधिक गर्म होगी, उत्सर्जन की तरंग दैर्ध्य उतनी ही कम होगी।
- एक्स-रे लाखों डिग्री सेल्सियस तापमान पर उत्पन्न होते हैं-जैसे पल्सर, गांगेय सुपरनोवा अवशेष और ब्लैक होल।

निष्कर्ष

- एक्स-रे पोलरिमीटर सैटेलाइट (XPoSat) लॉन्च करने का भारत का प्रयास देश के अंतरिक्ष अनुसंधान प्रयासों में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर है।
- पोलरिमीटर तकनीकों का उपयोग करके, ग्वैंज ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार और पल्सर सहित इन खगोलीय पिंडों की प्रकृति और व्यवहार में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा।
- XPoSat अपने लॉन्च की तैयारी कर रहा है, इसमें ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ का विस्तार करने और खगोल भौतिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने की क्षमता है।

पोलरिमीटर का महत्त्व

- प्रकाश के सभी रूपों की तरह, एक्स-रे में गतिमान विद्युत और चुंबकीय तरंगें होती हैं। आमतौर पर, इन तरंगों की चोटियाँ (Peaks) और घाटियाँ (Valleys) यादृच्छिक दिशाओं में चलती हैं।
- ब्रिटानिका के अनुसार, पोलरिमीटर का क्षेत्र ध्रुवीकृत प्रकाश के तल के घूर्णन के कोण के मापन का अध्ययन करता है (अर्थात, प्रकाश का एक पुंज जिसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगों का कंपन एक तल तक सीमित होता है) जिसके परिणाम स्वरूप कुछ पारदर्शी सामग्री के माध्यम से इसके पारित होने का परिणाम होता है।

XPoSat पेलोड

- अंतरिक्ष यान पृथ्वी की निचली कक्षा में दो वैज्ञानिक पेलोड ले जाएगा। प्राथमिक पेलोड, POLIX (एक्स-रे में पोलीमीटर उपकरण), पोलरिमीटर पैरामीटर (ध्रुवीकरण की डिग्री और कोण) को मापेगा।
- बेंगलुरू में इसरो के यू आर राव उपग्रह केंद्र (यूआरएससी) के सहयोग से आरआरआई द्वारा पेलोड विकसित किया जा रहा है।
- एक्सएसपीईसीटी (एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग) पेलोड स्पेक्ट्रोस्कोपिक जानकारी प्रदान करेगा (वस्तुओं द्वारा प्रकाश को कैसे अवशोषित और उत्सर्जित किया जाता है)। यह कई प्रकार के स्रोतों का निरीक्षण करेगा, जैसे एक्स-रे पल्सर, ब्लैक होल बायनेरिज, लो-मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रॉन स्टार आदि।

XPoSat द्वारा इसरो के प्रयास

- इसरो की वेबसाइट बताती है कि विभिन्न खगोलीय स्रोतों जैसे कि ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे, सक्रिय गांगेय नाभिक आदि से उत्सर्जन तंत्र जटिल भौतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है और इसे समझना चुनौतीपूर्ण है।
- अंतरिक्ष-आधारित वेधशालाएँ भी ऐसे स्रोतों से होने वाले उत्सर्जन की सही प्रकृति के बारे में जानकारी प्रदान करने में असमर्थ हैं। इसलिए, विशिष्ट गुणों को मापने के लिए नए उपकरणों की आवश्यकता होती है।

फोर्टिफाइड चावल

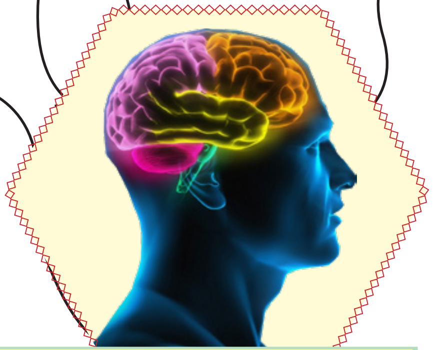

चर्चा में क्यों?

खाद्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने 24 मई, 2023 को सूचित किया कि सरकार 31 मार्च, 2024 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत 800 मिलियन लाभार्थियों को 35 मिलियन टन (एमटी) लौह युक्त चावल की आपूर्ति करेगी।

चावल के फोर्टिफिकेशन के बारे में

राईस फोर्टिफिकेशन चावल में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों को बढ़ाने की प्रक्रिया है ताकि खाद्य आपूर्ति की पोषण गुणवत्ता में सुधार किया जा सके और स्वास्थ्य के लिए न्यूनतम जोखिम के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा सके।

चावल को फोर्टीफाई करने के कारण

- भारत एक प्रमुख चावल उत्पादक देश है जोकि कुल वैश्विक चावल उत्पादन का 22 प्रतिशत अकेले उत्पादन करता है। भारत की 65% आबादी दैनिक आधार पर चावल का उपभोग करती है जिससे भारत में प्रति व्यक्ति चावल की खपत 6.8 किलोग्राम प्रति माह हो जाती है।
- चावल कैलोरी का एक बड़ा स्रोत है और भारत के अधिकांश हिस्सों में कृषि और पोषण का मुख्य घटक है। हालांकि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पायी जाती है।
- चावल की मिलिंग वसा और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर चोकर की परतों को हटा देती है जिससे आमतौर पर खपत होने वाले स्टार्च सफेद चावल का उत्पादन होता है। वहीं पॉलिश करने से 75-90% विटामिन (जैसे-विटामिन B-1, B-6, E और नियासिन) निकल जाता है।
- फोर्टीफाइंग चावल खोए हुए सूक्ष्म पोषक तत्वों को वापस जोड़ने का अवसर प्रदान करता है जिससे अन्य पोषक तत्व जैसे लोहा, जस्ता, फोलिक एसिड, विटामिन (B-12 और A) को भी जोड़ने का अवसर मिलता है।

चावल के फोर्टिफिकेशन के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकियां

फोर्टिफाई चावल के उत्पादन के लिए तीन मुख्य प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं –

- **कोटिंग:** कोटिंग विधि में, पोषक तत्व (विटामिन या खनिज मिश्रण) को गम्स (GUMS) और वैक्सेस (WAXES) जैसे अवयवों के साथ जोड़ा जाता है। फिर इसे चावल के दानों की सतह पर कई परतों में छिड़का जाता है। इसके बाद इसे पॉलिश किए हुए चावल के साथ लगभग 1:100 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है।
- **डस्टिंग:** डस्टिंग में, सूक्ष्म पोषक तत्वों को एक कण के रूप में थोक चावल के साथ मिश्रित किया जाता है। यह विधि चावल की सतह और सूक्ष्म पोषक तत्वों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक बलों का उपयोग करती है।
- बाहर निकालना (EXTRUSION)

भारत में उपलब्ध चावल फोर्टिफिकेशन तकनीक

- भारत में चावल को एक्सट्रूजन तकनीक का उपयोग करके फोर्टिफाई किया जाता है।
- इस तकनीक में पिसे हुए चावल को चूर्णित किया जाता है और विटामिन और खनिजों वाले प्रीमिक्स के साथ मिलाया जाता है।
- इस मिश्रण से एक एक्सट्रूडर मशीन का उपयोग करके फोर्टिफाई चावल के दाने (FRK) तैयार किए जाते हैं।
- एफआरके को पारंपरिक चावल में 1:50 से 1:200 के अनुपात में मिलाया जाता है जिसके परिणामस्वरूप फोर्टिफाई चावल सुगंध, स्वाद और बनावट में पारंपरिक चावल के लगभग समान हो जाते हैं।

मानक

मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत, 10 ग्राम एफआरके (FORTIFIED RICE KERNELS) को 1 किलो नियमित चावल के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए। FSSAI के मानदंडों के अनुसार, 1 किलो फोर्टिफाई चावल में शामिल होना चाहिए

- आयरन (28-42.5 मिलीग्राम)
- फोलिक एसिड (75-125 माइक्रोग्राम)
- विटामिन बी-12 (0.75-1.25 माइक्रोग्राम)

चावल को निम्नलिखित के साथ भी फोर्तिफाय किया जा सकता है–

- जिंक (10-15 मिलीग्राम)
- विटामिन ए (500-750 माइक्रोग्राम)
- विटामिन बी-1(1-1.5 मिलीग्राम)
- विटामिन बी-2 (1.25-1.75 मिलीग्राम)

फोर्टिफिकेशन राईस पर प्रभावी अध्ययन

भारत में किए गए अध्ययन:

- 2018-2020 के दौरान महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में राइस फोर्टिफिकेशन का पायलट स्टडी (PILOT STUDY)
- 2018-2019 में गुजरात के स्कूल में चावल के फोर्टिफिकेशन पर अध्ययन।
- 2014 में भारतीय स्कूली बच्चों में आयरन और विटामिन ए की स्थिति में सुधार हेतु अध्ययन।

अन्तर्राष्ट्रीय पर किये गए अध्ययन:

- 2013 में फोर्टिफाई चावल पर पब्लिक चाइल्ड डे केयर सेंटर ब्राजील में अध्ययन।
- ब्राजील के पब्लिक स्कूलों में 2013 में फोर्टिफाई चावल पर अध्ययन।
- 2012 में ब्राजील स्थित चाइल्ड डे केयर सेंटर में फोर्टिफाई चावल की स्टडी
- 2016 में इंडोनिशया में किशोर लड़कियों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर चावल का चिकित्सीय प्रभाव अध्ययन।

नया संसद भवन

चर्चा में क्यों?

भारत के नए संसद भवन (New Parliament Building) (एनपीबी) का उद्घाटन 28 मई, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। पीएम ने लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास ऐतिहासिक 'सेंगोल' स्थापित किया।

नए संसद भवन का शिलान्यास

पीएम ने 10 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में नए संसद भवन की आधारशिला रखी।

नई इमारत, नई सुविधाओं के साथ

- एनपीबी का निर्मित क्षेत्र लगभग 65,000 वर्ग मीटर होगा। इसका त्रिकोणीय आकार इष्टतम स्थान उपयोग सुनिश्चित करता है।
- एनपीबी और ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग एक साथ मिलकर एक कवर के रूप में काम करेंगे। इससे संसद के संचालन के सुचारू और कुशल कामकाज में सुविधा होगी।
- एनपीबी विधायिका के लिए बड़े कक्षों का निर्माण करेगा।
- एक बड़ा लोक सभा हॉल 888 सीटों तक की क्षमता वाला है, जो पीकॉक थीम पर आधारित है।
- एक बड़ा राज्य सभा हॉल 384 सीटों की क्षमता वाला है जो लोटस थीम पर आधारित है।
- लोक सभा हॉल में संयुक्त सत्रों के लिए 1272 सीटें की व्यवस्था हो सकती हैं।
- प्लेटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक होगी।

नए संसद भवन की आवश्यकता

- पुराने संसद भवन भवन का निर्माण 1921 में शुरू किया गया था और 1927 में इसका उद्घाटन किया गया था।
- यह लगभग 100 साल पुराना है और एक हेरिटेज ग्रेड-I इमारत है।
- पिछले कुछ वर्षों में संसदीय गतिविधियों और उसमें काम करने वाले लोगों और आगंतुकों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है।
- भवन के मूल डिजाइन का कोई रिकॉर्ड या दस्तावेज नहीं है।
- नए निर्माण और संशोधन तदर्थ तरीके से किए गए हैं।

सांसदों के बैठने की कम जगह:

- पूर्ण लोकतंत्र के लिए द्विसदनीय विधायिका को समायोजित करने के लिए वर्तमान भवन को कभी भी डिजाइन नहीं किया गया था।
- लोक सभा सीटों की संख्या, 1971 की जनगणना के आधार पर किए गए परिसीमन के आधार पर 545 अपरिवर्तित रही है।
- 2026 के बाद इसमें काफी वृद्धि होने की संभावना है क्योंकि सीटों की कुल संख्या पर रोक केवल 2026 तक लागू है।
- सेंट्रल हॉल में केवल 440 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है।

व्यथित बुनियादी ढांचा:

- समय के साथ सेवाओं में वृद्धि, जो मूल रूप से योजनाबद्ध नहीं थी, के कारण इमारत के समग्र सौंदर्यशास्त्र को क्षति हुई है।
- अग्नि सुरक्षा एक प्रमुख चिंता का विषय है क्योंकि इमारत को वर्तमान अग्नि मानदंडों के अनुसार डिजाइन नहीं किया गया है।

अप्रचलित संचार संरचनाएं:

- पुराने संसद भवन में संचार अवसंरचना और प्रौद्योगिकी पुरातन है।

सुरक्षा चिंताएं:

- भवन की संरचनात्मक सुरक्षा को लेकर भी चिंताएँ हैं।
- वर्तमान संसद भवन तब बना था जब दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र-II में था, वर्तमान में यह भूकंपीय क्षेत्र-IV में है।

कर्मचारियों के लिए अपर्याप्त कार्यक्षेत्र:

- कार्यक्षेत्रों की बढ़ती मांग के साथ, आंतरिक सेवा गलियारों को कार्यालयों में परिवर्तित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप असुविधा युक्त संकीर्ण कार्यस्थलों का निर्माण हुआ।
- लगातार बढ़ती हुई कार्यस्थलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, मौजूदा कार्यक्षेत्रों के भीतर उप-विभाजन बनाए गए थे, जिससे कार्यालय खचाखच भरे हुए हैं ।

कुछ आंकड़े

- 2304095 मानव दिवस रोजगार सृजित।
- 26045 एमटी स्टील का इस्तेमाल हुआ।
- 63807 एमटी सीमेंट का इस्तेमाल हुआ।
- 9689 क्यूबिक मीटर फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया गया।

विश्व ऊर्जा निवेश 2023

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने 'विश्व ऊर्जा निवेश 2023' शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में लगभग 2.8 ट्रिलियन डॉलर का ऊर्जा में वैश्विक स्तर पर निवेश किया जाना है, जिसमें से 1.7 ट्रिलियन डॉलर से अधिक स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और शेष $1 ट्रिलियन से अधिक, कोयला, गैस और तेल में किये जाने की अपेक्षा है।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी

- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) एक पेरिस स्थित स्वायत्त अंतरसरकारी-संगठन है , जिसे 1974 में स्थापित किया गया था।
- यह संपूर्ण वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र पर नीतिगत सिफारिशें, विश्लेषण और डेटा प्रदान करता है।
- आईईए के 31 सदस्य देश (भारत सहित) और 11 संबद्ध देश, वैश्विक ऊर्जा मांग के 75% का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- इसकी स्थापना 1973 के तेल संकट के बाद आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के अंतर्गत की गई थी।

आगे की राह

- अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा और भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है, विशेष रूप से निम्न-आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में निवेश को बढ़ावा देने के लिए, जहां निजी क्षेत्र उद्यम करने के लिए अनिच्छुक रहा है।
- जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने और जीवाश्म ईंधन से पूंजी के पुनर्वितरण के लिए, स्वच्छ ऊर्जा खर्च के बड़े पैमाने पर रैंप-अप के लिए, वित्तीय समुदाय की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।
- स्थायी वित्त प्रथाओं का प्रसार इस प्रवृत्ति का एक संकेतक है, वित्तीय संस्थानों की बढ़ती संख्या के साथ अपने वित्तपोषण को शुद्ध शून्य परिदृश्यों के साथ संरेखित करने का संकल्प लेना चाहिए।

अवलोकन और प्रमुख निष्कर्ष

सतत वित्त:

- स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में निवेश जीवाश्म ईंधन पर खर्च की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ रहा है।
- 2021 और 2023 के बीच वार्षिक स्वच्छ ऊर्जा निवेश में 24% की वृद्धि नवीकरणीय और इलेक्ट्रिक वाहनों द्वारा संचालित होने की उम्मीद है, जो इसी अवधि में जीवाश्म ईंधन निवेश में 15% की वृद्धि की तुलना में कहीं अधिक है।
- मजबूत आर्थिक विकास और अस्थिर जीवाश्म ईंधन की कीमतों के कारण हाल के वर्षों में ऊर्जा सुरक्षा के बारे में चिंता के कारण स्वच्छ ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा मिला।
- स्वच्छ ऊर्जा निवेश में सबसे बड़ी कमी उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में है। हालाँकि, यहाँ कुछ धवल बिंदु हैं, जैसे कि भारत में सौर ऊर्जा में गतिशील निवेश।

ऊर्जा दक्षता:

- सौर ऊर्जा के नेतृत्व में, कम उत्सर्जन वाली बिजली प्रौद्योगिकियों से बिजली उत्पादन में लगभग 90% निवेश की उम्मीद है।
- ग्लोबल हीट पंप की बिक्री में 2021 से दो अंकों की वार्षिक वृद्धि देखी गई है।
- इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में इस साल एक तिहाई की बढ़ोतरी की उम्मीद है।

आर एंड डी और प्रौद्योगिकी नवाचार:

- वैश्विक स्तर पर, ऊर्जा अनुसंधान और विकास पर सार्वजनिक खर्च 2022 में 10% बढ़कर लगभग 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसमें 80% स्वच्छ ऊर्जा के लिए समर्पित है।
- व्यापक आर्थिक अनिश्चितता के बावजूद, हाल के वर्षों में इस प्रवृत्ति ने नवाचार को बढ़ावा दिया है।

प्रारम्भिक परीक्षा आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

01. निम्नलिखित में से कौन-से, भारत में सूक्ष्मजैविक रोगजनकों में बहु-औषध प्रतिरोध के होने के कारण हैं?
1. कुछ व्यक्तियों में आनुवंशिक पूर्ववृत्ति (जेनेटिक प्रीडिस्पोजीशन) का होना
2. रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविकों (ऐंटिबॉयोटिक्स) की गलत खुराकें लेना
3. पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना
4. कुछ व्यक्तियों में चिरकालिक रोगों की बहुलता होना

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) 1, 3 और 4 (d) 2, 3 और 4

02. राज्य सभा की लोक सभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं?
(a) नई अखिल भारतीय सेवाएँ गठित करने के विषय
(b) संविधान में संशोधन करने के विषय में
(c) सरकार को हटाने के विषय में
(d) कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में

03. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) के अन्तर्गत निधियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-से सही हैं?
1. MPLADS निधियाँ टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती हैं।
2. प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति/जनजाति जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है।
3. MPLADS निधियाँ वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रेनीत नहीं किया जा सकता।
4. कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम-से-कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रति वर्ष निरीक्षण अनिवार्य है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3 और 4
(c) केवल 1, 2 और 3 (d) केवल 1, 2 और 4

04. निम्नलिखित में से कौन-सा/से भारत में 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद घटित हुआ/हुए है/हैं?
1. GDP में कृषि का अंश बृहत् रूप से बढ़ गया।
2. विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का अंश बढ़ गया।
3. FDI का अंतर्वाह (इनफ्लो) बढ़ गया।
4. भारत का विदेशी विनिमय भण्डार बृहत् रूप से बढ़ गया।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
(a) केवल 1 और 4 (b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

05. वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिनमें ''बृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण (The Macro Economic Framework Statement)'' भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है :
(a) चिरकालिक संसदीय परम्परा के कारण
(b) भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 तथा अनुच्छेद 110(1) के कारण
(c) भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के कारण
(d) राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के कारण

06. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए :

	अंतर्राष्ट्रीय समझौता / संगठन		**विषय**
1.	अल्मा-आटा घोषणा	-	लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल
2.	हेग समझौता	-	जैविक एवं रासायनिक शस्त्र
3.	तलानोआ संवाद	-	वैश्विक जलवायु परिवर्तन
4.	अंडर 2 गठबंधन	-	बाल अधिकार

उपर्युक्त में से कौन-सा/से युग्म सही सुमेलित है/हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 4
(c) केवल 1 और 3 (d) केवल 2, 3 और 4

07. संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें:
(a) संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है।
(b) सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है।
(c) सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है।
(d) सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती है।

08. भारत के संदर्भ में, नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन-सा उपयुक्त चरित्र-चित्रण है?
(a) संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण
(b) संघीय ढाँचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण
(c) राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण
(d) लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण

09. भारत के संविधान की उद्देशिका:
(a) संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती।
(b) संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती।
(c) संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग।
(d) संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है।

10. भारत के संविधान के भाग IV में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
1. वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे।
2. वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे।
3. इस भाग में अधिकथित सिद्धान्त राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3 (d) केवल 2 और 3

11. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे, संसद का सत्र आहूत (आह्वान) कर सकता है।
2. भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के तीन सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी तीन सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है।
3. एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3 (d) केवल 2 और 3

12. भारत के इतिहास के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए :
1. औरंग – राजकोष का प्रभारी
2. बेनियान – ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट
3. मिरासिदार – राज्य का नामित राजस्व दाता

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं ?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

13. भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए :
1. राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय
2. महेन्द्रवर्मन – I के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना
3. परान्तक – I द्वारा चोल सत्ता की स्थापना
4. गोपाल द्वारा पाल राजवंश की संस्थापना

उपर्युक्त घटनाओं का, प्राचीन काल से आरम्भ कर, सही कालानुक्रम क्या है?
(a) 2-1-4-3 (b) 3-1-4-2
(c) 2-4-1-3 (d) 3-4-1-2

14. निम्नलिखित में से कौन-सा उपवाक्य, उत्तर-हर्ष-कालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित 'हुंडी' के स्वरूप की परिभाषा बताता है?
(a) राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श
(b) प्रतिदिन का लेखा-जोखा अंकित करने वाली बही
(c) विनिमय पत्र
(d) सामन्त द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश

15. गाँधी-इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था/थे?
1. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए काँग्रेस को आमन्त्रित करना
2. असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना
3. पुलिस की ज्यादतियों की जाँच करने हेतु गाँधीजी के सुझाव की स्वीकृति
4. केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
(a) केवल 1 (b) केवल 1, 2 और 4
(c) केवल 3 (d) केवल 2, 3 और 4

16. अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्ष्यित कर, प्रथम मासिक पत्रिका 'विटाल विध्वंसक' किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी?
(a) गोपाल बाबा वलंगकर
(b) ज्योतिबा फुले
(c) मोहनदास करमचन्द गाँधी
(d) भीमराव रामजी अम्बेडकर

17. निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया?
"कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा-मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निन्दा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुँचाता है।''
(a) अशोक (b) समुद्रगुप्त
(c) हर्षवर्धन (d) कृष्णदेव राय

18. निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में नील की खेती का ह्रास हुआ?
(a) नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध
(b) नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना
(c) नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना

(d) उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण

19. वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी?
(a) उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा करने के लिए कहा था।
(b) वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुन: जाग्रत करना चाहता था।
(c) वह विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था।
(d) वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था।

20. प्राचीन भारत के विद्वानों/साहित्यकारों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है।
2. अमरसिंह हर्षवर्धन से संबंधित है।
3. कालिदास चन्द्र गुप्त-II से संबंधित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

21. विकास की वर्तमान स्थिति में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है?
1. औद्योगिक इकाइयों में विद्युत् की खपत कम करना
2. सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना
3. रोगों का निदान
4. टेक्स्ट से स्पीच (Text-to-Speech) में परिवर्तन
5. विद्युत् ऊर्जा का बेतार संचरण

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
(a) केवल 1, 2, 3 और 5 (b) केवल 1, 3 और 4
(c) केवल 2, 4 और 5 (d) 1, 2, 3, 4 और 5

22. "ब्लॉकचेन तकनीकी" के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है, परन्तु जिसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं करता।
2. ब्लॉकचेन की संरचना और अभिकल्प ऐसा है कि इसका समूचा डेटा केवल क्रिप्टोकरेंसी के विषय में है।
3. ब्लॉकचेन के आधारभूत वैशिष्ट्यों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 (d) केवल 1 और 3

23. कार्बन नैनोट्यूबों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. इनको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहकों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है।
2. इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त केशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है।
3. इनका जैव-रासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जा सकता है।
4. कार्बन नैनोट्यूब जैव-निम्नीकरणीय (biodegradable) होती हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 1, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

24. यदि आप अपने बैंक के माँग जमा खाते (Demand Deposit Account) से रुपये 1,00,000 की नकद राशि निकालते हैं, तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
(a) मुद्रा की समग्र पूर्ति में रु. 1,00,000 की कमी आएगी।
(b) मुद्रा की समग्र पूर्ति में रु. 1,00,000 की वृद्धि होगी।
(c) मुद्रा की समग्र पूर्ति में रु. 1,00,000 से अधिक की वृद्धि होगी।
(d) मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी।

25. भारत में, क्यों कुछ परमाणु रिऐक्टर "आई.ए.ई.ए. सुरक्षा उपायों" के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते?
(a) कुछ यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य थोरियम का
(b) कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का
(c) कुछ विदेशी उद्यमों द्वारा संचालित होते हैं और अन्य घरेलू उद्यमों द्वारा
(d) कुछ सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं और अन्य निजी स्वामित्व वाले

26. यदि आर.बी.आई. प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है, तो वह निम्नलिखित में से क्या **नहीं** करेगा?
1. वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलित करना
2. सीमान्त स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना
3. बैंक दर को घटाना तथा रेपो दर को भी घटाना

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

27. 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. शहरी क्षेत्रों में श्रमिक की उत्पादकता (2004-05 की कीमतों पर प्रति श्रमिक रु.) में वृद्धि हुई जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें कमी हुई।

2. कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में, गैर-कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई।
4. ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3 और 4
(c) केवल 3 (d) केवल 1, 2 और 4

28. भारत में, निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है?

1. सभी फसलों के कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना
2. प्राथमिक कृषि साख समितियों का कम्प्यूटरीकरण
3. सामाजिक पूँजी विकास
4. कृषकों को नि:शुल्क बिजली की आपूर्ति
5. बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफी
6. सरकारों द्वारा शीतागार सुविधाओं को स्थापित करना

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

(a) केवल 1, 2 और 5 (b) केवल 1, 3, 4 और 5
(c) केवल 2, 3 और 6 (d) 1, 2, 3, 4, 5 और 6

29. भारत में फर्म के "ब्याज-व्याप्ति अनुपात (Interest Coverage Ratio)" पद का क्या महत्त्व है?

1. यह उस फर्म, जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है, के वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है।
2. यह उस फर्म, जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है, के आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में मदद करता है।
3. उधार लेने वाली फर्म का ब्याज-व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा, उसकी ऋण समाशोधन क्षमता उतनी ही खराब होगी।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

30. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए :

	नदी		**में जाकर मिलती है**
1.	मेकोंग	–	अण्डमान सागर
2.	थेम्स	–	आयरिश सागर
3.	वोल्गा	–	कैस्पियन सागर
4.	जाम्बेजी	–	हिन्द महासागर

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3
(c) केवल 3 और 4 (d) केवल 1, 2 और 4

31. भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए :

1. परिव्राजक – परित्यागी व भ्रमणकारी
2. श्रमण – उच्च पद प्राप्त पुजारी
3. उपासक – बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-से सही सुमेलित हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

32. निम्नलिखित में से कौन-सा 'संरक्षित क्षेत्र' कावेरी बेसिन में स्थित है?

1. नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान
2. पापिकोंडा राष्ट्रीय उद्यान
3. सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र
4. वायनाड वन्यजीव अभयारण्य

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3 और 4
(c) केवल 1, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

33. 'अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान (Intended Nationally Determined Contributions) पद को कभी-कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है?

(a) युद्ध-प्रभावित मध्य-पूर्व के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए यूरोपीय देशों द्वारा दिए गए वचन।
(b) जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य-योजना।
(c) एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक) की स्थापना करने में सदस्य राष्ट्रों द्वारा किया गया पूंजी योगदान।
(d) धारणीय विकास लक्ष्यों के बारे में विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य-योजना।

34. प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में, नगर घंटाशाला, कदूरा तथा चौल किस लिए विख्यात थे?

(a) विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह
(b) शक्तिशाली राज्यों की राजधानियाँ
(c) उत्कृष्ट प्रस्तर कला तथा स्थापत्य से संबंधित स्थान
(d) बौद्ध धर्म के महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल

35. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन 'कार्बन के सामाजिक मूल्य' पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है?

आर्थिक मूल्य के रूप में यह निम्नलिखित में से किसका माप है?

(a) प्रदत्त वर्ष में एक टन CO_2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति।
(b) किसी देश की जीवाश्म ईंधनों की आवश्यकता, जिन्हें जलाकर देश अपने नागरिकों को वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करता है।
(c) किसी जलवायु शरणार्थी (Climate refugee) द्वारा किसी नए स्थान के प्रति अनुकूलित होने हेतु किए गए प्रयास।
(d) पृथ्वी ग्रह पर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अंशदत कार्बन पदचिह्न।

36. भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है।
2. कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है।
3. पिछले तीन दशकों में, जहाँ खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है, वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 2 (d) 1, 2 और 3

37. "यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है। उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए उसे कम-से-कम 210 पाला-रहित दिवसों और 50-100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है ।" यह फसल निम्नलिखित में से कौन-सी है?

(a) कपास (b) जूट
(c) गन्ना (d)चाय

38. कृषि में फर्टीगेशन *(fertigation)* के क्या लाभ हैं?

1. सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है।
2. रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है।
3. पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं।
4. रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी संभव है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

(a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 1, 2 और 4
(c) केवल 1, 3 और 4 (d) केवल 2, 3 और 4

39. निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए :

1. बेंटोनाइट 2. क्रोमाइट
3. क्यानाइट 4. सिलीमेनाइट

भारत में, उपर्युक्त में से कौन-सा/से आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज (major minerals) है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 4
(c) केवल 1 और 3 (d) केवल 2, 3 और 4

40. महासागर औसत तापमान (Ocean Mean Temperature/ OMT) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. OMT को 26°C समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है जो जनवरी-मार्च में हिन्द महासागर के दक्षिण-पश्चिम में 129 मीटर पर होती है।
2. OMT, जो जनवरी-मार्च में एकत्रित किया जाता है उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

41. भारत के 'मरु राष्ट्रीय उद्यान' के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?

1. यह दो जिलों में विस्तृत है।
2. उद्यान के अन्दर कोई मानव वास स्थल नहीं है।
3. यह 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' के प्राकृतिक आवासों में से एक है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

42. भारत के इतिहास के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए :

	प्रसिद्ध स्थल		**वर्तमान राज्य**
1.	भीलसा	-	मध्य प्रदेश
2.	द्वारसमुद्र	-	महाराष्ट्र
3.	गिरिनगर	-	गुजरात
4.	स्थानेश्वर	-	उत्तर प्रदेश

उपर्युक्त में से कौन-से युग्म सही सुमेलित हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1 और 4
(c) केवल 2 और 3 (d) केवल 2 और 4

43. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं।
2. केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षि (eye) उत्पन्न करते हैं।
3. चक्रवात की वाताक्षि के अन्दर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10°C कम होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 2 (d) केवल 1 और 3

44. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. पहली लोक सभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतन्त्र पार्टी था।
2. लोक सभा में "नेता-प्रतिपक्ष" को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी।
3. लोक सभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हों तो उसके नेता को नेता-प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

45. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) किस प्रकार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) से भिन्न है?

1. एन.जी.टी. का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है जबकि सी.पी.सी.बी. का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया है।
2. एन.जी.टी. पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है जबकि सी.पी.सी.बी. झरनों और कुँओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है, तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

46. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की नौवीं अनुसूची में डाल सकती है।
2. नौवीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

47. विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू-राजस्व की दर नियत होती थी।
2. कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2.

48. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम) समीक्षा समिति के प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है कि वर्ष 2023 तक केन्द्र एवं राज्य सरकारों को मिलाकर ऋण-जी.डी.पी. अनुपात 60% रखा जाए जिसमें केंद्र सरकार के लिए यह 40% तथा राज्य सरकारों के लिए 20% हो ।
2. राज्य सरकारों के जी.डी.पी. के 49% की तुलना में केन्द्र सरकार के लिए जी.डी.पी. की 21% घरेलू देयतायें हैं।
3. भारत के संविधान के अनुसार यदि किसी राज्य के पास केंद्र सरकार की बकाया देयतायें हैं तो उसे कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार से सहमति लेना अनिवार्य है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

49. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सी.ए.आर.) वह राशि है जिसे बैंकों को अपनी निधियों के रूप में रखना होता है जिससे वे, यदि खाता-धारकों द्वारा देयताओं का भुगतान नहीं करने से कोई हानि होती है, तो उसका प्रतिकार कर सकें।
2. सी.ए.आर. का निर्धारण प्रत्येक बैंक द्वारा अलग-अलग किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

50. वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सत्य हैं?

1. सहायता अनुदान व्यवस्था (ग्रांट्स-इन-एड) शुरू की गई।
2. विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई।
3. शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर

1.	(b)	14.	(c)	27.	(b)	40.	(b)
2.	(b)	15.	(b)	28.	(c)	41.	(c)
3.	(d)	16.	(a)	29.	(a)	42.	(a)
4.	(b)	17.	(a)	30.	(c)	43.	(c)
5.	(d)	18.	(b)	31.	(b)	44.	(b)
6.	(c)	19.	(d)	32.	(c)	45.	(b)
7.	(c)	20.	(c)	33.	(b)	46.	(a)
8.	(d)	21.	(d)	34.	(a)	47.	(c)
9.	(a)	22.	(d)	35.	(a)	48.	(c)
10.	(d)	23.	(d)	36.	(a)	49.	(a)
11.	(c)	24.	(d)	37.	(a)	50.	(a)
12.	(b)	25.	(b)	38.	(c)		
13.	(c)	26.	(b)	39.	(d)		

मुख्य परीक्षा विशेषः इतिहास व कला एवं संस्कृति पर आधारित महत्त्वपूर्ण प्रश्न

1. क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि टेराकोटा कला लोकप्रिय संस्कृति का प्रतिबिंब थी? उपयुक्त उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए।

बर्तन, आभूषण आदि बनाने में प्रयुक्त बिना पॉलिश की पकाई गई मिट्टी (आग में पकाई लाल-भूरे रंग की) टेराकोटा कहलाती है। लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईसवी तक बड़ी संख्या में और अत्यंत विविधता वाली उत्तम टेराकोटा वस्तुएं बनाई गई थी। इस अवधि के टेराकोटा चंद्रकेतुगढ़, मथुरा, कौशाम्बी और अहिच्छत्र जैसे स्थलों पर बहुतायत में पाए गए हैं। वे क्षेत्रीय शैलियों और विधियों की विविधता के साथ-साथ सजावटी विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रदर्शित करते हैं।

लोकप्रिय संस्कृति के प्रतिबिंब के रूप में टेराकोटाः

1. टेराकोटा व्यापक रूप से प्रचलित था। जहां एक ओर पत्थर की मूर्तियां उच्च वर्गों तक सीमित थी तो टेराकोटा आम लोगों की संस्कृति की अभिव्यक्ति थी।
2. टेराकोटा की कई मूर्तियां सांचों में ढाली गई और बड़े पैमाने पर उत्पादित की गई। यह इसके व्यापक उपयोग और मांग को प्रदर्शित करता है।
3. हड़प्पा काल के दौरान कुत्तों, भैंसों, बंदरों आदि जानवरों की प्रभावशाली टेराकोटा मूर्तियों की विविधता, एक विस्तृत गैर-कुलीन कला के रूप में इसके उपयोग को संदर्भित करती है।
4. पंचहकुड़ा के रूप में जानी जाने वाली आकृतियाँ एक ऐसी देवी का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिनकी पूजा पूरे उत्तर भारत में लोकप्रिय प्रतीत होती है।
5. यक्ष, यक्षिणी, नाग और नागिनो को विपुलता में चित्रित किया गया हैं। यह सभी लोकप्रिय पूजा परंपराओं से जुड़े थे।
6. सभी टेराकोटा प्रकृति में धार्मिक नहीं थे। अन्य विषयों में प्रेमरत जोड़े, जानवरों की लड़ाई, पहलवान और खिलौने शामिल थे। इन सब से पता चलता है कि इसका उपयोग रोजमर्रा की जिंदगी में किया जाता है।

हालांकि, टेराकोटा कला को गैर-अभिजात वर्ग की कला कहा जा सकता है फिर भी टेराकोटा मूर्तिकला के कई संदर्भ हैं जिन्हें अभिजात वर्ग का संरक्षण प्राप्त था। मौर्य और शुंग काल के दौरान उन्हें समाज के उच्च वर्ग जैसे व्यापारियों आदि का कुछ संरक्षण मिला। टेराकोटा का उपयोग वर्तमान संदर्भ में भी लोकप्रिय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यह आम जनता की मान्यताओं और व्यवहारों को समझने का महत्त्वपूर्ण साधन है।

2. आर्यभट्ट प्रथम को प्राचीन भारत के सबसे प्रमुख खगोलशास्त्री और गणितज्ञों में से एक क्यों माना जाता है? उपयुक्त उदाहरण देकर अपने मत की पुष्टि कीजिए।

आर्यभट्ट प्रथम (476 से 550 ईस्वी) भारतीय गणितज्ञ और खगोलशास्त्री थे, इन दोनो ही क्षेत्रों में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने आर्यभट्टीयम् और आर्य-सिद्धांत आदि ग्रंथों की रचना की।

आर्यभट्ट प्रथम के प्रमुख योगदानः

गणित के क्षेत्र में:

1. उन्होंने दशमलव स्थान मान सिद्धांत पर आधारित एक प्रणाली का आविष्कार किया जिसमें व्यंजन और स्वरों की सहायता से संख्याओं को व्यक्त करने की व्यवस्था थी। डायोफैंटाइन समीकरणों को हल करने वाले आर्यभट्ट पहले ज्ञात व्यक्ति थे।
2. साइन (ज्या), कोसाइन (कोज्या) आदि की उनकी परिभाषाओं ने त्रिकोणमिति के विकास को आधार प्रदान किया।
3. उन्होंने उस समय की जटिल गणितीय समस्याओं का सरल समाधान प्रदान किया है जैसे पहले 'n' पूर्णांकों का योग, इन पूर्णांकों के वर्ग और उनके घन का योग आदि।
4. उन्होंने त्रिभुज और वृत्त के क्षेत्रफलों की गणना की सही विधि बताई।
5. आर्यभट्ट की वर्गमूल और घनमूल निकालने की विधि में संख्याओं के दशमलव स्थान मान को भी शामिल किया गया है।

खगोल के क्षेत्र में:

1. आर्यभट्ट सिंद्धात उन पहले खगोलीय कार्यों में से एक है जो प्रत्येक दिन की शुरुआत के रूप में **मध्यरात्रि** को निर्दिष्ट करता है।
2. आर्यभट्ट ने ठीक कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी धुरी पर प्रतिदिन घूमती है और तारों की गति पृथ्वी के घूमने के कारण होने वाली सापेक्ष गति के कारण प्रतीत होती है।
3. आर्यभट्ट ने चंद्र और सूर्य ग्रहण को समझाने के लिए वैज्ञानिक प्रयोगों का इस्तेमाल किया। उनके अनुसार, ग्रह और चन्द्रमा परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण प्रकाशमान होते हैं।
4. आर्यभट्ट ने नक्षत्र घूर्णन (तारों के संबंध में पृथ्वी का घूर्णन) की गणना आधुनिक समय इकाइयों में 23 घंटे, 56 मिनट और 4.1 सेकंड में की।
5. आर्यभट्ट ने एक खगोलीय मॉडल दिया जिसमें कहा गया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उनके मॉडल में सूर्य से संबंधित ग्रहों की औसत गति की गणना भी दी गई।
6. आर्यभट्ट ने वर्ष की अवधि 365 दिन 6 घंटे 12 मिनट 30 सेकंड की गणना की, जो आज की गणना से केवल 3 मिनट 20 सेकंड अधिक है।

आर्यभट्ट के कार्यों ने भविष्य के शोधों के लिए आधार निर्मित किया। इनके ग्रन्थों को पूरे भारत में बाद के गणितीय और खगोलीय साहित्य में उद्धृत किया गया। हमारी पड़ोसी संस्कृतियों पर भी उनका बहुत प्रभाव था, जिसने उनके लेखन का अनुवाद किया। उनके कुछ स्पष्टीकरण अल-ख्वारिज्मी द्वारा उद्धृत किए गए हैं और 10 वीं शताब्दी में अल बरूनी ने उल्लेख किया है कि आर्यभट्ट के अनुयायियों का मानना था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इस महान भारतीय वैज्ञानिक को

सम्मानित करने के लिए भारत के पहले उपग्रह और चंद्र क्रेटर का नाम आर्यभट्ट रखा गया था।

3. कॉर्नवालिस ने तत्कालीन बंगाल में कृषि में गिरावट की प्रवृत्ति को देखते हुए भूमि राजस्व के स्थायी निर्धारण को इसके पुनरोद्धार की दिशा में सबसे अच्छा उपकरण माना। क्या कार्नवालिस की धारणा सही थी?

लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त का प्रस्ताव रखा। यह ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाली जमींदारों के बीच भूमि राजस्व तय करने के लिए एक समझौता था जिसका भारत के लिए दूरगामी प्रभाव हुआ।

स्थायी बंदोबस्त की ओर ले जाने वाली परिस्थितियां:

1. यह मानना था कि मौजूदा राजस्व प्रणाली से कंपनी को फायदा नहीं हो रहा था और साथ ही यह कृषि को बर्बाद कर रहा था।
2. कंपनी के व्यापार को लाभ करने वाली कृषि की धीमी वृद्धि।
3. कंपनी की औपनिवेशिक प्रकृति अधिक से अधिक राजस्व निकालना चाहती थी।
4. यह सोचा गया था कि इस स्थिति को सुधारने का विकल्प स्थायी रूप से भू राजस्व दर तय करना है। इस प्रकार, राजस्व प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए कॉर्नवालिस को विशिष्ट शक्तियों के साथ भेजा गया था।

स्थायी बंदोबस्त से उम्मीदें:

1. यह माना गया था कि यह भ्रष्टाचार को कम करेगा।
2. यदि संपत्ति के अधिकार सुरक्षित होंगे, तो जमींदार भूमि के उन्नयन में निवेश करेगा।
3. कंपनी को अपने कर नियमित रूप से प्राप्त होंगे और यदि आवश्यक हो, तो वह व्यापार और वाणिज्य पर कर लगाकर अपनी आय बढ़ा सकती है।
4. बड़ी संख्या में किसानों की तुलना में सीमित संख्या में जमींदारों से राजस्व एकत्र करना भी आसान था।

स्थायी बंदोबस्त का प्रभाव:

1. भूमि को निजी संपत्ति बनाया गया। हालाँकि, यह मिथ्या नाम था, क्योंकि पूर्ण स्वामित्व कंपनी द्वारा बरकरार रखा गया था। समय पर कर न चुका पाने के कारण संपत्ति की बिक्री बार-बार होती थी।
2. इसने जमींदारों में भूमि के अधिकार निहित किए, जिन्हें पहले राजस्व एकत्र करने के अधिकार प्राप्त थे। इससे किसानों का शोषण हुआ क्योंकि वे जमींदारों के काश्तकार बन गए थे।
3. अनौपचारिक बिचौलियों में वृद्धि हुई जिसने किसानों को और अधिक गरीब बना दिया।
4. कृषि तकनीक या सिंचाई अवसंरचना में कोई सुधार नहीं हुआ।
5. इसने समाज में सामाजिक-आर्थिक असमानता को गहरा किया। धीरे-धीरे जमींदारों ने विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए पर्याप्त संपत्ति अर्जित कर लिया, जबकि लोग गांवों में भूखे मर रहे थे।

इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि कार्नवालिस की धारणाएँ सही नहीं थीं। जल्द ही ब्रिटिश अधिकारियों ने इस प्रणाली के गुणों पर संदेह करना शुरू कर दिया, जबकि दोष अधिक प्रमुख हो गए। इस प्रकार रैयतवारी और महलवारी जैसी वैकल्पिक व्यवस्थाएँ तैयार की गई।

4. 18वीं शताब्दी में जब भारत औपनिवेशिक शासन के तहत तेजी से बदल रहा था, इसने दो प्रकार के सामाजिक-धार्मिक आंदोलनों को देखा। इस संदर्भ में भारत में सुधारवादी और पुनरुत्थानवादी सामाजिक- धार्मिक आंदोलनों के बीच अंतर करें।

स्वतंत्रतापूर्व भारत के इतिहास में 19वीं शताब्दी सामाजिक-धार्मिक क्षेत्र में तीन धाराओं के रूप में संक्रमण और संघर्ष की अवधि थी: सुधार, पुनरूद्धार और प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों की अस्वीकृति। ये विचार ही प्रख्यात बुद्धिजीवियों द्वारा शुरू किए गए उन सामाजिक-धार्मिक आंदोलनो या सामाजिक सुधार आंदोलनों के केंद्र में थे जिसे इस समय में प्रारंभ किया गया था। सुधारवादी और पुनरूत्थानवादी आंदोलनों को निम्नलिखित प्रकार से विभेदित किया जा सकता है:

पुनरूत्थानवादी सुधार आंदोलन:

- पुनरूत्थानवादी आंदोलन की प्रवृत्ति पूर्व रीति-रिवाजों या प्रथाओं को पुनर्जीवित करने और इस प्रकार समाज को गौरवशाली अतीत में वापस ले जाने की थी।
- पुनरूत्थानवादी आंदोलन का मानना था कि पश्चिमी सोच और मिशनरी प्रचार भारतीय संस्कृति और लोकाचार को बर्बाद कर देंगे, और इस प्रकार धर्म की रक्षा करने की आवश्यकता थी। वे पश्चिमी विद्वानों द्वारा प्रकाश में लाए गए भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से भी प्रभावित थे और उन्होंने पाया कि यह पश्चिमी संस्कृति से भी श्रेष्ठ थी।
- इस प्रकार के आन्दोलन के उदाहरण में -आर्य समाज, देवबंद, वहाबी आंदोलन आदि हैं।

सुधारवादी आंदोलन:

- सुधारवादी आंदोलन ने मौजूदा संस्थाओं के भीतर क्रमिक परिवर्तनों के माध्यम से समाज की मूलभूत व्यवस्था और संरचनाओं को बदलने का प्रयास किया।
- सुधारवादी आंदोलन सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्र में आधुनिक पश्चिमी विचारों जैसे लैंगिक समानता, जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता आदि से प्रभावित थे।
- इन आंदोलनों के नेताओं ने आधुनिक पश्चिमी विचारों को स्वीकार करते हुए भी पश्चिमी संस्कृति के अंधानुकरण का विरोध किया। उनका उद्देश्य आधुनिकीकरण था, पश्चिमीकरण नहीं।
- इस प्रकार के आन्दोलन के उदाहरण-ब्रह्म समाज, अलीगढ़ आंदोलन आदि हैं।

इस प्रकार, इन आंदोलनों ने राष्ट्रवाद के उदय के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया जिसने अंततः अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने और भारत को एक स्वतंत्र गणराज्य बनाने का मार्ग प्रशस्त किया।

5. 1857 के विद्रोह की असफलता के लिये ब्रिटिश दमनकारी नीतियों की तुलना में भारतीय अधिक उत्तरदायी थे।

टिप्पणी कीजिए।

1857 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरोध में, भारत में एक प्रमुख विद्रोह हुआ, 1857 का विद्रोह, इस घटना को सिपाही विद्रोह, भारतीय विद्रोह, महान विद्रोह, 1857 का विद्रोह, भारतीय पुनरूत्थान और भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जैसे कई नामों से जाना जाता है। विद्रोह को प्रारंभ के बाद के एक वर्ष में दबा दिया गया। भारी दमन के अलावा और भी कई कारण थे जिनके कारण इस शक्तिशाली विद्रोह का पतन हुआ इनमें कुछ का श्रेय देश के मूल निवासियों को भी जाता है। इसे निम्न प्रकार समझा जा सकता है:

- **राष्ट्रवाद की भावना का अभाव-** विद्रोह में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। ज्यादातर लोगों ने केवल 'फिरंगी' ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति साझी घृणा के कारण सिपाहियों का समर्थन किया।
- **अखिल भारतीय भागीदारी का अभाव-** 1857 में मेरठ से शुरू हुआ विद्रोह अधिक स्थानीकृत था यह देश के उत्तरी भाग जैसे कानपुर, बनारस, लखनऊ, झांसी में अधिक फैला जबकि अन्य भागों में इसके अधिक समर्थन नहीं मिला।
- **एकता का अभाव-** विद्रोहियों में एकता की कमी थी, बंगाल के सिपाही ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे जबकि पंजाब और बॉम्बे के सैनिकों ने सिपाहियों के खिलाफ कंपनी का समर्थन किया।
- **सभी वर्गों की भागीदारी का अभाव-** सभी वर्ग विद्रोह में शामिल नहीं हुए और कुछ वर्गों ने तो विद्रोह के खिलाफ अंग्रेजों का समर्थन किया। कैनिंग के अनुसार, बड़े जमींदारों और साहूकारों ने ''तूफान के लिए अवरोध'' के रूप में कार्य किया।
- **शासक वर्ग से कोई समर्थन नहीं-** उस समय के शासक वर्ग ब्रिटिश नीति के पक्षधर थे। उन्होंने विद्रोह में शामिल होने से इनकार कर दिया और अंग्रेजों को सक्रिय समर्थन प्रदान किया।
- **खराब हथियार और उपकरण-** जहां एक तरफ विद्रोही तलवारों, भाले और बहुत सीमित बंदूकों (लूटे गए शास्त्रों) के द्वारा संघर्ष कर रहे थे तो वहीं दूसरी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी एनफील्ड राइफल जैसे युद्ध के सबसे उन्नत हथियारों से लैस थी।
- **खराब संगठन-** विद्रोह के प्रत्येक नेता ने अपने क्षेत्र में अपनी लड़ाई लड़ी और दूसरों के साथ एकजुट नहीं हो सके।
- **कोई सामान्य लक्ष्य नहीं-** विद्रोह में इसके पीछे कोई सामान्य विचार या लक्ष्य नहीं था। कई क्षेत्रों पर नियंत्रण करने के बाद, नेताओं और विद्रोहियों के पास भारत के लिए कोई दूरदर्शी योजना नहीं थी वे पुराने दिनों की ही तरफ लौट रहे थे।
- हालाँकि, विद्रोह को अंग्रेजों ने दबा दिया, लेकिन 1857 के विद्रोह ने भारतीय लोगों को एकजुट करने और देशभक्ति की भावना जगाने तथा जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

6. कांग्रेस का उदय एक लंबी प्रक्रिया थी, यह कभी भी आकस्मिक घटना नहीं थी। क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन पहले के घटनाक्रमों की तार्किक परिणति थी?

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन दिसंबर 1885 में डब्ल्यू सी बनर्जी की अध्यक्षता में एक साझा मंच के रूप में और भागीदारी, नेतृत्व और मांगों के संदर्भ में क्षेत्रीय मतभेदों को पाटने के लिए किया गया था। कांग्रेस के गठन के संबंध में एक दृष्टिकोण यह है कि यह ए.ओ. ह्यूम के प्रयासों के कारण कांग्रेस अस्तित्व में आई। हालाँकि, 1885 में कांग्रेस के गठन से पहले की भारत की राजनीति को देखने से पता चलता है कि यह भारत में हो रही राजनीतिक गतिविधियों की तार्किक परिणति थी।

कांग्रेस-पूर्व संगठनात्मक प्रयास

1. शिक्षित भारतीयों के समूह तीनो प्रेसिडेंसियों में राजनीतिक रूप से सक्रिय थे। नागरिक स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए नित नए संगठन बन रहे थे और कई राष्ट्रीय मुद्दों पर देशव्यापी आंदोलन आयोजित हो रहे थे जैसे 1850 के लेक्स लोकी अधिनियम,1867 में आयकर, इल्बर्ट बिल विवाद, आदि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन।
2. 1851 में, कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई, और इसने अन्य दो प्रेसीडेंसियों में शाखाएँ स्थापित करने का प्रयास किया। यह अखिल भारतीय संपर्क स्थापित करने के पहले प्रयासों में से एक था।
3. फिर, 1877 में, दिल्ली दरबार के दौरान, भारतीय पत्रकारों ने नेटिव प्रेस एसोसिएशन बनाया और एस.एन. बनर्जी इसके पहले सचिव थे। वे प्रेस और देश से संबंधित मामलों के समाधान के लिए वर्ष में एक या दो बार मिलने के लिए सहमत हुए।
4. इंडियन एसोसिएशन (1876 में स्थापित) ने 1883 में कलकत्ता में और फिर 1885 में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया।
5. एक राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता की जांच करने के लिए 1884 में थियोसोफिकल सोसाइटी के वार्षिक सम्मेलन के मौके पर देश के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने मद्रास में मुलाकात की।

अतः, एक राष्ट्रीय संगठन का गठन अपरिहार्य था। हालाँकि, इन सभी क्षेत्रीय नेताओं को एक संगठनात्मक छत के नीचे लाने के लिए अभी भी एक मध्यस्थ की आवश्यकता थी। ह्यूम इस पद के लिए उपयुक्त थे, क्योंकि विदेशी होते हुए भी वे सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को स्वीकार्य थे। इस प्रकार, यह ह्यूम नहीं थे जिसके कारण कांग्रेस का गठन हुआ, बल्कि यह पहले के दशकों का विभिन्न प्रयासों का सम्मिलित परिणाम था।

7. स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय समाज का सबसे अधिक प्रभावित और सबसे अधिक भाग लेने वाला गुट किसान था। राष्ट्रवादी चरण के दौरान किसान आंदोलन की प्रकृति का मूल्यांकन करें।

औपनिवेशिक नीतियों के कारण भारतीय समाज का प्रत्येक वर्ग ब्रिटिश भारत के अधीन पीड़ित था। सरकार की दिलचस्पी केवल लगान को अधिकतम करने और राजस्व में अपना हिस्सा हासिल करने में थी। इसने भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए बहुत कम प्रयास किए। किसान, सरकार, जमींदार और उन्हें गरीब बनाने वाले साहूकारों के तिहरे बोझ तले दबे थे। इसलिए स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भारी भागीदारी हुई।

किसान आंदोलनों की प्रकृति

- किसान अपनी मांगों के लिए सीधे लड़ते हुए, कृषि आंदोलनों में मुख्य शक्ति के रूप में उभरे।
- इन आंदोलनों में मांगें लगभग पूरी तरह से आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित थी।
- आंदोलन किसानों के प्रत्यक्ष शत्रुओं-विदेशी बागान मलिकों और स्वदेशी जमींदारों तथा साहूकारों के खिलाफ केंद्रित थे।
- संघर्षों को विशिष्ट और सीमित उद्देश्यों और विशेष शिकायतों के निवारण के लिए निर्देशित किया गया था।
- उपनिवेशवाद इन आंदोलन का लक्ष्य नहीं थी। उपनिवेशवाद की पर्याप्त समझ का अभाव था।
- इन आंदोलनों का उद्देश्य किसानों की अधीनता या शोषण की व्यवस्था को समाप्त करना नहीं था।
- प्रादेशिक पहुंच सीमित थी।
- संघर्ष या दीर्घकालिक संगठन की कोई निरंतरता नहीं थी।
- किसानों ने अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता विकसित की और अदालतों के अंदर और बाहर उनका दावा किया।
- 19वीं सदी के किसानों के पास नई विचारधारा और एक नया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था।
- ये संघर्ष, हालांकि उग्रवादी, पुरानी सामाजिक व्यवस्था के ढांचे के भीतर हुए, जिसमें वैकल्पिक समाज की सकारात्मक अवधारणा का अभाव था।

प्रमुख किसान आंदोलनों के कुछ उदाहरण हैं: चंपारण सत्याग्रह, मोपला किसान विद्रोह, खेड़ा सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह और तेभागा आंदोलन।

8. स्वराज पार्टी ने राजनीतिक, संवैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के लिए औपनिवेशिक सरकार के कार्यों में बाधा को माध्यम बनाया। यह सभी स्वराज की प्राप्ति के लिए आवश्यक थे। स्वराज पार्टी किस हद तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रही?

कांग्रेस के गया अधिवेशन के बाद जनवरी, 1923 में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। पार्टी का नाम 'स्वराज' शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है 'स्व-शासन' या 'स्वतंत्रता'।

स्वराज पार्टी के उद्देश्य:

- 1923 में नई केंद्रीय विधान सभा के चुनाव में भाग लेने के लिए और,
- एक बार सदन में प्रवेश के बाद आधिकारिक नीति को बाधित करने और परिषद के भीतर सरकार विरोधी आंदोलन द्वारा ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए।
- देश की स्थिति के अनुकूल संविधान बनाने का अधिकार प्राप्त करना।
- स्वराज पार्टी के कार्यक्रम में जनसंपर्क, हिंदू-मुस्लिम एकता और सामाजिक कार्य के साथ-साथ सामाजिक सुधार भी शामिल थे।
- भारत के लिए प्रभुत्व का दर्जा प्राप्त करना पार्टी का तात्कालिक लक्ष्य घोषित किया गया था।

स्वराज पार्टी की उपलब्धियां:

- स्वराजवादियों ने 1923 के चुनावों में भाग लिया और वे काफी सफल रहे। उन्होंने केंद्रीय विधान सभा की 101 खुली सीटों में से 42 सीटें जीतीं।
- 1925 में स्वराजवादी विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कराने में सफल रहे। उन्होंने दमनकारी कानूनों की समाप्ति, नागरिक अधिकारों की बहाली आदि जैसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को भी उठाया।
- उन्होंने सरकारी कानून को बार-बार अवरुद्ध किया। सरकारी कानूनों को पारित कराने के लिए गवर्नरों और गवर्नर जनरल को विशेष शक्तियों का उपयोग करना पड़ा।
- वे कपास पर उत्पादन कर को समाप्त करने, नमक कर में कमी करने में सफल रहे।
- उन्होंने 1925 में 1919 के अधिनियम की जांच के लिए अलेक्जेंडर मुडीमेन समिति का गठन भी किया।
- उन्होंने अस्पृश्यता को दूर करने, बहिष्कृतों की शिक्षा, वयस्कों के लिए नाइट स्कूल, बच्चों के लिए डे स्कूल आदि के लिए काम किया।
- भारत के संवैधानिक विकास में स्वराजवादियों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान नेहरू रिपोर्ट था।

स्वराज पार्टी की विफलताएं:

- 1925 में, मोतीलाल नेहरू ने स्कीन समिति की सदस्यता स्वीकार की और विट्ठलभाई पटेल ने केंद्रीय विधान सभा के अध्यक्ष का पद स्वीकार किया। इन गतिविधियों ने यह आभास दिया कि स्वराजवादी पद के लाभों का आनंद ले रहे थे और वे अब असहयोग की नीति का पालन नहीं कर रहे थे। इस नकारात्मक प्रभाव ने उनकी सामूहिक अपील को प्रभावित किया।
- नेहरू रिपोर्ट ने बहुत विवाद उत्पन्न किया। इसने हिंदू और मुस्लिम नेतृत्व के बीच की खाई को भी चौड़ा किया।
- उनकी रणनीति विफल होने के लिए बाध्य थी क्योंकि स्वराज को संवैधानिक तरीकों से कभी नहीं जीता जा सकता था।

स्वराजवादियों की गतिविधियों ने कांग्रेस नेताओं को राजनीतिक अनुभव प्राप्त करने में मदद की जो भविष्य में तब काम आया जब अधिक से अधिक अधिकार भारतीय हाथों में स्थानांतरित हो गए। इसने जमीनी स्तर के नेतृत्व को बढ़ावा दिया और कांग्रेस संगठन की गहराई को बढ़ाया।

9. सांस्कृतिक मतभेदों के कारण बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ? बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारत द्वारा निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डालिए।

पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की वास्तविक मांगों की अनदेखी के परिणामस्वरूप केवल समान धर्म के आधार पर पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच बनाए गए बंधन पर सांस्कृतिक मतभेद हावी हो गए। इसके परिणामस्वरूप ही 1971 में बांग्लादेश का जन्म

हुआ।

सांस्कृतिक मतभेद जिसने बांग्लादेश को जन्म दिया:

1. बंगाली, पूर्वी पाकिस्तान की भाषा जो पश्चिमी पाकिस्तान की कई भाषाओं जैसे पंजाबी, सिंधी आदि से अलग थी।
2. इसके अलावा, बंगाली सबसे बड़ा भाषाई समूह था फिर भी बंगाली को पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली थी।
3. समान धर्म होने के बावजूद भोजन, वस्त्र आदि के मामले में पर्याप्त भिन्नताएं थीं। पूर्वी पाकिस्तान की इन सांस्कृतिक भिन्नताओं का सम्मान नहीं किया जाता था।
4. पूर्वी पाकिस्तान के अपेक्षाकृत उदार इस्लाम पर रूढ़िवादी इस्लामी प्रथाओं को लागू करना तथा सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के अधिकारों को सीमित करना आदि मतभेद के अन्य कारण थे।
5. पूर्वी पाकिस्तान का सांस्कृतिक केंद्र, ढाका सबसे बड़ा शहर होने के बावजूद राजधानी के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं था।

बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में भारत की भूमिका:

1. शुरुआत में भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के सांस्कृतिक रूप से प्रताड़ित लोगों के लिए नैतिक समर्थन प्रदान किया।
2. भारतीय सेना ने बांग्लादेश की मुक्ति सेना, मुक्ति वाहिनी को हथियारों और प्रशिक्षण के रूप में सहायता प्रदान की।
3. भारत ने शेख मुजिबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग को अंतरराष्ट्रीय समुदाय का समर्थन हासिल करने में मदद की।
4. पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना द्वारा ज्यादती की स्थिति में, भारत ने उत्पीड़ित प्रवासियों को शरण दी।
5. भारतीय सेना ने अंततः पाकिस्तान की सेना के आत्मसमर्पण को सुनिश्चित किया।
6. भारत सरकार ने बांग्लादेश के निर्माण के पक्ष में संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन प्राप्त किया।

इस प्रकार पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच सांस्कृतिक मतभेदों ने उप-राष्ट्रवाद को जन्म दिया और अंततः पाकिस्तान का विभाजन हुआ और 1971 में भारत के समर्थन से बांग्लादेश का जन्म हुआ।

10. ''आयरन कर्टन'' से लेकर बर्लिन की दीवार तक साम्यवाद का एक लंबा इतिहास रहा है। पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा?

20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक साम्यवाद ने दुनिया में मजबूत पैर जमा लिया था। 1970 के दशक तक दुनिया की एक-तिहाई आबादी किसी न किसी रूप में साम्यवाद के अधीन रह रही थी। हालाँकि, ठीक एक दशक बाद, दुनिया भर की कई प्रमुख कम्युनिस्ट सरकारें गिर गईं।

साम्यवाद के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति का विश्व पर प्रभाव:

1. 1991 में यूएसएसआर के पतन के परिणामस्वरूप लगभग 15 स्वतंत्र देशों का गठन हुआ जैसे आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया आदि।
2. ये नए राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे में चर्चा और समाधान के लिए नए मुद्दे लाए। समाजवादी गुट के टूटने और इन नए राष्ट्रों के जन्म के कारण बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों, विशेषरूप से आईएमएफ और विश्व बैंक से सहायता और निवेश की मांग में वृद्धि हुई।
3. यूएसएसआर के विघटन और पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट शासन के पतन ने भी दुनिया भर में, विशेष रूप से नवगठित राज्यों में लोकतांत्रिक राजनीतिक आंदोलनो को प्रेरित किया।
4. सोवियत संघ के पतन के बाद के वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रमुख वैश्विक महाशक्ति बनने में सफल रहा।
5. शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से, चीन एक प्रमुख विश्व महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हुआ है और यूरोपीय संघ ने उन क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाया है जो कभी मास्को नियंत्रित थे।
6. शीत युद्ध की समाप्ति, समाजवाद और समाजवादी गुट की विचारधारा के पतन के अलावा, आर्थिक वैश्वीकरण की प्रक्रिया के त्वरण का भी वाहक बनी।

साम्यवाद के पतन और शीत युद्ध के अंत ने भी बहुत अधिक घर्षण उत्पन्न किया जो आज भी जारी है। हालाँकि साम्यवाद लगभग समाप्त हो चुका है, फिर कुछ देश जैसेः चीन, क्यूबा आदि इस पर आधारित हैं।

11. भारत के बारे में प्रमुख यूनानी विवरण क्या हैं? क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि यह प्राचीन भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की अच्छी तस्वीर प्रस्तुत करता है?

बहुत से लोग जो विभिन्न देशों से भारत आए थे, उन्होंने विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपने विवरण दर्ज किए हैं। ये ग्रीक, लैटिन, चीनी और अरबी लेखन के रूप में उपलब्ध हैं।

प्रमुख यूनानी लेखन :

ग्रीक ग्रंथों में भारत का सबसे पहला उल्लेख ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से मिलता है और उसके बाद उनकी आवृत्ति बढ़ जाती है।

कुछ प्रमुख यूनानी लेखन हैं :

1. हेरोडोटस द्वारा लिखित इतिहास
2. मेगस्थनीज द्वारा लिखित इंडिका
3. एरियन के विवरण
4. रुफुस द्वारा सिकंदर महान का इतिहास
5. स्ट्रैबो द्वारा लिखित जियोग्राफिका
6. पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी (अज्ञात लेखक)

ग्रीक विवरणों से प्राप्त जानकारी-

सामाजिक:

1. वे सामाजिक परिस्थितियों जैसे सती, गरीब माता-पिता द्वारा लड़कियों की बिक्री, गुलामी आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं।
2. हेरोडोटस जनजातियों की सूची विस्तार से प्रदान करता है। मेगस्थनीज ने व्यवसाय के आधार पर भारतीय समाज के विभाजन का उल्लेख किया है।
3. भारतीयों द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों, खान-पान और दैनिक जीवन

के अन्य पहलुओं का भी उल्लेख मिलता है।

राजनीतिक:

1. वे सिकंदर के भारतीय अभियान का विस्तृत विवरण देते हैं और उस समय उत्तर पश्चिम भारत में रियासतों की संख्या के बारे में जानकारी देते हैं।
2. हमें विभिन्न शासकों जैसे नंद वंश, मौर्य आदि की सैन्य शक्ति के बारे में भी जानकारी मिलती है।
3. मेगस्थनीज पाटलिपुत्र की प्रशासनिक व्यवस्था का अच्छा विवरण प्रदान करता है।

आर्थिक:

1. हेरोडोटस हमें बताता है कि भारत फारसी साम्राज्य का सबसे समृद्ध क्षत्रप था।
2. पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी हमें विभिन्न भारतीय बंदरगाहों जैसे- टोंडी, मुचिरी आदि से आयात और निर्यात आदि के बारे में बताता है जिसके माध्यम से हम भारत के व्यापार संबंधों को समझते हैं।
3. मेगस्थनीज हमें बताता है कि कर निर्धारण के लिए, भूमि को मिस्र की तरह मापा जाता था और राज्य के अधिकारी भी पानी के उपयोग के लिए सिंचाई चैनलों की निगरानी करते थे।

भारत के संबंध में ग्रीक विवरण की कमियां:

1. वे भारतीय समाज के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझ नहीं सके जैसे-मेगस्थनीज ने कहा कि भारत में कोई गुलामी नहीं थी। उन्होंने भारतीय समाज को भी 7 जातियों में विभाजित किया।
2. वे ज्यादातर भारत के उत्तर पश्चिमी भाग से संबंधित थे और आम तौर पर अन्य भागों को छोड़ देते थे।
3. उन्होंने शिक्षित यूनानी लोगों के लिए लिखा और उनका उद्देश्य केवल सूचित करना ही नहीं बल्कि मनोरंजन करना भी था। इस प्रकार, उनमें अक्सर सटीकता और विश्वसनीयता की कमी होती है। जैसे-सोने की खुदाई करने वाली चींटियों का हेरोडोटस का विवरण।
4. प्रारंभिक यूनानी लेखकों की अधिकांश रचनाएँ लुप्त हो चुकी हैं और केवल टुकड़ों में उपलब्ध हैं।

विदेशी होने के कारण उनके काम उपयोगी थे क्योंकि उन्होंने भारतीय जीवन के उन पहलुओं को महत्व दिया था जिन्हें भारतीय अनदेखा करते थे। लेकिन उनके लेखन में भारत के बारे में ज्ञान और समझ की कमी है। इस प्रकार, हमें इन विवरणों की वैधता का पता लगाने के लिए इतिहास के अन्य स्रोतों के साथ पुष्टि करनी होगी।

12. यह दक्षिण भारत था जहां भक्ति आंदोलन लोकप्रिय हुआ। अलवार और नयनार किस सीमा तक धार्मिक क्षेत्र का लोकतंत्रीकरण करने में सक्षम हुये? महिलाओं और निम्न जाति की भागीदारी के संदर्भ में व्याख्या कीजिए।

भक्ति सिद्धांत की उत्पत्ति प्राचीन भारत की ब्राह्मणवादी और बौद्ध परंपराओं के साथ-साथ गीता जैसे विभिन्न ग्रंथों में भी देखी जा सकती है। 7वीं और 10वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत में भक्ति पहली बार धार्मिक समानता और व्यापक सामाजिक भागीदारी पर आधारित एक लोकप्रिय आंदोलन के रूप में विकसित हुई।

अलवार और नयनारो द्वारा धार्मिक क्षेत्र का लोकतंत्रीकरण:

1. दक्षिण भारत के शैव नयनार संतों और वैष्णव अलवार संतों ने जाति या लिंग की परवाह किए बिना समाज के सभी वर्गों में भक्ति के सिद्धांत का प्रसार किया।
2. इनमें से कुछ संत जैसे नंदनार और तिरुप्पन 'निम्न' जातियों के थे, जबकि अन्य, जैसे कि कराईक्कल अम्मैयार और अंडाल, महिलाएं थीं। संत-कवियों ने बड़ी भावना से भक्ति का प्रचार किया और धार्मिक समानता को बढ़ावा दिया।
3. उन्होंने संस्कृत के बजाय तमिल में भक्ति गीतों की रचना की और प्रचार किया। इन सभी विशेषताओं ने आंदोलन की लोकप्रियता में योगदान दिया।
4. उन्होंने जाति या लिंग की परवाह किए बिना सभी को भक्ति का मार्ग उपलब्ध कराकर रूढ़िवादी ब्राह्मणों के अधिकार की अवहेलना की।

अलवार और नयनारों की सीमाएं-

अछूतों के सम्बन्ध में:

1. सामाजिक स्तर पर, इसने कभी भी सीधे तौर पर ब्राह्मणवाद या वर्ण और जाति व्यवस्था का विरोध नहीं किया।
2. पूजा की श्रेष्ठ विधा के रूप में भक्ति पर जोर देने के बावजूद, मूर्ति पूजा, वैदिक मंत्रों का पाठ और पवित्र स्थानों की तीर्थयात्रा जैसे ब्राह्मणवादी अनुष्ठानों का कोई उन्मूलन नहीं हुआ।
3. चूँकि इन संत-कवियों ने जाति व्यवस्था की वैचारिक और सामाजिक नींव पर सवाल नहीं उठाया, इसलिए दक्षिण के भक्ति आंदोलन ने इसे लंबे समय में कमजोर करने के बजाय मजबूत ही किया।

महिलाओं के संबंध में:

1. इनमें बहुत कम महिला भक्ति संत हैं। नयनारों में तीन जबकि अलवर में केवल एक ही महिला संत है।
2. महिलाओं को मठों में प्रवेश नहीं दिया जाता था। केवल रामानुज के समय (11वीं शताब्दी) के दौरान और वीरशैव आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के साथ ही महिला भक्तों को शैव भक्ति में अधिक सक्रिय भूमिका दी गई।
3. पुरुषों और महिलाओं के भक्ति अनुभवों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर था। पुरुष संतों के मामले में गृहस्थ के जीवन और भगवान की भक्ति के बीच कोई संघर्ष नहीं था। जबकि महिलाओं के विवाह और पारिवारिक जीवन को भक्ति के साथ संतुलित कर पाना कठिन था।

यद्यपि भक्ति आंदोलन के नेतृत्व में कुलीन समूहों, विशेष रूप से ब्राह्मणों का वर्चस्व था फिर भी इस आंदोलन ने समाज के अन्य वर्गों के लिए आराधना व भक्ति का नया मार्ग सुझाया। आगे उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रसार हुआ और समय के साथ इसने समानता के भाव का भी प्रसार किया।

13. यह न केवल राजनीतिक क्षेत्र था जिसमें तुर्कों ने आक्रमण किया बल्कि सांस्कृतिक क्षेत्र में भी इनकी उपस्थिति महसूस की गई। भारत में तुर्कों द्वारा लाए गए नए वास्तुशिल्प नवाचारों के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या करें।

घुरिद वंश द्वारा उपमहाद्वीप पर आक्रमण के बाद, पांच राजवंशों ने क्रमिक रूप से दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। उन्होंने भारतीय राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में कई नई विशेषताएं समाहित की। तुर्क द्वारा लाए गए परिवर्तन-

1. **राजनीतिक:** इसने सामंती, बहु-केन्द्रित राज्य व्यवस्था को एक केंद्रीकृत राज्य से बदल दिया जिसमें सुल्तान को व्यावहारिक रूप से असीमित शक्ति प्राप्त थी। राजत्व के स्वरूप में भी परिवर्तन देखा गया।
2. **आर्थिक:** वे अपने साथ शहरी क्षेत्रों में रहने की परंपरा लेकर आए। इस प्रकार, शहरी अर्थव्यवस्था और संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा मिला।
3. **प्रशासनिक:** विभिन्न प्रशासनिक परिवर्तन किए गए, जैसे इक्ता प्रणाली की शुरुआत, नए विभागों का निर्माण आदि। सैन्य संगठन में भी बदलाव लाए गए।
4. **सांस्कृतिक:** उन्होंने फारसी साहित्य, लघु चित्रकला, सूफीवाद आदि का विकास किया।

तुर्कों द्वारा लाए गए नए वास्तुशिल्प नवाचार:

1. **चूना मोर्टार :** प्राचीन भारत में निर्माण की पारंपरिक बुनियादी इकाइयों में मिट्टी, पत्थर, लकड़ी और कभी-कभी ईंटें शामिल थीं। सबसे सरल सीमेंटिंग सामग्री या मोर्टार पानी के साथ मिश्रित सादी मिट्टी थी। तुर्कों ने चूने के मोर्टार को सीमेंटिंग सामग्री के रूप में प्रयोग किया। इसने परिष्कृत मेहराब के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया।
2. **परिष्कृत मेहराब और गुंबद:** पूर्व-तुर्की रूपों जैसे कि लिंटेल-बीम और कोरबेलिंग को मेहराबों से बदल दिया गया था और छतों (शिखर) के स्थान पर गुंबदों का प्रयोग किया गया। मेहराब और गुम्बद की जानकारी भारतीयों को पहले से थी, लेकिन इनका प्रयोग बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता था। मेहराब और गुम्बद के प्रयोग से ऊँचे और प्रभावशाली भवनों का निर्माण हुआ। मेहराब और गुंबद के संयोजन ने छत को सहारा देने के लिए बड़ी संख्या में स्तंभों की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया।
3. **पत्थर की चुनाई:** खिलजी काल के दौरान पत्थर की चुनाई की एक नई विधि का इस्तेमाल किया गया था। तुर्कों ने लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया।
4. **आइकॉनोग्राफी:** इस्लाम में जीवों के चित्रण की अनुमति नहीं थी। अत: ज्यादातर मामलों में सजावट के तत्व सुलेख, ज्यामिति और पत्ते थे।
5. **नए प्रकार के भवन:** मुस्लिम शासकों के आने से नए प्रकार के भवनों का निर्माण हुआ। बड़े पैमाने पर मस्जिदों और मकबरों का निर्माण किया गया। कुतुब मीनार जैसी मीनारों का भी निर्माण कराया गया। इसके अलावा सराय, कचहरी, डाक चौकी आदि सार्वजनिक भवनों का निर्माण कराया गया।

तुर्क शासकों द्वारा निर्मित प्रमुख इमारतें-

1. कुतुब मीनार
2. कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ढाई दिन का झोपड़ा
3. हजरत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा
4. अलाई दरवाजा
5. गयासुद्दीन तुगलक तथा अन्य शासकों के मकबरे आदि।

तुर्कों द्वारा शुरू की गई नई स्थापत्य विशेषताओं को बाद में मुगलों ने अपने नवाचारों के साथ और उत्कृष्ट बना दिया। इससे कई खूबसूरत इमारतों के साथ अद्‌भुत इंडो-इस्लामिक वास्तुकला का निर्माण हुआ।

14. अकाल ने पीढ़ियों से भारत को प्रभावित किया था। यद्यपि ब्रिटिश इस संबंध में विभिन्न नीतियां लेकर आए, लेकिन वे इस मुद्दे की जड़ तक पहुंचने में विफल रहे। भारत पर अकाल के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का विवरण दीजिए। ब्रिटिश अकाल नीतियों की विफलता के कारणों का भी विश्लेषण कीजिए।

प्राचीन भारत से हमारे पास अकाल के कई प्रमाण हैं। ये अकाल प्राकृतिक आपदाएँ थीं। हालाँकि, ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीति के कारण अकाल की घटनाओं में वृद्धि हुई।

प्रमुख अकाल:

- 1770 के बंगाल के अकाल में लगभग एक तिहाई आबादी काल का ग्रास बन गई।
- 1784 का मद्रास अकाल।
- 1792 का उत्तर भारत का अकाल।
- 1833 का गुंटूर अकाल जिसमें 40% लोगों की मृत्यु हो गई।
- 1860, उत्तर पश्चिमी प्रांतों में अकाल।
- 1873-74, बंगाल और बिहार में अकाल
- 1896, भारत के विभिन्न भागों में अकाल।
- 1943, बंगाल में अकाल।

अकाल नीति:

1. ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे पूरी तरह नजरंदाज किया। ब्रिटिश क्राउन को सत्ता के हस्तांतरण के बाद ही किसी प्रकार की अकाल नीति विकसित हुई।
2. 1861 में कर्नल बेयर्ड समिति नियुक्त की गई लेकिन इसने कोई महत्वपूर्ण अध्ययन नहीं किया और स्थिति काफी हद तक अपरिवर्तित रही।
3. 1866 में जॉर्ज कैंपबेल समिति का गठन किया गया था। समिति ने सुझाव दिया कि रोजगार पैदा करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए और अकाल राहत के उपाय किए जाने चाहिए।
4. 1880 में रिचर्ड स्ट्रेची आयोग नियुक्त किया गया था जिसने सुझाव दिया था - (1) एक अकाल संहिता तैयार की जाए, (2) अकाल

प्रभावित क्षेत्रों के लिए भू-राजस्व समाप्त किया जाना चाहिए।

5. 1896 के अकाल के बाद, जेम्स ब्रॉडवुड लायल आयोग नियुक्त किया गया था हालांकि कुछ ठोस कदम नहीं उठाए गए।
6. 1899 में मैकडॉनेल आयोग की नियुक्ति की गई जिसने सिफारिश की: (1) राहत उपायों के समन्वय के लिए अकाल आयोग की स्थापना की जाए, (2) अकाल संहिता को संशोधित किया जाए आदि।
7. बंगाल के अकाल के बाद जॉन वुडहैड आयोग नियुक्त किया गया जिसने खाद्य और कृषि विभागों के विलय और कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम उठाने का सुझाव दिया।

अकाल का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव:

1. इन अकालों का दीर्घकालिक जनसंख्या वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, विशेषकर 1871-1921 के बीच।
2. सामाजिक व्यवस्था के टूटने से बड़े पैमाने पर पलायन, भीड़भाड़, अस्वच्छता, पानी की खराब गुणवत्ता आदि विभिन्न समस्याएं पैदा हुई।
3. अकालों के कारण व्यापक अस्वच्छ स्थितियां, भयावह स्वच्छता समस्याएं और बीमारियों का फैलाव हुआ।
4. 'कपड़े के अकाल' के दौरान, बंगाल के गरीबों की लगभग पूरी आबादी को सर्दियों के दौरान नग्न या बहुत कम कपड़ों की स्थिति में छोड़ दिया गया था।

ब्रिटिश अकाल नीतियों की विफलता के कारण:

1. ब्रिटिश काल में अकाल भोजन की कमी के कारण नहीं बल्कि भोजन के वितरण में असमानताओं के कारण थे। यह ब्रिटिश साम्राज्य की अलोकतांत्रिक प्रकृति के कारण था।
2. कृषि में निवेश की कमी बनी रही, जो अकाल की स्थिति के विकास को रोकने के लिए आवश्यक थी।
3. ब्रिटिश नीतियों ने किसानों के संसाधनों को राजस्व बिचौलियों , साहूकारों और कृषि वस्तुओं के व्यापारियों के हाथों में जाने जैसे मुद्दों की अनदेखी की।
4. कंपनी की दोषपूर्ण अकाल नीतियां 1880 में अकाल आयोग की रिपोर्ट द्वारा भी स्वीकार की गई थीं, जिसमें राहत प्रदान करने के लिए कंपनी के आधे-अधूरे प्रयास की बात की गई थी।

ब्रिटिश सरकार ने विशेष रूप से अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों के लिए भारत पर कब्जा किया था। इसलिए, उन्होंने स्थानीय आबादी के बीच बढ़ती मृत्यु दर को देखने व कम करने के लिए बहुत कम या कोई दायित्व महसूस नहीं किया।

15. 1915 में जब गांधी वापस लौटे, भारत में राजनीतिक परिदृश्य भ्रमित था। इस अवधि के दौरान हुई प्रमुख घटनाओं पर प्रकाश डालते हुए, स्वतंत्रता संग्राम में केंद्रीय स्थान बनाने में गांधी की भूमिका पर चर्चा करें।

महात्मा गांधी 1915 में भारत पहुंचे। गांधी के आगमन से पहले, राष्ट्रवादी राजनीति केवल पश्चिमी शिक्षित पेशेवरों के एक छोटे समूह द्वारा की जाती थी। आम जनता का इन आंदोलनों और राजनीति से अधिक जुड़ाव नहीं था।

गांधी के आगमन के समय की स्थिति:

1. इसी समय राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था जिसने राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी थी।
2. प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था और भारत को ब्रिटेन की ओर से भाग लेने के लिए मजबूर किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती, अत्यधिक कर, युद्ध ऋण और युद्ध के कारण कीमतों में अचानक वृद्धि ने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों को नुकसान पहुंचाया था। इन सब ने ब्रिटिश और भारतीय हितों के बीच संघर्ष को बढ़ा दिया था।
3. एनी बेसेंट और तिलक के होम रूल आंदोलन ने भारतीय राजनीति को अधिक जागृत बना दिया।
4. बंगाल में युवा क्रांतिकारियों और उत्तरी अमेरिका में गदर पार्टी ने ब्रिटिश विरोधियों के साथ गठबंधन बनाकर स्थिति का लाभ उठाने का प्रयास किया। जर्मनी से हथियार और गोला-बारूद प्राप्त करने के प्रयासों के साथ-साथ सशस्त्र डकैतियों में वृद्धि हुई। 1914 में कुख्यात कामागाटामारू घटना हुई।
5. 1916 के लखनऊ समझौते ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक साथ ला दिया और भारतीय स्व-शासन के विचार को ब्रिटिश राजनीतिक हलकों में अधिक वैधता प्रदान की।
6. फिर मोंटेग्यू घोषणापत्र था, जिसमें कहा गया था कि भारत में ब्रिटिश नीति भविष्य में स्वशासी संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए तैयार की जाएगी।

गांधी ने कैसे केंद्रीय स्थान ग्रहण किया:

1. दक्षिण अफ्रीका में गांधी के अहिंसा के सिद्धांत (संघर्ष और सफलता) ने भारतीय राजनीतिक दायरे में गांधी के लिए सम्मान पैदा किया था।
2. गांधी ने सामाजिक न्याय का एक दृष्टिकोण अपनाया जिसमें आम जनता शामिल थी। उन्होंने मई 1915 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की जहां उन्होंने अपने विचारों को प्रसारित करने का प्रयास किया।
3. 1917 और 1918 के बीच, गांधी ने तीन सत्याग्रह शुरू किए: चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। तीनों मामलों में सफल बातचीत हुई और गांधी ने एक ऐसे व्यक्ति के रूप में ख्याति अर्जित की जिन्होंने स्थानीय समस्याओं को उठाया और वास्तविक परिणाम प्राप्त किए। यह पूर्व के आंदोलनो से भिन्न घटना थी।
4. उनकी पद्धति को ऊपर-नीचे के बजाय नीचे से ऊपर की ओर देखा जाने लगा।
5. सत्ता में उनका निरंतर उत्थान मुसलमानों, निम्न जाति के हिंदुओं और व्यापारियों के साथ उनके जुड़ाव से संभव हुआ- ये ऐसे समूह थे जिनका पूर्व में कांग्रेस की राजनीति में कोई विशेष स्थान नहीं था।
6. गांधी ने राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, वल्लभभाई पटेल आदि जैसे नए नेताओं को प्रोत्साहन दिया, जिन्होंने किसान और श्रमिक लामबंदी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

7. रॉलेट एक्ट के उदाहरण में, इसके बावजूद कि सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया, केवल गांधी ही थे जिन्होंने एक अहिंसक अखिल भारतीय जन विरोध का प्रस्ताव रखा था।

राष्ट्रीय राजनीति में गांधी का उदय उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं और विचारधारा के कारण था जिसकी जड़ें भारतीय संस्कृति में ही निहित थी। इसके साथ ही उनके आगमन के समय भारतीय राजनीति की तत्कालीन स्थिति के कारण नए दृष्टिकोण की आवश्यकता भी थी जिसे गांधी ने पूरा किया।

16. सविनय अवज्ञा आंदोलन ने भारत में महिलाओं के लिए एक स्थान बनाया। हालाँकि, इस स्वतंत्रता में महिलाएँ विभिन्न शर्तों के साथ आई थीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं द्वारा निभाई गई भूमिका का परीक्षण करें। क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की बड़े पैमाने पर भागीदारी प्रकृति में केवल प्रतीकात्मक थी?

गांधीजी अपने अनूठे तरीकों और तकनीकों जैसे उपवास, धरना, चरखा आदि के माध्यम से, जिसके साथ महिलाएं खुद को जोड़ सकती थीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन (सीडीएम) और आगे के राष्ट्रीय संघर्ष में महिलाओं की बड़े पैमाने पर भागीदारी सुनिश्चित करने में सफल रहे।

सीडीएम (सविनय अवज्ञा आंदोलन) में महिलाओं द्वारा निभाई गई भूमिका:

1. अतीत में एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू जैसी कुछ प्रमुख नेत्रियों द्वारा किए गए आंदोलनो ने जन भागीदारी बढ़ाने का आधार प्रदान किया।
2. महिलाओं ने अपने घरेलू बजट पर महंगे नमक के प्रभाव को अच्छी तरह से समझा था और इसलिए इसका जमकर विरोध किया।
3. यहां तक कि गांधीजी ने भी महिलाओं को आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए कहा।
4. उन्होंने खादी को बढ़ावा दिया और उत्पादन किया और साथ ही विदेशी कपड़े बेचने वाली दुकानों का बहिष्कार किया और उनके सामने धरने दिए।
5. आंदोलन के दौरान महिलाओं ने शराब की दुकानों और अफीम के ठिकाने के बाहर धरना देने जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी।
6. सरोजिनी नायडू ने आंदोलन का नेतृत्व भी किया, उदाहरण के लिए धरसाना साल्ट वर्क्स पर छापेमारी की गई।

बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी केवल प्रतीकात्मक नहीं थी क्योंकि-

1. इसने सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के प्रवेश को चिह्नित किया, इस प्रकार एक मुक्तिदायक अनुभव भी था।
2. आंदोलन के तरीके जैसे धरना, बहिष्कार आदि ने महिलाओं को सामूहिक शक्ति प्रदान की।
3. महिलाओं ने उन मुद्दों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी, जो उन्हें सरकारी करों के अलावा सबसे ज्यादा प्रभावित करते थे, जैसे शराब की बिक्री।
4. इसने बंगाल में क्रांतिकारी संघर्ष में भी महिलाओं की भागीदारी को प्रेरित किया जैसे बीना दास, कल्पना दत्त आदि की भूमिका।
5. बाद के संघर्षों में निरंतर बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी बनी रही, उदाहरण के लिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान।

महिला आंदोलनों की सीमाएं:

1. महिलाओं को अभी भी समान भागीदार के बजाय अधीनस्थ के रूप में माना जाता था।
2. महिलाओं की भागीदारी मुख्यत: शहरी परिघटना थी।
3. लड़कियों की शिक्षा, संपत्ति के अधिकार आदि जैसे महिला विशिष्ट मुद्दों को अभी भी राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाया गया था।
4. राष्ट्रवादियों के बीच रूढ़िवादी नेता सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी के पक्षधर नहीं थे।
5. राष्ट्रवादी लड़ाई में शामिल होने वाली ज्यादातर महिलाएं उन परिवारों से थीं जो पहले गांधीवादी संगठनों में सक्रिय थे। नतीजतन, महिलाओं के राजनीतिकरण के परिणामस्वरूप उनके व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंधों में कोई नाटकीय परिवर्तन नहीं हुआ।

इस प्रकार, सीडीएम में महिलाओं की भागीदारी निश्चित रूप से नारीवादी आंदोलन और एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिंस, सरोजिनी नायडू आदि जैसी नेताओं के लंबे समय से किए गए प्रयासों की परिणति थी, फिर भी भारतीय महिलाओं के पास अभी भी कई बाधाएं थीं जो उनकी वास्तविक क्षमता को सीमित करती थीं।

17. 1919 के अधिनियम को भारत में संसदीय लोकतंत्र के अग्रदूत के रूप में सम्मानित किया गया, जो उससे आपेक्षित था उससे बहुत कम प्रदान किया। 1919 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। परीक्षण कीजिए कि इसने राष्ट्रीय संघर्ष को कमजोर करने का प्रयास कैसे किया?

तत्कालीन राज्य सचिव लॉर्ड मोंटेग्यू के प्रस्ताव (अगस्त 1917) के आधार पर , मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों (1918) को आगे के संवैधानिक सुधारों के लिए घोषित किया गया था, इसी के आधार पर भारत सरकार अधिनियम, 1919 अधिनियमित किया गया था।

1919 अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

केन्द्रीय सरकार:

1. प्रशासन के लिए दो सूचियों में विषयों का विभाजन - केंद्रीय और प्रांतीय सूची बनाई गई।
2. वायसराय कार्यकारी परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या 8 में से 1 से बढ़कर 3 हो गई।
3. द्विसदनीय विधायिका बनाई गई। इसके तहत निचला सदन या केंद्रीय विधान सभा और उच्च सदन या राज्यों की परिषद बने।
4. विधायिका प्रश्न, पूरक प्रश्न पूछ सकती थी और स्थगन प्रस्ताव आदि पारित कर सकती थी।
5. विधायिका बजट के एक भाग (लगभग 25%) पर मतदान कर सकती थी।

प्रांतीय सरकार:

1. द्वैध शासन की शुरुआत की गई।
2. सभी विषयों को दो सूचियों में विभाजित किया गया था- **आरक्षित विषय** कार्यकारी पार्षदों द्वारा शासित थे इनमें कानून और व्यवस्था, वित्त, भूमि राजस्व आदि शामिल थे।
3. **स्थानांतरित विषय** मंत्रियों द्वारा शासित होते थे इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार आदि विषय शामिल थे।
4. विधायिका के प्रति मंत्रियों को उत्तरदायी बनाया गया।
5. विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों के अनुपात में वृद्धि की गई अब कुल संख्या के लगभग 70% सदस्य निर्वाचित होने थे।।
6. महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया।
7. सिखों, भारतीय ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार किया गया।

सुधारों की कमियां:

1. केंद्र में गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद पर विधायिका का कोई नियंत्रण नहीं था।
2. आरक्षित और हस्तांतरित में विषयों का विभाजन तर्कहीन था, और इस प्रकार प्रांतों में एक अव्यवहारिक प्रशासनिक ढांचा बन गया जो सुचारू रूप से नहीं चल सकता था।
3. यद्यपि सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण विषय जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जनता द्वारा चुने गए मंत्रियों को दिए गए थे लेकिन इनका वित्त पर कोई नियंत्रण नहीं था।
4. मताधिकार बहुत सीमित था जो की संपत्ति शिक्षा जैसे कुछ आधारों पर ही दिया गया था।

कमजोर राष्ट्रीय संघर्ष के रूप में:

1. राष्ट्रवादी नेताओं को शांत करने के लिए सुधारो को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया गया।
2. भारतीयों के बीच और विभाजन पैदा करने के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया।
3. सुधारों के मूल्यांकन के संबंध में राष्ट्रवादी नेतृत्व के बीच भी विभाजन उत्पन्न हुआ।
4. इस अच्छी दिखने वाले सुधारों की आड़ में, औपनिवेशिक सरकार ने रौलट एक्ट, 1919 जैसे क्रांतिकारियों के खिलाफ कठोर उपायों का इस्तेमाल किया है।

इस प्रकार, 1919 के अधिनियम की उथल-पुथल और धूर्तता को सुभाष चंद्र बोस के शब्दों में सर्वोत्तम रूप से अभिव्यक्त किया जा सकता है कि, भारत सरकार अधिनियम, 1919 ने लोगों के लिए नई बेड़ियाँ बनाई हैं।

18. भाषाई आधार पर राज्यों की मांग का एक लंबा इतिहास रहा है जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से पहले से है। इस संदर्भ में, स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विवरण दें। क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन एक सफल प्रयास रहा है?

भाषा पर आधारित राज्यों की मांग ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के बहुत पहले उठी थी। लोकमान्य तिलक शायद पहले राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने प्रांतों के भाषाई पुनर्गठन की माँग की।

स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन:

1. कांग्रेस शुरू में भाषा के आधार पर देश को प्रांतों में विभाजित करने के पक्ष में थी, लेकिन 1947 में देश के विभाजन ने कांग्रेस को प्रस्ताव छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया।
2. विभिन्न समितियों जैसे एस.के. धर आयोग, जेवीपी समिति ने राज्यों के भाषाई पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया।
3. जब 1952 में तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य के निर्माण के लिए आमरण अनशन पर बैठे पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई, तो हिंसक आंदोलन को देखते हुए भारत सरकार ने 1953 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग आंध्र प्रदेश राज्य बनाया।
4. आंध्र प्रदेश के निर्माण ने भारत के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह की मांगों को तेज किया, जिसके परिणामस्वरूप सरकार ने 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली आयोग की नियुक्ति की। इसकी सिफारिशों के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया, जिसके आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया।

राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के लाभ:

1. इससे क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृति का पोषण और प्रचार हुआ, जिससे राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई।
2. इसने देश के विभिन्न हिस्सों में चल रहे आंदोलनों और प्रदर्शनों से निपटने में भी मदद की।
3. भाषा के आधार पर बनाए गए राज्य प्रकृति में एकजुट थे क्योंकि लोगों की भाषा और संस्कृति समान थी।
4. इसने भारतीय लोकतंत्र में लोगों के विश्वास को मजबूत किया क्योंकि उनकी मांग को सरकार ने स्वीकार कर लिया था।

भाषाई आधारित पुनर्गठन के नकारात्मक प्रभाव:

1. इसने एक समान राष्ट्रीय पहचान के विकास की प्रक्रिया को बाधित किया और इसने क्षेत्रीय पहचानों को प्रभावी बने रहने दिया। क्षेत्रवाद को बल मिला और अपकेन्द्री शक्तियों को बल मिला।
2. आर्थिक विकास के मुद्दों को कम प्राथमिकता मिली जबकि भावनात्मक मुद्दों ने जोर पकड़ लिया।
3. इसने समान आकार की प्रशासनिक इकाइयों के निर्माण की अनुमति नहीं दी। नतीजतन, संघवाद की अवधारणा को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सका।
4. सरकार ने 1956 में भाषा को आधार बनाकर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया लेकिन यह सभी की मांगों को पूरा करने में विफल रही क्योंकि उस समय भारत में सैकड़ों भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा था। इस वजह से भारत में कई समूहों में असंतोष अभी भी बना हुआ है।

तात्कालिक अर्थों में यह रणनीति सफल रही क्योंकि इसने उस समय भारत के सामने आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने में मदद की। लंबे समय में भाषाई पुनर्गठन की रणनीति वांछित परिणाम देने में विफल

रही क्योंकि सामाजिक-आर्थिक विकास की जरूरतों पर उचित ध्यान नहीं दिया जा सका। भारतीय संघ के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का निर्माण लंबे समय में भाषाई पुनर्गठन की रणनीति की विफलता का स्पष्ट उदाहरण है।

19. माओत्से तुंग द्वारा प्रारम्भ किया गया ग्रेट लीप फॉरवर्ड चीन को कृषि समाज से आधुनिक, औद्योगिक समाज में बदलने में विफल रहा। चीन पर ग्रेट लीप फॉरवर्ड के प्रभाव की जांच करते हुए, इसकी विफलता के कारणों पर चर्चा करें।

माओत्से तुंग ने 1949 में कुओमितांग पर कम्युनिस्ट विजय के बाद टूटे हुए चीन के पुनर्निर्माण की शुरुआत की। इसी क्रम में माओ ने 1958 में 'ग्रेट लीप फॉरवर्ड' की शुरुआत की।

चीन के सामने आने वाली समस्याएं: ग्रेट लीप फॉरवर्ड की आवश्यकता-

1. लंबे समय तक चले गृहयुद्ध और जापान के साथ संघर्ष के बाद, देश में रेलवे, सड़कें और अन्य बुनियादी ढांचे नष्ट हो गए थे और खाद्यान्न की कमी लंबे समय से बनी हुई थी।
2. उद्योग पिछड़ा हुआ था, कृषि अक्षम थी और गरीबों की आवश्यकता की पूर्ति में असमर्थ थी, इन सब के अलावा मुद्रास्फीति नियंत्रण से बाहर हो गई थी।
3. माओ का मानना था कि चीन की इन अद्वितीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए कुछ नया और अलग करना अपेक्षित है
4. कुछ ऐसा जो रूसी अनुभव पर आधारित नहीं था।

ग्रेट लीप फॉरवर्ड के उद्देश्य और कार्यप्रणाली-

1. कम्यून्स की स्थापना 1958 और 1960 के बीच लाखों चीनी नागरिकों को कम्यून्स में स्थानांतरित कर दिया गया। कम्यून्स में, प्रत्येक कार्य को बांटा गया; चाइल्ड केअर से लेकर खाना पकाने तक, दैनिक कर्तव्यों को सामूहिक रूप से किया जाता था।
2. औद्योगिक विकास पर बल देना एक महत्वपूर्ण बदलाव था। माओ आयातित स्टील और मशीनरी पर चीन की निर्भरता को खत्म करना चाहता था। यूएसएसआर और पश्चिम फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर उत्पादन की नीति के बजाय माओ ने हर घर के पिछले भाग में भट्टियां बनाने का आग्रह किया जहां स्क्रैप धातु को उपयोगी स्टील में परिवर्तित किया जा सके।

यह क्यों विफल रहा?

1. अवैज्ञानिक कृषि रणनीतियों को अपनाना जैसे फसलों को एक साथ बहुत करीब से लगाना ।
2. परिवारों को इस्पात उत्पादन के लिए कोटा पूरा करना पड़ता था, इसलिए हताशा में, वे अक्सर उपयोगी वस्तुओं जैसे कि अपने बर्तन, धूपदान और कृषि उपकरण को पिघला देते थे।
3. पीली नदी की बाढ़ ने लगभग 2 मिलियन लोगों की जान ले ली। और 1960 में, एक व्यापक सूखे ने देश की समस्याओं को और बढ़ा दिया।
4. रूस और चीन के बीच संबंध टूट गए इस प्रकार रूस ने सभी सहायता वापस ले ली।
5. ग्रेट लीप फॉरवर्ड ने श्रमिकों के लिए भी उच्च मानक निर्धारित किए थे। इन मानकों और अवास्तविक अपेक्षाओ को पूरा करना श्रमिको के लिए कठिन था।

ग्रेट लीप फॉरवर्ड का प्रभाव:

1. इसने चीन के पारिस्थितिकी तंत्र पर कहर बरपाया। बैकयार्ड स्टील निर्माण योजना के कारण, स्मेल्टरों को बिजली देने के लिए जंगलों को काट दिया गया और जला दिया गया, जिससे यह क्षेत्र अपरदन की चपेट में आ गया।
2. भूमि की उर्वरता बनी रहने के कारण, ग्रेट लीप फॉरवर्ड की पहली शरद ऋतु, 1958 में, कई स्थानों पर एक बहुत अच्छी फसल हुई। हालांकि किसानों की बड़ी संख्या को इस्पात निर्माण में काम करने के लिए भेजा गया था इसलिए फसल काटने के लिए पर्याप्त श्रमिक ही नहीं थे। इसलिए फसलें खेतों में ही सड़ गई ।
3. कम्युनिस्ट अधिकारियों को शांत करने के लिए फसल के आंकड़ों को गलत तरीके से पेश किया गया था। इस तरह की अतिशयोक्ति के परिणामस्वरूप, पार्टी के अधिकारियों ने फसल के अधिकांश हिस्से को शहरों के लिए ले लिया, जिससे किसानों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न का अभाव हो गया।
4. अंत में, चीन में खराब आर्थिक नीति और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के संयोजन के परिणामस्वरूप लगभग 20 से 48 मिलियन लोग मारे गए।

ग्रेट लीप फॉरवर्ड पांच साल तक चलने वाला था, लेकिन केवल तीन दुखद वर्षों के बाद इसे रद्द कर दिया गया। चीन में, 1958 से 1960 के वर्षों को ''तीन कड़वे वर्ष'' के रूप में जाना जाता है। माओत्से तुंग के लिए इसके राजनीतिक दुष्परिणाम भी हुए।।

20. विभिन्न वर्तमान भू-राजनीतिक तनावों की जड़ें अतीत में हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से चल रहे रूस-यूक्रेन संकट के कारणों की चर्चा कीजिए।

वर्तमान में वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव की स्थिति बढ़ी हुई है, और इसका प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था, समाज के साथ-साथ राजनीति पर भी पड़ रहा है। वर्तमान काल के विभिन्न भू-राजनीतिक तनावों की जड़ों का पता अतीत में लगाया जा सकता है।

अतीत में जड़ें रखने वाले वर्तमान भू-राजनीतिक तनाव:

1. मध्य पूर्व में तनाव का लंबा इतिहास रहा है। जैसे- इजरायल का निर्माण, यूएस-ईरान तनाव आदि।
2. भारत-पाकिस्तान के वर्तमान संबंधों की जड़ें अतीत में हैं।
3. चीन-ताइवान संबंधों में तनाव के भी ऐतिहासिक कारण हैं।
4. उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया संघर्ष का कारण भी अतीत में निहित है।
5. वर्तमान में चल रहा रूस-यूक्रेन युद्ध भी ऐतिहासिक कारणों से ही प्रेरित है।

रूस-यूक्रेन संकट का ऐतिहासिक संदर्भः

1. ऐतिहासिक रूप से, क्रीमिया में सेवस्तोपोल सहित, गर्म पानी के (वर्षभर खुले रहने वाले)बंदरगाहों की प्रचुरता के कारण रूस ने काला सागर को अपनी सुरक्षा के केंद्र के रूप में देखा। कैथरीन द ग्रेट ने 1783 में क्रीमिया को ऑटोमन तुर्क साम्राज्य से अलग कर लिया था। 2014 में रूस समर्थित विद्रोहियों ने क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया था, जिसे बाद में रूस द्वारा कब्जा कर लिया गया। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण और क्रीमिया पर कब्जा काला सागर पर नियंत्रण की नीति की निरंतरता है।
2. सदियों से रूस, यूक्रेनी लोगों को रूसी सभ्यता में आत्मसात करने की कोशिश कर रहा है। यह सांस्कृतिक आत्मसातीकरण राष्ट्रवादी यूक्रेनियों को पसंद नहीं आया। वर्तमान भू-राजनीतिक तनाव यूक्रेन की स्वायत्तता की मांग की अभिव्यक्ति भी है।
3. पुतिन ने कहा कि आधुनिक यूक्रेन पूरी तरह से रूस द्वारा बनाया गया था और रूस के यूक्रेनियों के साथ गहरे संबंध हैं। यूक्रेन में हस्तक्षेप न करना अपने ही परिवार को त्यागने जैसा होगा। वास्तव में पुतिन का लक्ष्य रूस के सुनहरे अतीत को पुनर्जीवित करना है।
4. पश्चिमी शक्तियों द्वारा नाटो के गठन ने शीत युद्ध के तनावों के लिए आधार तैयार किया। वर्तमान संकट रूसी सीमा पर नाटो सैन्य उपस्थिति के डर के कारण भी है।
5. पूर्व सोवियत गणराज्य जैसे लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया पहले ही नाटो में शामिल हो गए थे जिसे रूस ने मुश्किल से स्वीकार किया था। इसके बाद रूस ने यूक्रेन और जॉर्जिया के मामले में सीमा रेखा खींची और इसे किसी कीमत पर रोकने की कोशिश कर रहा।
6. शीत युद्ध को बढ़ावा देने वाले साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच लंबे समय से वैचारिक तनाव भी वर्तमान रूस-यूक्रेन संकट के कारणों में से एक है।
7. ऐतिहासिक रूप से रूस ने यूरोप में, विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र में अपने प्रभाव क्षेत्र को बनाए रखने की कोशिश की है। वर्तमान संकट का उद्देश्य भी पूर्वी यूरोप में रूस का प्रभाव पैदा करना भी है।

अतः यह स्पष्ट है कि वर्तमान समय के विभिन्न भू-राजनीतिक तनावों की जड़ें इतिहास में हैं। हालांकि, भू-राजनीति में लगातार बदलाव हो रहा है। कभी भारत और चीन को भाई माना जाता था, लेकिन आज वे लद्दाख क्षेत्र में आमने-सामने हैं। इस प्रकार, इतिहास और वर्तमान दोनों ही दुनिया में भू-राजनीति की स्थिति को निर्धारित करते हैं।

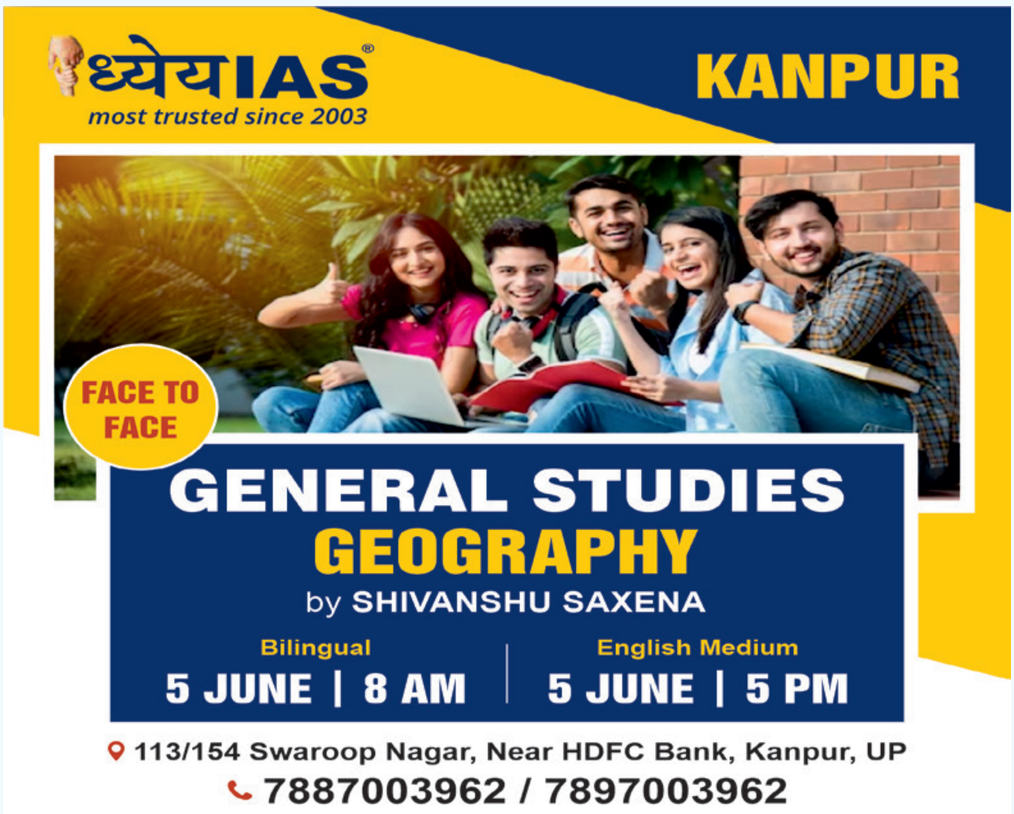

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. बाह्य अंतरिक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
1. बाह्य अंतरिक्ष वह विस्तार है जो आकाशीय पिंडों के बीच और पृथ्वी और उसके वातावरण से परे मौजूद होता है।
2. बाहरी अंतरिक्ष मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम के साथ-साथ विद्युत चुम्बकीय विकिरण, चुंबकीय क्षेत्र, न्यूट्रिनो, धूल और ब्रह्मांडीय किरणों से बना होता है।
3. बिग बैंग से पृष्ठभूमि विकिरण द्वारा निर्धारित बाह्य अंतरिक्ष का आधारभूत तापमान 2.7 केल्विन (-270 डिग्री सेल्सियस; -455 डिग्री फारेनहाइट) होता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सत्य है/हैं?
A. केवल एक B. केवल दो
C. तीनों D. कोई नहीं

उत्तर- C

2. अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
1. अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन बाह्य अंतरिक्ष में सुरक्षित पहुंच, बाह्य अंतरिक्ष में संचालन और भौतिक या रेडियो-आवृत्ति हस्तक्षेप से मुक्त बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी पर वापसी को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी और नियामक प्रावधानों का एक सेट है।
2. अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स (IAA) द्वारा परिभाषित किया गया है
3. अंतरिक्ष यातायात में लॉन्च वाहन, साथ ही परिक्रमा करने वाली वस्तुएं जैसे सभी आकार के उपग्रह और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन शामिल हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
A. केवल एक B. केवल दो
C. तीनों D. कोई नहीं

उत्तर- C

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. स्टंटिंग, जिसे तीव्र कुपोषण के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें बच्चे का वजन उनकी ऊंचाई के लिए स्वस्थ माने जाने वाले वजन से काफी कम होता है।
2. वेस्टिंग को लंबाई के अनुपात में कम वजन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह एक बच्चे की ऊंचाई की तुलना उसी आयु वर्ग के बच्चों की औसत ऊंचाई लेकर मापा जाता है।
3. मोटापे को शरीर में वसा के अत्यधिक या असामान्य संचय के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?
A. केवल एक B. केवल दो
C. तीनों D. कोई नहीं

उत्तर- C

4. निम्नलिखित पर विचार करें:
1. एक छोटे उद्यम में संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होता है।
2. एक मध्यम उद्यम में संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 250 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
A. केवल 1 B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर- A

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
1. माइक्रोप्लास्टिक 5 मिमी व्यास तक के छोटे प्लास्टिक कण होते हैं।
2. समुद्री कूड़े (Marine litter) को किसी भी स्थायी, निर्मित या संसाधित ठोस सामग्री के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे समुद्री वातावरण में त्याग दिया जाता है, निपटाया जाता है या छोड़ दिया जाता है।
3. विश्व स्तर पर, प्लास्टिक की वस्तुएं (माइक्रोप्लास्टिक्स सहित) समुद्री कूड़े का सबसे प्रचुर प्रकार हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?
A. केवल एक B. केवल दो
C. तीनों D. कोई नहीं

उत्तर- C

6. गोंगाडी शॉल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. गोंगड़ी स्वदेशी गोंड समुदायों द्वारा बुना गया एक पारंपरिक ऊनी शॉल है।
2. ये सभी मौसम की स्थिति का सामना करने और लंबे समय तक बरकरार रहने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं।
3. गोंगाडी शॉल को बिना किसी रंग के जैविक रूप से तैयार किया जाता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है/हैं?
A. केवल एक B. केवल दो
C. तीनों D. कोई नहीं

उत्तर- B

7. FAO-WFP द्वारा आयोजित 'हंगर हॉटस्पॉट्स' विश्लेषण का क्या उद्देश्य है?
A. कृषि उत्पादकता के उच्चतम स्तर वाले क्षेत्रों की पहचान करना।
B. खाद्य असुरक्षा और अकाल के लिए सबसे कमजोर क्षेत्रों का निर्धारण करना।
C. वैश्विक भुखमरी प्रवृत्तियों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करना।

D. विभिन्न जनसंख्या समूहों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं का विश्लेषण करना।

उत्तर- B

8. हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट 'बॉर्न टू सून: डिकेड ऑफ एक्शन ऑन प्री-टर्म बर्थ' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और यूनिसेफ द्वारा जारी की गई है।

2. रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में अनुमानित प्रीटर्म बर्थ श्रीलंका में सबसे अधिक (16.2%), उसके बाद मलावी (14.5%) और पाकिस्तान (14.4%) में है।

3. शहरी केंद्रों में जीवनशैली में बदलाव, पुरानी बीमारियां और आईवीएफ गर्भधारण जैसे कई कारक प्रीटर्म जन्मों में वृद्धि के साथ जुड़े हुए हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. 1, 2 B. 2, 3
C. 1, 3 D. केवल 1

उत्तर- C

9. नासा के इम्पैक्ट कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. इम्पैक्ट नवाचार, साझेदारी और प्रौद्योगिकी के माध्यम से नासा के पृथ्वी-अवलोकन डेटा के उपयोग के विस्तार के लिए जिम्मेदार है।

2. टीसीएस ने नासा के सहयोग से एक नए भू-स्थानिक फाउंडेशन मॉडल का अनावरण किया, जिसे नासा के इम्पैक्ट के तहत उपग्रह डेटा को उच्च-रिजॉल्यूशन मानचित्रों में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर- A

10. ग्रीनवाशिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. यह किसी उत्पाद, सेवा, या निवेश अवसर के पर्यावरणीय लाभों के बारे में अतिरंजित, भ्रामक, या निराधार दावे करने की प्रथा है।

2. यह उपभोक्ता के भरोसे को कम करता है, क्योंकि लोग गलत सूचना के आधार पर खरीदारी का निर्णय ले सकते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर- D

11. 'अद्वितीय आर्थिक अपराधी संहिता' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. इसके तहत आर्थिक अपराध वाले व्यक्तियों और कंपनियों को टैग किया जाएगा और उनका 360 डिग्री प्रोफाइल होगा।

2. यह केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की मदद से आर्थिक अपराधों की रिपोजिटरी प्रणाली का समन्वय करेगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर- C

12. भारत में मुद्रास्फीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

2. WPI में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का वेटेज सबसे ज्यादा है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर- B

13. ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. ओएनडीसी आपस में जुड़े ई-मार्केटप्लेस का एक नेटवर्क है, जिसके माध्यम से विक्रेता, यहां तक कि ब्रांड भी किसी भी बिचौलियों को दरकिनार कर अपने उत्पादों को सीधे ग्राहकों को बेच सकते हैं।

2. ONDC कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत स्थापित एक गैर-लाभकारी संगठन है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर- A

14. एसेट मैनेजमेंट कंपनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें?

1. एएमसी उच्च-जोखिम और कम-जोखिम दोनों प्रतिभूतियों में निवेश करके पोर्टफोलियो की विविधता को बनाए रखते हैं।

2. सभी एएमसी सेबी द्वारा विनियमित होते हैं।

3. एएमसी को मनी मैनेजमेंट फर्म भी कहा जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है/हैं?

A. केवल एक B. केवल दो
C. तीनों D. कोई नहीं

उत्तर-C

व्यक्तित्व

पंडित राम प्रसाद बिस्मिल

"सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
देखना है जोर कितना बाजूएँ कातिल में है।"

इस पंक्ति के रचयिता महान लेखक, कवि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल है, ये उन महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, जो देश की आजादी के लिये अंग्रेजी शासन से संघर्ष करते हुये शहीद हो गये थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून, 1897 को शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता मुरलीधर, शाहजहांपुर नगरपालिका में कार्यरत थे। राम प्रसाद बिस्मिल महान कवि के साथ-साथ शायर भी थे। इन्होंने उर्दू और हिंदी में अज्ञात, राम और बिस्मिल नाम से कविताएं लिखीं तथा "बिस्मिल कलमी" नाम से प्रसिद्ध हुए। सरफरोशी की तमन्ना जैसे अमर गीत को इन्होंने ही लिखा था जो प्रत्येक भारतीय के दिल में जगह बनाई। इन्होंने हिंदी से बंगाली में अनुवाद का काम भी किया था। इनके द्वारा किए गए काम में बोल्शेविक प्रोग्राम, अ सैली ऑफ द माइंड, स्वदेशी रंग और कैथरीन आदि शामिल हैं। ऋषि अरबिंदो की योगिक साधना का राम प्रसाद बिस्मिल ने अनुवाद किया था। इनके सभी कार्यों को 'सुशील मेला' नाम की सीरीज में प्रकाशित किया गया है। ये आर्य समाज से भी जुड़े थे जहां इनको "सत्यार्थ प्रकाश" नाम की किताब से प्रेरणा मिली। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया है। अपने गुरु और आर्य समाज के प्रचारक स्वामी सोमदेव के माध्यम से इनका संपर्क लाला हरदयाल से भी हुआ था। लाला हरदयाल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक सदस्य थे।

काकोरी कांड : एक नजर

राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 10 लोगों ने सुनियोजित कार्यवाही के तहत 9 अगस्त, 1925 को लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर ब्रिटिश रेलवे द्वारा ले जाई जा रही संग्रहित धनराशि को लूट लिया गया था तथा गार्ड के डिब्बे में तिजोरी को तोड़कर आक्रमणकारी दल चार हजार रुपये लेकर फरार हो गए थे। इस कांड में अशफाकउल्लाह, चन्द्रशेखर आजाद, राजेन्द्र लाहिड़ी, सचीन्द्र सान्याल, मन्मथनाथ गुप्त, राम प्रसाद बिस्मिल आदि शामिल थे। काकोरी कांड ने ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया था। काकोरी कांड के क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करवाने में मदद के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा इनाम घोषित किया, फिर क्रांतिकारियों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी की गई और मुकदमा चलाया गया। रेकॉड्र्स के मुताबिक 18 जुलाई को अवध चीफ कोर्ट में बिस्मिल द्वारा सजा माफी की अपील की गयी थी, वहीं 16 सितम्बर को प्रांतीय वॉयसराय को दया-प्रार्थना भेजी गयी, जिसे अस्वीकृत कर दिया गया। जहाँ 16 दिसम्बर को उन्होंने राष्ट्र के नाम सन्देश भेजा। फांसी से तीन दिनों पहले उन्होंने अपनी मां और दोस्त अशफाकउल्लाह खान को पत्र में लिखा था कि पूरा देश उनकी शहादत को याद करेगा।

उन्होंने मां से प्रार्थना करने को कहा ताकि वह अपना जीवन अपनी मातृभूमि के लिए न्योछावर कर सकें। फांसी देने से पहले जब उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मैं ब्रिटिश शासन का अंत देखना चाहता हूं और यह कहकर उन्होंने शहादत को गले लगा लिया। 19 दिसम्बर 1927 को हमेशा के लिए अमर हो गये। उत्तर रेलवे ने काकोरी स्टेशन का नाम इनके सम्मान में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल रेलवे स्टेशन रखा है। भारत सरकार ने 19 दिसंबर 1997 को बिस्मिल के जन्म शताब्दी वर्ष में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और उनकी रचनायें हमारे बीच हमेशा जिन्दा रहेंगी।

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

UPPCS MAIN BATCH

GENERAL STUDIES
5th & 6th PAPER

HINDI & ENGLISH MEDIUM

5 June | 11:00 AM

For Other Student - 12,000/-
For Dhyeya Student - 10,000/-

UPPCS MAIN TEST SERIES

GENERAL STUDIES + ESSAY + GENERAL HINDI

HINDI & ENGLISH MEDIUM

4 June
9:00 AM & 1:00 PM

For Other Student - 15,000/-
For Dhyeya Student - 12,000/-

COMBO PACK OTHER STUDENT - 22,000/-
COMBO PACK DHYEYA STUDENT - 18000/-

1. If candidate, appeared for the UPPSC interview atleast once, joins the UPPSC Main Examination test series, will get free classes for Paper 5 and Paper 6 in the UPPSC mains batch.
2. If candidate, appeared for the UPPSC Main Examination atleast once, joins the UPPSC Main Examination test series, will be provided with 50% fee waiver for Paper 5 and Paper 6 in the UPPSC mains batch.

SP MARG, CIVIL LINES, PRAYAGRAJ   8853467068, 7459911157

ध्येयIAS®

most trusted since 2003

20 वर्षों का भरोसा

सफलता ही हमारी परम्परा!

4500+ SELECTIONS IN IAS & PCS

₹ 55

dhyeyaias.com

Face to Face Centres

North Delhi : A 12, 13, Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009, Ph: 9205274741/42/44 I **Laxmi Nagar :** 1/53, 2nd floor, Lalita Park, Near Gurudwara, Opposite Pillar no.23, Laxmi Nagar, Delhi -110092, Ph: 9205212500/9205962002 I **Greater Noida :** 4th Floor Veera Tower, Alpha 1 Commercial Belt., Greater Noida, UP - 201310, Ph: 9205336037/38 I **Prayagraj :** II & Ill Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Prayagraj, UP - 211001, Ph: 0532-2260189/8853467068 I **Lucknow (Aliganj) :** A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow, UP- 226024, Ph: 0522-4025825/9506256789 I **Lucknow (Gomti Nagar) :** CP-1, Jeewan Plaza, Viram Khand-5, Near Husariya Chauraha, Gomti Nagar, Lucknow, UP - 226010, Ph: 7234000501/ 7234000502 I **Lucknow (Alambagh) :** 58/1 , Sector-B Opposite Phoenix Mall Gate No. 3, L.D.A Colony , Alambagh Lucknow,, Ph: 7518373333, 7518573333 | **Kanpur :** 113/154 Swaroop Nagar, Near HDFC Bank, Kanpur, UP - 208002, Ph: 7887003962/7897003962 I **Gorakhpur :** Narain Tower, 2nd floor, Gandhi Gali, Golghar, Gorakhpur, Uttar Pradesh 273001, Ph: 7080847474 I **Bhubaneswar :** OEU Tower, Third Floor, KIIT Road, Patia, Bhubaneswar, Odisha -751024, Ph: 9818244644/7656949029

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

ध्येयIAS most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 9205274741, 9205274742, 9205274744